



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राविद्यार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

1] नई दिल्ली, अधिकार जनवरी 1, 1983//पौष 11, 1984
1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1983/PAUSA 11, 1984

इस भाग में चिन्ह पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह इसमें संकलन के रूप में रखा जा सके।
A separate page is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Ministry Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

घोषना मंत्रालय
(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

1.—इस विभाग के दिनांक 1 दिसम्बर,
अधिसूचना संख्या एम-12011/4/82-भा. सं. के
के क्रम संख्या तीन में डा. बी. पी. अधिकारी के स्थान
के लिए जे. के. घोष का नाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान के
प्रतिनिधि के रूप में रखा जाए।

[संख्या एम-12011/4/82-भा. सं. स.]
महेन्द्र नाथ, उप-सचिव

MINISTRY OF PLANNING
(Department of Statistics)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 1.—In this Department's Notification No. M-12011/
42-ITI dated 1st December, 1982 against Sl. No. 3 of para
the name of Prof. J. K. Ghosh is substituted for Dr.
P. Adhikari as representative of ISI on the Committee.

[No. M-12011/4/82-ITI]
MAHENDRA NATH, Dy. Secy.

विस संत्रालय

(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

(आय-कर)

का०जा० 2.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त विविधों
का प्रयोग करते हुए, श्री शिव बाल योगी महराज इस्ट, बंगलौर को 'विरागण
वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली धरविंश के लिए
उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं. 4976/का० सं. 197/125/81-आ०क(ए)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd November, 1982
(INCOME-TAX)

S.O. 2—In exercise of the powers conferred by clause
(v) of the sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby
notifies "Shri Shiva Balayogi Maharaj Trust, Bangalore" for
the purpose of the said section for the period covered by the
assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4976/F. No. 197/125/81-IT(A)]

आयकर

का० आ० ३ --केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री महादेवी बिला मेमोरियल चैरिटी ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचना करती है।

[म 4982/का० स० 197/171/80-आ०क० (प)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3.--In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Mahadevi Birla Memorial Charity Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4982 F. No. 197/171/80-IT(AI)]

आयकर

का० आ० ४ --केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'फिलिप्पिन इस्टीट्यूट फॉर दि स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी' को निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[म 4984/का० स० 197/123/79-आ०क० (प)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4.--In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Christian Institute for the study of Religion and Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1980-81 to 1982-83.

[No. 4984/F. No. 197/123/79-IT(AI)]

आयकर

का० आ० ५ --केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'सेवा निधि ट्रस्ट' को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[स० 4987/का० स० 197/81/80-आ०क० (प)]

(INCOME-TAX)

S.O. 5.--In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Seva Nidhi Trust' for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4987 F. No. 197/81/80-IT(AI)]

आयकर

का० आ० ६ --केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'श्री लिंगपुर मठ' को निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[स० 4988/का० स० 197/12/81/आ०क० (प)]

मिलाप जैन, अवर सचिव

(INCOME-TAX)

S.O. 6.--In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of the section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Shri Chitrapur Math' for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1980-81 to 1983-84.

[No. 4988 F. No 197/12]

MILAP JAIN,

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड

तर्फ दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

आयकर

का० आ० ७ --केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड आयकर ३, 1961 (1961 का 13) की धारा 121 को
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वर्तमान अवधि, मा० 4501 तारीख ३-३-८१ को आणि क्षण में उत्तमता करते हुए निम्नलिखित संशोधन करती है। क्रम मा० 23८० के भास्त्रे स्वभा० १.२ और ३ के तीने को विश्वास प्रविद्यार्थी के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएँगी--

| आयकर आयकर | मुद्द्यालय | अधिकारिना |
|--------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 23८० पश्चिमी बंगाल | कलकत्ता | १. जिला I (१), कलकत्ता २. जिला III (३) क ३. जिला हावड़ा, कनका० ४. विशेष मर्वेश्वर सर्किल कलकत्ता। ५. विशेष मर्वेश्वर सर्किल कलकत्ता। ६. काशी जिला ६, |
| | | यह अधिसूचना 19-4-1982 में प्रभावी होती। |
| | | [मा० स० ५८.] |

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 17th April, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 7.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in partial modification of the previous notification No. 4501 dated 3-3-82 the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments. The existing entries under Column 1,2,3 against Sl No. 23E, shall be substituted by the following entries:—

| Commissioner | Headquarters | Jurisdiction |
|--------------------|--------------|--|
| of Income-tax | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 23E West Bengal-VI | Calcutta | 1. Distt. II (1), Calcutta. 2. Distt. III (3), Calcutta, 3. Distt. Howrah, Calcutta 4. Spl. Survey Cir., Calcutta. 5. Spl. Survey Cir., Calcutta. 6. Companies Distt. Calcutta. |

This notification shall take effect from 19-4-1982.

[No. 4576 /F.No.187/14/-82IT(A

(अधिक)

आय-कर

का०आ० 8.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपग्रहा (1) ने प्रदूष जालियों के प्रतीक वर्णन हुए आय पूर्व वर्ती अधिवित्तन, मा० 4394 तारीख 24-12-1981 का आणिक स्पष्ट में उपलब्धित करने हुए अधिवित्तन संशोधन करता है। इस सा० 10 ओग 1982 के माने स्तम्भ 1, 2 और 3 के नीचे की विचारात् प्रवित्तियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा—

आय-कर आयुक्त

मुख्यालय

अधिकारिता

| 1 | 2 | 3 |
|---------------|--|---|
| 10 गुजरात-I | अहमदाबाद कम्पनी संकिल, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 और 15 अहमदाबाद | |
| 10A गुजरात-II | अहमदाबाद कम्पनी संकिल, 3, 10, 11, 12, 13 और 14 अहमदाबाद संकिल, 1, 2 और 3 अहमदाबाद इ० डी-कम-आर्ड टी संकिल, अहमदाबाद। हिम्मत नहर संकिल। मादासा संकिल। पालनपुर संकिल। | |

यह अदेश 19 अप्रैल, 1982 में प्रभाव होता।

[मा० 4577 फा० सा० 187/14/8-प्राईटी (१३ आई)]

(INCOME-TAX)

S.O. 8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in pursuance of the previous Notification No 4394 dated 24-12-1981 the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment. The existing entries under Col 1, 2 and 3 against Sl No 10 & 10A shall be replaced by the following—

| Commissioner of Income-tax | Headquarters | Jurisdiction |
|----------------------------|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 Gujarat-I | Ahmedabad | Companies, Circles I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV & XV, Ahmedabad |
| 10A Gujarat-II | Ahmedabad | Companies, Circles III X, XI, XII, XIII & XVI Ahmedabad. Circle-I, II & III, Ahmedabad. ED-cum-IT Circle, Ahmedabad. Himatnagar Circle. Modasa Circle. Palanpur Circle. |

This order shall take effect from 19th April, 1982.

[No. 4577/F. No/87/14/82-IT (AI)]

का०आ० 9.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपग्रहा (1) द्वारा प्रदूष जालियों का प्रयाग करने हुए और इस बाबत मध्ये पूर्ववर्ती अधिवित्तनाओं को आशिक स्पष्ट से उपलब्धित करने हुए निदेश देता है कि इससे उप बड़े अनुशूली के स्तम्भ (2) में उत्तिविति। आय-कर आयुक्त अपनी अधिवित्तियों का प्रयोग, ऐसे थोको या अधिकारी के वर्गों या आय या आय के वर्गों या ऐसे समझों या मामलों के वर्गों की बदल करेगा जो उक्त अनुशूली के स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट आय-कर संकिलों/वर्डों या जिलों में समाविष्ट हैं।

परन्तु यह कि आयुक्त आयुक्त ऐसे अधिकारी या मामलों की बाबत भी कृत्य करेगा जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उसके [अधिनियम किसी आय-कर प्राधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं। किए जाए।

परन्तु यह और कि आयुक्त ऐसे अधिकारी या मामलों की बाबत कृत्य नहीं करेगा जो उसकी अधिकारिता के बाहर किसी आय-कर प्राधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं। किए जाए।

| क्रम सा० | आयकर आयुक्त | मुख्यालय | अधिकारिता |
|----------|-------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | दिल्ली-I | नई दिल्ली | 1 कपनी संकिल- 1, नई दिल्ली। 2 कपनी संकिल 7 नई दिल्ली। 3 कपनी संकिल 10 नई दिल्ली। 4 कपनी संकिल 14, नई दिल्ली। 5 कपनी संकिल 15, नई दिल्ली। 6 कपनी संकिल 19, नई दिल्ली। 7 विशेष संकिल 15, नई दिल्ली। 8. विशेष संकिल 1, नई दिल्ली। 9 विशेष संकिल 3, नई दिल्ली। |
| 8क | दिल्ली-II | नई दिल्ली | 1 कपनी संकिल 1, नई दिल्ली। 2 कपनी संकिल 4, नई दिल्ली। 3 कपनी संकिल 5, नई दिल्ली। 4 कपनी संकिल 6, नई दिल्ली। 5 कपनी संकिल 8, नई दिल्ली। 6. कपनी संकिल 9, नई दिल्ली। 7 कपनी संकिल 11, नई दिल्ली। 8 कपनी संकिल 17, नई दिल्ली। 9 कपनी संकिल 18, 21, 25, नई दिल्ली। 10 कपनी संकिल 24, नई दिल्ली। 11 जिला 6 (13), नई दिल्ली। |
| 8ग | दिल्ली-III | नई दिल्ली | 1 जिला 5(8) का छोड़कर जिला 5, नई दिल्ली के सभी बाई। 2 जिला 8, नई दिल्ली के सभी बाई। 3 अतिरिक्त योग्यकांश संकिल 4, नई दिल्ली। 4 कपनी संकिल 3, नई दिल्ली। 5 कपनी संकिल 12, नई दिल्ली। 6 कपनी संकिल 13, नई दिल्ली। |

| | | | |
|----|----------|-----------|--|
| 8क | दिल्ली-2 | नई दिल्ली | 1 कपनी संकिल 1, नई दिल्ली। 2 कपनी संकिल 4, नई दिल्ली। 3 कपनी संकिल 5, नई दिल्ली। 4 कपनी संकिल 6, नई दिल्ली। 5 कपनी संकिल 8, नई दिल्ली। 6. कपनी संकिल 9, नई दिल्ली। 7 कपनी संकिल 11, नई दिल्ली। 8 कपनी संकिल 17, नई दिल्ली। 9 कपनी संकिल 18, 21, 25, नई दिल्ली। 10 कपनी संकिल 24, नई दिल्ली। 11 जिला 6 (13), नई दिल्ली। |
| 8ग | दिल्ली-3 | नई दिल्ली | 1 जिला 5(8) का छोड़कर जिला 5, नई दिल्ली के सभी बाई। 2 जिला 8, नई दिल्ली के सभी बाई। 3 अतिरिक्त योग्यकांश संकिल 4, नई दिल्ली। 4 कपनी संकिल 3, नई दिल्ली। 5 कपनी संकिल 12, नई दिल्ली। 6 कपनी संकिल 13, नई दिल्ली। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------|---------|--|------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| 84 विली 4, | नई विली | 7. कपनी सकिल 16, नई दिल्ली 8 कपनी सकिल 20, नई दिल्ली 9 कपनी सकिल 23, नई दिल्ली 10 मम्पवा शुल्क तथा आय-कर संवित, नई दिल्ली। | | 6 जिला 11, नई दिल्ली के सभी बाहू। | 7 विशेष सकिल 14, नई दिल्ली। | 8 विशेष सकिल-6 (अतिरिक्त) और विशेष सकिल-16 नई दिल्ली, जो उन सभी व्यक्तियों के मामलों के सबूत में कार्यवाही करने के लिए है जिनके सबूत में आनंदगी सुखा अधिनियम (नस्करि किला याप) और विशेषी मुद्रा वृ. यूडास्ट के लिए (ओर/वा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्खीन निवारण अधिनियम, 1974 के प्रशीन निराधारेण किया गया है और जो आयकर आयुक्त केन्द्रीय) नई विली को छोड़कर दिल्ली स्थित सभी आयकर आयुक्तों की प्रधिवाचिनी के अवीन है। | 9 जिला 5(8), नई दिल्ली। | |
| 85 विली-5, | नई विली | 1 जिला-3-क, नई दिल्ली के सभी बाहू। 2 जिला-3-ज, नई दिल्ली के सभी बाहू। 3 जिला-3-ग, नई दिल्ली के सभी बाहू। 4 ग्रामीण सकिल, नई दिल्ली। 5 सर्वेक्षण सकिल, 3, नई दिल्ली। | 85 विली-8, | नई विली | 1 जिला 10, नई दिल्ली व सभी बाहू। 2 गवाहण सकिल 4, नई दिल्ली। 3 उकेदार सकिल नई दिल्ली, जो भी व्यक्तियों के, (जिनके अन्यांत यथास्थिति फसी या कार्यवाही करते हैं या उनके आगीदारों या उनके निवेशकों के जो आयकर आयुक्त, दिल्ली 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 और आयुक्त या आयुक्त (अन्वेषण) दिल्ली, नई विली की अधिकारिता के अधीन सड़क परिवहन प्रबालकों का कार- बार या बृति करते हैं। सामग्रे भी हैं सबूत में कार्यवाही करते हैं | 4 जिला 11, नई दिल्ली के सभी बाहू। 5 विशेष सकिल 6 और 10, नई दिल्ली। 6 चार्टर्ड अकाउटेंट सकिल, नई दिल्ली जो भी व्यक्तियों के (जिनके अस्तगत फसी और उनके आगीदारों के मामले हैं) जो आयुक्त दिल्ली- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आयकर आयुक्त | | |
| 86 विली 6, | नई विली | 1 देश पालिन, नई विली। 2 प्राइवेट वेतन सहित, नई दिली। 3 टी डी एस सकिल, नई विली। 4 न्याय सकिल, नई विली। 5 अलिय्य निधि सकिल नई दिली | | | | | | |
| 87 विली 7, | नई विली | 1. जिला 1, नई विली के सभी बाहू। 2. जिला 3, नई विली के सभी बाहू। 3. जिला 3 (19) से (23) और जिला 3(27) नई विली। 4. जिला 6 (13) नई विली को छोड़कर जिला 6, नई विली के सभी बाहू। 5. जिला 9 नई विली के सभी बाहू। | | | | | | |

1 2 3

4 5 6 7 8

(अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली की प्रधिकारिता के प्रधन चार्टड प्रकाउटेंटों वा बार-बार या बूनि करते हैं, संबंध में कार्रवाई करता है।

7 विधि अवधारी मर्किल नई दिल्ली जो सभी व्यक्तियों के, (जिसके अन्तर्गत कर्मी, उनके आगीदारों के मामले भी हैं) जो आयकर आयुक्त (अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली, की प्रधिकारिता के अधीन विधि अवधारी का जिसके अन्तर्गत साती-सिटर और व्यवित्रता भी है कारबार या सूचि करते हैं, संबंध में कार्रवाई करता है।

8 चिकित्सक गर्किल, नई दिल्ली जो सभी व्यक्तियों के (जिसके अन्तर्गत पर्नी और उसके आगीदारों के मामले भी हैं) जो आयकर आयुक्त विल्ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आयकर आयुक्त अन्वेषण विल्ली, नई दिल्ली की प्रधिकारिता के अधीन एकाधिक, हीमोपथिक यूनिटी, अयुर्वेदिक या चिकित्सा की कोई प्रत्येक घटना के विभिन्ना अवधारी विकारण चिकित्सक और रोगतिकारी का कारबार या बूनि करते हैं, संबंध में कार्रवाई करता है।

(अन्वेषण) दिल्ली मर्किलों, ऐसे मर्फी नए मामलों के संबंध में कार्रवाई करते थाले सर्वेक्षण/वार्ड/सकिल जहो विवरणियाँ प्रथम बार 1-5-1980 को या उसके पश्चात् फाइल को आती हैं या ऐसे मामले जिनके संबंध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है और जहाँ आयकर अधिनियम की घारा 139 (2) या 148 के प्रदीन सूचना 1-7-1980 को या उसके पश्चात् आरी

भी जारी है और जो कपड़ों मर्किलों, टेक्निकल मर्किलों, परिवहन मर्किलों, बैनर मर्किलों प्राइवेट वेन्यू मर्किलों, टोँडी-ग्रूप मर्किलों वाले एकाउटेंट मर्किलों विकिसक नर्किलों, फिल अपैलारी मर्किलों और प्रसिद्ध सकिलों, नई दिल्ली को आइकर आयकर, आयुक्त दिल्ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आयकर आयुक्त (अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली को अत्राव अधिकारिता के हैं।

यह अधिसूचना 19 अप्रैल, 1982 को प्रवाही हार्दी।

[सं. 4578/फांस० 197/14/4-प्राइटी (ग भाई)]

S.O. 9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of all previous modifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto shall exercise jurisdiction in respect of such areas or of such persons or clauses of persons or of such incomes or classes of incomes or of such cases or classes of cases as are comprised in the Income-tax Circles, Wards or Districts referred to in the Column (4) of the said Schedule.

Provided that a Commissioner of Income-tax shall also perform his functions in respect of such persons or of such case as have been or may be assigned by the Central Board of Direct Taxes to any Income-tax Authority Subordinate to him.

Provided further that a Commissioner shall not perform his functions in respect of such persons or such cases as have been or may be assigned to any Income-tax Authority outside his jurisdiction.

SCHEDULE

| S. No. | Commissioner of Income-tax | Headquarters | Jurisdiction | |
|--------|----------------------------|--------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Delhi-I | New Delhi | 1. Companies Circle-II, New Delhi, 2. Companies Circle-VII, New Delhi, 3. Companies Circle-X, New Delhi, 4. Companies Circle-XIV, New Delhi, 5. Companies Circle-XV, New Delhi. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------|------------|---|---|----|-----------|--|
| | | | | 6. Companies Circle-XIX, New Delhi. | | | 5. Survey Circle-III, New Delhi. |
| | | | | 7. Special Circle-XV, New Delhi. | | | 6. Transport Circle, Delhi dealing with the cases of all persons (includ- ing the cases of firms or companies the part- ners or as the case may be, the Directors there- of carrying on busi- ness or profession as Road Transport Opera- tors under the juris- diction of Commis- sioner of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII & Commissioner of In- come-tax, (Inv.), Delhi, New Delhi. |
| 8A | Delhi-II | New Delhi | | 1. Companies Circle-I, New Delhi. | | | |
| | | | | 2. Companies Cir. IV, New Delhi. | | | |
| | | | | 3. Companies Cir. V, New Delhi. | | | |
| | | | | 4. Companies Cir. VI, New Delhi. | | | |
| | | | | 5. Companies Cir. VII, New Delhi. | | | |
| | | | | 6. Companies Cir. IX, New Delhi. | | | |
| | | | | 7. Companies Cir. XI, New Delhi. | 8D | Delhi-V | New Delhi. |
| | | | | 8. Companies Cir. XVII, New Delhi. | | | 1. All Wards in Distt. II, New Delhi. |
| | | | | 9. Companies Cir. XVIII, XXI, XXV, New Delhi. | | | 2. All Wards in Distt. IV, New Delhi. |
| | | | | 10. Companies Cir. XXIV, New Delhi. | | | 3. All Wards in Distt. VII, New Delhi. |
| | | | | 11. Distt. VI(13), New Delhi. | | | 4. Refund Circle, New Delhi. |
| 8B | Delhi-III | New Delhi. | | 1. All Wards in Distt. V, New Delhi except Distt. V(8). | 8E | Delhi-VI | New Delhi. |
| | | | | 2. All Wards in Distt. VIII, New Delhi. | | | 1. Salary Circles, New Delhi. |
| | | | | 3. Addl. Survey Cir. IV, New Delhi. | | | 2. Pvt. Salary Circles, New Delhi. |
| | | | | 4. Companies Cir. III, New Delhi. | | | 3. T.D.S. Circles, New Delhi. |
| | | | | 5. Companies Cir. XII, New Delhi. | | | 4. Trust Circles, New Delhi. |
| | | | | 6. Companies Cir. XIII, New Delhi. | 8F | Delhi-VII | New Delhi. |
| | | | | 7. Companies Cir. XV, New Delhi. | | | 1. All Wards in Distt. I, New Delhi. |
| | | | | 8. Companies Cir. XX, New Delhi. | | | 2. All Wards in Distt. III-D, N. Delhi. |
| | | | | 9. Companies Cir. XXIII, New Delhi. | | | 3. Distt. III (19) to (23) & Distt. III (27), New Delhi. |
| | | | | 10. Estate Duty-cum-II Circle, New Delhi. | | | 4. All Wards in Distt. VI, New Delhi except Distt. VI (13), New Delhi. |
| | | | | 11. Addl. Estate Duty- cum-I.T. Circle, New Delhi. | | | 5. All Wards in Distt. IX, New Delhi. |
| 8C | Delhi-IV | New Delhi. | | 1. All Wards in District- III-A, New Delhi. | | | 6. All Wards in Distt. XI, New Delhi. |
| | | | | 2. All Wards in District- III-B, New Delhi. | | | 7. Spl. Cir. XIV, New Delhi. |
| | | | | 3. All Wards in District- III-C, New Delhi. | | | 8. Special Circle-VI (Addl.) and Special Circle-XVI, New Delhi for dealing with the cases of all persons in respect of whom an |
| | | | | 4. Evacuee Circles, Ne Delhi. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|

order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security Act (for smuggling activities) and foreign Exchange racketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and which are under the jurisdiction of all Commissioners of Income-tax at Delhi excluding the Commissioner of Income-tax (Central), New Delhi.

9. Distt. V(8), New Delhi,

8G Delhi-VIII New Delhi.

1. All Wards in Distt. X, New Delhi.
 2. Survey Circle-IV, New Delhi.
 3. Contractors Circles, Delhi dealing with the cases of all persons (including the cases of firm or companies, the partners of as the case may be, the directors thereof) carrying on business or profession as Architects, Engineers and Contractors for carrying out any work (including supply of labour for carrying out any work under the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi).

4. Companies Cir. XXII
New Delhi.

5. Spl. Cir. VI & X,
New Delhi.

6. Chartered Accountant's Circles, New Delhi, dealing with the cases of all persons (including in the cases of firm partners, thereof carrying on business or profession as Chartered Accountants under the Jurisdiction

of Commissioners of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioners of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi.

7. Lawyer's Circle, New Delhi dealing with the cases of all persons (including in the case of firms partners thereof) carrying on business or profession as Lawyers (including solicitors and advocates) under the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi.

8. Doctors Circles, New Delhi, dealing with the cases of all persons (including in the cases of firms, partners thereof) carrying on business or profession as Medical Practitioners of Allopathic, Homeopathic, Unani, Ayurvedic or any other system of medicine Radiologists and Pathologists under the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi.

8H (Inv.) Delhi. New Delhi.

Survey Wards/Circles dealing with all new cases where returns are filed for the first time on or after 1-5-1980 or cases which have not neither to been assessed and where notice u/sec. 139(2) or 148 of Income-tax Act, 1961 is to be issued on or after 1-7-1980 pertaining to the territorial jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.) Delhi, New Delhi except cases relating to

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|-----|------------|--------|---|
| | | | Companies Circles, Contractor Circles, Transport Circles, Salary Circles, Private Salary Circles, T.D.S Circles, Trust Circles, Chartered Accountants Circles, Doctors Circles, Lawyers Circles and Refund Circles, New Delhi | 21घ | तमिलनाडु-5 | मद्रास | 1 नगर संकिल- VI, मद्रास 2 विल्लुपुरम संकिल 3 पाडिचेनी संकिल 4 कुड्डोलोर संकिल 5 नामपट्टनम संकिल 6 यजावूर मंकिल । 7 काचीपुरम संकिल । 8 वेलोर मंकिल । 9 तावरम मंकिल । |

This notification takes effect from 19th April, 1982.

[No 4578/F No 187/14/82-IT (AI)]

का०आ० 10—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपशारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बाबत सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आशिक रूप से उपायानियन्त्रित करने हुए निर्देश देती है कि इससे उपाय अनुसूची के संभव (2) में उल्लिखित आयकर आयुक्त आपनी अधिकारिता का प्रयोग, ऐसे क्षेत्रों या व्यक्तियों के बारे या आय या आय के बारे या ऐसे मामलों जो मामले के बारे की बाबत करेगा जो उक्त अनुसूची के संभव 4 में निर्दिष्ट आयकर संकिलों, वार्डों या ज़िलों में समाविष्ट हैं ।

परन्तु यह कि आयकर आयुक्त ऐसे व्यक्तियों या मामलों की बाबत भी कृत्य करेगा जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उनके अधीनस्थ किसी आयकर प्राधिकारी का समन्वयनित किए गए हैं या किए जाएं ।

परन्तु यह और कि आयुक्त ऐसे व्यक्तियों या मामलों की बाबत कृत्य नहीं करेगा जो उसकी अधिकारिता के बाहर किसी आयकर प्राधिकारी को समन्वयनित किए गए हैं या किए जाएं ।

अनुसूची

| क्रम सं० | आयकर आयुक्त | मुख्यालय | अधिकारिता |
|----------|-------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | तमिलनाडु-1 | मद्रास | 1 नगर संकिल- I, मद्रास 1 2 विदेश अनुभाग, मद्रास |
| 21क | तमिलनाडु-2 | मद्रास | 1 कंपनी संकिल-I, मद्रास 2 कंपनी संकिल-II, मद्रास 3 नगर संकिल III, मद्रास 4 नगर संकिल-IV, मद्रास |
| 21घ | तमिलनाडु-3 | मद्रास | 1 इडी तथा आई टी संकिल, मद्रास 2 द्वडी तथा आई टी संकिल, यजावूर 3 कंपनी संकिल III, मद्रास 4 नगर संकिल II, मद्रास 5 नगर संकिल-VII, मद्रास 6 हुड्डी संकिल, मद्रास I |
| 21ग | तमिलनाडु-4 | मद्रास | 1 वेतन संकिल-I, मद्रास 2 वेतन संकिल II, मद्रास 3 प्रतिशाय संकिल, मद्रास 4 नगर संकिल-V मद्रास 5 फिल्स संकिल, मद्रास |

| 21घ | मदुरै | मदुरै | 1 कंपनी संकिल- I, कोइंबतूर । 2 कंपनी संकिल-II, कोइंबतूर 3 कंपनी संकिल III, कोइंबतूर 4 कंपनी संकिल IV, कोइंबतूर 5 कंपनी संकिल V, कोइंबतूर 6 नगर संकिल I, कोइंबतूर 7 नगर संकिल II, कोइंबतूर 8 नगर संकिल III, कोइंबतूर 9 वेतन संकिल, कोइंबतूर 10 उदाकमड संकिल । 11 पोलाची संकिल 12 तिरुप्पुर संकिल 13 इरोडे संकिल 14 कुण्णगिरि संकिल । 15 कंपनी संकिल, मलेम । 16 संकिल, मलेम । 17 संकिल-II सलेम । 18 संपदा शुल्क तथा आयकर संकिल, कोइंबतूर । |
|-----|-----------|--------|--|
| 21घ | (अन्वेषण) | मद्रास | 1 विशेष संवेषण संकिल, मद्रास । 2 विशेष संवेषण संकिल, मदुरै । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------|---|---|---|
| | | 3 विशेष सर्वेक्षण मण्डिन, कोडंबतूर। | 21C Tamil Nadu-IV Madras | 1. Salary Circle-I, Madras. | | | |
| | | 4 विशेष सर्वेक्षण मण्डिल I, II, और III मद्रास। | | 2. Salary Circle-II, Madras. | | | |
| | | 5 विशेष सर्वेक्षण मण्डिल कोडंबतूर। | 21D Tamil Nadu-V Madras | 3. Refund Circle, Madras. | | | |

यह प्रधिकृतता १९-४-८२ से प्रभावी होगी।

[सं ४५७९/फा०मं० १८७/१४/८२-प्र०१००टा (ए.आई.)]
पी०वी० श्रीनिवासन, सचिव

(INCOME-TAX)

S.O. 10.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of all previous modifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax mentioned in Column (2) of the Schedule annexed hereto shall exercise jurisdiction in respect of such areas or of such persons or classes of persons or of such incomes or classes of incomes or of such cases or classes of cases as are comprised in the Income-tax Circles, Wards or Districts referred to in the column (4) of the said Schedule:

Provided that a Commissioner of Income-tax shall also perform his functions in respect of such persons or of such cases as have been or may be assigned by the Central Board of Direct Taxes to any Income-tax Authority subordinate to him;

Provided further that a Commissioner shall not perform his functions in respect of such persons or of such cases as have been or may be assigned to any Income-tax Authority outside his jurisdiction.

SCHEDULE

| S. No. | Commissioner Head- quarters of Income-tax | Jurisdiction | |
|-----------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Tamil Nadu-I Madras | 1. City Circle-I, Madras. 2. Foreign Section, Madras. | |
| 21A | Tamil Nadu-II Madras | 1. Company Circle-I, Madras. 2. Company Circle-II, Madras. 3. City Circle-III, Madras. 4. City Circle-IV, Madras. | |
| 21B | Tamil Nadu-III Madras | 1. ED-cum-IT Circle, Madras. 2. ED-cum-IT Circle, Thanjavur. 3. Company Circle-III, Madras. 4. City Circle-II, Madras. 5. City Circle-VII, Madras. 6. Hundi Circle, Madras. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 21C | Tamil Nadu-IV Madras | 1. Salary Circle-I, Madras. | 1. Salary Circle-I, Madras. |
| | | 2. Salary Circle-II, Madras. | 2. Salary Circle-II, Madras. |
| | | 3. Refund Circle, Madras. | 3. Refund Circle, Madras. |
| | | 4. City Circle-V, Madras. | 4. City Circle-V, Madras. |
| | | 5. Film Circle, Madras. | 5. Film Circle, Madras. |
| | | 6. City Circle-VI, Madras. | 6. City Circle-VI, Madras. |
| | | 7. Villuputnam Circle. | 7. Villuputnam Circle. |
| | | 8. Pondicherry Circle. | 8. Pondicherry Circle. |
| | | 9. Cuddalore Circle. | 9. Cuddalore Circle. |
| | | 10. Nagapattinam Circle. | 10. Nagapattinam Circle. |
| | | 11. Thanjavur Circle. | 11. Thanjavur Circle. |
| | | 12. Kanchipuram Circle. | 12. Kanchipuram Circle. |
| | | 13. Vellore Circle. | 13. Vellore Circle. |
| | | 14. Tambaram Circle. | 14. Tambaram Circle. |
| | | 15. Com. Cir., Tiruchirappalli. | 15. Com. Cir., Tiruchirappalli. |
| | | 16. City Cir. I, Tiruchirappalli. | 16. City Cir. I, Tiruchirappalli. |
| | | 17. City Cir. II, Tiruchirappalli. | 17. City Cir. II, Tiruchirappalli. |
| | | 18. Karur Circle. | 18. Karur Circle. |
| | | 19. Pudukkottai Circle. | 19. Pudukkottai Circle. |
| | | 20. Karaikudi Circle. | 20. Karaikudi Circle. |
| | | 21. Company Circle, Madurai. | 21. Company Circle, Madurai. |
| | | 22. Madurai Circle. | 22. Madurai Circle. |
| | | 23. Spl. Cir. Madurai. | 23. Spl. Cir. Madurai. |
| | | 24. Dindigul Circle. | 24. Dindigul Circle. |
| | | 25. Tuticorin Circle. | 25. Tuticorin Circle. |
| | | 26. Virudhunagar Circle. | 26. Virudhunagar Circle. |
| | | 27. Nagercoil Circle. | 27. Nagercoil Circle. |
| | | 28. ED-cum-IT Circle, Madurai. | 28. ED-cum-IT Circle, Madurai. |
| | | 29. Com Cir. I, Coimbatore. | 29. Com Cir. I, Coimbatore. |
| | | 30. Com. Cir. II, Coimbatore. | 30. Com. Cir. II, Coimbatore. |
| | | 31. Com. Cir. III, Coimbatore. | 31. Com. Cir. III, Coimbatore. |
| | | 32. Com. Cir. IV, Coimbatore. | 32. Com. Cir. IV, Coimbatore. |
| | | 33. Com. Cir. V, Coimbatore. | 33. Com. Cir. V, Coimbatore. |
| | | 34. City Cir. I, Coimbatore. | 34. City Cir. I, Coimbatore. |
| | | 35. City Cir. II, Coimbatore. | 35. City Cir. II, Coimbatore. |
| | | 36. City Cir. III, Coimbatore. | 36. City Cir. III, Coimbatore. |
| | | 37. Salary Circle, Coimbatore. | 37. Salary Circle, Coimbatore. |
| | | 38. Ootacamund Circle. | 38. Ootacamund Circle. |
| | | 39. Pollachi Circle. | 39. Pollachi Circle. |
| | | 40. Tiruppur Circle. | 40. Tiruppur Circle. |
| | | 41. Erode Circle. | 41. Erode Circle. |
| | | 42. Krishnagiri Circle. | 42. Krishnagiri Circle. |
| | | 43. Com. Cir., Salem. | 43. Com. Cir., Salem. |
| | | 44. Circle I, Salem. | 44. Circle I, Salem. |
| | | 45. Circle II, Salem. | 45. Circle II, Salem. |
| | | 46. ED cum IT Cir., Coimbatore. | 46. ED cum IT Cir., Coimbatore. |
| | | 47. Coimbatore. | 47. Coimbatore. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

| | |
|----------------------------|--|
| 21G (Investigation) Madras | 1. Spl. Survey Cir., Madras. |
| | 2. Spl. Survey Cir., Madurai. |
| | 3. Spl. Survey Cir., Coimbatore. |
| | 4. Spl. Inv. Circles, I, II & III, Madras. |
| | 5. Spl. Inv. Circle, Coimbatore |

This notification shall come into force from 19-4-1982.
[No. 4579/F. No. 187/14/82 IT (AI)]

V.B. SRINIVASAN, Secy

नई दिल्ली, 29 प्रैम, 1982

प्राप्तिकर्ता

का० ३०। ११—प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भागकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्मितयों का प्रयोग करने हुए, पर्याप्त अधिवृत्ता सं० 4579 तारीख 17-4-82 का निम्नलिखित संशोधन करता है।

अब सं०-२१ग और २१इ के सामने स्तम्भ 4 के नीचे निम्नलिखित प्रविधियाँ जोड़ी जाएंगी।

| अब सं० भागकर ज्युक्त | सुधारात्मक | प्रधिकारिता | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21C समिलनाडु-IV | मद्रास | 6 कंपनी मण्डिल IV मद्रास | |
| 21C समिलनाडु-V | मद्रास | 10 कुंबकोनम सकित। | |

यह आवेदन 19-4-1982 से प्रभावी होगा।
[सं० 4592/का० सं० 187/14/82-बाई टी. (ए बाई)]
मिलाप जैन, अधिकारी, सचिव

New Delhi, the 29th April, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 11.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to its Notification No. 4579 dated 17-4-82.

The following entries shall be added under Col. 4 against Sl. No. 21 C and 21D.

| Sl. No. | Commissioner Head quarters | Jurisdiction |
|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 21C | Tamil Nadu IV Madras | 6, Comp. Circle IV, Madras. |
| 21D | Tamil Nadu V Madras | 10, Kumbakonam Circle. |

This order shall take effect from 19-4-1982.

[N]. 4592/F. No. 187/14/82 IT (AI)
MILAP JAIN, Under Secy.

आदावक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

का० ३०। १२—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शर्मितयों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय रिजर्व बैंक द्वारा सिफारिश पर एन्टद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपब्रह्म, एवं धारा 9 की ओर अर्थे का अवधि के लिए अधिनियम 20 दिसम्बर, 1983 तक, बैंकिंग बैंक लिमिटेड, मंगलोर १३ उम सोमा तक लागू नहीं होने जहाँ तक इनका सबध, कुंडोल, जिला-धारवाहक, बांगटिक में इसके द्वारा १०,८११ और ८१२ अधिनियम सभ्याओं वाली दुकान तथा ठीन के महाराष्ट्र महिला दो भौजिला मकान की अक्षत सम्पत्ति की घारिता से है।

[मंद्या १६/३२/८२-व० ओ०-III]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 12.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Karnataka Bank Ltd., Mangalore, for a further period of one year i.e. upto the 29th December, 1983 in respect of the immovable property of a two storied house including shop and tin godowns bearing municipal Nos. 810, 811 and 812 held by it at Kundgol, Dharwar District, Karnataka.

[No. 15/32/82-B.O III]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1982

का० ३०। १३.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शर्मितयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एन्टद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपब्रह्म (I) और (II) के उपब्रह्म 28 जून, 1983 तक की अवधि के लिए केन्द्र बैंक पर उम सीमा तक लागू नहीं होगे, जहाँ तक ये उपब्रह्म इसके अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के केरल इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कॉन्सलटेसी आर्मेनियन इंजीनियरिंग लिमिटेड, के निदेशक होने पर इसलिए पांच वर्ष लगाते हैं कि वह, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत एक कंपनी है और (ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपब्रह्म 28 जून, 1983 तक की अवधि के लिए केन्द्र बैंक पर उम सीमा तक लागू नहीं होगे, जहाँ तक ये उपब्रह्म उक्त बैंक के केरल इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कॉन्सलटेसी आर्मेनियन इंजीनियरिंग की शेयर घारिता पर पावडी लगाते हैं।

[मंद्या १५/२८/८२-ब० ओ०-II J]

एन० डी० बत्ता, अधिकारी, सचिव

S.O. 13.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that (a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Canara Bank for a period upto 28th June, 1983 in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Managing Director from being the Director of the Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd., being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and that (b) the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply to Canara Bank for a period upto the 28th June, 1982 in so far as the said provisions prohibit it from holding shares in the Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.

[No. 15/28/82-B.O.III]
N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1982

का० आ० 14—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 56 के माय पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शर्कियों के अनुमति में और भारत के दिनांक 4 अगस्त, 1979 के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली की दिनांक 19 जुलाई, 1979 को सा० आ० स० 2639 के प्रधीन प्राप्तित अधिसूचना सं० 8(22) 79—ए० सी० के रूप में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर गतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 और 34 के उपर्यंथ, किसी महकारी बैंक पर, 20 जुलाई, 1985 तक की और अवधि के लिए वहाँ तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक, राष्ट्रीय महकारी वित्त निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महकारी वित्त निगम ने इस प्रकार के बैंक द्वारा लिए गए ऋणों अपवाह अधिमों के संबंध में उभयूत वाधिकों के सदर्भ में महकारी बैंक द्वारा नकदी प्रारक्षितियों तथा परिसंपत्तियों की प्रतिशतता बनाए रखना आवश्यक है।

वर्णते कि, धारा 18 के अधीन नकद प्रारक्षिति की गणना करते थे। उपर्युक्त बैंक द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उा धारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन रखी गई परिसंपत्तियों की गणना करने में अन्य सभी मांग और समय देयनामों के संबंध में, निगम से लिए गए झण के असंवितरित भाग और निगम में लिए गए उधार के संबंध में निगम को प्रेरित न की गई वसूलियों को छाड़ दिया जाएगा।

[संख्या 8-32/82-ए० सी०]
राम बैरा, अवर मंचित

New Delhi, the 10th December, 1982

S.O. 14.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 7 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) (hereinafter referred to as the said Act) and in continuation of the aforesaid order of the Government of India,

Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi under No. 8(22)/79-AC dated the 19th July, 1979 published at S.O. No. 2639 of the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated 4 August 1979, the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sections 18 and 24 of the said Act shall not, for a further period upto 20 July 1985 apply to a co-operative bank insofar as they require the co-operative bank to maintain the percentage of cash reserve and assets respectively mentioned therein in respect of liabilities arising out of the loans or advances availed of by such bank from National Co-operative Development Corporation established by Government of India under the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962):

Provided that in computing the cash reserve under Section 18 and the assets which the said bank maintained under clause (a) of sub-section (2A) of Section 24 respectively of the said Act, in respect of all other demand and time liabilities, the undisbursed portion of the loan availed of from the Corporation and the unremitted recoveries to the Corporation on account of the borrowing from the Corporation shall be excluded.

[No. 8-32/82-AC]
RAAM BEHRA, Under Secy.

(आयकर विभाग)

(आयकर आयुक्त का कार्यालय)
कोचीन, 4 दिसम्बर, 1982

का० आ० 15.—केन्द्रीय सरकार की राय में धनकर अधिनियम, 1957, की धारा 42-क के प्रधीन निर्धारितियों का नाम और अन्य विशिष्टियों को प्रकाशित किया जाना लोकहित में आवश्यक और समीचित है। प्रतः आयकर आयुक्त, कोचीन प्रभार में वित्तीय वर्ष 1981-82 में 10 लाख रुपये से अधिक शुद्ध धन पर धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रधीन कर निर्धारित किये गये निम्नलिखित व्यक्तियों ('ए' से सूचित किया है) और हिन्दू ओवेम्बर कुटुम्बों ('एच. यू. एफ' से सूचित किया है) के नाम और अन्य विशिष्टिया जैसे (1) निधित्व वर्ष (2) निर्वाचित धन (3) निर्धारित धन (4) कर देय और (5) कर प्रदत्त (सभी रकम रुपये में) एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

1. श्री एम० ए० अजित प्रसाद जैन, मनियूर एस्टेट, कम्पेट्टा 'ए'

(1) 1977-78 (2) 1214000 (3) 1568700
(4) 29315 (5) 29315

(1) 1978-79 (2) 1124800 (3) 1648000
(4) 31451 (5) 31451

(1) 1979-80 (2) 1041500 (3) 1585600
(4) 29214 (5) 29214

(1) 1980-81 (2) पुनर्रूपण/रिट फ्यूल नहीं
किया है (3) 2000000 (4) 43750
(5) नहीं

2. श्री बर्टन रैट, कुट्टनेल्लूर 'ए'

(1) 1980-81 (2) 1079500 (3) 1079500
(4) 16135 (5) 16135

3. श्री के० ए० एनियाकुट्टी विश्वर 'ऐ'
 (1) 1980-81 (2) 1269000 (3) 1337200
 (4) 23866 (5) 23866
4. श्री ए० पी० जोर्ज, इरजालकुडा 'ऐ'
 (1) 1981-82 (2) 1195690 (3) 1156800
 (4) 18454 (5) 18454
5. श्री ए० बी० गोपालकृष्ण वेणाय, न्यू गुण वेणाय आन्ट को द्वारा, एरणाकुलम, 'ऐ'
 (1) 1977-78 (2) 1059568 (3) 1677800
 (4) 32473 (5) 32473
6. श्रीमति म्हाडिस एस० कोडर, 'ऐ'
 (1) 1979-80 (2) 1717000 (3) 1680400
 (4) 25941 (5) 26192
- (1) 1980-81 (2) 1793400 (3) 1784900
 (4) 33298 (5) 32070 और
- (1) 1981-82 (2) 2101545 (3) 2094200
 (4) 32452 (5) 41690
7. श्री जोस अन्टेणी तुनेवत्, चालकुडी 'ऐ'
 (1) 1979-80 (2) 2025000 (3) 2073400
 (4) 46320 (5) 46320
8. श्री के० एफ० जोम, विश्वर 'ऐ'
 (1) 1979-80 (2) 1090000 (3) 1421200
 (4) 24280 (5) 24280 और
- (1) 1980-81 (2) 1535200 (3) 1720100
 (4) 39755 (5) 39755
9. श्री ए० के० कादरकुट्टी, पविलकृष्ण बंगली, टेलिच्चेरी 'ऐ'
 (1) 1977-78 (2) 1216700 (3) 1239700
 (4) 19743 (5) 19743
10. श्रीमति मरियाम्मा कुर्यन, कोलरी, एस्टेट, मेप्पाडी, 'ऐ'
 (1) 1979-80 (2) 937414 (3) 1053200
 (4) 14625 (5) 14454
11. 1 श्री सी० पी० माणी, चालिशेरी हाऊस, विश्वर 'ऐ'
 (1) 1981-82 (2) 1055500 (3) 1055500
 (4) 15415 (5) 15415
12. स्वगीय श्री के० पी० मोयदीनकुट्टी, के० पी० एम० कुंजहम्मद के अधिकृत उत्तराधिकारी, मन्नारकाट 'ऐ'
 (1) 1978-79 (2) 310500 (3) 1198300
 (4) 18707 (5) 1291
13. श्री सी० एम० मुहम्मद कासीम, मरुण मंजिल, चालकुडी, 'ऐ'
 (1) 1981-82 (2) 1004100 (3) 1008900
 (4) 14107 (5) 14017
14. श्री के० बी० मोहम्मद, झंबीर तहीर मंजिल, करवन्नूर 'ऐ'
 (1) 1981-82 (2) 1415800 (3) 1415800
 (4) 26223 (5) 26223
15. श्री ए० एम० नारायण वेणाय, मैसर्म न्यू गुण वेणाय आन्ट को, एरणाकुलम 'ऐ'
 (1) 1977-78 (2) 687817 (3) 1127440
 (4) 16935 (5) 16935
16. श्री एम० एस० नारायणन, एरणाकुलम 'ऐ'
 (1) 1981-82 (2) 1407769 (3) 1402800
 (4) 25834 (5) 25834
17. श्री नीलिकन्ठी कुंजहम्मद हाजी, कलपेटा 'ऐ'
 (1) 1977-78 (2) 478065 (3) 1567200
 (4) 28750 (5) 7500
18. श्री उम्मत पी० कोशी, अलसाडा, एस्टेट, बी० लियझन, पड़गिरी, 'ऐ'
 (1) 1979-80 (2) 1277400 (3) 1217800
 (4) 33873 (5) 33873 और
- (1) 1980-81 (2) 1023200 (3) 1465800
 (4) 25395 (5) 25395।
19. श्रीमति एन० टी० सरोजिनी अम्मा, चेलूर विल्सा, काककनाड, 'ऐ'
 (1) 1979-80 (2) 783803 (3) 1105606
 (4) 16390 (5) 6604
20. श्री एम० सुबैर, हाजी, मारी कुलु, कालिकट 'ऐ'
 (1) 1981-82 (2) 901800 (3) 1036600
 (4) 14665 (5) 11588
21. श्री ए० एस० सुरेष शेणाय, न्यू गुण शेणाय आन्ट को द्वारा, एरणाकुलम 'ऐ'
 (1) 1977-78 (2) 777167 (3) 1248300
 (4) 19958 (5) 19958
22. श्रीमति आर स्वर्णम नारायणन, प्रीति, चिट्टूर रोड, एरणाकुलम 'ऐ'
 (1) 1981-82 (2) 1453300 (3) 1387400,
 (4) 25372 (5) 25372

| | |
|---|---|
| 23. श्री तोमस थी० कांशी, ए०, डिविजन, पड़गिरि नेलियांपती, 'ऐ' | (1) 1971-72 (2) 500000 (3) 2466700 (4) 78465 (5) -- |
| (1) 1979-80 (3) 1799900 (3) 1810500 (4) 37117 (5) 37117 और | (1) 1972-73 (2) 500000 (3) 1877800 (4) 66244 (5) -- |
| (1) 1980-81 (2) 1513100 (3) 1536700 (4) 27535 (5) 27535 | (1) 1973-74 (2) 500000 (3) 1877800 (4) 66244 (5) -- |
| 24. श्री ए० एल० बासुदेव शेणाय, न्यू गुण शेणाय आन्ट को, द्वारा, पर्याकृतम् 'एच० य० एफ०' | (1) 1974-75 (2) 500000 (3) 1877800 (4) 66244 (5) -- |
| (1) 1980-81 (2) 700454 (3) 1003200 (4) 23910 (5) 23910 | (1) 1975-76 (2) 500000 (3) 1882400 (4) 98184 (5) -- |
| 25. श्री बेणुगोपाल बर्मा राजा, कूलनेगांड, 'एच० य० एफ०' | (1) 1976-77 (2) 500000 (3) 1882400 (4) 98184 (5) -- और |
| (1) 1961-62 (2) 226538 (3) 1585200 (4) 196 (5) -- | (1) 1977-78 (2) 500000 (3) 1934000 (4) 50560 (5) -- |
| (1) 1962-63 (2) 501033 (3) 1606900 (4) 1896 (5) -- | 26. श्री एम० जे० विजय पद्मन, विजय मंदिरम, कलपेटा, 'ऐ' |
| (1) 1963-64 (2) पुनरीक्षण रिट फायल नहीं किया है (3) 1707100 (4) 2100 (5) -- | (1) 1976-77 (2) 247600 (3) 1469200 (4) 38764 (5) 8000 और |
| (1) 1964-65 (2) पुनरीक्षण रिट फायल नहीं किया है (3) 1702200 (4) 2460 (5) -- | (1) 1977-78 (2) 8334 (3) 1620700 (4) 26974 (5) -- |
| (1) 1965-66 (2) 500000 (3) 1679900 (4) 4972 (5) -- | [सी० सं० 212/82-83 आर०] जी० आर० पटवधन आयकर आयुक्त |
| (1) 1966-67 (2) 500000 (3) 1679900 (4) 22098 (5) -- | |
| (1) 1967-68 (2) 500000 (3) 1679900 (4) 220 98 (5) -- | |
| (1) 1968-69 (2) 500000 (3) 1679900 (4) 22098 (5) -- | |
| (1) 1969-70 (2) 500000 (3) 1676600 (4) 25755 (5) -- | |
| (1) 1970-71 (2) 500000 (3) 3425700 (4) 81961 (5) -- | |

(Income-tax Department)
Office of Commissioner of Income-Tax
Cochin, the 4th December 1982

S.O. 15.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to publish under section 42A of the Wealth-tax Act, 1957 the names and other particulars relating to the following individuals (indicated by 'P') and Hindu Undivided Family (indicated by 'H.U.F.') who have been assessed under the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) on net wealth exceeding Rs. 10 lakhs, in the Charge of the Commissioner of Income-tax, Cochin, during the financial year 1981-82, such particulars like (i) Assessment year, (ii) Wealth returned, (iii) Wealth assessed, (iv) Tax payable, (v) Tax paid (all amount in rupees) are hereby published:

1. Sri M.A. Ajit Prasad Jain, Maniyur Estate, Kalpetta 'P'

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|------------|-------------|
| (i) 1977-78 | (ii) 1214000 | (iii) 1568700 | (iv) 29315 | (v) 29315 |
| (i) 1978-79 | (ii) 1124800 | (iii) 1648000 | (iv) 31451 | (v) 31451 |
| (i) 1979-80 | (ii) 1041500 | (iii) 185600 | (iv) 29214 | (v) 29214 & |
| (i) 1980-81 | (ii) R/W not filed | (iii) 2000000 | (iv) 43750 | (v) Nil. |

| | | | | |
|-----|---|--------------|----------------|---------------------------|
| 2. | Sri Bartan Wright, Kuttinelloor 'I' | | | |
| (i) | 1980-81 | (ii) 1079500 | (iii) 1079500 | (iv) 16135 (v) 16135 |
| 3. | Sri K.A. Elakkutty, Trichur. 'I' | | | |
| (i) | 1980-81 | (ii) 1269000 | (iii) 1337200 | (iv) 23865 (v) 23866 |
| 4. | Sri A.P. George, Irinjalakuda. 'I' | | | |
| (i) | 1981-82 | (ii) 1195690 | £(iii) 1156300 | (iv) 13454 (v) 13454 |
| 5. | Sri A.V. Gopalakrishna Shenoy, C/o. New Guna Shenoy & Co., Ernakulam. 'I' | | | |
| (i) | 1977-78 | (ii) 1059568 | (iii) 1677800 | (iv) 32473 (v) 32473 |
| 6. | Mrs. Gladys S. Koder. 'I' | | | |
| (i) | 1979-80 | (ii) 1717000 | £(iii) 1680400 | (iv) 25941 (v) 26192 |
| (i) | 1980-81 | (ii) 1793400 | (iii) 1784900 | (iv) 33298 (v) 32070 & |
| (i) | 1981-82 | (ii) 2101545 | £(iii) 2094200 | (iv) 43452 (v) 41690 |
| 7. | Sri Jose Antony Thulevath, Chalakudy. 'I' | | | |
| (i) | 1979-80 | (ii) 2025000 | (iii) 2073400 | (iv) 46320 (v) 46320 |
| 8. | Sri K.F. Jose, Trichur. 'I' | | | |
| (i) | 1979-80 | (ii) 1090000 | (iii) 1421200 | (iv) 24280 (v) 24280 & |
| (i) | 1980-81 | (ii) 1535200 | (iii) 1720100 | (iv) 39755 (v) 39755 |
| 9. | Sri A.K. Kaderkutty, Pallichon Bungallow, Tellickerry. 'I' | | | |
| (i) | 1977-78 | (ii) 1216700 | (iii) 1239700 | (iv) 19743 (v) 19743 |
| 10. | Mrs. Mariamma Kurien, Colerie Estate, Mepoadi. 'I' | | | |
| (i) | 1978-79 | (ii) 937414 | (iii) 1053200 | (iv) 14625 (v) 14454 |
| 11. | Sri C. P. Maney, Chalissery House, Trichur. 'I' | | | |
| (i) | 1981-82 | (ii) 1055500 | (iii) 1055500 | (iv) 15415 (v) 15415 |
| 12. | Late, Sri K. P. Moideenkutty, by L/HK. P.M. Kunjahamed, Mannarghat.. 'I' | | | |
| (i) | 1978-79 | (ii) 310500 | (iii) 1198300 | (iv) 18707 (v) 1291 |
| 13. | Sri C.M. Mohamed Kassim, Maroon Manzil, Chalakudy. 'I' | | | |
| (i) | 1981-82 | (ii) 1004100 | (iii) 1008900 | (iv) 14017 (v) 14017 |
| 14. | Sri K.V. Mohamed' Zakir Thahira Manzil, Karuvannur. 'I' | | | |
| (i) | 1981-82 | (ii) 1415800 | (iii) 1415800 | (iv) 26223 (v) 26223 |
| 15. | Sri A. S. Narayana Shenoy, M/s New Guna Shenoy & Co., Ernakulam. 'I' | | | |
| (i) | 1977-78 | (ii) 687817 | (iii) 1127440 | (iv) 16925 (v) 16935 |
| 16. | Shri S. S. Nayanan, Ernakulam. 'I' | | | |
| (i) | 1981-82 | (ii) 1407769 | (iii) 1402800 | (iv) 25834 (v) 25834 |
| 17. | Sri Neelikandi Kunhammed Hari Kalpetta. 'I' | | | |
| (i) | 1977-78 | (ii) 478065 | (iii) 1567200 | (iv) 28750 £(v) 7500 |
| 18. | Sri Oommen P. Koshy, Alexandra Estate, B. Division, Padagiri. 'I' | | | |
| (i) | 1979-80 | (ii) 1277400 | (iii) 1217800 | (iv) 33873 (v) 33873 & |
| (i) | 1980-81 | (ii) 1023200 | (iii) 1465800 | (iv) 25395 (v) 25395 |
| 19. | Smt. N. T. Sarojini Amma, Cheloor Villa, Kakkanad. 'I' | | | |
| (i) | 1979-80 | (ii) 783803 | (iii) 1105605 | (iv) 16390 (v) 6604 |
| 20. | Sri M. Subair Haji, Marikunnu, Calicut. 'I' | | | |
| (i) | 1981-82 | (ii) 901800 | (iii) 1036600 | (iv) 14665 (v) 11588 |
| 21. | Sri A. S. Suresh Shenoy, C/o. New Guna Shenoy & Co., Ernakulam 'I' | | | |
| (i) | 1977-78 | (ii) 777167 | (iii) 1248300 | (iv) 19958 (v) 19958 |

22. Smt. R. Swarnam Narayanan, Preethi, Chittoor Road, Ernakulam, 'T'

(i) 1981-82 (ii) 1451300 (iii) 1387400 (iv) 25372 (v) 25372

23. Sri Thomas P. Koshy, A. Division, Padagiri, Nelliomuthy, 'T' [

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|
| (i) 1979-80 | (ii) 1799900 | (iii) 1810500 | (iv) 37117 | (v) 37117 & |
| (ii) 1980-81 | (ii) 1513100 | (iii) 1536700 | (iv) 27535 | (v) 27535 |

24. Sri A. L. Vasudeva Shenoy, C/o. New Guna Shenoy & Co., Ernakulam 'HUF'

1980-81 (ii) 700454 (iii) 1003200 (iv) 23910 (v) 23910

25. Sri Venugopala Varma Raja, Kollengode, 'HUF'

| | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|------------|-------|
| (i) 1961-62 | (ii) 226538 | (iii) 1585200 | (iv) 196 | (v) - |
| (i) 1962-63 | (ii) 501033 | (iii) 1606900 | (iv) 1896 | (v) - |
| (i) 1963-64 | (ii) R/W not filed | (iii) 1707100 | (iii) 2100 | (v) - |
| (i) 1964-65 | (ii) R/W not filed | (iii) 1702200 | (iv) 2460 | (v) - |
| (i) 1965-66 | (ii) 500000 | (iii) 1679900 | (iv) 4972 | (v) - |
| (i) 1966-67 | (ii) 500000 | (iii) 1679900 | (iv) 22098 | (v) - |
| (i) 1967-68 | (ii) 500000 | (iii) 1679900 | (iv) 22098 | (v) - |
| (i) 1968-69 | (ii) 500000 | (ii) 1679900 | (iv) 22098 | (v) - |
| (i) 1969-70 | (ii) 500000 | (iii) 1679900 | (iv) 25755 | (v) - |
| (i) 1970-71 | (ii) 500000 | (iii) 3425700 | (iv) 81961 | (v) - |
| (i) 1971-72 | (ii) 500000 | (iii) 2466700 | (iv) 78465 | (v) - |
| (i) 1972-73 | (ii) 500000 | (iii) 1877800 | (iv) 66344 | (v) - |
| (i) 1973-74 | (ii) 500000 | (iii) 1877800 | (iv) 66244 | (v) - |
| (i) 1974-75 | (ii) 500000 | (iii) 1877800 | (iv) 66244 | (v) - |
| (i) 1975-76 | (ii) 500000 | (iii) 1882400 | (iv) 98184 | (v) - |
| (i) 1976-77 | (ii) 500000 | (iii) 1882400 | (iv) 98184 | (v) - |
| (i) 1977-78 | (ii) 500000 | (iii) 1934000 | (iv) 50560 | (v) - |

26. Sri M. J. Vijaya Padman, Vijayam Indiram Kalpetta, 'T'

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
| (i) 1976-77 | (ii) 247600 | (iii) 1469200 | (iv) 38764 | (v) 8000 & |
| (i) 1977-78 | (ii) 8334 | (iii) 1620700 | (iv) 26974 | (v) - |

Ernakulam, Cochin-16.

[C. No. 212/82-83/R]

G. R. PATWARDHAN,
Commissioner of Income Tax, Cochin

4.12.82

Dated :

13.9.904

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

खाद्य

मई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1982

का०ग्रा० 16.—यह: केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाधि निदेशालयों और खाद्य विभाग के बेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के नारीय 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट नारीय के अन्तर भारतीय खाद्य नियम के कर्मचारी न अनन्त के अपने आज्ञा को उक्त अधिनियम की धारा 12 ए के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य नियम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अन्तर संशोधित की धारा 12 ए द्वारा प्रदत्त शर्वितयों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार द्वन्द्वारा निम्न-

अतः अब खाद्य नियम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अन्तर संशोधित की धारा 12 ए द्वारा प्रदत्त शर्वितयों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार द्वन्द्वारा निम्न-

लिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है:

| क्रम सं० | प्रधिकारी/ का नाम | केन्द्रीय सरकार के पद | स्थानान्तरण के समय के लिए केन्द्रीय सरकार के पद | भारतीय खाद्य निगम में स्थान- न्तरण की तारीख |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री ए०पी० मलिक | तकनीकी अधिकारी | महायक निदेशक (तकनीकी) | 30-12-70 |
| 2. | श्री ए०प०ए० मुखर्जी | तकनीकी सहायक | तकनीकी अधिकारी | 1-3-69 |
| 3. | श्री माया राम सुपुत्र श्री शंकर दत्त | - | वाचमैन | 1-3-69 |

[मं० 52/1/82-एफ०सी०-III]

प्रार०क०सिह, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1982

S.O. 16.—Whereas the Central Government has caused to perform the function of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the circular of the Central Govt. dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India, as required by the proviso to Section 12 A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12 A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date, the Central Government hereby transfers the following employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them:—

| Sl. No. | Name of the Officer/ employee | Permanent post held under the Central Govt. | Post held under the Central Govt. at the time of transfer | Date of transfer to FCI |
|------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Shri A. P. Malik | Technical Officer | Asstt. Dir. (Tech.) | 30-12-70 |
| 2. | Sh. N.N. Mukherjee | Technical Asstt. | Tech. Officer | 1-3-69 |
| 3. | Sh. Maya Ram S/o Shri Shanker Dutt | — | Watchman | 1-3-69 |

[No. 52/1/82-FCG-III]
R.K. SINGH, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण बंग्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

S.O. 17.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित दूरदर्शन केन्द्रों को जिनके कर्मचारीवृन्द के हिन्दी का कार्यमाधिकारान् प्राप्त कर रहा है, अधिसूचित करती है:—

1. दूरदर्शन रिले केन्द्र, बंगलौर,
2. दूरदर्शन, केन्द्र, जयपुर,
3. दूरदर्शन केन्द्र, कानपुर,
4. दूरदर्शन केन्द्र, नागपुर,
5. दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई।

[मं० ई-11011/5/82-हिन्दी]

इन्हुं भूषण कर्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 17.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Doordarshan Kendras, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:—

1. Doordarshan Relay Centre, Bangalore.
2. Doordarshan Kendra, Jaipur.
3. Doordarshan Kendra, Kanpur.
4. Doordarshan Kendra, Nagpur.
5. Doordarshan Kendra, Bombay.

[No. E-11011/5/82-Hindi]

I. B. KARN, Under Secy.

श्रम संथा प्रमोर्स संचालन

(श्रम नियम)

नंदे दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० 18.—मिस्री देह विभाग लिमिटेड, 30, के० दुबाश मर्ग
फोर्ट, बम्बई-२३, (महाराष्ट्र/५०६१), (जिसे इसमें इसके पश्चात्
उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी ५. नियम नियि और प्रकारण उपलब्ध
प्रधिनियम, 1952 (1952 का १९) (जिसे इसमें इसके पश्चात्
उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की ओर १७ की उपधारा (२५) के
प्रधीन छूट दिए जाने के लिए अनुमति दिया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के
कर्मचारी, किसी पृथक अधिकारी या प्रीमियम का संदाय किए जिता ही,
भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के संधीय कीवन
बीमा के क्षम में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये कायदे
उन कायदों से प्रतिक भनुकूल हैं जो कर्मचारी नियम सदरबद्ध बीमा स्कीम,
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन
उन्हें अनुमेय हैं।

यथा, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की ओर १७ की उपधारा (२५)
इसके प्रति संविधानों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपावद्ध भनुकूल में
नियिष्ट बातों के प्रधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को नियम सदरबद्ध बीमा स्कीम,
के लिए उक्त स्कीम के सभी उपलब्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुमति

१. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रदेशिक भविष्य नियि भायुकूल
भनुकूल को ऐसी विवरणियों देते हों और ऐसे देखा रखेगा तथा निरीकण
के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर
नियिष्ट करे।

२. नियोजक, ऐसे निरीकण प्रभारी का प्रत्येक भास की समाप्ति के
१८ विन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की
ओर १७ की उपधारा (२५) के बांद (क) के प्रधीन समय-समय पर
नियिष्ट करे।

३. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके प्रधीन नेताओं का
रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय,
नेताओं का अनुराग, नियंत्रण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले
सभी घरों का बहुत नियोजक द्वाय किया जायेगा।

४. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा भनुकूल द्वाय की सामूहिक बीमा
स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए,
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वहस्तका की भाषा में
उसकी उक्त बातों का यनुकूल, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

५. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य नियि का या उक्त
प्रधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किये स्थापन की सविष्य नियि का पाप्त हो
से सवध्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक
सामूहिक बीमा स्कीम के नियम के क्षम में उसका नाम धुरल दर्ज करेगा
और उसकी बाबत में प्रथक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को
उक्त कायदों से अधिक वनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुमेय है।

६. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे
वहाएँ जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों
को उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा
जिसे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे
उक्त कायदों से अधिक वनुकूल हो जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुमेय है।

७. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए लों, यदि किसी
कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के प्रधीन संदेश रकम उस रकम से कम
है, जो कर्मचारा की उत्ता वास में सवेय होती, जब वह उक्त स्कीम प्रधीन
होता हो, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर
के रूप में उनीं रकमों के अनुर के बदावर रकम का संदाय करेगा।

८. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रदेशिक
भविष्य नियि भायुकूल भनुकूल के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया
जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल
प्रभाव पड़ते ही संशोधन हो जाए, प्रदेशिक भविष्य नियि भायुकूल, प्रभाव
प्रभुमोदत देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत सम्बद्ध करने
का व्यक्तिगत अवसर देगा।

९. यदि किसी कारणणामा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा
नियम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है
प्रधीन नहीं हो जाते हैं, या इस स्कीम के व्यक्तिगत कर्मचारियों को ब्राप्त
होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की
जा सकती है।

१०. यदि किसी कारणणामा, नियोजक उक्त नियत नारीक के भीतर,
जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रेतियम का संदाय करने में
प्रमाणन रहता है, और पालिसी को अपापत हो जाने दिया जाता है, तो,
छूट रद्द की जा सकती है।

११. नियोजक द्वाय प्रधिनियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम
की बात में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को
जो यदि यह, छूट न ही गई होती तो उदा स्कीम के प्रधीन होते, बीमा
कायदों के संदाय का इतरहायित नियोजक पर होता।

१२. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, उस स्कीम के प्रधीन प्राप्त
मामे किसी संबंध को मृत्यु होने पर उसके हक्कदार नाम निर्देशितियों/
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक
स्था में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होते के सात
किए के भीतर सुनिषित करेगा।

[संख्या एस-३५०१४/३८०/८२-०००००२]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, 6th December, 1982

S.O. 18.—Whereas Messrs Trade Wings Limited, 30, K.
Dubash Marg, Fort, Bombay-23, (MH/5064) (hereinafter
referred to as the said establishment) have applied for
exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Em-
ployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act,
1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the
employees, of the said establishment are, without making
any separate contribution or payment of premium, in enjoy-
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life
Insurance which are more favourable to such employees than
the benefits admissible under the Employees' Deposit-Link
Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said
Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred
under sub-section (2A) of section 17 of the said Act and ac-
cording to the conditions specified in the schedule annexed hereto
the Central Government hereby exempts the said estab-
lishment from the operation of all the provisions of the
Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment
submit such returns to the Regional Provident Fund
Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and pro-
vide such facilities for inspection, as the Central Governmen
direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges
Central Government may, from time to time, direct
clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said
within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the
Insurance Scheme, including maintenance of account
of returns, payment of insurance premia, li-

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall make prompt payment of the sum assured to the nominee/heirs entitled for it and in any case within 7 days of receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

ज्ञान वा १९--मैरेव मैचुरी स्प्रिंग प्रॉड मैक्सोरिंग कम्पनी
१०, अटेंड, रेलवे गवल, डॉ. एंटी नरसंह रोड, मुंबई-१०००१५ (मालाराड़/
१३९) (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थलन नहीं दिया गया है) ने कर्मचारी
परिव निधि और प्रबोधन उपचार अधिनियम, १९५२ (१९५२ वा १९)
(जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा १७
की उपचारा (३क) के अंती छूट दिया जाने के लिए आवेदन किया
है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान ही यहा है कि उक्त स्थापन
के कर्मचारी, जिसी पृथक अधिनियम का सदाय बिए बिना
ही, भारतीय जीवा निधि की समूहिक जीवा स्कीम के अधीन
जीवा जीवा के रूप में कापार उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए
ये कापार उठा कापारों से वाहन अनुकूल हैं जो कर्मचारी (जीवा गहवड
जीवा स्कीम, १९७६ (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है))
के अधीन रहे शुद्ध हैं।

ग्रन्त केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा १७ की उपचारा
(३क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपचार
अनुकूल में नियन्त्रित भारी के बावजूद रहते हुए, उक्त स्थापन का तीन
वर्ष की प्राप्ति के लिए उक्त स्कीम के द्वारा उपचारों के प्रकार से छट
देती है।

अप्रूपता

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रबोधन समिति नियन्त्रित,
मालाराड़ वा ऐसी विवरणों जिनमा और ऐसे जैवा रखेगा सभी निर्वाचन
के लिए ऐसी दुष्करियाँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, नियन्त्रित वा
नियन्त्रित है।

2. नियोजक, ऐसे नियोजन प्रभारी का प्रत्येक भाग का समान्दर्भ
के १५ दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम
की धारा १७ वी उपचारा (३क) के बांद (क) के अधीन समय-समय पर
नियन्त्रित है।

3. समूहिक जीवा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखांकों
का रखा जाता, विवरणों का प्रमुख किया जाता, जीवा प्रोमोशन का
सदाय, जैवांकों का ग्राहण, नियोजन प्रभारी का सदाय आदि है, हाँ तो
काले सभी उपचारों का बहु नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, जैवांक साकार द्वारा अनुमोदित जामहिन जीमी और
कृष्णजी की एक गति, और जब कमी डार्म योग्यता दिया जाता, तो
उक्त संजोधन की प्रति सदा रामेश्वरियों की बहुसंख्या की भावा में उपकी
मुख्य जातों का अनुकाद, स्थापन के शुल्क पर प्रदान करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी गविष्य नियन्त्रित जा जा
उक्त अधिनियम के अंती छूट धार्य किसी स्थान की दशिय निधि
या पद्धति की सदाय है, उक्त स्थान में नियोजित किया जाता है तो,
नियोजक, रामेश्वरियों की जीवा स्कीम के सदाय के रूप में उमका नाम तरफ
दर्ज करेगा और उक्ती जावत साकार, प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा
नियम की संदर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों द्वारा उपचार फालदे जाता
जाते हैं तो, नियोजक समूहिक जीवा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की
उपचार फालदों में सम्बन्धित रूप से दूष्ट जीवने वी अवस्था करेगा
जिसमें कर्मचारियों के लिए मामूलिक जीवा स्कीम के अधीन उपचार
फालदे जा फालदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन
प्राप्त हों।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी साल के होते हुए भी, यदि किसी अधिकारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दण में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता है, नियंत्रक वर्गचारी के विधिक पारिश्रम निर्देशित वो प्रतिकर के रूप में दूनों रकमों के घन्तुर के बनावट रकम का मदाय होता है।

8. सामूहिक नीति एवं सर्वे उपबन्धों में जोई भी संशोधन, प्रदर्शन भविष्य निधि आयुर्वा, महा एट्र के पूर्व तुमोदान के लिये यही किया जायेगा और यह निम्न मंत्रालय से कर्मचारियों के होते हुए प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रारंभिक संवित्र आयुर्वा, एवं प्रायोदान देने से पूर्व कर्मचारियों को आपापा दृष्टियोग स्पष्ट बताए जा युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थान के कर्मचारी, भारतीय चौकर बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थान पर्याप्तता द्वारा है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रति होने वाले कायदे किसी भीत से करने द्वारा जाते हैं, तो यह छूट रकम की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियंत्रक उस नियम तारीख के भोद्दर, जा भारतीय चौकर बीमा नियम तारीख के, प्रीमियम का संदाय करने में, व्यापक रहता है, और यानिको का व्यापक हो जाने दिया जाता है, तो छूट रकम की जा सकती है।

11. नियंत्रक द्वारा प्रीमियम के तारीख में किए गए किसी अकिञ्चन की दशा में, उन मृत स्वत्यों के दाय निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कार्यालयों के संदाय का उत्तराधिकार नियंत्रक पर होता।

12. उक्त स्थान के संबंध में नियंत्रक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सरकार की मृत्यु होने पर उसके हक्कावार सामिनिर्दिशितियों/विधिक वारिसों को बीमाहत रकम का संदाय तत्परता से और प्रयोक दशा में भारतीय चौकर बीमा नियम से बीमाहत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस० 35014/272/82-पी.एफ०-II]

S.O. 19.—Whereas Messrs Centuary Spinning and Manufacturing Company Limited, Centuary Bhawan, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400025 (M.R./4269), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(272)/82-PR II]

का० आ० 20.—मैत्रस अमर निटिंग चॉर्च, ग्वालिपर (मध्य प्रदेश 1900), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थान दर्शा दिया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपकरण भविष्यन्वय, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

प्रधिनियम कहा गया है) की घारा 17 की उपधारा (अ) के प्रधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

झाँके केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिकाय या प्रीमियम वा सदाय किए जिन ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी नियम सहज बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उह हैं अनुकूल हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उन अधिनियम की घारा 17 की उपधारा (अ) द्वारा प्रदत्त शर्कियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुमती में विनियोग शर्तों के अधीन उह हूँ, उक्त स्थापन को सीन वर्ष की समर्पण लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

- उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राविधिक भविष्य नि आयुक्त, भव्य प्रदेश को ऐसी विवरणिया भेजा जाए और ऐसे लेखा रखना तथा नियोजन के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर विनियोग करेगा।

- नियोजक, ऐसे नियोजन प्रभारी का प्रत्येक मात्र की समाप्ति के 16 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 की उपधारा (अ) के बाण्ड (क) के अधीन समय-समय पर विनियोग करेगा।

- सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधानत में, 'जिसके प्रत्येक नेटवर्कों का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम वा सदाय, लेजार्डों वा अन्तरण, नियोजन प्रभारी का सदाय आदि भी है, हाँ वाले सभी व्ययों का अनुकूल द्वारा किया जायेगा।'

- नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बढ़ुआया की भावा में उसकी मूला वार्ता का अनुकूल, स्थापनके सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

- यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य नियंत्रित का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अनियंत्रित का गहने ही सक्षम है, उसके स्थापन में नियोजित विभा जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वाक्त आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संवर्त करेगा।

- यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे देता जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन मानुष्य हैं।

- सामूहिक बीमा स्कीम में किसी वात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवैत्र रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस वात में संवैत्र होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विविध बारिद/नामिर्दिवेशता को प्रतिकर के रूप में उन्होंने रकमों के अन्तर रकम वा सदाय करेगा।

- सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रारंभिक भविष्य नियंत्रित आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और वहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव पहने की संभावना हो, यहाँ प्रारंभिक भविष्य नियंत्रित आयुक्त, प्रपत्ता अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण मन्द करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहने प्रपत्ता बुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रौप्य से नहीं हो जाते हैं, तो वह छूट रुपी की या सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रारंभिक का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यवगत हो जाने किया जाता है तो, वह छूट रुपी की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदर्भ में कागज, किसी अतिक्रम की वापा में उन सूत सबस्तों के नाम निर्देशितियों या विविध बालिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उस स्कीम के ग्राहक होते, बीमा कारबॉने के संदर्भ का उत्तरवायित नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हृकदार नाम विदेशितियों/विविध बारिसों को बीमाकृत रकम का संवाद तत्परता से घोर प्रयेक वापा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर विनियित करेगा।

[संख्या एस-35014/289/82-पी.एफ-11]

S.O. 20.—Whereas Messrs Amar Knitting Works, Gwalior (MP/1800) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment a/c, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

- The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

- The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

- All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

- The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(289)/32-PF-11]

कांगड़ा २१ - मैसर्स नीडेन इण्डिस्ट्रिज (एफिड्या) निर्माण, नीडेन हाउसर्स्ट्रीज चाकवर ६४३७४३ (रोटीगारीज) (नंपिलनाडु/५५१), जिसे इसमें इनके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिक निश्चय और प्रकारीण उपबल्लभ अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९), (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की द्वारा १७ की उपलापा (२क) के मध्यीन छठ दिन जाने के लिए आवेदन किया है;

और केवल सरकार ना मानवत हो गया है कि उक्त स्थापन के कमज़ारी, किसी पुस्तक श्रमिकाय या श्रीमिम का भद्राय फ़िर बिना ही मार्त्तीय जीवन यीमा नियम की सामृहिक यीमा स्टीम के इधरीन जीवन यीमा के रूप में फ़ायदे उठा रहे हैं और ऐसे कमज़ारियों के लिए वे फ़ायदे उन फ़ायदों से प्रधिक अनुकूल हैं जो कमज़ारी नियम मुद्रबद्ध यीमा स्टीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्टीम कहा गया है) के प्रभीन उसके अन्तर्गत हैं;

प्रातः केन्द्रीय यत्कार उक्त समस्थानम् की घटा 17 की उपलब्ध
(2k) वृत्तरा प्रदत्त मानवियों का प्रयोग करते हुए और हस्तसे उपावद शामुखी
में विनिर्विष्ट जाती के पश्चीत रहने हुए, उक्त स्थान को तीव्र वर्ष की घटविष्ट
के लिए उक्त स्थीय के सभी उपचारों के प्रवर्तन से छठ देती है।

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

१ उक्त स्थान के सन्दर्भ में नियोजिक प्रदेशीक भाषण निधि आपुक, तत्त्वज्ञान को ऐसी विवरणिया में जो भी ऐसे लेखा रखेगा तथा फिरक्षण के किए ऐसी सुविधाएँ प्रदान होंगी जो कल्पीय सरकार, भाषण-भवन पर निर्विज्ञ करे।

2. नियाजक ऐसे निरोग्य प्रभारा दा प्रत्येक भास की समस्ति के 15 दिन के भीतर सदृश रहेगा जो कल्पनीय साकार, उस अधिनियम की धरा 17 की उपधारा (३६) के खाड़ (प) के श्रध्वं यम-समय पर निषिद्ध करे।

१ समिति की समाप्ति के प्रगति या विनोद वन्देश्वरों का
प्रभाव जल्द, विवरणियों का प्रभाव जल्द जाता, चंद्रमा प्रीमियम का संवाद,
अखातों का जल्द या निरीक्षण प्रयत्नों के गहराय लाइट ही है, होने वाले
सभी अध्ययनों का बहुत लियो जाना छोड़ा जाएगा।

४ फिल्मकार, ऐनीस मराण द्वारा । ॥ १० ॥ नमस्करित सामृद्धि कीमा
संकेत के नियमों का एक प्रति, और जब कर्भी उसमें संशोधन किया जाए,
जब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुत अल्पता में उसकी
मुख्य बातों का अनुवाद, अलाइ के सुनना-हुआ यह प्रदर्शित करेगा।

५ यदि कोई गेमा कम्पनी, जो कम्पनीरी भविष्य निधि का पा उक्त व्यापकियम के अधीन सूट प्राप्त नहीं होता; की भविष्य निधि का पहले हो सदस्य है, उसके स्थापन में नियंत्रित किया जाता है तो, नियंत्रक समूहिक बिमा स्ट्राइक के सदस्य के रूप में उक्ता साम पुरुष द्वारा करेगा और उसकी वाक्ता भावशक्ति प्राप्तियम शारीरिक शीर्ण बीमा नियम को बदल देंगे।

६ यदि उक्त स्त्रीम के अधीन कर्मचारियों को उत्तरव्य कापदे बढ़ाए जाएं हैं तो, नियोजक समूहिक वीमा स्त्रीम के अधीन कर्मचारियों को उत्तरव्य कापदे में समुचित रूप से बढ़िये दी जाने की व्यवस्था बरेग। जिन्हें कर्मचारियों के लिए सामूहिक वीमा स्त्रीम का अधीन उत्तरव्य कापदे उपलब्ध हो अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्त्रीम के प्रधीन अनुकूल है।

७ सानुद्विष्ट वैमा स्फीम ने तिसी बात के द्वारा हुए भी धर्म विसी कम्बचारी की यून्य पर इस स्फीम के अधीन संदेश रखने उत्तराम से आये हैं, जो कम्बचारी का उम दाग मास के द्वारा हुआ तो, जब वह उत्तराम के अधीन द्वाता हो, तिसी वन्देशारी के विधिक वारिस/वासानिर्दीणकों को प्रतिकर के रूप में दोनों राजभौमों के अन्तर के बाराबर व्याप का संदर्भ करेगा।

४ सार्वजनिक वर्तमान संक्षेप के उपचरण्या में कार्यभाग साधारण, प्रविशेषक वर्द्धन निधि आयुक्त, लाभिलनाडु के पूर्व जनसंघ के बिना नहीं हिन्दा जाएगा और यह इसी समाधान से कर्मदारों के लिए पर श्रावकल प्रभाव पहुँचने का समावत हो जाएगा। निधि आयुक्त, अपना अनुभव देने से पूर्व दर्शकाधिकारी को "एनडूफोलोग स्पष्ट करने का व्यक्तिमुक्त लाभमत देना।

७ यद्यपि किंवद्दनं स्थापित के रहनेवाली, ग्रन्थांशुद्धि तो देन बीमा इतनाम नहीं उत्तरांश के विभाग स्थीय के, जिसे रघुवा एवं वसा चुका है अप्रीत नहीं रह सकता है, मग इस रक्षण के प्रधानीलक्षणात्मकों दो प्राप्त होने वाले फलादे किंतु रीति में कम हो जाते हैं ॥ यह छठ वष की जा सकती है ।

१० अदि १२वा प्रारंभिक लियाहन उस वर्ष में आर्टिस्ट के भीतर
जो भारतीय गीतों का समावेश नहीं है तो वे विभिन्न जगह रहते हैं। ऐसे
भ्रस्तचक्र रहता है और पांचसौ को बड़ा हो जाते दिया जाता है तो
छठ रथ की जो सप्तरी है।

11. स्थिरजनक दाग श्रीमियम के संदर्भ में किए जाने वाली व्यापारग की दशा में उन पूरे उत्तमों के अन्तर्गत शरणियों का विधिक बारंबा दो जा यदि यह छूट दी गई होती तो उन स्तरों के अन्तर्गत होती, जिनमें के अन्तर्गत का उत्तरवाचिक विवेक पर होता।

12. उक्त स्थान के संबंध में विवेक, उन स्तरों के अन्तर्गत आने वाले विस्तीर्ण स्थान की वृद्धि इस पर उत्तरवाचिक विवेकों/विधिक बारंबा का बीमाकृत रूप का संदर्भ उत्तराखण से और प्रयोक दशा में भवत्ताव विवेक जिनमें से विवेक इस प्रकार होते होने के लाल की के अन्तर्गत नुस्खा रहता।

[मध्या ८३-३५०१४/२९०/८२-पी.एफ. II]

S.O. 21.—Whereas Messis Needle Industries (India) Ltd., Needle Industries, Post Office Nilgiris-643243 (TN/354) (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employers' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(290)/82-PF. II]

कठो आ० 22.—मैसर्स मार्डन बेक्रिज (शिल्पिय) लिमिटेड, वम्बई पृतिट, शाह जिन्ना नालानी गोडांगंड ईस्ट, वम्बई-६५ (महाराष्ट्र/18357) जिसे इसमें इसके पक्षात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भवित्व निधि और प्रकोण उपचाल अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पक्षात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपचारा (२) के अन्तर्गत छूट दिए जाने के लिए गवेदन किया है;

और केवल सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के उपचार, जिसे दूरक शमियाय या प्रेसियम का संदर्भ किया जाता है, भागीय रूप से नियम की भासूदाक भीमा स्कॉम में भवेन द्वारा बीमा के रूप में कायदे उड़ा रखे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए कायदे उन फायदों से अधिक प्रत्यकूल हैं जो कर्मचारी निकेप सहबद भीमा स्कॉम, 1976 (जिसे इसमें इसके पक्षात् उक्त स्थापन कहा गया है) के अन्तर्गत उड़े अनुदोष हैं,

इन अन्तर्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (२) द्वारा प्रकृत अधिनियम का प्रयोग करते हुए, और इससे उपचाल गतिशील से विनियोग शर्तों के अधीन रखते हुए, उक्त स्थापन को तीन दर्जे के अवधि के लिए उक्त स्थापन के मध्ये उपचारों के गवेदन से छूट देती है।

अनुदोष

1. उक्त स्थापन के अवधि में नियोगक प्रादेशिक अधिक्षय निधि धार्यक, महाराष्ट्र (वम्बई) का देश निवारणीयों में जो दूरक से नियम लेखा रखेगा तथा नियोग के लिए देश सुविधाएं देना करेगा जो केवल भारतीय सरकार, नागर-समर्पण पर नियोग करे।

2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारी का भवय का मास की समता के 15 दिन के भीतर संवाद करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्हें अधिनियम ही द्वारा 17 की उपचारण (एफ) के खण्ड (क) के प्रवोत तमवल्लभ पर विविष्ट करे।

3. सामूहिक बैंगा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, नियोजियों का प्रत्युत किया जाता, बैंगा प्रधिनियम का संदाय, लेखाओं का आनंदण, नियोजक प्रभारी का संवाद आदि भी है, जौते वाले सभी व्ययों का वृद्धि नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमंडित सामूहिक बैंगा स्कीम के नियमों को एक प्रति, और अब कभी उनमें संशोधन कियों जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुमंध्य, की भाषा में उसकी मूल्य वालों का आवाद स्थापन के मूल्यांपट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी अधिक निधि का या उक्त अधिनियम के प्रधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मूल्य है, उसके स्थापन में नियंत्रित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बैंगा स्कीम के सदस्य ने इसे मूल्य के उपका नाम मुरुरा वर्च करेगा और उनको उक्त आदर्शक प्राविधिक मार्गीय जीवन बैंगा नियम को संबल करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बैंगा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूलिक बैंगा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन मनुष्य हैं।

7. सामूहिक बैंगा स्कीम ने किसी द्वारा हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन यद्येष रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उन यथा संवैय होती, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता, नियोजक कर्मचारी के विधिक जीवन/नामनिर्देशियों की प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के तराफ़र रकम का संवाद करेगा।

8. सामूहिक बैंगा स्कीम के उपकार्यों ने कोई भी संशोधन, प्राविधिक भविष्य निधि आवृत्त, सहाराटु के पूर्व अनुसूचित के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्राकृत प्रभाव पहले की संभावना हो वहाँ, प्राविधिक भविष्य निधि आवृत्त, अपना अनुसूचित देने से पूर्व कर्मचारियों को अनन्त इंस्टिक्योन स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवक्षर बेश।

9. यदि किसी कानूनदाता, रकम के कर्मचारी, भारतीय जीवन नियम की उस सामूहिक बैंगा स्कीम के लिए स्थापन गहरे अपना बुका है अपेन नहीं रहते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को ब्राप्त होने वाले कानूने किसी रूप से कम हो जाने हैं, तो यह छूट यह की जा सकती है।

10. यदि किसी कानूनदाता, नियोजक उस नियत पारिष के अंतर्गत, जो भारतीय जीवन बैंगा नियम नियम करें, प्रधिनियम का संदाय करते में अवक्षर रहता है, और पारिष को अवागत हो जाने दिया जाता है तो हृद रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा अधिनियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में उन मूल मदम्यों के नामनिर्देशियों या विधिक नामियों को जो यदि यह, छूट वाले रही होती तो उक्त स्कीम के प्रधीन होने, बैंगा कायदों के संशय का उत्तरायिक नियोजक पर शोग।

12. उक्त स्थापन के आवधि में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी मूल्य की मृत्यु होते पर उसके दृष्टि राम निर्देशियों

विधिक बारिसो को बैंगा कृत रकम का संबाय तत्परता से और अत्येक दशा में भारतीय जीवन बैंगा नियम से बैंगा कृत रकम आप्त होने के बात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/325/82 पी०एफ-2]

S.O. 22—Whereas Messrs Modern Bakeries (India) Limited, Bombay-Unit, Aarey Milk Colony Ghatgaon East, Bombay 65 (11H/18357) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 o the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employee.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately him as a member of the Group Insurance Scheme and necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees of the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the payable under this scheme be less than the amount would be payable had employee been covered under Scheme, the employer shall pay the difference to heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(325)/82-PF. II]

का० आ० 23.—पीसी सैक्यानिकम् एच एलेक्ट्रोल्स लिमिटेड, 'ग० शिवसागर एस्टेट, ऑफिचर अधीन बगत रोड, वर्ली, महाराष्ट्र-18 (महाराष्ट्र/9599) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थान कहा गया है) से कर्मचारी परिष्युक्त और प्रकोण उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिया जाने के लिए प्रावेदन किया है;

प्रोर केन्द्रीय सरकार का मान्यान ही गय है कि उक्त स्थान के कर्मचारी, किसी वृद्ध अभियाय या प्रीमियम का संदाय किए जाना ही, भागीन जीवन दीमा नियम की सामूहिक दीमा स्कीम के प्रश्न जीवन दीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे जापदे उक्त कायदों से अधिकानकूल हैं जो कर्मचारी मिशेप साथम दीमा कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम फूटा गया है) के अन्तर्न उन्हें जनुरोग है;

आम: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपचार दुकूनी में विनियिट शर्तों के अधीन यहाँ हुए, उक्त स्थान को तीन के प्रत्येक के लिए उक्त स्कीम के सभी उपयोगों के प्रबंधन से छूट दी है।

अनुमति

1. उक्त स्थान में नियोजक प्रावेशिक अधिकारी नियुक्त आयुष्ट, दृ (1-पर्व) ली ऐर्स नियांगिया बेंजेना और ऐसे लेखा रखेगा तथा ये के लिए ऐसे मुद्रियार्थ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, ममत-सम्बन्धित करेगा।

नियोजक, ऐसे नियोजन प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के तक सातर लाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की तीन उपधारा (2क) के लाई (र) के प्रश्न भव्यता पर करें।

सामूहिक दीमा दीमा के प्रश्नान्तर्में, नियोजन के अधीन लेखार्थों का

भव्यता, नियोजन प्रभारों का संदाय आदि भी है, जो ऐसे अधीन का बहुत नियोजक द्वारा किया जावेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक दीमा रोड नं. १८ नियम। १८ के प्रति, और जब कर्मचारी उक्त संशोधन किया जाए, तब उक्त संशोधन की प्रति सभा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भावा में, उसकी मुख्य वार्ता का अनुवाद, स्थान के सूचना-पट्ट पर ब्रह्मित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी परिष्युक्त नियम का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थान की अधिक्षय नियम का पहले ही रद्दस्थ है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक दीमा स्कीम के लिए उक्त दार्ता दर्ज करेगा और उसकी वाक्त साथम भावशक्ति प्रीमियम भारतीय जीवन दीमा नियम को संबंधित करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उत्तराधि कायदे व्यवस्था होते ही रद्दस्थ है, उसके स्थान में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक दीमा स्कीम के अधीन उत्तराधि कायदे उक्त कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञाएँ हैं।

7. सामूहिक दीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संचय रकम उस रकम के कम है, जो कर्मचारी को उक्त दशा में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन हीमा नी, नियोजन कर्मचारी के विधिक बारिस/नामनिर्णयितों को प्रतिकूल के हाथ में दोनों रकमों के अध्यर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक दीमा स्कीम के उपयोगों में कोई भी संग्रहाल, प्रावेशिक परिष्युक्त नियम आयुक्त, दिल्ली के पूर्व] अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संग्रहाल से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हों संभावना हो, वहाँ प्रावेशिक अधिक्षय नियम आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना बुटिकोण स्पष्ट करने का पुकारितयुक्त अध्यर के दैवत है।

9. यदि किसी कारणावश, स्थान के कर्मचारी, भारतीय जीवन दीमा नियम की उक्त सामूहिक दीमा स्कीम के, जिसे स्थान के पहले अपना दुकूल होता है प्रधान नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों दीमा प्रावेशिक दीमा से अधिक होते होने के कायदे हो जाते हैं, तो यह छूट रकम की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणावश, नियोजक उक्त नियम सारेके भीतर, जो भारतीय जीवन दीमा नियम करे, प्रीमियम का संदाय करने में असकूल रहता है, और प्रतिकूल को अवगत ही जाने किया जाता 'है सो' छूट रकम की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उक्त मृत सदस्यों के नाम निर्वेशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट रकम की गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, दीमा कागदों के संदाय का उत्तराधित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थान के मंड़ब में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी रकम की मृत्यु होती पर उसके हृत्वार नाम निर्वेशितियों विधिक वारिसों की दीमाकृत रकम का संदाय लेखता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन दीमा नियम से दीमाकृत रकम प्राप्त होने के साथ दिन के भीतर सुनित्यित करेगा।

[सू. एस 35014/321/82 पृ. एफ-11]

S.O. 23.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals Limited, A. Shivasagar Estate Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18, (MH/9599) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the

1.52 7 22. Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-Linked Scheme as Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

SCHEDULE
1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Mumbai (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Wherever an employer, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and here any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employers under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(326)/S2-PF. II]

का०आ० 24—भैसं फीसो इन्हें दिनिक १०८ रुपौला तिथिंदेश
ने मधिस रोड, संजगाप, गवर्ड-४०००१० (गुजरात/५०१) (जिसे इनमे
हसके पश्चात् उत्तर स्थापन कहा गया है) ने कावर्त्री भवन तिथि और
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५२ (१९५२ का १९) (जिसे इनमे प्राप्त
पश्चात् उत्तर अधिनियम कहा गया है) की धारा १७ की उधारा (२८)
के अधीन छट दिए जाने के लिये आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उन्हें स्थानिक के नामंजाने, जिससे पृथक अधिकार भा प्रीमियम का सदाचार लिए बिना ही, भारतीय जीवन वीभा नियन की सामूहिक वीभा स्कीम के अधीन जीवन वीभा के रूप में फायदे उठा सके हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से प्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी नियंत्रण संस्थाएँ वीभा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उन्नत स्कीम कहा गया है) के अधीन सम्मुखीकृत हैं;

प्रति केन्द्रीय सरकार, उसना अधिनेत्रम् को धारा 17 की उपचाया, (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इनमे उत्तरवाच प्रत्यक्षी में विनिर्दिष्ट भारती के व्यवहार रहते हुए उत्तरास्पान को तोते थे वे ही प्रबलि के लिए उनका स्वीकार के तरीके उद्यमों के प्रबर्तन मे छठ पैती है।

અમસુલી

1. उक्त स्थान के संबंध में नियोजन प्रादीपिक चरित्रम तिथि आगत महाग्रहों को ऐसी विवरणिया भेजेता और एक लेख जैवा तत्त्व नियोजन के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेता जो केवल राशनर गवद-गवद पर लिपिट्ठ करे।

2. नियोजन, ऐसे निरीक्षण प्रवारों का प्रतिवेदन जाप की समाप्ति के 16 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केंद्रीय सलाह, उत्तम अधिकारों की द्वारा 17- की उपचारा (उक) के लिए (क) के लिए; सरकारने दर निर्दिष्ट करे।

३. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का एका जनना विवरणयों का प्रस्तुत लिख जाना, वीमा प्रेमिभवष का सदाये, भौताप्तों का धर्मस्तरण, निर्दिष्टाण प्रारंभों का नदार आदि भी है होने वाले सभी घटों का अहन विवेजक द्वारा किया जावे।

4. नियोजक, केस्ट्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक वीभा क्षेत्रों के नियमों की एक प्रति, भौतिक और अवधारणा के संशोधन किया जाता, तथा उस संशोधन की प्रति तथा कर्तव्यायों का बहुरांकन की धारा में उसकी व्यवस्था बातें का अन्वयवाच, स्पष्टात्मक संस्करण भूमि पर व्यवर्थित करेगा।

५. यदि कोई ऐसा कर्मचारी है, जो कर्मचारी भविष्य निधि का दो उक्त अधिकारियम के द्वारा छठ प्राप्त किसी स्थापत्य में भविष्य निधि का पहले ही सहस्र है, उसके स्थापत्य में नियोजित होना चाहिए है तो, नियोजन सारांशिक शीमा स्तरिय के सहस्र के रूप में उपलब्ध गोम तुरन्त दर्ज करेंगे और उसकी बाबत आवश्यक प्रभावित भारतीय जीवन वंगा निगम वर्तों संदर्भ करेंगे।

६ यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फार्डे देना चाहे हैं तो, नियोक्तक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन दर्शकों द्वारा योग्य उपलब्ध फार्डों में समूचित रूप में अद्वितीय लागत का दायरा कराया जायगे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फार्डे "उन कार्यदर्थों से प्रधान अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधान भूत्तान हैं।

7. ग्राम्यिक बीमा स्कीम में किसी बान के हीम हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संचय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में बदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, तियोजक कर्मचारी के विधिक भार्गम/ताम निर्देशित को प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के प्रमध के बाबत रकम का सदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रांदेशिक विविध निधि आयुक्त, मतागाल्ड के पूर्ण अनुसूचित के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रांदेशिक विविध निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्ण कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भ्रयमर्द देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारों, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कागदे किसी रीति से कम ही जाते हैं, तो यह छूट रहकी जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का संदाय करते हैं असफल रहता है, और पालिसी को अपग्रेड हो जाने विषय जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में विषय गए किसी व्यक्तिका की यथा में, उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कागदों के संदाय का उन्नतावित्त नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन भावे भावे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तात्परा में और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने की मात्र विन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[पं. प्र-35014/334/82-प्र० अफ-III]

S.O. 24.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals Limited, Nesbit Road, Mazagaon, Bombay-400010 (MH/3104) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(334)/82-PF. III]

का० आ० 25—मेरेहा एण महिना लिमिटेड इण्टरेस्टल ट्रेस्टस डिवीलन, हम्पलाईज को-ऑपरेटिव फैस्लैन सोसाइटी लिमिटेड, काउंटीली ईस्ट ग्राम्प-100001 (महाराष्ट्र/11705), जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी विविध और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिलाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी ग्राम्य अधिनियम या प्रीमियम का संदाय विषय विना ही,

भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी नियम सहबद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उन स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेय हैं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन बर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (अ.) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियाँ का प्रत्युत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्यांगों का बहुनियन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मूल्य छातों का अनुदाद स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संबंध करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बड़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्बन्धित रूप से बढ़ि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आवा अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है

अवैन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अवैन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे विसी रीत से कम हो जाने हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पलियो को व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्वारता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/335/82-प्र० एफ-II]

S.O. 25.—Whereas Messrs Mahindra & Mahindra Limited International Tractors Division, Employees' Co-operative Canteen Society Limited, Kandivli East, bombay-400001 (MH/11705) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that, the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(335)/82-PF.II]

कांगड़ा। 26.—सेवर्स मध्य मिलन स्टॉटेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, आगरा बम्बई रोड, देवास-455001 (मध्य प्रदेश/3387) (जिसे इस में इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार के समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिकारीय या प्राविधिक की संदर्भ किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निषेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुरोध हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त अधिकारीय या प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा

तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के अंतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गत, निरीक्षण प्रभारों का संदेश आदि भी है, होने वाले सभी व्यायों का वहने नियोजक द्वारा नियमित जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमति संबूद्धिक घंटा स्कीम के नियमों की दृष्टि प्रति, और जब कानून में लक्षाधन किया जाता, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की आपात उसकी मुख्य बातों का अनुबाद, स्थापन के सूचना पृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की अनुमति विधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्राविधिक भारतीय जीवन बीमा नियम को संदर्श करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे दर्ज होते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की अवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन शामिल हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की अनुमति पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रकम उस रकम से कम है; जो कर्मचारी को उस दिन में संदेश होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बायावर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहुंचे की संभावना हो, वहाँ प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को शपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे की रीत से कम हों जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के अंतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम के, प्राविधिक भविष्य निधि की संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यवस्था दी जाने विधा जाता है तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्राविधिक भविष्य निधि के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दिशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दिष्टियों/विविक वानियों को वैमानिक रूपमें का संभाय उपलब्ध कराया जाए और प्रत्येक दिया में भारतीय जनन विश्वास से बोमाकून रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुनिवित करेगा।

[संख्या: प्र०-35014/336/82-पौः-एफ०-II]

G.O. 26.—Whereas Messrs Alachu Mi'an Syntex (P) Limited, Agga Bombay Road, Dewas (MP/3287) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any deduction on payment of premium, in enjoying all benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employee.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(336)/82-PF.II]

का० आ० 27—संग्रह जल न महाकारी बैंक लिमिटेड, दैनिक विलिङ्गा, महाराष्ट्र नं. ४, फार्म-११६१६ (कागड़/१५१६७) (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारों भविष्य निधि और प्रक्रीय उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की भारा 17 की उपचारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारों, किसी पृथक् व्यक्तिगत या ग्रीष्मियम वा सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन वे ना नियम की सामूहिक वैमानिक स्कीम के अधीन जीवन वीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये कायदे उन कायदों से प्रधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारों नियमें भवितव्य रूपमें स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम द्वारा गया है) के अधीन उक्त अनुसूचे हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रदत्त अनुसूची का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद अनुसूची में विनिर्दिष्ट गती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को सीधे वर्षे की प्रवत्ति के लिए उक्त स्कीम के मध्ये उपचारों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक ग्रांडिग्राम भविष्य निधि भायुक्त महाराष्ट्र की ऐसी विवरणिया जैजगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भवित्व समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की भारा 17 की उपचारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का रेखा आना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा ग्रीष्मियम का सदाय, दोषाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का सदाय आदि भी है, हीने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उम संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों वी मुकुसंस्था की भावा में उसकी मुद्रा वर्ती का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त व्यापारिक सूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही मदद्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के संबंध के स्पष्ट में उसका नाम तुरन्त दर्ज करना और उक्त बाबत आवश्यक प्राप्तिष्ठित भाग्यता जीवन बीमा नियम को सदृश करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बड़ा जाते हैं, तो, नियोजित सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में संबंधित स्पष्ट गेवृद्धि की जाएगी अवधारणा बोगा जिसमें कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक प्रभुत्व होंगे, जो उक्त स्कीम के प्रधान भूत्तीय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम व किसा बात के हात हुए भी, यदि किसी कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सन्वेद रकम उक्त रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश हाते, तब वह उक्त स्कीम के प्रधान द्वारा तो, नियोजित कर्मचारी के विविध वार्तानिवृत्तियों और प्रतिक्रिया के स्पष्ट में दोनों रकमों के अन्तर के बगवार रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्राप्तिष्ठित भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रवेश के पूर्व प्रभुत्वादत के बिना नहीं किया जाएगा, और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने को संशोधन हो, वहाँ प्राप्तिष्ठित भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमान देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण संपर्क करने का युक्ति-युक्त शक्तिपूर्व देगा।

9. यदि किसी कारणबाट, स्थापन के कर्मचारी, भाग्यता जीवन बीमा नियम नी तक सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुना है प्रधान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीत से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणबाट, नियोजित उस नियत तारीख के भीतर, जो भाग्यता जीवन बीमा नियम नियम कर, प्रोमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी का अवधारण हो जाने दिया जाता है तो, यह छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजित द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी भविष्यतम की दशा में उन मुत सदस्यों के नामनिवृत्तियों पर विविध बासियों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रधान होते, बीमा फायदों के संदाय का उन्नरदायित्व नियोजित पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संघर्ष में नियोजित, उस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हाताहर नाम नियोजितियों/विविध बासियों की बीमाहात रकम का संदाय तत्पत्ता से और प्रत्येक दशा में भाग्यता जीवन बीमा नियम से बीमाहात रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/337/8 नं-००५०-११]

S.O. 27.—Whereas Messrs. Janta Sahakari Bank Limited, Karale Building, Mahabir Nagar, Sangli-416416 (MH/15467) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities of inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme is less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, it any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(337)/82-PF. III]

काठा आरो 26 - मैरार्स मोटर इंडियन अफ्टर्सेर्विसेंस, 75, एम्बर आर्ट, दीलो गोड एस्टेट मिल्फर्म रोड, नासिक-12300 (महाराष्ट्र 1053), (जिसे इसमें उक्त कंपनी उक्त स्थान कहा गया है) ने बर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीय उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपचारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृष्ठक भविष्य वा प्रीमियम का संवाद किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन अधीन बीमा के रूप में कायदे उठा रखे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी नियोप महबूद बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उड़वे अनुकूल हैं;

अतः, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपचार अनुसूची में विनिष्ट प्रतीकों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन बाँधों द्वारा जिए उक्त स्कीम के सभी उपचारों के प्रबलता से छूट देते हैं।

नासिक

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रविधिक भविष्य निधि धारक, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया देंगे और ऐसे सेवा देंगे तथा नियोजक के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे नियोजक प्रधारों का प्रयोग भास की समाजिक के 15 दिन के भीतर संबंध करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (3क) के अधीन समझ-धम्य पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अधीनत बेकारों का रहा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाद, बेकारों का अन्तरण, नियोजक प्रधारों का संवाद आदि भी है, इसे बासे भासी व्ययों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संकेतन किया जाए, तब उस संकेतन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंबंध की आवाज में उसको मृद्यु बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सबस्थ है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सबस्थ के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत सामूहिक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपचार फायदे देते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपचार कायदों में समुचित रूप से विविध की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपचार फायदे उन कायदों के प्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुकूल हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बान के हाथे हुए भी यदि किसी संस्थार्गी को पृथक् इस स्कीम के अधीन गन्तव्य रूपम उम एकम से कम है, तो कर्मचारी को उस दिशा में सदैय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होना चाही तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक शाखा/नामनिर्देशिती दो प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के ब्रावबर रूपम का सवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपचारों में योई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त नियमानुच्छेद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकृम प्रभाव पड़ते हों संभासन हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, स्थापना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को आगाम दृष्टिकोण स्पष्ट करने का विवितपूर्वक अवगत देश।

9. यदि किसी जारीवाण, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पृथक् लपता नुस्खा है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों पों प्राप्त होने वाले कायदे किसी रूप से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवाण, नियोजक उस नियन्त्रण वारीष के प्रतिरुद्ध और जीवन बीमा नियम नियन्त्रण करें, प्रीमियम का संवाद करने में असफल रहता है, और पालसी को अवश्य हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाद में दिए गए, किसी व्यवित्रित की दिक्षा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों पों जो यदि यह एक न दी गई होती हो स्थापन के अन्तर्गत होते, बीमा कायदों के मंदाव का उत्तराधारित नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन प्राप्त वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की जीयाहात रकम का संवाद तत्पत्ता से घोर प्रत्येक व्ययों में सारतीय जीवन बीमा, नियम से बीमाहात रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम-35014(338)/82-पी०-एफ-III]

S.O. 28.—Whereas Messrs Motor Industries Company Limited, Nasik Division, 75, M.I.D.C. Estate, Satpur, Nasik (MH/12053), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of rates, premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(338)/82-PF. II]

का० आ० 29--मैसर्स केनर (इंडिया) लिमिटेड, 19/21, मनोहर दास स्ट्रीट, डाकघर बाजार 1307, बम्बई-1 (महाराष्ट्र/14526), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीण उपबन्ध प्रविधियम 1952 (1952 का 10) (जिसे इसमें

उक्त स्थापन 1977 का (का 27 अगस्त 1977) को धारा 17 के द्वारा (2क) के द्वारा दृढ़ दिए जाने के लिए ग्राहित किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समझान हो गा है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अनियम या श्री नियम का संदर्भ निए विनाहे भारतीय जनकर्त्ता वीमा लियन की सामूहिक वीमा स्कीम के घर्वात् जीवन वीमा के रूप में कायदे उक्त रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उक्त धारा 17 स्थापन स्वरूप 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन का गहरा गया है) के अधिनि उक्त अनुकूल हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रतिनिधित्व द्वारा धारा 17 की उपबन्ध (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुकूलीय वीमा लियन के अधिनि रहने हुए, उक्त स्थापन को तन वर्षों को अवधि के लिए उक्त स्थापन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देने है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राविधिक भविष्य निधि आयुक्त भवारायट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संबाद दारेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपबन्ध (3क) के विषय (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक वीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वीमा श्री नियम का संबंध, लेखाओं का अन्तर्गत, निरीक्षण प्रभारों का संदर्भ जाविष्ट है, हमें वाले सभी व्यवों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की वहुसंख्या की भावा में उमरी संलग्न वालों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रस्तुत करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उम्रका नाम तुरल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक श्रीमियम भारतीय जीवन वीमा नियम को लादल करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अन्तर्न कर्मचारियों जो उक्त व्यवहार दर्ज हैं तो, नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के अन्तर्न कर्मचारियों को उपलब्ध फादरों में सम्बूधित है से दृढ़ि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के अन्तर्न अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक वीमा स्कीम में किसी वाले के होने हुए घटे, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सादेय रकम उन रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में दादेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिनिविश्वानी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 स मूलिक बमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सरोबर, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त यहाँ लाइफ के पूर्व मनुमोक्त के बिना नहीं बिया जा एगा और जहाँ किस सशाधन से कमचारियों के हित पर प्रतिकल प्रशाशन पठने के सभावना हो, वहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुभावदान देने से पूर्व कमचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के उपचार अवसर देगा।

9 यदि दिन करणदश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जवान बमा फिल्म के उस समूहिक बमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुना है अथवा नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अध्यन कर्मचारियों को प्राप्त हो। उसे कानून से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रहा जा सकता है।

10 यदि किस करणदश, नियाजक उस नियत तारख के भीतर, जो भारतीय जवान बमा नियम नियत रहे, प्रियम का सदाय करने से अपकर रहा है, और परिस्थि को व्यपगत हो जाने विष जाता है तो, छूट रहा जा सकता है।

11 नियाजक द्वारा प्रियम के सदाय में किए गए किस व्यक्तिगत का दशा में उन मृत सदस्यों के नार्वन्देशियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दे गई होता तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजित पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कीम के अध्यन आने वाले किस सदस्य के मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जवान बमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[मध्या एम्- 35014/348/82-पी-एफ-II]

90 29—Whereas Messrs Fenner (India) Limited 19/21, Marchardes Street Post Office Box 1307 Bombay-1 (MH-14526) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable than those than the benefits admissible under the Life Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of own's payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee or the nominee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Mumbai (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default if any made by the employer in payment of premium etc the responsibility for payment of a sum assured to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the said Scheme the employer in respect to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee etc within 15 days from the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S 35014(348) 82 FF III]

कानून 30—मैसर्स वालचन्दनगर इण्डनर्ज लिमिटेड (सेट ट्रॉलीट) जिला पूणे, डाकघर वालचन्दनगर-113114 (महाराष्ट्र राज्य) (मह/ 9104) (जिसे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम दट्टा गया है) की घोषा 17 की उपधारा (2) के अध्यन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समझान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रियम का सदाय दिए बिना है, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन

बीमा के रूप में प्रतिवेदन कर्ता हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये आयदे उन कार्यदों से अधिक अनुकूल हैं जो कम्पनी नियोग तहवाल बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमेय हैं;

भ्रत, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपलब्ध (2क) द्वारा प्रत्येक शक्तियों का प्रयाप करते हुए और इससे उपर्युक्त अनुकूलों में विनिश्चित शब्दों के अधिन रहते हुए, उक्त स्वापन को उन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम द्वारा उपलब्धी के प्रकरण से दूर देते हैं।

अनुच्छेद

1. उक्त स्वापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रबोधिक अधिकारी नियिक अनुकूल, महाराष्ट्र (बवर्डी) का एवं नियोजित सेवा और ऐसे लेखा रखेगा तथा नियोजक के लिए ऐसे सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केंद्रीय गवर्नर, समस्याएँ पर लियेंगे।

2. नियोजक, ऐसे नियोजन प्रभारी का प्रत्येक भास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाद प्राप्त करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपलब्ध (उक्त) के लिए (क) के अधीन समस्याएँ पर लियेंगे।

3. सामुहिक बीमा स्कीम के अन्वारा में, जिसके अन्तर्गत लेखालों का उत्तर आया, नियोजियों का अनुकूल किया जाना, बीमा प्रोभियम का संदाय, लेखालों का अन्वारण, नियोजन प्रभारी का संदाय आदि भी हैं जो उन्हें सभी अधिकारी का महुसास पृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा दस अनुमोदित सामुहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और उन कर्ता उनमें संशोधन किया आए, तब उत्तर संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का अनुसंधान की भास में उसको मुख्य बाहरों का अनुवर्त्त, स्वापन के मूल्य पृष्ठ पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई एयर कर्मचारी, जो कर्मचारी अधिक नियिक का या उक्त प्रबोधियम के अन्तर्गत दूर प्राप्त किया स्वापन की अधिकारी का एहते ही समस्या है, उनके लालकड़ में नियोजित किया जाता है कि, नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के संवर्तन के रूप में उसका नाम अनुसन्धान करेगा और उक्त बायक द्वारा प्रदर्शित अधिनियम भारतीय अंक बीमा नियम को संदर्भ करेगा।

6. परं उक्त स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं तो, नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुक्ति रूप से वृद्धि की जाते की अवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए जानुहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कार्यदे उन कार्यदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत अनुमेय हैं।

7. सामुहिक बीमा स्कीम में किसी भास के हाते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रत्येक सालेय रकम उन रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश दिया जाता है, तब उक्त स्कीम के अधीन होता ही, नियोजक कर्मचारी के विधिक परिवर्तन/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्वर के बराबर रकम का संवाद करेगा।

8. सामुहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रबोधिक अधिक नियिक अनुकूल महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के विना नहीं किया जाएगा और जाहीं विना संशोधन से एवं शक्तियों के दिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभवता ही, वही प्रबोधिक अधिक अधिकारी नियिक अनुकूल, अपना अनुमोदन देने से पूर्व विवरियों को उपलब्ध नियोजक राज्य करें का प्रस्तुत्युक्त घोषणा देगा।

9. यदि किसी राज्यसभा, राज्यालय के अधीनी, सारकारी जीवन बीमा नियम की दस सामुहिक बीमा स्कीम के जिसे स्वापन पृष्ठ सम्बन्ध

मुका है अवैन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कार्यदे किसी रौसि के कम हो जाते हैं, तो यह दूर का जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत सारिंज के भीतर, जो भारतीय अधीन नहीं है, नियम नियत भारत, प्राप्तिकूल करने में असफल रहता है, और पालिसों को अपग्रेड हो जाने दिया जाता है तो, यह दूर का जा सकता है।

11. नियोजक द्वारा प्रोभियम के संदाय में किए गए किसी अधिकारी का वास, में उन मूल सदस्यों के नामदिर्शकालियों वा विधिक बालियों को जो यदि यह दूर न हो जीता तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कार्यदों के संदाय का उत्तरवायिक नियोजक पर होता।

12. उक्त स्वापन के संबंध में लियोजक, इस स्कीम के अधीन यहने वाले दिली सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कार नाम नियोजित/विधिक शासियों को बीमाकृत रकम का संदाय तप्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेंगे।

[राज्या एस-35014/349/82-पी०एक II]

S.O. 30.—Whereas, Messrs Walchandnagar Industries Limited, (Motor Transport), District Pune, Post Office Walchandnagar-413114, (Maharashtra State), (MH/9124), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner. Mahaashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(349)/82-PF. II]

का० 31.—मैसों प्रोरेटल पावर केबल्स लिमिटेड, नरेंद्र हाऊस, ३५-लक्षपति शिंगारी महानगर मार्ग, अस्प्ही-३०, (महाराष्ट्र/18099), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उन्न स्थापन यहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रतिरोध उपबन्ध प्रविनियम, 1952 (1952 भा 19) (जिसे इसके पश्चात् उक्त भविष्यनियम कहा गया है) के भाग १७ की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

दोर केन्द्रीय सरकार का सम्बोधन हैं यथा है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, जिसे पृष्ठक भविनाव वा प्रतिरोध वा संदाय किया जिता है, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बोमा स्कॉम के अधीन अंतर्वर्ती बोमा के रूप में कायदे उठा रखे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कारबोरों से अधिक ग्राहक हैं जो उन्हें बोरी करना चाहते हैं। यही कारबोर के अधीन उक्त कारबोरों के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं।

थिं, केन्द्रीय सरकार, उक्त भविष्यनियम की भाग १७ की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त विविधों का ग्राहक करते हुए मार्ग इससे उपलब्ध प्रमुखों में विविध बोरों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को उन वर्ष की घटविक के लिए उक्त स्कॉम के सभी उपबन्धों के अधीन ये छूट दी जाएं।

मुद्रांक

1. उक्त स्थापन के स्वन्वन्व में नियोजक प्राविधिक भवित्व विधि प्रमुख महाराष्ट्र का ऐसा विवरण जेवें और ऐसा देश खेदा तक उक्त स्थापन के लिए ऐसी युविधाएं प्रदान करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त स्थापन पर विद्युत करें।

2. नियोजक, ऐसे विवरणों का प्रत्येक मास के समाप्ति के 15 दिन के अंतर सदाय करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त भविष्यनियम की भाग १७ की उपधारा (2क) के अंत (५) के मध्यें तथा उक्त स्थापन पर विद्युत करें।

3. सामूहिक बोमा स्कॉम के प्रयोगन में, जिसके अन्तर्गत लेखांशों का रक्षा जाना, विवरणीय प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रतिरोध का संदाय, सेवाओं का अन्तरण, नियम प्रभारी का सदय आदि भी है, ऐसे बोरों द्वारा विवाह आवेदन किया जानेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रत्येक बोमा स्कॉम के नियमों की एक प्राप्ति, और उस फोर्म उनमें संसोधन किया जाए, तब उस संसोधन यो प्रति उक्त कारबोरियों की बहुसंख्या की भावा में उसकी मुख्य बोरों का अनुबाद, स्थापन के सूचना प्रट पर प्रदर्शित करें।

5. यदि कोई देश कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त भविष्यनियम के भाग १७ छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का प्राप्त हो सकता है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बोमा स्कॉम के सदय के रूप में उक्त नाम तुरन्त उक्त करेगा और उसकी बाबत आपराधिक भारतीय जीवन बीमा नियम को बदल करेगा।

6. यदि उक्त स्कॉम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बदल जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बोमा स्कॉम के प्रबोन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से बदल को जाने की व्यवस्था करेगा और उसके लिए उक्त सामूहिक बोमा स्कॉम के प्रबोन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अविवाद छान्दू लगे, जो उक्त स्कॉम के अधीन प्रत्येक हैं।

7. सामूहिक बोमा स्कॉम में किसी बात के होते हुए ये, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कॉम के प्रबोन सन्देश रकम उक्त रकम से कम है, जो कर्मचारों को उस दशा में मरीज होता, जब वह उक्त स्कॉम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिनियों को प्रतिक्रिया के रूप में वार्ता रकमों के प्रत्यक्षर करावार रकम का संबोध करेगा।

8. सामूहिक बोमा स्कॉम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्राविधिक भविष्य निधि या मूलत महाराष्ट्र के पूर्व मनुमोदन के दिन नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहुँचे की संभावना हो, वही प्राविधिक भविष्य निधि या मूल भोग्य देने से पूर्व कर्मचारियों को यथा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का भूलिय पूछत घबराह देगा।

9. यदि किसी कारबोर, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बोमा स्कॉम के, विशेष स्थापन पहुँचे घटना कुका है प्रबोन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कॉम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त हुने वाले कायदे किसी राति से कम हो जाते हैं, तो यह हूँ रह कां आवाहन है।

10. यदि किसी कारबोर, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस नियत तारख के भोग्य, जो भारतीय जीवन बीमा नियम के विवरण कर्मचारियों को अपवाहन हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्राविधिक के मादाय में किंवद्दन किसी व्याविधि की दशा में उन मूल संशोधों के नामिनियों द्वारा विधिक भारियों को

जा याद वृद्धि न का भर देता तो उक्त स्थापन के अन्तर्गत हो, बासा कार्यपा के संबंध का उत्तराधिकार नियाजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सदाय में नियाजक, इस स्थापन के अधिन आने वाला होना सदाय के मूल्य रूप पर उक्त हक्कदार नाम निदाशात्मक/विधिवालीका वनकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्यक्ष दरा म नारताय जावन बम, नियाज से बासाकृत रकम ग्राह्य होने के सात दिन के भत्तर सुनाक्षरत करेगा।

[संख्या एस- 35014/372/82-पा०एफ-11]

13 31—Whereas Messrs Oriental Power Cables Limited, Nariman P. House, 44, Chhatrapati Shivaji Manzil Marg, Bombay 39, (मील 10099), hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) or section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) or Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner or, if such a and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(372)/82-PF II]

का० आ० 32 —मैरां ट० के० स्टल इंडिया (पैटेट), लिमिटेड, एम० आ० ३०, प्लाट न० ७, इ१ डॉ०, च००५८८
पुणा-१९ (महाराष्ट्र/15871), (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन, कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 का उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का साधारण हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, उसी पृष्ठक अधिनियम का सदाय किए बिना है, भारत य ज वन बमा नियम की समूहिक बमा स्कम के अधिन ज वन बमा के द्वारा फायदे उठा रखे हैं और ऐसे कर्मचरियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निषेध सहबद्ध बमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञय हैं,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयाप करने हुए ओर इनसे उपबन्ध अनुसूच में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधिन रखने द्वारा उक्त स्थापन को तन वर्ष के अवधि के लिए उन स्कम के सभ उपबन्ध का प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुगूणी

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक प्रत्येक भविष्य निधि अध्य०८, मा० १५८ को ऐस विवरणिया भेजेग और रे० तेजा रखेगा। या निर बन के लिए ऐस सुविधार प्रदत्त करेग जा बेन्द्रीय सरकार समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निर क्षण प्रभारों के प्रत्येक मास के सम्पति के 15 दिन के भीतर सदाय करेग, जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3न) के खड़ (क) के अवन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 समूहिक बमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओ ना रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बमा प्रमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निर क्षण प्रभारों का सदाय आदि भा है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

४. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रामुखिक समृद्धिक बंधा सर्कार के लियाजा ने एल प्रति श्रीग जब कर्त्ता उत्तर संगोष्ठी किया जाए, तब उस संगोष्ठी के प्रति तथा कार्यपालिया को दृष्टिगति के भावामें उम्मीद मूल्य तरों का अनुदान, स्थापन के सूचना पट्ट प्रसंश्नित होता।

५. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी संघिण नियत करा या उक्त अधिनियम के पार्थ न पूट प्राप्त लियो स्थापन के भवित्व तिथि का पहले है दृष्टि है, उसके स्थान में नियोजक लिया जाता है तो, नियोजक न गृहित होता, रूपरेख के गद्य के रूप में उन्होंने नाम तुरन्त दर्ज करता, आगे उसका बाबत अवश्यक प्रगति भारत य जैवन बोध लियामात्र संदर्भ होता।

६. यदि उक्त रूपरेख के अप्रत्यक्ष कर्त्तव्यों का उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक न मृदृग वाम, रक्षम के अन्तर्न कर्मचर रिया को उपलब्ध कराता से नारुता व्यप से वृद्धि हो जान क, व्यवस्था करना जिसमें कि कर्मचारिया के लिए मृदृग वाम रक्षम तुरन्त उपलब्ध फायदे उत्तर कावदों से अधिक मूल्य हो, जो उत्तर स्थान के अनुदान अनुज्ञेय है।

७. मृदृग वाम, रक्षम में किया जाने के होने हुए भ, यदि किसी कर्मचार के नारुता व्यप के प्रति उत्तर के प्रति न दी रखा तभी उस रक्षम से कम है, जो कर्मचार को उत्तर में विद्युत हात, जब यह उक्त रक्षम के अर्थ न होता तो, नियोजक नार्तन रा के लियो व्यवस्था नियंत्रित को प्रतिकार के व्यप में दोनों रक्षमों से अन्तर के बाबत रक्षन का संदाय करेगा।

८. मृदृग वाम, रक्षम के उत्तराधीन संवादों में वाई व्यप संवाद, प्रावेशिक भविष्य तिव्र प्रायुक्ति सार्व इके पूर्व उत्तराधीन के लिया जाए, आगे जहाँ नियोजक नार्तन से रक्षम के लियो व्यवस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संवादना हो, वह प्रावेशिक भविष्य तिव्र प्रायुक्ति, यापना अनुभाव देने भे पूर्व व्यवस्थाओं को अपना व्युत्पन्न स्थान करने का युक्तियुक्त अवागाहन होगा।

९. यदि नियोजक नार्तन के नार्तनी, भारतीय जीवन वीक्षा नियम की उस गामृदृग वीक्षा स्थित के, जिसे राष्ट्रपा पहले यापन कृता है अधीन नहीं रह जाते हैं, तो इस स्थित के प्रति नार्तनों को प्राप्त होने वाले कर्त्तव्य नियोजित होने वाले होते हैं, या यह छूट रह की जा रहती है।

१०. यदि नियोजक नार्तन, नियोजक नार्तन भारतीय के भीतर, जो भारतीय जीवन वीक्षा नियम दरे, प्रीमियम का गवाय करने में आकार रहता है, श्रीग पानियों को व्यवाह हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा रहती है।

११. नियोजक नार्तन प्रेसिडेंस के नियोजित नार्तन व्यवस्था की दृष्टि में उन मूल नदियों के नार्तनीजीवनी नायिक वालियों को जो यदि यह छूट न हो गई होने जा रही हो तो उन्हें नार्तन होने, वीक्षा फायदों के संवाद का उत्तराधीन नियोजन पर होता।

१२. उक्त रक्षन के संबंध में नियोजक नार्तन के अधीन जाने वाले नियोजक नार्तन की मूल होने पर उत्तर संवाद नार्तन नियंत्रितयों/विधिक वालियों को व्यवाह रक्षम का गवाय नार्तन से श्रीग प्रत्येक घटा में आर्जी व्यवस्था नार्तन गे व्यवस्था रक्षन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर नुस्खित करेगा।

[नियोजन-35014/373/82-पौण्ड-11]

S.O. 32.—Whereas Messrs T. K. Steel Industries (Private) Limited, MIDC, Plot No. 7, D-1 Block, Chinchwad, Poona-19, (MH/15871) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(373)/82-PF. II]

का० जा० 33.—मैत्री स्टेट एल्युमिनियम एस्टेट लिमिटेड, 1, मिडलेटन स्ट्रीट, कलकत्ता-71, (पश्चिम बंगाल/5137) और उसकी 39-जीटी०रोड, बेलूर मठ, हावड़ा, (पश्चिम बंगाल/185) पर रिप्ट कार्पोरेशन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया ह) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रिया उत्पन्न अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपचारा (2) के अन्तर्गत छूट देने के लिए आवेदन किया है;

प्राप्त केन्द्रीय संकार का वराधान हो गया है कि इका स्थापन के कर्मचारी, जिसी पृष्ठ भविष्य या प्रक्रियम का नियम किए जिनमें ही भारतीय जीवन वीवा नियम की राष्ट्रीय वीवा स्कीम के जीवन वीवा के रूप में सापेक्ष उठा रखे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कारबैंड उत्तराधिकारी से भविष्य अनुरूप हैं जो कर्मचारी नियम सहबद धीन स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुरूप हैं;

अन्, केन्द्रीय संकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (2) द्वारा प्रदत्त विवरणों का प्रयोग करते हुए और इन्हें उपचार अनुरूपी में विविध शर्तों के जीवन रहने के उपचार अनुरूप होने की तीव्रता वाली अवधि के लिए स्कीम के सभी उपकरणों के प्रयोग से छूट देती है।

अनुलूप्ति

1. उका स्थापन के उन्नाम में नियोजित प्रादीपिक भविष्य निधि आयुक्त परिवर्तन बाल को ऐसी विवरणियों द्वारा दी जाना जाता है कि विवरण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय संकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे लिरीजन प्रभारों का प्रयोग नाम की स्थापन के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (2) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक वीवा स्कीम के प्रशासन में, जिसके उत्तराधिकारी द्वारा जाना जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, वीवा प्रारंभिक का संवाद, लेखांशों का अन्तर्गत, लिरीजन प्रभारों का संवाद आदि भी है, हीने वाले सभी व्ययों का अनुवाद द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुसंधित सामूहिक वीवा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कर्मी उनमें संबोधित किया जाए, सब उस संबोधन की प्रति यथा कर्मचारियों की ब्रूमेंज्या की जापा ये सभी मुद्रण वालों का अनुवाद, स्थापन के सूक्ष्मान्तर पर वर्णित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के जीवन रहने के उपकरण की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है हाँ, नियोजक सामूहिक वीवा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त ऐसे करेगा और उसकी बाल प्राविष्टिक प्रारंभिक जीवन वीवा नियम की संवाद करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपकरण कायदे वाले ही तो, नियोजक सामूहिक वीवा स्कीम के जीवन कर्मचारियों

को उत्तराधिकारी द्वारा किया जाने की व्यवस्था करेगा तिसे ये कर्मचारियों के लिए गाम्भीर्य वीवा स्कीम के जीवन उत्पन्न करवाए जो जीवन स्कीम से अधिक अनुकूल हो, और उक्त स्कीम के अधीन अनुरूप है।

7. गाम्भीर्य वीवा स्कीम में जिसी बाल के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की सूत्र पर वह स्कीम के अन्तर्गत गोदय रखने उस स्कीम से कम है, जो कर्मचारी का उक्त वीवा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ही, तियोजित कर्मचारी के विविध वारिस/नामनियोशितों की प्रतिक्रिया के रूप में उसकी रकमों के भवित्व के बराबर रखने का संवाद करेगा।

8. सामूहिक वीवा स्कीम में जोई भी संवीधान, प्राविष्टिक विविध नियम आयुस परिवर्तन बाल के पूर्व इन्द्रोदान के लिए नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संबोधन ने वर्वर्तारियों के लिए पर एकीकृत प्रभाव पहने की संभवता हो, वहाँ प्राविष्टिक विविध आयुस प्रभाव अनुसूदत देने से पूर्व कर्मचारियों को उनका वृद्धिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवधार देगा।

9. यदि किसी कारणान्तर, व्यापार के कर्मचारी, भारतीय जीवन सीमा लिया हो तो उक्त सामूहिक वीवा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुना है जीवन रहने हैं, जो इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले जापे रखने से जाते हैं, तो वह छूट देने की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणान्तर, नियोजित उक्त लियत सारोंपत्र के भीतर जो भारतीय जीवन लिया जाता है, प्रारंभिक का संवाद वारीपत्र अनुसूदत देता है, तो उक्त वारीपत्र का अन्तर जो जाता है, जो अनुरूप की जाती है।

11. नियोजक द्वारा प्रारंभिक के नदाव व फिल्म गए फिल्म व्यापत्रक के द्वारा में उन सूत्र संबोधियों के नाम लियेंविलियों वा विविध वारियों का जो यदि यह छूट न दी जाए है, तो उक्त सूत्र के संबोधित जीवन वाले लियत से वर्तित रखने वाले हों तो उक्त विलिय वारीपत्र की जाती है।

12. उक्त स्थापन के सदस्य में लियत इस स्कीम के अधीन वाले विस्तार संपत्ति की भूमि का उक्त इन्द्रोदान नाम लियेंविलियों/विविध वारियों को ब्रौमेंज्या रखने का तथा उक्त स्कीम से और अन्य द्वारा में भवताव जीवन वाले लियत से वर्तित रखने वाले हों का साथ दिन के भीतर जुटाया करो।

[No. S-35014/124/83-ग्रा० ए-11]

S.O. 33.—Whereas Messrs Indian Aluminium Company Limited, 1, Middleton Street, Calcutta-71 (WB/RE-5137) and its Factory at 39, G. T. Road, Belur Math, Howrah, (WB/185) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premiums etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

लाइन नं. 34 --मैयर्स बुर्गल फेल्डोडस्ट्रीट, 33/ए, इण्डियन एलेन्ट, गुरुग्राम, दोभान-161013, (मध्य प्रदेश/2055), जिसे इसमें 2 में पश्चात् उक्त स्थापत कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रबंधन उच्च अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 की उपाधारा (2क) के अन्त में उक्त विधि का लिए दायर बना किया गया है;

पैर केन्द्रीय सरकार का समझौता हो गया है कि उक्त स्थापत के कर्मचारी, किसी पृथक शाखाका या ग्रामीणम का संवाद किए जाना ही, मार्गी जीवन वीमा नियम की सामूहिक वीमा स्कीम के प्रधीन जीवन वीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से भविष्य नहीं हैं तो कर्मचारी नियम साहृदय वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें घटनीय है,

उत्त , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपाधारा (2क) दायर अस्त शाखागों का प्रयोग करने हुए और इससे उपाधार भग्नाशकी में विभिन्न ग्रामी शर्तों के प्रधीन रहो हुए, उक्त स्थापत को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मध्ये उपलब्धों के प्रबंतन से छूट देती है।

लाइन 35

1. उक्त स्थापत के मम्मन्डल से नियोजक प्राविधिक अधिकारी नियम आयुष्मन विधि प्रदेश को ऐसा विवरणादार भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा विवरण के लिए ऐसी युक्तिशाली प्रक्रम करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विळ फरे।

2. नियोजक, ऐसा नियम प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति में 15 दिन के भत्तर सदाचार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 17 का उपाधार (2क) के विषय (क) के अधीन समय-समय पर निर्विळ फरे।

3. सामूहिक वीमा स्कीम के उपलब्ध में, जिसके अंतर्गत लेखाधारी का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत रिपोर्ट दीजा जाना, दीप, प्रीमियम का संवाद, देखायी दा अन्तर्णल, तिरकारी प्रभारों का संदर्भ आदि भी है, होने वाले सभी विवरणों का बहुत विवरक रूप से लेखा जायेगा।

4. विवरण, विवरणीय सरकार द्वारा, यदा भव्यमोदित सामूहिक वीमा स्कीम के नियमों का नियम प्राप्त, और ग्रन्थ की उनमें संशोधन किया जाए तब उस गंभीरत्व की प्रति तथा कर्मचारियों को यहांमध्या की आशा में उसकी भव्य व्याप्ति का अनुग्राम रापतने से अवकाश-पद्धति पर प्रदर्शित करेगा।

5. अदि वोड ऐसा लाइन 1, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापत की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापत में नियोजित दिनों जाता है तो, नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के उपलब्ध में उसकी नाम सुरक्षा दर्ज करेगा और उसकी वालन आवश्यक रूप से नियम अधीन वीमा विवरण को सदृश करेगा।

6. यदि उक्त स्थापत के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध फायदों में सम्बन्धित रूप से बृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें जिस कर्मचारियों के लिए यह सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन कायदों से भविष्य अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुशोध हैं।

7. सामूहिक वीमा स्कीम में विवरक वीमानी के भविष्य निधि के प्रधीन फायदों की मध्य पर इस कार्य के भविष्य नियम से उपलब्ध रूप है, जो कर्मचारी का उक्त व्यापार में सदृश दूरी, अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ही, नियोजक कर्मचारी के विविध विवरक वीमा समिक्षिती की

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के भीतर के बाहर रकम का संदर्भ करेगा।

8. ग्राम्यिक बीमा स्कीम के उपलब्धी में कोई भी सशोधन, प्रवेशिक भवित्व नियंत्रण मध्ये प्रतीक्षा के पूर्व अग्रदृश के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी गंभीरता से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रारंभिक भवित्व नियंत्रण अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को घटना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का वृक्षितरुप आवास देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारों, भारतीय अधिकारी व या नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पूर्णे घटना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के भारतीय कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रूप से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय अधिकारी व या नियम विभाग नियत करें, प्रारंभिक कार्यम का संदर्भ करने में असफल रहता है, और पालिमी की व्यवस्था हा जाते दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रारंभिक के संदर्भ में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नाभिवैशितियों वा विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होती भी उक्त स्कीम के अंतर्गत होने, बीमा कार्यों के संदर्भ का उत्तराधिकार नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कावार नाम निवैशितियों/विधिक वारिसों की बीमाहृत रकम का संदर्भ तत्परता से और प्रत्येक दृष्टि में भारतीय अधिकारी व या नियम से बीमाहृत रकम प्राप्त होने के गात्र दिन के भीतर मुनिषित करेगा।

[संख्या एस० 35014/375/82-पी०-एफ० II]

S.O. 34.—Whereas Messrs Sushil Fabricators, 33/A, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal-462023, (MP/2055) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(375)/82-PF. III]

का० अ० ३५--सैम्य देव य० कालान्त्री यैनालैक्सिंग
आर्ट्स (ग्राहनेट) लिमिटेड, १७-१९ पीनीग्राउण्ड, बृन्दावन-३ (मध्य प्रदेश-
१६४९), /निये होने वाले प्रत्येक वर्ष रथोत्तम पूर्ण ग्रा०/ द्वारा
वैष्णवीय भवित्व वाले वर्षों ग्राम्य अधिनियम, १९५२ (१९५२
का १०) (जिसे ग्राम्यके प्रत्यावर लक्ष्य अधिनियम कहा गया है) की द्वारा
१७ की उपाधा (२) के अधीन कूट दिए जाने के लिए आवेदन किया
है;

प्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिनियम या प्रीमियम का संदाय किए बिना हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम जो सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं प्रीर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निषेच सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञा है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवल जीवितों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावड़ अनुसूची में विनिश्चिट जटी के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन बर्ष की प्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आवृत्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियों देंगे और ऐसे लेखा रखें कि अंग्रेजी-डॉक्टरेशन्स द्वारा, सुविधाओं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, अनुसूची में विनिश्चिट जटी के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन बर्ष की प्रवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आवृत्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियों देंगे और ऐसे लेखा रखें कि निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्रिताएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, अनुसूची पर निश्चिट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक भास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संबंध करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समझ-धमय पर निश्चिट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रदानन के अन्तर्गत लेखाओं का रहा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गत, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, इसे जाने सभी व्यवहारों का अनुकूल, स्थापन के सुविधा पर प्रवर्तित करेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संकेतन किया जाए, तब उस संकेतन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहानें की आवाज़ उसको मूल्य जानों का अनुकूल, स्थापन के सुविधा पर प्रवर्तित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी गविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की प्रवधि निधि का प्राप्त ही सबस्त है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त बर्ज करेगा और उसकी बास प्रावधान प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संहस्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध कायदे बहाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध कायदों में समुचित रूप से पृष्ठ की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध जायदे उन कायदों के प्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञा है।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के लिए स्थापन पहले प्रयत्न द्वारा है, अधीन नहीं रहे जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीत से कम हो जाते हैं तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के पीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में प्रसंगल रहता है, और पालिसी को व्यवहार हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यवित्रित की दशा में उन मूल सबस्तों के नामनिर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती हो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय का उत्तराधित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्त की मूल्य होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विविध वारिसों की बीमाहत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक व्यापार में असंकल रहता है, और पालिसी को व्यवहार हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

13. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के पीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असंकल रहता है, और पालिसी को व्यवहार हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

14. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यवित्रित की दशा में उन मूल सबस्तों के नामनिर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती हो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय का उत्तराधित्व नियोजक पर होगा।

15. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सबस्त की मूल्य होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विविध वारिसों की बीमाहत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक व्यापार में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाहत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014(138)/82-पी.एफ.-II]

S.O. 28.—Whereas Messrs Motor Industries Company Limited, Nasik Division, 75, M.I.D.C. Estate, Safpur, Nasik (MH/12053), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominees of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium to within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for start of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(376)/82-PF. II]

का० आ० 36 पैमंप शोगा इन्डियन सेल्स कार्पोरेशन, वी०-६५ नारायण इन्डियन एस्ट्रिंग, फै०-१८ नई दिल्ली-११००२८ (दिल्ली-२२३५), (जिसमें इसके पात्रता उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी नियम और प्रविधि उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का. 19) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) वी० धा० १७ की उपधारा (२क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए संवेदन दिए हैं।

और केवल सरकार का समाधान ही गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृष्ठक अधिवाय या श्रीमियम का संवाद किए बिना ही, भारतीय जीवन वी० नियम की मानूषिक वी० स्टीम के पर्वत जीवन वी० मानूषिक वी० स्टीम के रूप में काफ़ी उड़ा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये काफ़ी उड़ा जान्दारों से अधिक ग्रनूकल हैं जो कर्मचारी निषेप सहबद्ध वी० स्टीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्टीम कहा गया है) के अधीन उन्हें ग्रनूकल हैं;

अन्. केवल सरकार, उक्त अधिनियम की धा० १७ की उपधारा (२क) द्वारा प्रदत्त अनुक्रमों का प्रयोग करते हुए और इसी उपबन्ध अनुक्रम में विनियिष्ट गती के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन बार की प्रवधि के लिए उक्त स्टीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रावेशिक भविष्य नियम आयुष्ट, तर्दे दिल्ली को ऐसी विवरणियों द्वारा और ऐसे लेखा रखना तथा निरोक्षण के लिए ऐसी सुविधाओं प्रयोग करना जो केवल सरकार, समय-समय पर, नियिष्ट है।

2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाद करना जो केवल सरकार, उक्त अधिनियम की धा० १७ की उपधारा (२क) के अधीन समय-समय पर नियिष्ट है।

3. मानूषिक वी० स्टीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाधी का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, वी० स्टीम प्राविष्टम का संवाद, लेखाधी का अन्तर्गत, निर्वाचन प्रभारी का संतान भावि० र्थ है; इने भले गवाई व्यवों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केवल सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक वी० स्टीम के लियों को एक प्रति, और जब कभी उनमें संपर्क रखना है, तो नियोजक, सामूहिक वी० स्टीम के मददस्त के रूप में उक्त नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी भूम्य वालों का अनुशासन, स्थापन के सूचनान्वय पर प्रवर्तित करेगा।

5. यदि कोई वी० स्टीम कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य का पा० उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त कियी स्थापन की भविष्य नियम का पहुँच ही सदस्य है, उम्मे स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक वी० स्टीम के मददस्त के रूप में उक्त नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी शाब्द आदर्शक प्रो० नियम का संदर्भ भूम्य हो रहा।

6. यदि उक्त स्टीम के अधीन कर्मचारियों को उल्लंघन कराये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक वी० स्टीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फाल्यों में संबूद्धि लें से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक वी० स्टीम के अधीन उपबन्ध फाल्दे उन फाल्दों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्टीम के अधीन प्रनुभेय हैं।

7. सामूहिक वी० स्टीम में किसी बात के हानि हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की नृथू पर इस स्टीम के प्रवीन गद्देय रखने उस रकम से कम है, और कर्मचारी को उस दशा में संरेय होती जब वह उक्त स्टीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विप्रिक वारिलानामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों दोनों के लिए उक्त रकम का संवाद फाल्दे उन फाल्दों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्टीम के अधीन प्रनुभेय हैं।

8. सामूहिक वी० स्टीम के उपबन्धों में सोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य नियम आयुष्ट, तर्दे दिल्ली के पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहने की संभावना नहीं, वह प्राविष्टम भविष्य नियम जारी, अपना अनुमोदित रैते से पूर्व कर्मचारियों को अपना द्रृष्टिकोण स्थान करने का पुराणपूर्वक भवसर होगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन वी० नियम की उम्मे जारी करने वाले नियम तिरने रहे, प्रो० नियम का संवाद करने में असफल रहता है, और प्रतिकूल की अवसर को जारी रखता है, तो यह छूट रह जी जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन वी० नियम तिरने रहे, प्रो० नियम का संवाद करने में असफल रहता है, और प्रतिकूल की अवसर को जारी रखता है, तो यह छूट रह जी जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रतिवेदन के तदाय ने कि! यह किसी व्याधिकल की दशा में उन भूत भवतियों व नाम निर्देशितियों या नियुक्ति घासियों का जो यदि यह छूट न हो तो गई होती तो उस स्थान के घटनात् होते, जीमा फायदों के सदाचार का उत्तरवाचित्व प्राप्त नहीं होता।

12. उक्त स्थापन के तदाय में नियोजक, इस स्कैम के अधीन आन वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हक्कात् नाम निर्देशितिया/नियुक्ति घासिया का बानाकृत रकम का संदाय तत्परत, से छोट प्रत्येक दशा में आवाहन जारी बना। नियन से बानाकृत रकम प्राप्त होने के साथ दिन के भीतर मूल्यांकित करेगा।

[सच्चा एस-35014/378/82-पी०एफ०-II]

S.O. 36.—Whereas Messis Chopra Electrical Sales Corporation, B-65 Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110023 (DLI/2235) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees, under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employers than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employer been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(378)/82-PF. II]

का० आ० 37--मैसर्ज इण्डिया प्रैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, डाक बक्स नं० 2190 5 मंडी, वैतारी रोड वैतारी-14 (कनटिक-3657), (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भवित्व निधि और प्रक्रीय उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपचारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए प्रवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी युवक अभियान या श्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन वीमा नियम की नामूदिक वीमा समिति के अधीन जीवन वीमा के रूप में फॉर्म उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए भी फायदे उन कायदों से आधिक प्रत्यक्ष हैं जो कर्मचारी नियम समूहवद वीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञय है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इससे उपचार प्रायुक्ति के अधिनियम शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

बन्धुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राविधिक भवित्व निधि आयुक्त, कनटिक' (कनटिक) को इस अधिनियम द्वारा और ऐसे लेखा रखेगा वहा निरोक्तम के लिए ऐसी मुद्रिता व्रतन करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे नियोजन प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की विधा 17 की उपचारा (उक्त) के बाण्ड (क) के अधीन समय-समय पर विषिट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखांशों का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, सेवाओं का प्रत्यक्षण, नियोजक प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्यापों का बहुत नियोजक विधा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति व्यापक व्यवसंक्षम की भाषा में उसकी मूल्य वालों का अनुबाद, स्थापन के मूल्य-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्ते स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदर्श करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कापड़ देने जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कापड़ों में नमुनिन कृप से बढ़ि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कापड़ उन कापड़ों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन नहीं हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संबंध रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी का उस दण में संबंध होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता ता, नियोजक कर्मचारी के विविध पारिस/नाम नियोजितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के घन्तार के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, कानूनिक (अंगूली) के पूर्व प्रानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रावेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिकूल भवसर रेगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं २९ जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कापड़ की रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत नारीक के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और परिसी को अपना द्वारा जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा रक्ती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिका भी वशा में उन मृत सदस्यों के साम निर्विकलियों या विविध वारियों को जो यदि वह, छूट द दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होती, बीमा कापड़ों के संदाय का उत्तराधिक नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आवे वाले किसी भवस्य की मृत्यु पर होने उसके बराबर भाव निवेशितियों/

विधिक वारियों का बीमाकृत रकम का संदाय उत्तरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014/379/82-पा०-एफ०-11]

5.O. 37.—Whereas Messrs India Packaging Products (Private) Limited, Post Box No. 2480, 5th Mile, Bellary Road, Bangalore-24 (KN/3657) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka (Bangalore) maintain, such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka (Bangalore) and where any amendment is likely to affect

adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain under their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(379)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1982

का० आ० 38.—मैसें खण्डेयवाल पं० अल्लौद्धज लिमिटेड, डाकघर-खण्डेयवाल नगर फिला, नागपुर-441402 (महाराष्ट्र/8658), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा भया है) ने कर्मचारी मधिष्य निधि और प्रक्रीये उपचात् अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा भया है की घारा 17 को उपचारा (2क) के प्रधान छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केंद्रीय सरकार दा रामाधन ही गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, जिसी पृथक् अधिदाव या प्रीमियम का संदाय किए जिन्हा ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहायता बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा भया है) के अधीन उह अनुकूल हैं;

गत, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 को उपचारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपचारा अनुमति में विविष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तात्पर्य की प्राप्ति के लिए उक्त स्कीम के सभी उपचारों के प्रभाव से छूट देती है।

अनुमति

1. उक्त स्थापन के सदृश में नियोजक प्रादेशिक अधिष्य निधि यात्रुक्त महाराष्ट्र, दा ऐमो विवरणिया भेजेगा और ऐसे लिखा रखेगा स्थान निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर मिलिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक् भास की समाप्ति के 15 दिन के लाईर सदृश करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की घारा 17 को उपचारा (2क) के अधीन समय-समय पर मिलिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के उपचारा में, जिसके वरदान लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रमुख दिया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्ण, निरीक्षण प्रभारों एवं सदृश गावि भी है, होने वाले सभी अध्यों का दहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा यथा प्रमुखोंद्वारा सामूहिक बीमा स्कीम के वियों की एक प्रति, और उक्त कर्मचारी उनमें संशोधन किया जाए, तब उक्त संशोधन की प्रति तथा वर्दमारियों की बदुसंवय की घास में उक्तकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि ऐसे कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निवि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निवि का वहाँ ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियंजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के स्पष्ट में उसका नाम सुरक्ष दर्ज करेगा और उसकी जावत् ग्रावयक ग्रीष्मियम भारतीय जीवन बीमा नियम का संदर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समृद्धि रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसके कार्यकारियों के लिए नामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिक प्रभुकूल हैं, जो उक्त स्कीम के प्रधीन द्वारा देते हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पार इस स्कीम के प्रधीन संवेद्य रूप से उस रकम से काम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता है, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती की अतिकर के रूप में दोनों एकत्रों के अन्तर के यांत्रिक रकम का संबंध फैला।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक अधिष्य निधि यात्रुक्त महाराष्ट्र, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और उक्त किसी सामाजिक से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहुँचे की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक अधिष्य निधि यात्रुक्त, अपना अनुमोदन दोनों से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृत्तिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त मतस्तर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना द्वारा है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट यह को जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम नियन्त करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिती का व्यवहार हो जाने दिया जाता है तो, वह इसे जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रोमियम के सदाय में किए गए किसी अतिकर की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितीयों या विधिक वारिसों की ओर यह, छूट न दी गई होती हो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय का उत्तराधिकार नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन प्राप्त वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम नियंत्रितीयों/विधिक वारिसों की अनुमोदन रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बोमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मूलिष्य करते।

[संख्या एस-35014/484/82-पी०एफ०-11]

New Delhi, the 9th December, 1982

S.O. 38.—Whereas Messrs Khandelwal Ferro Alloys Ltd, P.O. Khandelwal Nagar, District Nagpur-441402 (M.I. 8658) (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under sub-section (2A) of section of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts, and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

Q. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, exemption shall be liable to be cancelled.

Championship shall be limited to 30 contestants.

10. Where, for any reason, the employee fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heir entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(284)/82-PF. II]

कांग आ० 39 -मैमस 'पृष्ठाटित इमलोहित प्रदेशीराज (मुंबई), २०/५, मध्यराजा, फरदबाद (हरिपाणी) ४ (पक्ष/१६१८), जिसे इसमें
इसमें प्रकाश उत्तर स्थित (हा गया है) ने वर्तन्चारी भविष्य निधि और
प्रकारण उपब्रह्म धर्मिनियम, १९५२ (१९५३ का १९) (जिसे इसमें उपर्युक्त
उत्तर अधिनियम कहा गया है) कि धर्मा १७ की उपनिषद् (२५) के
बर्धन छठ द्वितीयाने के लिए प्रावेदन शिक्षा है;

धौर के जीवा संस्कारा तो समावेश हैं; गया है कि उक्त स्वापन हें कर्मचारी, जिसी पृथक् नियन्त्रण या प्रतिष्ठित वा संताप किए जित ही भास्तुय जीवन बीमा तिथि की आधिक नीमा स्फीट के प्रवृत्त जीवन बीमा के स्पष्ट में फारड़े उक्त गहरे हैं और ये कर्मचारियों के लिए ये काफ़िदे उन काफ़िदों से श्रद्धिक मनुद्वारा हैं जो कर्मचारी तिथि न गवाव बीमा स्फीट, 1976 (जिसे इसने इसके प्रभाव उक्त राजिम करा दिया है) के वधुत उन्हें भनते हैं;

प्रता, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिकारिता का धूम 17 जू उपायारा (2क) द्वारा प्रदत्त प्रक्रियों वा प्रयोग करने हुए और इस उपायका प्रभुत्व में विनिर्दिष्ट सभी को प्रधान रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्षों की प्रधानिक के द्वारा उक्त स्थापन के सभी उपवयों के प्रबन्ध से छद्म करो है।

‘अनांशी’

1. उक्त स्वतंत्रता के सबसे में नियाजक प्रादेशिक शक्तियाँ लिपि प्रायुक्त पञ्चव (हिन्दूणा) को ऐसी विवरणिया भेजेगा और इसे लेवा, रखेगा तथा निराकाश के लिए ऐसे उपचाराद् प्रदान करेगा जो केवल इन सभी, सम्पूर्ण एवं एक लिपिक बने।

२ विधिका, जो निरोक्तन प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर नदाय गरेगा तो केवल यह उक्त घटितात्मक की घाटा 17 की उपशाशा (३५) के संड (क) के अधीन समवन्नम-परिविहार है।

। गायूहिक वोभा स्त्रीम के प्रशासन में, जारीक धरणीगत नेपाली लोक अल्पसंख्यक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, वोभा प्रीमियम का दर्शय, अवधारणों पर भर्त्याण, विनीक्षण प्रभागों का सदाच आदि भी है, दूसरे वाले सम्बन्धों पर विवरण द्वारा किया जाता है।

४. विभिन्न केंद्रीय राज्यों द्वारा पाया गया मार्गार्दि तथा बुद्धिमत्ता समूह के लिए जो एक प्रति, प्रोटो-जप कर्त्ता उदयों और धन्य किए जाएँ तब उस संशोधन की प्रति हप्ता कर्मचारियों को अवश्य संकेता की जाया जैसे उत्तरकालीन विषय सार्वतों का प्रनाशण तथा उनके उत्तरान्तर्दृष्टि पर प्रबोधित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कमेंटारी, जो क्रमशः सर्विष्य निधि का या उत्तम अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया गया है तो, नियंत्रक द्वारा इसे ही, उसके स्थान से नियंत्रित किया जाता है तो, नियंत्रक द्वारा इसे एक सदृश के रूप में उसका नाम तुरल्ट दर्ज करेगा और उसकी धाक्का प्राप्तवक प्रीरिष्यम भारतीय जीवन वीक्षा नियम को संबल करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के सदानं कर्मचारियों को उत्तरवाद फालडे रहा है जाने हैं तो, नियोजक समूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उत्तरवाद कावयों में सूचित रूप से दृढ़ि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए गामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उत्तरवाद फालडे उन कावयों से प्राधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के प्रधीन अनुकूल हैं।

7. नियोजक बीमा स्कीम द्वे विभिन्न बाहु के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु एवं उस स्कीम के प्रधीन संदेश रकम उस रकम से कम है जो वर्दंचारी को उस दणा में संदेश होता, जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक आरिस्तान नियोजित को प्रतिक्रिय के रूप में दातों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदेश करेगा।

8. मामूलिक बीमा स्कीम के उपबंधों से कोई भी संशोधन, प्रदेशिक भविष्य निधि गायकून महाराष्ट्र बैंक के पूर्व अनुबंध के बिना ही लिया जायेगा और जहाँ किसी गण धन से कर्मचारियों वे लिया पर प्रतिकृष्ट प्रबन्ध पड़े फी संभवता हो तब, प्रदेशिक भविष्य निधि गायकून, अपना अनुबंध देने से पूर्व कर्मचारियों का प्रपत्ता इस्तीफ़ान माल रखने का युक्तिमुक्त गवाह देगा।

9. यदि किसी कारणवाला स्वयं के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस मामूलिक बीमा स्कीम के, जिसे प्राप्ति पड़ने अपार चाहा है शास्त्रीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का सदाचार करने में शास्त्रीय रहता है, और पानियों को घायल होता तो उक्त स्कीम के अनंगत होते, बीमा कावयों के सदाचार का उत्तराधिकृत नियोजक पर होगा।

10. यदि किसी कारणवाला, नियोजक उस नियत नार्त्यके अधीन जो शास्त्रीय जीवन बीमा नियम नियत करें, प्रीमियम का सदाचार करने में शास्त्रीय रहता है, और पानियों को घायल होता तो जीवन दिया जाना है तो, छूट रही की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सशाय में किए गए विभिन्न की वस्तु में उन मूल सदस्यों के भाग्यनिर्देशित्यों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अनंगत होते, बीमा कावयों के सदाचार का उत्तराधिकृत नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्कीम के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन आने वाले किसी राजस्व लो मूल्य होने पर उक्तके हकदार नाम नियोजित्यों/विधिक वारिसों की वीमानुत रकम का सदाचार तत्त्वात्मा से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से विनीहत रकम प्राप्त होने के लिए दिन के भीन्दा दूर्निवालन करेगा।

[भाग 4-35014/30/82-पैग-II]

S.O. 39.—Whereas Messrs Escorts Employees Ancillaries Limited 20/4, Mathura Road, Faridabad (Haryana) (PN/4628) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab (Haryana), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employee's Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominees of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab (Haryana) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. When, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(302)/82-PF II]

का०आ० 40 - मैमसं प्रभिनेण एड प्लास्टिमिजर्म लिमिटेड, "छो" बिल्डिंग निव सागर इस्टेट, डॉक्टर अच्छी बसर्ट रोड, वर्णी, घट्टबैठ-18 (महाराष्ट्र/14187) जिसे इसके पश्चात उत्तर द्यात रहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रक्रीय उत्तर अधिनियम, 1952 (1952 का 18) जिसे इसके पश्चात उत्तर अधिनियम कहा गया है, जो धारा 17 की उपचारा (2क) के अधीन छूट दिए जाएं जिसे के लिए प्राप्त किया है;

भीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उत्तर स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीभियम का संदाय लिए जिना ही भारतीय जीवन शीलन नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे, उन कायदों में शाखिक प्रत्यक्ष होते हैं जो कर्मचारी नियोजित सहबद बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उत्तर स्कीम कहा गया है) के अधीन उत्तर अनुचय हैं :

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उत्तर अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रवत्त जाकर्त्तों का प्रयोग करने हुए और इसके उपचारा अनुचय में विविष्ट भागों के अधीन रहते हुए, उत्तर स्थापन को तीन वर्षों की अधिक के लिए उत्तर स्कीम के सभी उपचारों के प्रवर्तन में छूट देते हैं।

अनुचय

1. उत्तर स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि सामूहिक 'महाराष्ट्र' को देसी विवरणियों में जो आ और ऐसे जीवा रखें तथा निरोक्षण के लिए देसी सुविधाएँ प्राप्त करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, भवदसभय पर निविष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे नियोजित प्रभारों का प्रत्येक भाग की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेंगा जो केन्द्रीय सरकार, उत्तर अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (2क) के छूट (क) के अधीन समयसमय पर निविष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाधीनों का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रो नेट का संदाय, लेखाधीनों का अन्तर्णाल, नियोजित प्रभारों का संदाय अधिक भी है, होने वाले हमसी व्ययों का अनुदान स्थापन के दृष्टान्त-रद्द पर प्रदर्शित करेंगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रस्तुत सामूहिक बीमा स्कीम के लियों की एक प्रति, और जब किसी उत्तर संगोष्ठन किया जाए, तब उत्तर संगोष्ठन की प्रति तथा अंतर्गतियों की बहुसंघटा की आवाज में उसकी मुख्य बातों का अनुदान; स्थापन के दृष्टान्त-रद्द पर प्रदर्शित करेंगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य लिधि का या उत्तर अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के संबंध के रूप में उसका नाम तुरन्त बद्ध करेंगा और उसकी नायत भावस्थक प्रीभियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संदर्भ करेंगा।

6. यदि उत्तर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपचार कायदे द्वारा नायत हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपचार कायदों में समुक्त रूप में दृढ़ि की जाने की व्यवस्था करेंगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपचार कायदे उपलब्ध हों जो उत्तर अनुचय के भाग/वर्ष अनुसूची हों।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदैव रकम उम रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदैव होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विवेक वारियम/नामनिर्देशनी को प्रतिकर के रूप में होनी रकमों के अंतर के बाबत रकम का नंदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपचारों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य लिधि सामूहिक महाराष्ट्र, के पूर्व प्रनुभोदम के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पहने की संभावना हो वहां प्रावेशिक भविष्य निर्वाचन सामूहिक, अपना श्रमुदोदय देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रपत्त करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के लिये स्थापन पहने प्रभाव छुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीत से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उम नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम लियत करें, प्रीभियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को अपनात हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीभियम के संदाय में किए गए किसी अविकल की दशा में उत्तर सदस्यों के नायनिर्देशियों या विवेक वारियों को जो यदि यह, छूट न हो गई होती तो उत्तर स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय का उत्तरवायिक नियोजक पर होगा।

12. उत्तर स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हहदार नाम निर्देशियों विविक आरोग्य की बीमाकृत रकम का संबाय तत्परता से भीर प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के बात विन के भीतर सुनिश्चित करेंगा।

[संख्या एस-35014/410/82-पी०-एफ०II]

S.O. 40.—Whereas Messrs Amines and Plasticizers Limited, "D" Building Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18 (M.H./14187) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

⁷ The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(410)/82-PF. III]

कांग्रेस 41 - मैमर्प डेवलपमेन्ट कनसल्टेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड,
पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16, (पश्चिम बंगाल/13709),
(जिसे इसमें उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और पक्की उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें
1085 GI/82-7

ज्ञके पञ्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की वारा 17 की उपचारा (क) के अधीन छूट दिए जाने के (उक्त अधिनियम का 11)

आर केन्द्रीय सरकार का आवाजान दो गए हैं कि उक्त गांव में रंपार, किस पृथक् प्रभवाय वा प्रृथक् गांव या नदी या झील, भारतीय जंगल वीभा जिले को सामूहिक वीभा स्कीम के अन्तर्गत वीभा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारीयों के लिए ये फारदे जा फायदों से अविकल्प अनुकूल हैं जो कर्मचारी नियोजित स्कीम 1976 (जिसे इसके पञ्चात् उक्त स्थान कहा गया) के अवान उहे अनुज्ञे हैं,

आर केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की वारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इनपे उपचार अनुसूची में विविध शारीरिक अधीन रहने हुए, उक्त स्थान को नोड वीभा की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मध्ये उपबंधों के प्रवर्तन ये छूट देंगे हैं।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रारंभिक सामूहिक गांवों परिचय बंगाल को ऐसी विवरणों भेजेगा और ऐसे नोड वीभा द्वारा याता निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समन्वय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रयोग सत्र की सामिन के 15 दिन के मीनार संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की वारा 17 की उपचारा (3क) के खड़ (क) के प्रवीन नामनामन पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक वीभा स्कीम के प्रयोगन में, जिसके प्रार्थी देवाओं का रखा जाता, विवरणों का प्रयुक्ति किए जाते, वीभा प्रभियों का सदृश लेखाचो का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय अर्द्ध भी है, होने जाने समझ व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा ग्रामोदेन गांवोंने उक्त स्कीम के नियनों की एक प्रति और जब कमों उर्मांगों द्वारा जाए तब उक्त संशोधन की प्रति तथा कर्विट्रियों की बढ़ुपदी को भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनाएँ पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पद्धत ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन मामूलिक वीभा स्कीम के सदस्य के लिए उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीनियम भारतीय जीवन वीभा नियम को सदृश करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबंध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक वीभा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबंध कायदों में सदृचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक वीभा स्कीम के अधीन उत्तरवाद कायदे उक्त कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुबंध हैं।

7. सामूहिक वीभा स्कीम में किसी वात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदृश रकम उन रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाभिनियमों को प्रतिक्रिया के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बाबत रकम का वृद्धि करेगा।

8. मामूलिक वीभा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि अनुपोदत्त परिवर्तन बंगाल के पूर्व अनुपोदत्त के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिक्रिया प्राप्त होने की संभावना हो, वह प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुनामन

वेत्ते से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्थिर करने का युक्तियुक्त प्रबल देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उमा सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पट्टे अपना कहा है, प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अवैतन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजित उन नियन तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियन करें प्रीभाव का सदर गठन में प्रकार रहता है और पानिसीं को उपयन हो जाने विद्या जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजित द्वारा प्रीभाव के संदर्भ में किए गए किसी वित्तीकरण की दशा में उन मूल मदलों के लाभान्वीकरणों या विधिक वारिसी को जो यदि यह छूट न दी गई होती हो उक्त स्कीम के प्राप्ति होते, बीमा कायदों के संदर्भ का उत्तरदायित्व नियोजित पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजित इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हस्ताक नाम निर्दिष्टतयों विधिक वारिसों को बीमाहृत रकम का संदाय तरतुता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम में बीमाहृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/416/82-पी०एफ०-11]

S.O. 41.—Whereas Messrs Development Consultants (Private) Limited, 24-B, Park street, Calcutta-16 (WB/13709) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced, in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(416)/82-PF. II]

S.O. 42.—मैमस पोष्टम (एप्लिया) लिमिटेड, नं. 26, कमाण्डर-इन-चौक गोड, मद्रास-600108 (पमिल नं. 5394), जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकारी उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की शारा 17 की उपशारा (2क) के अधीन छूट दिया जाने के लिए आवेदन किया है;

धौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक भविष्य या भविष्यम का संदाय किए जिना ही भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं धौर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से भविष्य अनुकूल हैं जो कर्मचारी निश्चेप भविष्य बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के प्रधीन रूप में अनुकैय हैं;

यथा: केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त विविधाएँ का प्रयोग करते हुए, और इससे उपावद अनुमति में विनियोग गतीं के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष से अधिक के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपलब्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

भासूची

1. उक्त स्थापन के मबद्दल में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा। तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएँ प्रशान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर नियिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के अन्तर संवाद करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के छूट (क) के अधीन समय-समय पर नियिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, वाले वाले सभी व्ययों का, बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की घटुसंघ्या की भाषा में उसकी मुष्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूक्ष्म-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त कियी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त बदल करेगा और उसकी वापस आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बदल जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समृद्धि रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से प्रधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुलेप्य हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हांते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस बात में संदेश हांती, तब वह उक्त स्कीम के अधीन होती है, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में हानी रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रशान पड़ने की संशयता हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृद्धिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रवाहर देगा।

9. यदि किसी को जनवरा, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी भी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणबाट, नियोजक उस सियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियुक्त करे, प्रीमियम का संदाय करने में घसफर

रहता है, और पालिसी को व्यपन हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिका दोष में उन मृत संघस्या के नाम निर्देशितियाँ या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न ही दी जाती है उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा कायदों के संदाय का उत्तराधिकार नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के मबद्दल में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी संघस्य की मृत्यु होने पर उसके हफकदार नाम निर्देशितियाँ/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से श्रीर प्रदेश के भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस०-३५०१४/४१८/८२-पी० एफ०-II]

S.O. 42.—Whereas Messrs Ponds (India) Limited, No. 26, Commander-in-Chief Road, Madras-600108, (TIN/5394) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (10 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of salient features thereof, in the language the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund in his establishment, the employer shall immediately make him as a member of the Group Insurance Scheme and necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits available under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamilnadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(418)/82-PF. II]

कां० आ० ४३ - मैसर्स टो० टी० इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड ट्रैडर्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाका नं० ५१, वृक्ष रोड, (यूटिल ईन्टर्नेशनल, तंजुवर) तंजुवर, (मॉमलनाडू-६४३९) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (२क) के प्रधीन छूट दिया जाने के लिए आदेत किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अनिवार्य या प्रीमियम का संदाय हित बिता ही, अस्तीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा की रूप में कारोबार उठा सके हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कारोबार के अधिक घनकृत हैं जो कर्मचारी निशेष महबूब बीमा स्कीम, ९७६ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें उमेय हैं;

अब: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (२क) द्वारा प्रदत्त अधिनियम को प्रयोग करने हुए और इससे उपर-प्रत्यक्ष भूमि में वितरित शर्तों के अधीन इसे हुए, उक्त स्थापन तंत्रान वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपलब्धों के रूप में छूट देती है।

आनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि तंत्रिताद्यु को ऐसी विवरणिया देंगा और ऐसे लेखा दर्शेगा तथा इन के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे विवरण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 देरीतर मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 धारा (२क) के द्वारा (क) के प्रधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रयासम में, जिसके अन्तर्गत संख्याओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, जो भी प्रमियम का मदाय, लेखाधी का अंतरण, निरोक्षण प्रभारों का संदाय प्राप्त हो है, होने वाले सभी ध्ययों का वहां नियोजक द्वारा किया जावेता।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के एक प्रति, और जब कर्मचारी उनमें समाप्त किया जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भावा में उम्मी शुभ्य बासों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रतिनित घरेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी विषय निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त कियो स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को सदस्य करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध करायदे बात जाने हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध करायदो में सदृचित रूप से बढ़ि की जाने की व्यवस्था करेगा। जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध करायदे उन कारबों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजीय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी जात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अध्येन सदैय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस बात में सदैय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक शारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के स्पष्ट में दोनों रकमों के अधीन रकम का संघर्ष करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबाधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त अनिलनाडू के पूर्व अनुसादन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर अतिरिक्त प्रभाव पहने की संभावना हो थीं, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना यूटिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना अनुजीय नहीं रख जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कारबों किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उम्मी दर्जे के भागर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियन करे, प्रमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यवगत हो जाते हैं तो, यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी अतिरिक्त की दशा में उन सूत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक बारिसों को जीवन बीमा नियम से बोझकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के प्रधीन भाने जाने की सदैय की प्रधीन भाने पर उनके हक्कार नाम निर्मितियों/विधिक बारिसों को जीवन बीमा रकम का संदाय तत्परता से भीर प्रयोक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बोझकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

S.O. 43.—Whereas Messrs T. I. Investments and Trades Private Limited P.B. No. 52, Vallam Road, (Unit Tanteek, Thanjavur), Thanjavur (1N/6839) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and bay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(283)/82 PF. II]

कांग आ० 44 मैर्स कोलेज प्रिंसिपल, पोर्टलॉड न्यूयॉर्क-१६
(निम्न तारीख/1905) पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कम्पनीरी विवर निधि और प्रक्रिया उपचार अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे उपचारा (2क) के उक्त अधिनियम कहा गया है) की पारा 17 की इसमें इसके पश्चात् अधीन लूटदिये जाने के लिए मार्गदर्शन किया है;

ओर केन्द्रीय सरकार का समावान हो गया है कि उक्त स्थापन के कम्पनीरी, किर्म पृथक् अधिनियम का प्रतियोगिता का मदाप्र किए विना ही भारतीय जीवन, भा. नियम का लाप्तिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन वीमा के भूमि में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे उन कायदों से अधिक प्रभुकृत हैं जो कर्मचारी नियोग लाभवश्व वीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त रूप से कहा गया है) के अधीन उन्हें लानुप्रयोग हैं;

प्रत, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की पारा 17 की उपचारा (2क) द्वारा प्रदल अधिकारी का प्रयोग करने के लिए और इससे उपचार अनुमति में विविध दिल दातों के अवृत्त रहने के लिए उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अधिकारी प्रबोधन उक्त स्कीम के भव्य उपचारों के प्रयोग से छुट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक विधि निधि शायुक्त (निम्नांक) को ऐसा विवरणिका से जैवा और ऐसे लेखा लेखा तथा नियोजित दातों के अवृत्त रहने के लिए ऐसो मुक्तिवार्ता प्रबोधन करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे नियोजित प्रबोधनों या प्रत्येक याम की भागिता के 15 दिन के भीतर संदर्भ करेता जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की पारा 17 की उपचारा (3क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक या भी स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का रक्षा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, वा मूल्यांकन का संदर्भ, लेखाओं का अन्तर्णाल, नियोजित प्रबोधन का संदर्भ भवित्व है, दोसे बाले मर्मी घटयों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा मानुषोद्धार समृद्धिक या भी स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें बद्धाधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की व्यवसंगत की राता में उसकी मुख्य यातो का अनुकूल, स्थापन के सूचना-प्राप्त पर प्रतिशत करेगा।

5. यदि ओह ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भवित्व निधि का उक्त अधिनियम के अधीन लूटदिये वाला है तो, नियोजक मानुषिक या भी स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपचार फायदों में सम्बन्धित रूप से बुलि की जाए जीवन वीमा करेगा। जिसमें कर्मचारियों के लिए सामूहिक या भी स्कीम के अधीन उपचार कायदे उन कायदों से अधिक प्रभुकृत हैं, जो उक्त स्कीम के अधीन लानुप्रयोग हैं।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे वाले हों तो, नियोजक मानुषिक या भी स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपचार फायदों में सम्बन्धित रूप से बुलि की जाए जीवन वीमा करेगा। जिसमें कर्मचारियों के लिए सामूहिक या भी स्कीम के अधीन उपचार कायदे उन कायदों से अधिक प्रभुकृत हैं, जो उक्त स्कीम के अधीन लानुप्रयोग हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम से किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्विचितों को प्रतिकर के रूप में वोनों रकमों के अन्तर के बीचारे रकम का संबंध करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबंधन, प्रादेशिक धर्मिय निधि आयुक्त, नियमन नाम के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संबंधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते की सनावना हो वहाँ, प्रादेशिक धर्मिय निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारण वश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना जाका है अर्थात् नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले फायदे किसी रूप से कम हो जाते हैं, तो यह सूट रक्ष का जा सकता है।

10. यदि किसी कारण वश, नियोजक उस नियन नामीन के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संबंध फरने में असफल रहता है, और पारिसंस को अवगत हो जाने विया जाता है, तो सूट रक्ष का जा सकता है।

11. नियोजक द्वारा प्रीग्राम के संबंध में किए गए किसी घटनाक्रम की दशा में, उस मूल मददों के नामनिर्विचित्रियों या विधिक वारिसों को जो, यदि वह छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फालदों के संबंध का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होते पर उसके हक्कार नामनिर्विचित्रियों/विधिक वारिसों को वै माहूल रकम का संबंध स्तररक्त से और प्रथेक वशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाहूल रकम प्राप्त होने के साथ दिन के भीतर मुनिश्वत करेगा।

[मा.एस-35014/281/82-पौ.एक०२]

S.O. 44.—Whereas Messrs. Facit Asia Limited, Perungudi, Madras-96 (TN/4805) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Link Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

का० आ० 45 - मैनर्स इनिट्रोन लिमिटेड, 1-2, इण्डियन पैनल एन० प्राइ० टी० १० फर्नीचारी (हरियाणा) (पञ्चाव/238), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिकारी निधि और प्रकीर्ति उपलब्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधानियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केंद्रीय सरकार का ममादात हो गया है कि उक्त स्थापन के बार्मारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए जिना ही, भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निषेष सहबद बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुप्येय हैं;

अन्. केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए और इसने उपायक अनुमति में विनिरिप्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपलब्धों के प्रबलन ने छूट देती है।

अनुमति

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रावेशिक अधिकारी निधि आयुक्त, अरियाणा (चंडीगढ़) को ऐसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधा एवं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर निर्विघ्न करे।

2. नियोजक, ऐसी निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के लिए (क) के अधीन समय-समय पर निर्विघ्न करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाद्वारों का रक्त जना वाला विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाद्वारों का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा दधा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भावा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का होने ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त बंद करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम को संबंध करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सुनिश्चित है से बढ़ि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुप्येय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संरेख रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेश होती, जब वह उस स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामिनिश्चिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपलब्धों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा (चंडीगढ़) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रभिक प्रसाध पड़ने के संभावना हो, वहाँ प्रावेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्थान करने का युक्तियुक्त अवसर पेगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन गहले अपना अचुका है अधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिंस वो अपग्रेड हो जाने दिया जाता है तो, छूट एवं रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिका की बात में उन मूल सदस्यों के जारीनिवेशितियों या विधिक भारिमा की जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रस्तुतीत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तराधित्य नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर उसके हक्कदार नामिनिश्चितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम के संवाद तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियम से बीमाकृत रकम माप्त होने के सात दिन भी भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० ३५०१४/४०८/८२-पी एफ-२]

S.O. 45.—Whereas Messrs Unitron Limited, 1-2, Industrial Area, N.I.T. Faridabad, (Haryana) (PN/238) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment aforesaid, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana (Chandigarh), maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, sub-

mission of return, payment of insurance premium, transfer of account, payment of initiation charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana (Chandigarh) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date specified by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (408)/82-PF. II]

का० ला० 46 ---मैर्स्ट इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेसीटिकल्स लिमिटेड, पोस्ट अफिल बालानगटान नजिप, ब्रैडगवाड (आंध्र प्रदेश/3107), (जिसे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निवि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपचारा (2क) के अधीन छूट दिया जाने के लिए आवेदन किया है;

पोर केन्द्रीय ग्राहक का सम्बन्ध न हो गया है कि उक्त स्थापन के अधीन, इन दूषण यथिदृष्टि वा प्रभियम तासंदर्शक विनाई, 1952 य उक्त विनाई नियम के मानुषिक वा मानीम के अधीन जैवन वा मान के रूप में फार्माचैट उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फार्माचैट उक्त फार्माचैट में अधिक अनुकूल हैं जो ऊर्ध्ववर्द्ध नियम ग्राहक वाले वर्ष 1952 (प्रभियम उक्त सम्बन्ध वाले स्थापन की धारा 15, 3 (प्रभियम इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है)) के अधीन उन्हें अनुबोध है,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपचारा (2क) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपलब्ध अनुसूची में विनियोजित विनाई के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन वो नियम वर्ष 1952 अधिविध के लिए उक्त स्थापन के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संतुलित में नियोजक प्राविधिक विष्य निवि आयुक्त, हैदराबाद, को प्रभियम भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा नियोजक विनाई के लिए ऐसा सुविधार्थ प्रदान करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, समव्यवस्थ पर नियोजित करे।

2. नियोजक, ऐसे नियोजन प्राप्तों का प्रत्येक मान की समाप्ति के 15 दिन के भातर संदाय देंगे। जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपचारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन रामय-सम्बन्ध पर नियोजित करे।

3. मानुषिक वा मानुषिक के प्रश्नान में, जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विनियोजियों के प्रस्तुत किया जाता, वे मानुषियम का संशोधन, लेखाओं का अंतरण, तिर लण प्रभरों द्वा नियोजन करना है, हेतु वाले गर्भ व्यया का बहन नियोजक द्वारा विधा जाता।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक वा मानुषिक के विनाई को एक प्रति, और जब कमी उनमें समीक्षन किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुम्ह दर्ज करेगा और उसके बाद उक्त वाला अवश्यक प्रियम भारतीय जीवन वीमा नियम को संदर्भ करेगा।

5. यदि कोई ऐसा नर्वनर्व, जो कर्मचारी भविष्य निवि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया स्थापन की विष्य निवि का पहले है मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित विधा जाता है तो, नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुम्ह दर्ज करेगा और उसके बाद उक्त वाला अवश्यक प्रियम भारतीय जीवन वीमा नियम को संदर्भ करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाने हैं तो नियोजक सामूहिक वीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध के ग्रदो में समुचित रूप से बढ़ि की जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कर्मचारियों के लिए मानुषिक वीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञय हैं।

7. मानुषिक वीमा स्कीम में किसी वाल के होने द्वारा भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेश रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दिन से संदेश होता। जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विष्यक वरियम/न.मनियोजिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बाबत रकम वा मंदिय करेगा।

8. सामूहिक बोमा स्कीम के उपबंधीयों में कोई भी संशोधन, प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा; और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रावेशिक भविष्य निधि भायुक्त, जपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृद्धिकोण स्पष्ट करने का वृक्षितयुक्त प्रबल सर देगा।

9. यदि किसी कारणबाट, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुना है प्रधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले कायदे किसी रीत से कम हो जाते हैं, तो यह छूट एवं की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणबाट, नियोजक चस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय बीमा निगम नियम लागत करे, श्रीमियम का संबंध करने में घसफर रहता है, और पानिसों को अपनात ही आगे दिया जाता है तो यह छूट की जा सकती है।

11. नियोजक चारा श्रीमियम के संबंध में किए गए किसी व्यापक बीमा में, उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितयों या विधिक बारितों को ओ, यदि यह छूट न ही गई होती तो उसके स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा बारितों के संबंध का उत्तरवाचिक नियोजक वर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आगे आगे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कावार लाभनिवृत्तियों/विधिक बारितों को बीमाहृत रूप से संबंध तत्परता से भीर प्रत्येक बात में भारतीय बीमा निगम से बीमाहृत रूप माप्त होने के साथ दिन के भीतर व्युत्पन्नित करेगा।

[सं.प्र. 35014/419/82-प्र.एफ-2]

S.O. 46.—Whereas Messrs Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Post Office Balanagar Township, Hyderabad (AP) 3107 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Hyderabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

1085 GI/82—8.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominees of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Hyderabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982

New Delhi, the 8th December, 1982

का० आ० 47.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2143, तारीख, 9 अगस्त, 1974 को अधिकान्त करते हुए, गुजरात राज्य के लिये एक क्षेत्रीय समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

अध्यय :

1. सचिव,
श्रम और रोजगार विभाग,
सचिवालय, गांधीनगर।
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त

सदस्य :

2. उप सचिव,
श्रम और रोजगार विभाग,
सचिवालय, गांधीनगर।
3. वित्तीय सलाहकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
सचिवालय, गांधीनगर।

गज्य सरकार की सिफारिश
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा
नियुक्ति दो व्यक्ति

4. श्री रजनीकान्त आर० नागरी,
प्रबन्ध निदेशक,
नागरी मिल का० निमिट्टे
ग्रहमदावाद।
5. श्री बी० बी० पटेल,
द्वंगरसोल रेन्ड इण्डिया,
जी० आर्ह० डी० सी०,
तरोदा, ग्रहमदावाद।
6. श्री जयन्तीलाल एम० शाह,
गुजरात चेष्टर आफ कार्मस
एण्ड इण्डस्ट्रीज,
पी० बाक्स नं० 4045,
रणछोड़ लाल मार्ग,
ग्रहमदावाद।
7. श्री अरविन्द भाई० दावे,
ग्रहमदावाद मिल मजदूर यूनि-
यन, खांनपुर गेट के सामने,
ग्रहमदावाद।
8. श्री मंगलदास एस० पटेल,
जनरल सेकेटरी,
टीक्सटाइल लेबर यूनियन,
नादियाड।
9. श्री समीर मनसूरी,
मंत्री,
केमिकल मजदूर सभा,
फतेपुरा,
याकूतपुरा के पास,
वादोदारा।

राज्य में कर्मचारियों के
संगठन के प्रारम्भ से केन्द्रीय
सरकार द्वारा नियुक्त कर्म-
चारियों के प्रतिनिधि।

S. O. 47.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.O. 2143, dated the 9th August, 1974, Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Gujarat consisting of the following persons, namely:

Chairman :

1. Secretary, Appointed by the Central
Labour and Employment Government
Department, Sachivalaya,
Gandhinagar

Members :

2. Deputy Secretary, Two persons appointed by the
Labour and Employment Central Government on the
Department, Sachivalaya recommendation of the
Gandhinagar State Government.

3. Financial Adviser, Labour and Employment
Department, Sachivalaya,
Gandhinagar

4. Shri Rajnikant R. Nagari,
Managing Director,
Nagari Mill Co. Limited,
Ahmedabad.

5. Shri B.B. Patel, Three representatives of
Ingarol Rand India, GIIDC, employers appointed by
Niroda, Ahmedabad. Central Government in
consultation with organi-

6. Shri J. Yaatil M. Shah, Gujarat Chambers of Com-
merce and Industries, Post Box No. 4045, Ranchhodlal
Marg, Ahmedabad

7. Shri Arvindbhai D. Dave, Ahmedabad Mill Majdoor
Union, Opposite Khanpur
Gate, Ahmedabad.

8. Shri Mangaldas S. Patel, General Secretary,
Textile Labour Union,
Nadiad.

9. Shri Samir Mansoori, Mantri,
Chemical Majdoor Sabha
Fatepura,
Near Yakutpura,
Vadodara

[No.V-20012(2)/78-PF-II]

का० आ० 48.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में श्रीर भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1052, तारीख 22 मार्च, 1975 को अधिकान्त करते हुए, बिहार राज्य के लिये एक क्षेत्रीय समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

अध्यय :

1. सचिव एवं श्रायुक्त,
बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
पटना।
केन्द्रीय सरकार द्वारा
नियुक्त।

सदस्य :

2. अम आयुक्त,
बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
पटना।
3. संयुक्त सचिव,
बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार,
पटना।
4. श्री ओ० पी० अदुकिया,
महासचिव,
मैमसं न्यू इण्डिया शूगर मिल्स
लिमिटेड,
दाकघर हमन पुर शूगर मिल्स,
(बिहार शूगर मिल्स एसोसिएशन) जिला समस्तीपुर,
बिहार।
5. श्री सी० एस० सिंह,
वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी,
मैमसं टाटा इंजीनियरिंग एण्ड
लोकोमोटिव कॉ०लि० (बिहार
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन), एम-
31, श्री कृष्णनगर, पटना-800001,
6. श्री एस० सी० जैन,
महाप्रबन्धक, रोहतास इण्डस्ट्रीज
लिमिटेड,
आमय भवन, फासर रोड,
(बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स),
पटना-800001
7. श्री जी० बी० राधवन,
हिन्द मजबूर सभा,
माईको लेबर यूनियन,
दाकघर गिरिढ़ीह,
जिला हजारीबाग, बिहार।
8. श्री शंख शारण सिंह,
महासचिव,
फटीलाईजर फेक्टरी बर्क्स यूनियन,
(इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन, कांग्रेस,
एल-594, सहरपुरा, सिन्दरी
(धनबाद)
9. श्री राज किशोर प्रसाद मिह,
सचिव,
बिहार स्टेट कमेटी ऑफ आल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 4, नारायण
मार्केट, लंगर टोली, पटना-800504.

राज्य सरकार की सिफारिश
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा
नियुक्त दो व्यक्ति

राज्य में नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय
सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि।

राज्य में कर्मचारियों के
संगठनों के परामर्श से
नियुक्त कर्मचारियों के
तीन प्रतिनिधि।

S.O. 48.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in late Ministry of Labour No. S.O. 1052 dated the 22nd March, 1975, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Bihar consisting of the following persons:—

Chairman.

1. The Secretary and Commissioner to the Government of Bihar, Department of Labour and Employment, Patna.

Members :

2. Labour Commissioner, Government of Bihar, Patna.

3. The Joint Secretary to the Government of Bihar, Department of Labour and Employment, Patna.

4. Shri O.P. Adukia, General Secretary, M/s. New India Sugar Mills Ltd., P.O. Higanpur Sugar Mills, (Bihar Sugar Mills Association), District Samastipur, Bihar.

5. Shri C.S. Singh, Senior Executive, Officer, M/s Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., (Bihar Industries Association), M-31, Shri Krishna Nagar, Patna-800001.

6. Shri S.C. Jain, General Manager, Rohtas Industries Ltd., Abhay Bhawan, Fraser Road, (Bihar Chamber of Commerce) Patna-800001.

7. Shri G.V. Raghavan, Hind Mazdoor Sabha, Mica Labour Union, P.O. Giridhi, District Hazaribagh, Bihar.

8. Shri Shambhu Saran Singh, General Secretary, Fertilizer Factory Workers' Union, (Indian National Trade Union Congress,) L-594, Siharpur, Sindri, (Dhanbad).

9. Shri Rakeshwar Pd. Singh, Secretary, Bihar State Committee of All India Trade Union Congress, 4, Niram Market, Langertoli, Patna-800004.

Appointed by the Central Government

} Two persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.

Three representatives of employers appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employers in the State.

Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employees in the State.

[No. V. 20012/8/78-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० अग्र० 49—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वासि) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त जक्कियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा, इस विभाग की दिनांक 6-12-82 की अधिकृता मा० 1(19)/विशेष सैल 82 पा० 11 द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त नामिनामु भरकार के राजस्व विभाग में संपूर्ण सचिव (पुनर्वासि) तथा उपसचिव (पुनर्वासि) का प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार को

हस्तांतरित मुश्ताकजा पूल की समस्त अंजित निष्कात्त सम्पत्तियों के निपटान के लिये तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम के नियम 87, 88, 90 (1) (क) 90 (1) (ख) 90 (11) 90 (12) और 101 के अधीन अपनी शक्तिया सौंपते हैं।

स० १(१९)/८(बगेवमैन/८२-ए स.ए.स.११ख
एस० के० बसु, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 49.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Secretary (Rehabilitation) and Deputy Secretary (Rehabilitation) as the case may be, in the Revenue Department, Government of Tamilnadu, appointed as Settlement Commissioner vide Notification No. 1(19)/Spl. Cell/82-SS. II(A) dated the 6th December, 1982, his powers under rule 87, 88, 90(1)(a), 90(1)(b), 90(11), 90(12) and 101 framed under the said Act for the purpose of disposal of all acquired evacuee properties forming part of compensation pool, transferred to the State Government of Tamil Nadu, under administrative and financial arrangements with immediate effect.

[No. 1(19)/Spl. Cell/82-SS. II(B)]

S. K. BASU, Chief Settlement Commissioner

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

का० आ० ५०—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (VI) के उपवर्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना स० का ग्रा० 2271 तारीख 7 जून, 1982 द्वारा दिल्ली भिल्क स्कीम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 जून, 1982 से छ० मास की कालावधि के लिये उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्र सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ० मास की ओर कालावधि के लिय बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

आत; अब, ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा द्वारा शक्तियों का प्रयोग का प्रदर्श करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 दिसम्बर, 1982 से छ० मास की ओर कालावधि के लिए लीक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

एल के० नारायणन, अवर सचिव

[संख्या एस 11017/14/81-ए(१)]

New Delhi, the 14th December, 1982

S.O. 50.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest as required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2271 dated the 7th June, 1982, the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 23rd June, 1982.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service or the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 23rd December, 1982.

[No. S-11017(14)/81-D.I.(A)]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 1st December, 1982

S.O. 51.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Engineering Stores Depot, Panagar, and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 36 of 1972

PARTIES :

Employers in relation to the Engineer Stores Depot,
Panagar

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. K. K. Ganguly, Advocate.

On behalf of Workmen—Mr. D. L. Sen Gupta, Advocate, with Mr. Nand Seemani, Advocate.

STATE : West Bengal

AWARD

By Order No. L-14011/2/71-LRI dated 22nd May, 1972, the then Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, Government of India sent the following dispute to this Tribunal for adjudication :

(1) Whether the action of the Officer Commanding, Engineer Stores Depot, Panagar in terminating the services of Sarvashri B. R. Ganguly, S. Roy and Kashi Prasad, IMEs with effect from the 15th November, 1971 is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?

(2) Whether the action of the Officer Commanding, Panagar in transferring Sarvashri N. C. Chakraborty and A. K. Ghatak, Joint Secretary and Treasurer respectively of the Military Engineer Workers Union, Engineer Stores Depot, Panagar from Panagar is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

2. This reference has come on remand under Order dated 15th July, 1977 passed by the Hon'ble High Court at Calcutta in a Writ application No. 3567(W)/73 setting aside the award of Sri S. N. Bagchi dated May 3, 1973 published in the Gazette of India dated June 2, 1973.

3. So far as the dispute No. (2) relating to the transfer of the Officers mentioned in the Schedule of reference is concerned, it has ceased to exist as stated by both the parties before this Tribunal and hence a 'no dispute' award is passed in respect of dispute No. (2).

4. As regards dispute No. (1) it appears that Messrs B. R. Ganguly, S. Roy and Kasmi Prasad were drivers, Mechanical Equipment under the Defence Military Engineering Service at Panagarh on temporary basis, that is, they were civilians connected with the Defence department. They were rendered surplus in January, 1970. As they could not be absorbed elsewhere even after the lapse of more than one year, the Officer Commanding, Panagarh, was directed by the Chief Engineer, Eastern Command, Calcutta during July, 1971 that the surplus men will be asked to accept the lower post and if unwilling their services will be terminated as per provisions of the Special Army Order No. 45/55. Accordingly, the three concerned drivers were asked to accept the lower post of DES which they did not accept. So their services were terminated after expiry of the notice period of one month on 15/19 November, 1971.

5. The case has been argued both on preliminary points as well as on merit. Two preliminary points have been raised by the management, (i) Whether the ESD, Panagar of the Defence Service was an industry within the meaning of Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947 and, (ii) whether the concerned three persons were subject to the Army Act, 1950 and as such excluded from the definition of "workman" in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act.

6. Preliminary point 1—Whether industry.—The first question is whether the ESD, Panagarh was an industry under Section 2(j) of the Industrial Disputes Act. Mr. K. Ganguly, learned Advocate appearing for the management contended that Regal or Sovereign activity of the Government is excluded from Section 2(j) and such activity is not an industry. So far as this proposition of law is concerned, he is right. The Supreme Court in State of Bombay v. Hospital Mazdoor Sabha, AIR 1960 SC 610 at page 615-1960 I LLJ 251 observed, "negatively stated the activities of the Government which can be properly described as regal or sovereign are outside the scope of Section 2(j). These are functions which a constitutional Government can and must undertake for governance and which no private citizen can undertake." The same view was taken in the Corporation of City of Nagpur v. Its Employee, AIR 1960 SC 675-1960-1 LLJ 523. It was laid down that the inalienable functions of the Government were outside the spell of industry. This view was accepted by the majority view in Bangalore Water Supply & Sewerage v. A. Rajappa, 1978 Lab. IC 467 1978 I LLJ 349-AIR 1978 SC 548 and 969 wherein it was observed : ".....sovereign functions, strictly understood (alone) qualify for exemption, not the welfare activities or economic adventures undertaken by the Government or statutory bodies. Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within Sec. 2(j)". It is thus clear that if the Government departments discharge purely sovereign functions of the State in exercise of its inalienable functions its activities shall be outside the circle of industry but not the other governmental activities are excluded from Sec. 2(j). Such essential constitutional (inalienable) functions of the State are, like administration of justice, administration of laws and legislative powers. In the words of Lord Watson these activities are, "The primary and inalienable functions of a constitutional government" vide Richard Coomber v. Justices of the County [(1883) 9 AC 61]. It is thus clear that whatever be the definition of "industry" it cannot include the regal or sovereign functions of the State. Lord Watson in the said case has described these functions as administration of justice, maintenance of order and repression of crime as amongst primary inalienable functions of a constitutional Government. It is to be noted that the definition of industry in the Industrial Disputes Act, 1947 is on the model of Australia and the Indian decisions on the

concept of industry are greatly indebted to the Australian judgments. In an Australian case Issacs, J., in his dissenting judgment in Federated State School Teachers' Association of Australia v. State of Victoria (1928-29) 41 CLR (569) states thus at page 585.

"Regal functions are inescapable and inalienable. Such are the legislative power, the administration of law, the exercise of the judicial power. Non-regal functions may be assumed by means of the legislative power. But when they are assumed, the State acts simply as a huge corporation, with its legislation as the charter. Its action under the legislation, so far as it is not legal execution of the law, is merely analogous to that of a private company similarly 'authorised.'

From the above it is obvious that regard and sovereign functions of the State are outside the pale of industry as denied in Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947.

7. Mr. Sen Gupta, learned Advocate appearing for the Union, however, contends that the activity of the ESD in the present case was not regal or sovereign but it will come within the definition of "industry" as given in Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act. His argument is that the activities of the ESD will be covered by the expression "manufacture" used in that definition. His contention, I think, is sound. Section 2(j) runs as follows :

"(j) 'industry' means any business, trade, undertaking, manufacture or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workmen."

It follows from the above that for an activity to be called as 'industry' the employer must be engaged in any business, trade, undertaking, manufacture or calling. The term "industry" also includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of the employees. Thus the definition of an industry is of wide import. In an Australian case Jumbunna Coal Mines No. liability v. Victorian Coal Miners' Association, 6 CLR 309 (370) (HCA) Issacs, J., speaking for the High Court of Appeal, picturesquely illustrated the terms used in the definition of 'industry' to mean a business (as merchant), a trade (as cutler), a manufacturer (as a flour miller) undertaking (as a Gas Company), a calling (as an Engineer or Serviceman (as a carrier)) or an employment (a general term like calling embraces some or the other and intended to extend avocations which might not be comprised with anything of the rest)....." From the above observation of Issacs, J., it is quite clear that the word "manufacture" has been explained by the example of a Flour Miller. In New Grand High Class Bakery v. ESI Corp, 1976 Lab IC 1466. The making of bread in the bakery was held to be a manufacturing process. Manufacture, in my opinion, is a kind of productive activity in which the making of the articles or materials (obtained in large scale) is by physical labour or mechanical power. In Webster's New Word Dictionary, "manufacture" means the making of goods and articles by hand or specially by machinery obtained on a large scale with division of labour. The same meaning has been given in the concise Oxford Dictionary. A question, therefore, does arise whether the ESD, Panagar manufactured any article in the sense stated above. WW-2 Balaram Ganguly, one of the three concerned employees, has stated in his evidence in-chief that nut, bolts, brackets, etc were manufactured for running repairs. There seems to be no denial of this fact. So the contention of Sri Sen Gupta has force. But, apart from it there are other materials to indicate that ESD was an industry. According to WW-2 the ESD had several sections. There was one section Bridging, Building, etc. There was another section of technical work. It was the store of electric motors, pumping sets, electric materials etc. There was also a workshop in which there was running repairing. There was another section, namely, Moulding section and a Blacksmithy section. The workshop activities were carried on in connection with carpentry also. There is nothing in the cross-examination of WW-2 to discredit him. WW-1, M. K. Mitra, the General Secretary of the MES Workers Union, ESD, Panagar has deposed that maintenance of stores, repair of stores, and several shons were at Panagar Depot. Various machines were kept for the purpose of repair and there were about 1000 workers both

industrial and non-industrial in 1971-72. Clerks, supervisory staff, store keeping personnel, fire fighting staff were non-industrial workers whereas all types of technicians and the tradesmen were included in industrial workmen. He has further stated that there was Works Department at Panagar unit constituted by the Officer Commanding, ESD Panagar according to the Industrial Disputes Act, 1947 and that the ESD was a factory registered under the Factories Act. There is no specific cross-examination by the management on these points. I rely on his evidence. MW-1 A. K. Mukherjee the Barrack Stores Officer has deposed that the ESD, Panagar was a store holding unit and used to cater for stores required for different military engineering services. Besides several operational type of stores such as, bridges, different types of Boards removable sets for military necessity were maintained. He also said that articles to be stored at the ESD, Panagar were purchased at the direction of the Army Headquarters and that for day-to-day work hay and other materials were purchased for packing purposes to be despatched to different centres and that the unserviceable articles were sold by Officer Commanding at Panagar through Government Auctioneer. Sri Ganguly drew my attention to the Written Statement of the Employer which states that ESD, Panagar is a defence establishment under the Ministry of Defence and that its functions relate primarily to holding and handling of stores required for defence purposes and that it was not a manufacturing or productive concern. It further states that the workload is based on the tonnage of the stores held and handled. He submitted that in the ESD there has never been any question of production bonus and that it is not a productivity unit. Learned Counsel points out that the unit is connected with the Defence Department and that the cars, lorries all belong to military unit and that the President cannot be conceived of running an industry. It is said that the President is the Supreme Commander of the Army, Navy and Air Force in exercise of sovereign functions. In short, his argument is that the ESD is a military department and is maintained under exercise of regal or sovereign functions of the Government. In my opinion, the activities of the ESD aforesaid can not be said to have been done in exercise of the sovereign functions of the State. They cannot be called primary and inalienable functions of the State. Sovereign functions cannot be destroyed. It is inseparable and inalienable from the conception of the State. In the present case admittedly the entire unit of the Defence Department, Panagar was closed and dismantled (perhaps in the year 1976) because it had no utility for the Government of India. I would like to point out here that admittedly the ESD was a defence establishment (vide the written statement of the management). If, so, it was an industry according to entry No. 8 of the First Schedule of the Industrial Disputes Act, 1947. Sri K. Ganguly referred to the case of Management, Station Canteen, Bangalore v. Presiding Officer, Labour Court, Bangalore & Ors., 1972 Lab. IC 776; Indian Naval Canteen Control Board v. Industrial Tribunal, Calicut, 1971 Lab. IC 1326 and the Supreme Court case of 1970 Lab. IC 1172 in the case of Safdar Jung Hospital, New Delhi v. Kuldip Singh Sethi for the purpose of explaining the meaning of industry. The last case of the Supreme Court was over-ruled by the latest Supreme Court decision in Bangalore Water Supply & Sewerage Board etc. v. A. Rajappa & Others, 1978 I LLJ 349. The Mysore case aforesaid has relied on Safdar Jung case. After the latest pronouncement made by Hon'ble Supreme Court in the Sewerage Board case it is not necessary to discuss the case relied upon by Sri K. Ganguly. I am of opinion that the activities in question were analogous to 'business' and come within the purview of Sec. 2(i) of the Industrial Disputes Act, 1947. I hold so accordingly. Thus the point raised by the management has no force.

8. Preliminary point 2—Whether subject to Army Act ?

The next question is whether the three concerned persons of the ESD, Panagar are subject to the Army Act, 1950 and as such excluded from Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. Sri Ganguly for the management argues that these persons should be held to be subject to the Army Act in view of the provisions of Section 2(1)(i), 3(1)(a), (b) and (c) and Section 9 of the Army Act read with the two army orders of 1962 and 1972 and hence they were not workmen in 1971 or in 1972 and therefore no industrial

dispute existed which could be referred to this Tribunal for adjudication. It is pointed out that though the two army orders of 1962 and 1972 were withdrawn in the year 1979 by army order No. 1/75 of 1977 and probably these persons could now raise dispute but they were not competent to do so in 1971 or 1972 when the provisions of the two army orders of 1962 and 1972 were in force. He submits that the validity of the reference is to be judged by the law as it existed at the date when the reference was made in 1972. It will be better to quote the different sections of the Army Act to which reference has been made, Section 2(1)(i) reads as follows :

- “2. Persons subject to this Act—(1) The following persons shall be subject to this Act wherever they may be, namely :

** ** ** **

(i) persons not otherwise subject to military law who, on active service, in camp, on the march or at any frontier post specified by the Central Government by notification in this behalf, are employed by, or are in the service of, or are followers of, or accompany any portion of, the regular Army.”

Section 3 runs as below :

- (i) ‘active service’, as applied to a person subject to this Act, means the time during which such person—
- (a) is attached to, or forms part of, a force which is engaged in operations against an enemy, or
- (b) is engaged in military operations in, or is on the line of march to, a country or place wholly or partly occupied by an enemy, or
- (c) is attached to or forms part of a force which is in military occupation of a foreign country.”

Section 9 provides :

“Power to declare persons to be on active service—Notwithstanding anything contained in Cl. (i) of Section 3, the Central Government may, by notification, declare that any person or class of persons subject to this Act shall, with reference to any area in which they may be serving or with reference to any provision of this Act or of any other law for the time being in force, be deemed to be on active service within the meaning of this Act.”

Admittedly Section 3 of the Act does not apply to these three persons. These three persons were not on active service within the meaning of that section. Mr. Ganguly, however, strongly relies on Section 9 and contends that these persons shall be deemed to be on active service by virtue of the notification issued by the Central Government under that section and hence they shall be subject to the Army Act within the meaning of Section 2(1)(i). He says that all the three sections, namely, Section 2(1)(i), 3 and 9 have to be read harmoniously and if so read these three persons shall be deemed to be on active service by virtue of the provisions of the army orders of 1962 and 1972 read with Section 9 of the Army Act.

9. In my opinion the contention is not sound. Section 2(1) in clauses (a) to (i) of the Army Act enumerates the persons who are subject to the operation of the Act. According to sub-clause (i) of this section persons governed by the Act included persons not otherwise subject to military law who, on active service, in camp, on the march or at any frontier post specified by the Central Government by notification in this behalf are employed by, or in the service of, or are followers of, or accompanying any portion of, the regular army. In other words, this sub-clause includes the civilians of the defence service. If such civilians are on active service and employed by the regular army or if they are in camp and are in the service of the regular army or if they are on the march and are followers of the regular army or if they are serving at any frontier post and accompany any portion of the regular army they shall be subject to the Act. Section 9 applies only to persons who are already subject to the Army Act but not on active service as contemplated by Section 3, they are deemed to be on active service by virtue of notification of

the Central Government. Such notifications in the present case are Exhibits M-3 and M-4. The first notification in the present case, namely Ext. M-3 is the army order No. 517/62 published in the Defence Gazette Notification No. 6E dated 28th November, 1962. It declares all persons subject to the Army Act as on active service. It runs as below :—

"Government of India, Ministry of Defence Gazette Notification No. 6-E dated 28th November, 1962 is reproduced below :—

"In exercise of the powers conferred by section 9 of the Army Act, 1950 (46 of 1950) the Central Government hereby declares that all persons subject to that Act, who are not on active service under clause (i) of Section 3 thereof, shall wherever they may be serving, be deemed to be on active service within the meaning of that Act for the purpose of the said Act and of any other law for the time being in force."

Exhibit M-4 is another army order No. 267/72 dated 10th June, 1972 and declares all persons who are subject to the Army Act as on active service. M-4 is "Government of India, Ministry of Defence Notification No. SRO dated 28th November, 1962." Thus the two notifications were issued by the Central Government, Ministry of Defence in exercise of powers under Section 9 of the Army Act, 1950. It is clear that all these persons must be already subject to the Army Act but not on active service from before the notifications. This fact is clear from the wording of Section 9 under which only a person or class of persons subject to the Army Act can be declared to be on active service. This is also clear from the two army orders of 1962 and 1972 which has used similar words. Mr. Ganguly argued that all civilians in defence service were declared to be on active service by notification under Section 9 and so they came within the purview of Section 2(1)(i). In my opinion he is not right. It is only those civilians of the defence service who are already subject to Army Act who are declared to be on active service. I think that Section 9 does not at all relate to the civilians of the defence service unless they are already subject to the Army Act prior to the notification. Section 9 does not make any person subject to the Army Act but it only declares civilians to be on active service. I have already said that Exhibits M-3 and M-4 have used words from which it is clear that only persons subject to the operation of the Army Act but not on active service can be declared to be on active service by the Central Government by issuing notification under Section 9. The contention thus fails. It follows that the contention of the management that the three concerned employees from 28th November, 1962 were governed by the two successive notifications (Exhibits M-3 and M-4) and were subject to the Army Act, 1950 under Section 2(1)(i) read with Section 9 of the Act is not tenable for the simple reason that the notifications aforesaid dealt with only those persons who were already subject to the Army Act and not with other civilians connected with the defence service. So, the concerned persons were not excluded from the definition of workman by reason of the provision of Section 2(s)(i) of the Industrial Disputes Act which reads thus ".....but does not include any such person, who is subject to the Army Act, 1950, or the Air Force Act, 1950 or the Navy (Discipline) Act, 1934". The management relied on Sach Dev Sharma v. Union of India & Others. AIR 1964 J & K, 21 Div., in which it was held that if the person is attached for the time being to or forms part of a force which is engaged in operation against an enemy, he is amenable to the Army Act. That was a case where a civilian officer attached to Works Engineer in Defence Service was declared to be on active service by notification under Sec 9 of the Army Act and was held to be amenable to the Army Act and could be tried by a Court of Enquiry set up under 177 of the Rules framed under the Army Act. It is clear that the officer in that case was attached to or formed part of a force. Such is not the case here. Moreover it seems that the J & K Bench in that case has not construed the expression "any person or class of persons subject to this Act" in Section 9 which clearly means that only such person as are subject to the Act can be declared to be an active service. There being no interpretation of that expression in the said decision it cannot be of much assistance in the present

case in which the interpretation of the provision of Section 9 and of the two army orders is in question.

10. Counsel appearing for the management next relied on Ous Kutiling Achudan Nair and Others v. Union of India and Others, AIR 1976 SC 1179. In that case it was held by the Hon'ble Supreme Court that the employee of the Defence Establishment such as cooks, chowkidars, lascars, Barbars, Carpenters, Merchants, Bootmakers, Tailors, etc. who were in the Training establishments could not form trade unions as their fundamental right had been completely taken away by the Central Government. It would be noticed, however, that in that case those persons were in Training establishments and answered the description of members of armed forces. Further, it was their duty to follow or accompany the army personnel on active service, or in camp or on the march. It was in these circumstances that it was held that although they were non-combatant and were in some matters governed by the civil services regulations, yet they were integral to the armed forces. It was observed that though they answered the description of "members of the armed forces" within the contemplation of Article 33 of the Constitution of India and consequently by virtue of Section 21 of the Army Act, the Central Government was competent by notification to make rules curtailing their fundamental rights. That case therefore is not of any assistance to the management because in the present case it has not been shown that the three concerned motor drivers were on active service employed by the regular army or in camp in the services of the regular army or on the march following regular army or at the frontier post accompanying any portion of the regular army. There is no evidence on record to that effect.

11. Another point which is vitally connected with this question is whether the three concerned employees are workmen. They will not be workmen simply because they are not excluded from Sec. 2(1). They have to be brought under any of the four specified categories, namely, skilled or unskilled manual, technical, clerical or supervisory. In my opinion these persons will come under the category of skilled manual. They will therefore, be workmen. My conclusion, therefore, is that the three employees were workmen within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947.

12. In connection with the above two preliminary points a further point has been argued by Sri Sen Gupta for the workmen that the Industrial Disputes Act itself indicates that industry can be carried by or under the authority of the Central Government. He has referred to Section 2(a) of the Industrial Disputes Act, 1947 and also to some of the provisions of the Standing Orders issued by the Engineer-in-Chief, Army Headquarter, of the year 1971 printed in 1972. His contention is sound. Section 2(a) of the said act shows it. It is further clear from the entries in the First Schedule of the Act under which even the Indian Government Mints are industries. It will not be out of place to mention here that modern State is a Welfare State under the Constitution of India. Its activity is no confined only to safeguard the country from external aggression or internal disturbances. It builds Dam construct railways, operates buses and trams, flies planes digs canals, generates electricity, maintains fair price shops, runs schools and colleges and so on. It performs a lot of multifarious functions. There are several government undertakings and Government Corporations employing large number of workers. I do not see as to why Industrial Disputes Act will not apply to government activities except that which is undertaken in exercise of its sovereign functions. Item 92 of the aforesaid Standing Orders of 1971 permits a civilian subordinate to form trade unions under the provisions of the Trade Unions Act. Item 94 permits formation of Works Committee as provided in the Industrial Disputes Act, 1947 in the MFS units: item 96 provides for Joint Consultative Committee for promoting harmonious relations and to secure greater measure of cooperation between the government and its employees in the matter of common concern. Under item 99 all enactments on Labour Laws are applicable to the MFS units except where they are specifically exempted from the application of certain provisions of the Act by competent authority. Reference may also be made to the case of M/s. Hindustan Aeronautics Ltd. v. The Workmen and Ors., 1975

I ab IC 1218—AIR 1973 SC 1737 where the Barrackpore branch of the Bangalore Division of the Government Company was engaged in an industry of repairs of air crafts or the like at Barrackpore This was admittedly an industry Mr Ganguly appearing for the management argued that three concerned employees were full-fledged government servants and they were controlled by civil services regulations, defence service regulations for the MES 1968. Standing Orders issued by the Engineer-in-Chief, MES, Regulation Chapter X dealing with stores and by manual of Indian Military Law and so they were not competent to raise industrial dispute I do not agree with this contention. In my opinion, even government servants of an industry run by or under the authority of government can raise industrial dispute From the above discussion it is quite obvious that the ESD, Panagar was an industry, that the three concerned employees were workmen and that the Industrial Disputes Act, 1947 applied to them I have also found that they were not subject to the operation of the Army Act, 1950

13 Point 3—I will now touch the merits of the case Admittedly the services of the three concerned employees S Roy B R Ganguly and Kashi Prasad were terminated under the provisions of Para 14 of SAO/S/53 with effect from 15 November, 1971 under the Order of Lt Col Engineer-Officer Commanding dated 16th October, 1971 on the ground that they did not accept the lower post of DES after they had been rendered surplus consequent upon reduction of workload The orders terminating their services are Exhibits M-9(a), M 9(b) and M-9 Mr Ganguly submitted that the termination of their service being in accordance with the provisions of the special Army Order 4/H/53 cannot be held to be invalid He pointed out that the conditions of service of these employees were determined by Army Headquarters at New Delhi, that the policy decisions were recorded by notifications and as such the validity cannot be challenged before this Tribunal He further argued that the management acted in accordance with Statutory Army Order 4/H/53 para 14 and hence the termination order is valid I do not agree The management had no doubt right to terminate the service of the concerned employees but that right can be exercised only in accordance with law The termination amounts to retrenchment and hence the Industrial Disputes Act is also applicable Admittedly no retrenchment compensation was paid to any of them The provisions of Section 25F therefore were not complied with This will make the termination of service illegal and void Mr Ganguly argued that the termination of service did not amount to retrenchment In my opinion the argument is not correct In the State Bank of India v M Senderamoni 1976—I ILJ 478 the Supreme Court observed “termination for any reason whatsoever are the key words Whatever the reason every termination spells retrenchment Termination embraces not merely the act of termination but the fact of termination however produced” In Santosh Gupta v State Bank, Patiala, 1980 II LLI 72 the Supreme Court again held that retrenchment means termination of service for any reason whatsoever and it covers every kind of termination of service except those not expressly included in Section 23F or not expressly provided for by any other provision of the Act such as 25FF and 25FFF The view taken in this case was upheld in I Robert D'Souza v Executive Engineer South Eastern Railway and Another 1982 I ILJ 330 I would therefore hold that the termination of service constituted retrenchment within the meaning of expression “retrenchment” in section 2(00) of the Industrial Disputes Act 1947 It is true that this interpretation was given in 1976 1980 and 1982 but the provisions of Section 2(00) existed at the time of termination of service of those employees and there is no reason as to why correct interpretation should not be applied to those provisions

14 For the above reasons the orders contained in Exhibits M-9, M-9(i) and M-9(b) are set aside So far as the back wages are concerned I think that the amount be the full back wages and hence I would direct the defence authority concerned under whom the Panagarh depot was working and some load of which after its closure has been taken by Kariknara Depot (vide MW 1) to pay to the three concerned employees S Roy B R Ganguly and Kashi Prasad full back wages from the date of termination of service till date They will be deemed to be in service and paid all consequential benefits that would have been available to them had they been in service The management however

will be entitled, if it so likes, to terminate the services of these three employees in view of their non-acceptance of the lower post in accordance with law and after complying with the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act 1947 It may also be mentioned that if any of the three workmen has reached the age of superannuation by this time, he will be paid upto that date only

This is my Award

Calcutta,
The 12th November, 1982

M P SINGH, Presiding Officer
[No L 14011(2)/71 LRT]

S.O 52—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Employees' State Insurance Corporation and their workman, which was received by the Central Government on the 26th November, 1982

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1 AT BOMBAY

PRESENT

Justice M D Kamblu Esqr, Presiding Officer

Presiding Officer

Reference no CGIT-23 of 1981

PARTIES

Employers in relation to the Management of Employees' State Insurance Corporation.

AND

Their Workman

APPEARANCES

For the employer—Mr. H V Advocate

For the workman—Mr. V. R Datar, Advocate

INDUSTRY

Insurance

STATE

Maharashtra

Bombay the 30th October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No L-15012(1)/81-D II B dated 31st October, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the Employees' State Insurance Corporation and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below —

SCHEDULE

“Whether the management of ESIC is justified in terminating the services of Smt M P Kulkarni, LDC, with effect from 3-1-1980? If not, to what relief is the said worker entitled?”

2 The workman, Mrs M P Kulkarni was employed as a Lower Division Clerk in the employer corporation Her appointment was at Pune with effect from 16-3-1978, under the order of appointment dated 7-3-1978 The letter of the appointment states that she had been selected and was offered a purely temporary post of Lower Division Clerk The appointment was to last to 31-5-1978 after which date unless

the tenure of appointed was extended her services were to stand terminated automatically without giving her any further notice. According to the workman, during her employment with the corporation a number of artificial breaks were given in the service, and finally her services were terminated with effect from 3-1-1980 A.M. In the statement of claim the workman has given the dates of the actual employment. The case as pleaded in the statement of claim by the workman is that the work she was doing was of regular nature and there was no justification on the part of the corporation to keep the workman as a temporary employee. There was no justification for the corporation to give breaks in the service of the workman. During her employment with the corporation there were no adverse reports against her from any of her superiors or despite this the corporation from time to time gave artificial breaks in her service. It was also pleaded that while terminating her services the corporation did not give any reasons for the same. Referring to the contention of the corporation that the workman had not successfully passed the test conducted by the corporation, the workman stated that at the time of her initial appointment she was not told that she was required to pass any selection test. It was alleged that no rules have been framed by the corporation requiring a candidate to pass a selection test. It was further stated that there are some other employees who are retained in the service of the corporation though they have not passed the selection test. There was therefore violation of Article 14 of the Constitution of India, as the Corporation is a state within the meaning of Article 12 of the Constitution of India. According to the workman, after the termination of her service the corporation has recruited fresh hands in Pune office where the workman was working. The corporation has therefore violated the right of the workman under Section 25-H of the Industrial Disputes Act. The workman submitted that the termination of her services amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act and while terminating her services the corporation did not pay the retrenchment compensation and notice wages in accordance with the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act and therefore the termination of the services of the workman was illegal. The workman therefore prayed that the corporation be directed to reinstate the workman with continuity of service and back wages.

3. The employer-corporation by its written statement contended that it was a statutory body constituted under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 and that the corporation has several branch offices in the State of Maharashtra and one of the Sub-Regional Offices is at Pune. According to the corporation, the workman was employed as a Lower Division Clerk with effect from 16-3-1978 on a purely temporary and ad hoc basis. By the letter of appointment it was made clear that the appointment was to last upto 31-5-1978. The corporation appointed the workman on the same basis subsequently under various orders. Under these orders the services of the workman were liable to be terminable at any time without any notice and without assigning any reason thereof, the appointment being on purely temporary and ad-hoc basis. It was stated that the corporation in pursuance of the power vested in it under the said Act of 1948 has framed the Regulations governing the recruitment of their employees and that the said Regulations are called "Employees' State Insurance (Recruitment) Regulations, 1965". It was pointed out that Regulation 5 and Regulation 21(2)(f) deals with the eligibility for appointment of a candidate in the corporation and that no candidate to a post can be appointed on a permanent basis in contravention of the Employees' State Insurance Regulations. According to the corporation, for the purpose of eligibility for appointment the candidate must be within the prescribed age limit and that the candidate to a post must possess the prescribed educational qualifications and experience and that as provided under Regulation 21(2) the recruitment to a post of Lower Division Clerk has to be made only by open competitive examination and the candidate who qualifies in the written test can only be appointed as Lower Division Clerk. The letters of appointment issued to the workman made it clear that her services were liable to be terminated at any time without any notice and without assigning any reason. In view of this position, the workman has no lien on appointment. The workman appeared as many as four times for the open competitive examination, but she failed

in those examination. Had she qualified in the competitive examination her services would have continued. The outside candidate for the test is required to be sponsored by Employment Exchange only. But, as the workman had crossed 25 years of age the Employment Exchange did not sponsor her name.

4. It was further stated by the corporation that as per the policy of the corporation which is an All India Organisation, as and when the Lower Division Clerks are required, open competitive examinations are being held as per the Regulations of 1965 and the candidates who pass the open competitive examination are being provided regular employment depending upon the availability of vacant post. No person can be appointed on a regular basis in contravention of the provisions of the Recruitment Regulations of 1965. The corporation denied that there was no rule requiring any employee to pass the selection test as alleged. It was pointed out that the rule about the test is to be found in Regulation 21(2)(f) of the Regulations of 1965. It was alleged that the corporation could not make any permanent appointment in contravention of this Regulation.

5. The corporation denied that the termination of the services of the workman amounted to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It was pleaded that the workman had no right to remain in service as per the corporation's Regulations and that all her appointments were purely temporary. Her services were terminated as per the terms of appointment as contained in the order of appointment. On these pleadings the corporation prayed that the reference be rejected.

6. Now, it is not in dispute that the services of the workman were terminated on 3-1-1980. It is also not in dispute that before this date of termination the workman had put in service for more than 240 days in the period of 12 months preceding 3-1-1980. By virtue of the provisions in Section 25-B of the Industrial Disputes Act, the workman therefore shall be deemed to be in continuous service for a period of one year. It is not in dispute that the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act were not complied with. The workman was not given one month's notice nor she was paid in lieu of notice, wages for the period of the notice. It is therefore contended for the workman that the order of the termination of her service was illegal and inoperative. As against this, it is contended very strenuously by the learned counsel Mr. Mehta, for the corporation that the services of the workman were temporary. The workman had not passed the qualifying test to enable her to continue in the service. The termination of the services of the workman therefore was perfectly justified. It was also contended that the termination of the services of the workman did not amount to retrenchment. Mr. Mehta placed reliance upon Regulation 21(2)(f) of the Employees' State Insurance (Recruitment) Regulations, 1965. It provides that recruitment to certain categories of posts, including the category of Lower Division Clerk shall be made by open competitive examination. Mr. Mehta further submitted that the workman was appointed on a purely temporary basis. He pointed out to the last letter of appointment dated 11-12-1979. That letter states that the appointment will last upto 29-2-1980 after which date, unless her tenure of appointment is extended, her services will stand terminated automatically without giving her any further notice. Now, the services of the workman were terminated by the letter of the Regional Director dated 21-1-1980, in which it is said that the workman may be deemed to have been relieved of her duty with effect from 3-1-1980 A.M. It may be conceded that the appointment of the workman was purely temporary and the corporation had a right to terminate her services as she had not passed the open competitive examination. However, if the termination amounted to retrenchment, the mandatory provisions laid down in Section 25-F of the Industrial Disputes Act will have to be complied with. The question therefore is whether the termination of the services of the workman amounts to retrenchment. Now, the expression "retrenchment" has been defined in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It is provided there :-

"retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include,—

- (a) voluntary retirement of the workman; or
- (b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or
- (c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health;"

7. Reliance is placed on behalf of the workman on the decision of the Supreme Court in State Bank of India v. N. Sundaramoney (1976 I. L.L.J. 478). It was observed there that "termination for any reason whatsoever" were the key words in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. Whichever the reason, every termination spells out retrenchment. A termination is where a term expires either by the active step of the master or the running out of the stipulated term. The Supreme Court observed that the termination embraces not merely the act of termination by the employer, but the fact of termination, however, produced. It was observed :—

"To write into the order of appointment the date of termination confers no moksha from Section 25-F(b) is inferable from the proviso to Section 25-F(1)."

The Supreme Court repelled the contention that automatic extinguishment of service by effluxion of time did not amount to retrenchment.

8. Now, it cannot be disputed that the workman had rendered continuous service for a period of one year within the meaning of Section 25-F read with Section 25-B of the Industrial Disputes Act. Now, the Supreme Court has in the case of L. Robert D'Souza v. Executive Engineer, Southern Railway (Indian Factories Journal and Factories Journal Reports, Vol. 60 p. 144) decided on February 16, 1982, observed :—

"Once the case does not fall in any of the excepted categories, the termination of service, even if it be according to automatic discharge from service under agreement, would none the less be "retrenchment" within the meaning of section 2(oo) of the Act."

It is further observed :—

"Even assuming that the workman whose service was terminated was a daily worker, once he has rendered continuous uninterrupted service for a period of one year or more within the meaning of section 25-F of the Act and his services are terminated for any reason whatsoever and the case did not fall within any of the excepted categories, notwithstanding that the rules governing his service would be attracted, they would have to be read subject to the provisions of the Act, and the termination would amount to "retrenchment"."

It was therefore necessary for the corporation to comply with the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act as the termination of the services of the workman amounted to retrenchment. No one month's notice nor retrenchment compensation was paid to the workman. The termination of the services of the workman therefore would be ab initio void.

9. Mr. Mehta for the corporation submitted that the workman could not be retained in service as she did not pass the competitive examination as required by the Regulations framed by the corporation. Her termination was therefore justified. He relied upon the decision of the Orissa High Court in a case of compulsory retirement in terms of and Village Industries Board (1981 II J.I.J. n. 411). It was held in that case that the termination being in terms of the Service Regulations, did not amount to retrenchment

and that therefore there was no necessity for complying with the provisions of Section 25-F. In coming to that conclusion the Orissa High Court tried to take support from the decision of the Supreme Court in the case of Hariprasad Shivshankar Shukla v. A. D. Divikar (AIR 1959 S. C. 121). It may be mentioned that the case before the Orissa High Court was a case of compulsory retrenchment in terms of the Service Regulations. However, the Supreme Court has now in the decision of Santosh Gupta v. State Bank of Patiala (1980 I.L.C. p. 687—AIR 1980 S. C. 1219) observed :—

"The expression "termination of service for any reason whatsoever" in Section 2(oo) covers every kind of termination of service except those not expressly included in Section 25F or not expressly provided for by other provisions of the Act such as 25FF and 25FFF."

It was expressly held in this case :—

"Thus, the discharge of the workman on the ground she did not pass the test which would have enabled her to be confirmed was 'retrenchment' within the meaning of Section 2(oo) and, therefore, the requirement of Section 25F had to be complied with."

The earlier decision of the Supreme Court in the case of Hariprasad Shivshankar Shukla v. A. D. Divikar (AIR 1957 S. C. 121) was considered in this case. The decision of the Orissa High Court in the case of Purna Chandra Giri v. Krisha Khadi and Village Industries Board (supra) therefore will be of no avail to the employer-corporation.

10. The services of the workman were terminated on 3-1-1980. Despite the breaks in service the workman had admittedly worked for more than 240 days in the year preceding 3-1-1980. It is clear that the termination of the services of the workman amounted to retrenchment within the meaning of that expression in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, since it did not fall within any of the excepted categories mentioned in Section 2(oo). It must, therefore be held that the termination of the services of the workman amounted to retrenchment and as there was no compliance with the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, the retrenchment was bad and invalid.

11. A reference may be made in this connection to the decision of the Kerala with Court in the case of Bhaskaran v. Sub-Divisional Officer (1982 I.L.J. p. 248) where it is observed :—

"The provisions of Ss. of 25F, 25G and 25H have overriding effect. Anything inconsistent contained in any other "law", which necessarily includes the Service Rules, cannot be given effect to. They have simply to be ignored, if the establishment in question is an industry."

The above decision will support the view that if an employee does not pass a written test required for absorption in permanent service and the services of such an employee are sought to be terminated the employer is not exempted from the operations of Section 25-F of the Industrial Disputes Act merely because the passing of a written test is compulsory under the service rules or regulations. In view of this discussion, I hold that the retrenchment of the workman was improper, invalid and inoperative.

12. The next question is what relief should be given to the workman. A reference may usefully be made in this connection to the decision of the Supreme Court in the case of Surendra Kumar v. Industrial Tribunal cum-Labour Court, New Delhi (1980 I.L.C. 1292). In this case it was observed :—

"Plain common sense dictates that the removal of an order terminating the services of workmen must ordinarily lead to the reinstatement of the services of the workmen. It is as if the order has never been and so it must ordinarily lead to back wages

too. But there may be exceptional circumstances which make it impossible or wholly inequitable vis-a-vis the employer and workmen to direct reinstatement with full back wages. For instance, the industry might have closed down or might be in severe financial doldrums; the workmen concerned might have secured better or other employment elsewhere and so on. In such situations, there is a vestige of discretion left in the Court to make appropriate consequential orders."

In the above case the termination of the services of the workmen was in violation of the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act. The Labour Court refused to give the workmen the relief of reinstatement in service with full back wages, but instead directed the payment of compensation of six months' salary to each of the workmen in addition to the retrenchment compensation. The Labour Court in making this order was influenced by the fact that the termination of the services of the workmen was a consequence of their failure to pass the test prescribed for permanent absorption into the service of the Bank and their reinstatement would have the effect of equating them with the workmen who had qualified for permanent absorption by passing the test. The workmen-appellants claimed before the Supreme Court that they should be awarded the relief of reinstatement with full back wages. After having considered the earlier decisions of the Supreme Court cited before them their Lordships observed that in the case before them they were unable to see any special impediment in the way of awarding the relief of reinstatement. The Labour Court, as is pointed out above observed that the award of the relief of reinstatement with full back wages would put the workmen on a par with those who had qualified for permanent absorption by passing the prescribed test and that would create dissatisfaction amongst the latter. Their Lordships of the Supreme Court disagreeing with the view of the Labour Court observed that the workmen could never be on par since reinstatement would not qualify them for permanent absorption and they would continue to be temporary, liable to be retrenched. The Supreme Court allowed the appeal of the workmen-appellants and they were directed to be reinstated with full back wages. However, the order of reinstatement was qualified with the following directives :—

"We, however, super-impose the condition that the salary on reinstatement of the workmen will be the salary which they were drawing when they were retrenched (subject of course to any revision of scales that might have been made in the meanwhile) and the period from the date of retrenchment to the date of reinstatement will not be taken into account for the purpose of reckoning seniority of the workmen among temporary employees. The respondent is free to deal with its employees, who are temporary according to the law."

13. I would therefore, in accordance with observations of the Supreme Court follow the same course viz., granting reinstatement to the workman with full back wages with the conditions super-imposed as was done by the Supreme Court.

14. Mr. Mehta, the learned counsel for the employer-corporation, submitted that in case this Tribunal took the view that the termination of the services of the workman was illegal and inoperative, to reinstatement should be ordered, instead the workman should be given compensation equivalent to a few months' pay and allowances. I must confess that I had accepted this submission in a similar case, being Reference No. CGIT-1 of 1980 where this corporation was the employer. The facts of that case were similar in as much as the services of the workman there were terminated as the workman had not passed the test. The services of the workman were so terminated without complying the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act. Instead of granting the relief of reinstatement I had ordered that the workman should be given compensation equivalent to six months' pay and allowances, if any. In making that order, I had relied upon certain observations of the Supreme Court in the case of Gujarat Steel Tubes Ltd. v. Its Mazdoor Sabha (1980 L.I.C. 1004). The decision of the Supreme Court in Surendra Kumar v. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi (supra) was not brought to my notice at that time. In view of what is observed by the Supreme Court in the case of Surendra Kumar v. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi (supra) where facts were identical I am of the view that the workman, Mrs. Kulkarni

should be reinstated with full back wages. The salary of the workman, however, on reinstatement will be the salary which she was drawing when she was retrenched from service (subject to any revision of scales that might have been made in the meanwhile) and the period from the date of retrenchment to the date of reinstatement will not be taken into account for the purpose of reckoning seniority of the workman among temporary employees.

15. In the result, I find that the management of E.S.I.C. is not justified in terminating the services of the workman, Mrs. M. P. Kulkarni, with effect from 3-1-1980. She would be entitled to the relief of reinstatement with full back wages with conditions as stipulated above.

16. My award accordingly. No order as to costs

M. D. KAMBHJI, Presiding Officer
[No. L-15012(1)/81-D. II (B)]

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 53.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Railway and their workmen, which was received by the Central Government on 7-12-82.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.
Reference No. CGIT-2/31 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Central Railway.

AND
Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. R. Pai, Advocate.

For the workmen—Shri V. B. Mahadeshwar, Convenor, Jt. Action Committee of Clerical Staff of C. Rly. Parel.

INDUSTRY : Railways.

STATE : Maharashtra.
Bombay, dated the 19th November, 1982

AWARD

By their order No. L-41011(13)/81-D.IIB dated 2-11-1981 the Central Government have referred the following two issues for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the demand of the workmen for filling up of the upgraded post of Office Superintendent at Parel Workshop on unitwise basis is justified? If so, to what relief are the workmen entitled?

Whether the action of the Central Railway in applying para 315 of the Indian Railway Establishment Manual for fixing the seniority of Chief Clerks for the purpose of filling up of the upgraded post of Office Supdis, is justified? If not to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The matter is being agitated by Joint Action Committee for Central Railway Clerical Staff Struggle and this Committee who has filed statement of claim in support of the claim. The record speaks that there are two unions working in the field namely Parel Workshop, Central Railway, by name National Railway Mazdoor Union and the Central Railway Mazdoor Sangh, who were served with notice of the present proceeding but none of them turned up with the result that the Action Committee has remained the sole agitator. The Railways however have not challenged the right of the said Committee to espouse the cause of the workmen and as such on reference, the matter has to be adjudicated. The silence observed by the two unions lead to the inference that they do not want to add anything to what is contended by the Action Committee and therefore did not feel it necessary to come forward.

3. The contention of the Committee as seen from the statement of claim Ex. 3/W is that initially the clerical cadre of the Central Railway Workshop Parel which is inclusive of Kurduwadi Workshop was combined with the clerical cadre of Chief Mechanical Engineer's Office, Matunga Workshop and Jhansi Workshop for the purpose of promotion to the selection post of Chief Clerk in the grade of Rs. 335-425

(AS)/Rs. 550-750(RS). However the recruitment to the lowest grade clerical post of Clerk in the scale of Rs. 110-180(AS)/260-400(RS) was all along being effected by each of the units separately, partly by direct recruitment through the Railway Service Commission, and appointments on compassionate grounds and partly by promotion from Class-IV. Similarly promotions to the next higher grade posts namely Senior Clerk/Time-keepers in the same scale of Rs. 130-300 (AS)/Rs. 330-560 (RS) and the Head Clerk/Time keeper in the scale of Rs. 210-380 (AS)/Rs. 425-700 (RS) were made on the basis of Unit-wise seniority. It is alleged that because of the creation and operation of comparatively more number of higher posts in the office of the Chief Mechanical Engineer, the Junior and Senior Clerks in the said office were able to secure promotions to the post of Head Clerk much more earlier than their counterpart serving in Parel Workshop despite having put in longer years service in the relevant grade posts than the former. The promotions to the selection post of Chief Clerk was also in the combined seniority of all separate units together, drawn on the basis of the date of the entry to the grade of Head Clerk, as a result of which, it is alleged, Head Clerks of the Chief Mechanical Engineer's office though comparatively junior became eligible and secured promotion to the post of Chief Clerk much more earlier than the senior clerical staff of the Parel Unit. This was in spite of the Central Railway letter No. 21800-RA/Spl. IV dated 26-12-1968 to decentralise ministerial cadres and effect promotions upto grade Rs. 335-425 (AS) on unit-wise basis. Similarly, the Railway Board's instructions in the letter No. PC-63/Pt. 4/4 dated 15-12-1967 to the effect that the clerical posts, based on the percentage of distribution of posts in the various grades, including grade Rs. 335-425 (AS) should be evenly distributed amongst all the units was also not given effect to in respect of Parel Clerical Unit. It is alleged that a number of clerical posts in the grade Rs. 335-425(AS) were actually operated in the Chief Mechanical Engineer's office and this was despite the Railway Board's mandatory order contained in the letter No. PC. III/74-PS-3/UPG/5 dated 14-2-1977. By the said letter the Ministry of Railways have expressed their desire to ensure that due share of higher grade posts sanctioned under the scheme in each category is allotted to various divisional/subordinate offices without any undue weightage being given to Headquarters offices.

4. Because of this great injustice there were joint representations, interviews and meetings with the concerned authorities when it was ultimately decided by the Central Railway Administration by their letter No. HPB/201/UPG, dated 23-6-1979 to decentralise and fill up the posts of Chief Clerks, grade Rs. 550-750 (RS) from among the eligible candidates of each seniority unit, this decision, it is alleged, made effective from 1-1-1979 and only eligible candidates from among the Parel Unit were considered and a panel of selected candidates was drawn and approved by the competent authority on 8-8-1979.

5. Later on, under the scheme of restructuring of the clerical cadres, four posts of Chief Clerks grade Rs. 550-750 (RS) from amongst the total posts of Chief Clerks within the cadre of Parel Workshop became due for upgradation to the post of Office Superintendent in the grade Rs. 700-900 (RS). It is alleged that this upgradation of the Chief Clerks to office Supdt. did not involve or envisage any change or additions to the duties and responsibilities attached to such upgraded posts. It is also a non-selection post to be filled in from amongst the Chief Clerks of Parel Unit in the order of their seniority. However instead of following the proper procedure, it is complained, the Central Railway Administration posted candidates from other Units thus depriving the eligible candidates of Parel Unit of their due chance of promotion.

6. Regarding point No. 2 it is contended that for the purpose of filling up the upgraded post of Office Supdt. in the grade Rs. 700-900 (RS) on the basis of the pooled seniority of all the four units the procedure laid down is to draw out a combined seniority list of all the Chief Clerks of the four units namely Parel Workshop, Matunga Workshop, Jhansi Workshop and Chief Mechanical Engineer's office, Bombay, as contemplated under para 314 of the Indian Railways Establishment Manual and then to effect the promotion to the post of office Supdt. It is alleged that the panel of the Chief Clerks of Parel Workshop was approved by the competent authority on 8-8-1979 while the panels for other three units were drawn and approved much time thereafter. It is alleged that in terms of para 314 of the Manual all the empanelled Chief Clerks of Parel Unit are eligible to have their seniority

fixed enblock over the Chief Clerks of all other concerned units thus entitling the senior-most Chief Clerks of Parel Unit to promotion to the four posts of Office Supdt. in their own Unit. However, the Central Administration erroneously regulated the seniority and promotion by mis-applying para. 315 of the Manual, thereby depriving the eligible Chief Clerks of Parel Workshop of the chance of promotion.

7. It is therefore prayed that the up graded post of Office Supdt. should be filled in by seniority on Unit-wise basis and that while fixing the seniority not para.315 but para.314 should be the governing paragraph and suitable declaration to be given accordingly.

8. By their written statement Ex. 2/M the Railways refuted these contentions. They admit that the clerical post upto and including grade Rs.550-750 (RS) have been decentralised and are being filled in by Unit-wise from amongst the staff of that Unit. It is however contended that the posts of grade Rs. 700-900 (RS) are centrally controlled at the Head-quarters level and filled in on pooled seniority in the various Units. Therefore the four posts of Parel Workshop, it is alleged, are filled/to be filled by senior-most suitable candidates on pooled seniority basis observing 40 points roster for employees belonging to reserved communities. It is alleged that the post of Office Superintendent is to be filled in by promotion from amongst the senior-most suitable candidates in the next lower grade and if that date of appointment is the same, the date of entry to the grade next below shall be the determining factor. It is therefore contended that the total length of service in the clerical cadre is not the criterion to determine the seniority. Lastly it is stated that the question of decentralising the posts of Office Supdt is under consideration in consultation with the organisation of labour and till such time the promotion channel cannot be changed unilaterally by the Railways and so the reference should be dismissed.

9. On the above pleadings the following issues arise for consideration and my findings thereof are :—

ISSUES..

FINDINGS

1. Whether the orders contained in the letters Only relevant No. 21800-RA /Spl. IV dated 26-12-1968, for proving the PC-63/Pt.4 .dated 15-12-1967 and letters history. PC. III/74- PS- 3/ UPG/5 dated 14-2-1977 have relevance and whether they govern the question of Unit-wise seniority?
2. Whether the demand of employees for filling up the upgraded posts at Parel Workshop on unit-wise basis is Justified ? Yes
3. If yes what relief is possible? As per award.
4. Whether the Railways have wrongly applied paragraph 315 of the Indian Railway Establishment Manual and should have applied paragraph 314 ? Yes
5. If yes whether the seniority of Chief Clerks No for the purpose of filling up of the upgraded posts of Office Superintendent has been rightly fixed ?
6. If not to what relief the concerned employees are entitled? Does not arise.
7. What award? As per award .

REASONS

10. Both the parties decided not to adduce any oral evidence in the case but relied upon the documents and other material brought on record. At Ex. 5/W there is a Railway-Board's letter dated 15-12-1967 wherein the injustice caused by the pooled seniority was considered and it was decided that the higher grade posts should be distributed between Headquarters and Divisions or Workshops or other subordinate offices, separately for each of the Units of promotion in grades for which promotion is unitwise and not all Railway-wise basis. Next comes the D.O. letter dated 18-7-1977 written by the Dy. Chief Mechanical Engineer Parel recommending that selection for the post of Chief Clerk and Personnel inspectors should not be held on pooled basis but on unit basis. We find a reflection thereof in the letter of the Chief Mechanical Engineer, Bombay V.T. Ex. 7/W dated 23-6-79 whereby the Railways decided to decentralise the post of Chief Clerk with effect from 1-1-1979 and to fill in the vacancies from amongst the eligible candidates of each seniority unit. It was directed to take immediate action to form panels for filling up the upgraded selection grade posts

of Chief Clerks in the grade of Rs. 550-750(RS) by the Units themselves. At Ex. 8/W there is a letter dated 15-7-1977 calling for the considered opinion of the Unions regarding the avenue of promotion of clerical staff of Parel Workshop. At Ex. 9/W dated 10-8-199 we find the names of employees-workmen—for filling the post of Chief Clerk/Time-keepers Grade I in the scale of Rs. 550-750 (RS) of Parel and Kuduwad Workshop.

11. We have already noticed that all along the demand of the Parel Workshop was to treat them as a separate unit for avenue of promotion and in this demand they got the support from the Dy. Mechanical Engineer, Parel as seen from the letter dated 31-10-1979 Ex. 10/W who found this demand as just and genuine. The same Officer by another letter Ex. 11/M dated 18-3-1980 suggested that seniority for promotion for the post of Office Superintendent in the scale Rs. 700-900 (RS) should have been based on the seniority of the Chief Clerk in the grade immediately below, under paragraph 314 of the Indian Railways Establishment Manual. The Officer has pointed out that in the past the seniority for promotion to P.I. Scale Rs. 550-750 (RS) was based on the principle laid down in paragraph 314 of the Establishment Manual and the staff of Matunga workshop were treated as senior for promotion as P.I. and as they were placed on the panel in the scale Rs. 425-640 (RS) earlier than the staff of Parel and the same analogy should be applied.

12. As far back as in the 1967 by letter dated 15-12-67 the Railway Board had taken a decision that the higher grade posts should be distributed between Headquarters and Divisions or Workshops or other subordinate offices, separately for each of the Units of promotion in grades for which promotion is unit-wise and not all Railway-wise basis strictly according to the prescribed percentages. It was found that the centralised system caused injustice to the other officers like Parel Workshop etc. As a result of this letter by another letter dated 26-12-1968 Ex. 13/M it was decided that each departmental Headquarters would be an independent unit upto and inclusive of the grade Rs. 335-425 (AS) and the posts in the grade of Rs. 350-475 (AS) will be filled on the basis of pooled seniority of the staff in the grade of Rs. 335-425 (AS) of all Headquarters units. However on 23-6-1979 a directive was issued that the post of Chief Clerk in the grade of Rs. 550-750 should be decentralised with effect from 1-1-1979 and filled from among the eligible candidates of each seniority unit. Now from Ex. 16/M we come to know that in the year 1979 as well as in the year 1980 the number of clerical posts in the Parel Workshop remained the same at 375 and the only change was effected in the various grades being 9 posts of Office Superintendent with effect from 1-10-1980, in the scale of Rs. 700-900 (RS).

13. It was urged on behalf of the Railways that although there was decentralisation of the post of Chief Clerks, when the question of posting of Office Supdt. comes in, not the Unit-wise seniority but pooled seniority should be the criterion and it was suggested that till this issue is under consideration no unilateral action could be taken by the Railways. We have already seen that decentralisation was effected in order not to allow an unit to get advantage over other units because of various factors and ultimately even the posts of Chief Clerk from amongst whom upgraded posts of Office-wise were to be filled in were also decentralised on Unit-wise basis. Now once the principle that decentralisation is necessary stands accepted, there is no reason why this should not be extended further and it is made applicable to the post of office Supdt. especially when the contention of the Action Committee in para. 2(V) of Ex. 3/M to the effect that the upgradation of the posts from Chief Clerk to Office Supdt. did not involve or envisage any change or additions to the duties and responsibilities attached to such upgraded posts, is not refuted. It is also a non-selection post and therefore must be filled in on seniority basis. There is great force in the contention of the Action Committee that if the pooled seniority is taken into account, candidates from other units are likely to gain advantage at the costs of Chief Clerks serving at the Unit at Parel and the former decentralisation being the result of removal of such injustice, the same rule will have to be followed in the case of Office Supdt. also. Atlast the Railways could not point out as to how the rules of pooled seniority of office Supdt. would be just particularly when upto the posting of Chief Clerks the same was discarded being causing injustice. I therefore answer issue No. 2 suitably namely that the demand for Unit-wise seniority is justified. Various circulars are referred

to for issue No. 1 but they have got no direct bearing except for tracing the history about decentralisation at various stages.

14. Even one of the officers has found the demand true and genuine and the Railways have also not rejected the demand but kept it under consideration. Having regard to this fact and further having regard to the circumstances discussed above rules of seniority of Unit-wise basis will have to be applied from date of reference atleast if not earlier and suitable promotional avenues will have to be given to the person concerned. Once point No. 1 is answered suitably really appearing point No. 2 would not arise at all. However, since there is a reference finding one way or other will have to be noted. The Rules regulating seniority of non-Gazetted Railway servants are to be found in Chapter III of the Railway Establishment Manual. Under the Para 314 which lays down seniority in selection posts, it has been laid down that seniority of two or more officiating railway servants selected at different selections for a particular selection post should be fixed with reference to the date of selection, that is to say, railway servants borne on an earlier panel shall be senior to those selected later even though the latter may be continuously officiating in the selection post as a local arrangement from a date prior to the date of promotion of the former or the latter may be substantively senior to the former. We have already seen that in his letter dated 18-3-1980 the Dy. Chief Mechanical Engineer Parel had drawn the attention of his superior that the seniority for the promotion at Parel in the grade Rs. 550-750 was based on the principle laid down in paragraph 314 of the Establishment Manual and it is further stated that the staff of the Matunga Workshop was treated as senior for promotion as P.I. as they are placed on the panel earlier than the staff of Parel. It is the contention of the workmen that in pursuance of the direction given in the letter dated 23-6-1979 the Parel workshop had formed a panel while other units had lagged behind.

15. The Railways are applying paragraph 315 but it is attracted only if the date of appointment to a grade is the same. After the panels were formed and when para. 314 is clear it would be the said paragraph and not paragraph 315 which would govern the seniority. If at all there is another paragraph applicable it would be paragraph 321 which determines the relative seniority of employees in an intermediate grade belonging to different seniority units appearing for selection/non-selection post in higher grade. Different seniority units are therefore considered separately at the same time if the inter-se seniority is to be fixed the said paragraph would be attracted. Therefore answer issue 4 suitably and hold that the seniority of the Chief Clerks on the basis of paragraph 315 is wrongly fixed and it should be under paragraph 314. However since point No. 1 is decided in favour of the Action Committee no relief need be granted on this account. Award accordingly.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
[No. L-14011(13)81-D. II (B)]
S. S. PRASHER, Desk Officer.

Dated : 25-11-82.

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 54.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhulanbararee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhulanbararee, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the

Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 43 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhulanbararee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhulanbararee, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. Prasad, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 6th December, 1982

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012/144/81-D.III(A) dated the 28th July, 1981 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the demand of the workmen of Bhulanbarree Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited at and Post Office Bhulanbarree, District Dhanbad, that Shri Rama Shankar Singh should be designated as a Munshi and paid in the scale of pay attached to that post is justified? If so, to what relief is the workman entitled?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement dated 2-12-1982 has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer
[No. L-20012/144/81-D.III(A)]

Ref. No. GM-PER/XI/81/5643-45

Date 16-10-1981

MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58 OF INDUSTRIAL DISPUTE CENTRAL RULES, 1957
Representing the Management : Representing the Union:
Shri P.K. Roy, Dy. Personnel Manager
Shri SRK Rao, Personnel Officer.

Shri Ram Janam Singh, Branch Secretary, R.C.M.S. Bhulanbarree Branch.
Shri Rama Shankar Singh, OBR Bhulanbarree Colliery.

SHORT RECITAL OF THE CASE

An industrial dispute was raised before A.L.C. (C) Dhanbad in respect of Sri Rama Singh claiming the wages and category of Munshi. The dispute ended in failure and the Ministry of Labour referred the matter for adjudication under the following terms :—

"Whether the demand of the workmen of Bhulanbarree Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited at the Post Office Bhulanbarree, District Dhanbad that Shri Rama Shankar Singh should be designated as a Munshi and paid in the scale of pay attached to that post is justified? If so, to what relief is the workman entitled?"

The matter was referred to H.Q. and it was decided to settle the dispute between the parties on the following terms and conditions :—

1. That Sri Rama Shankar Singh, OBR was working as Munshi and he should be designated as Munshi as per Wage Board and be paid in Clerical Grade III with immediate effect.

2. That it was agreed between the parties that Sri Rama Shankar Singh shall not claim the wages of Munshi prior to the date of the settlement.

3. It was agreed between the parties that since the dispute has been referred to the Industrial Tribunal for a decision, the parties will file a joint compromise petition before the Hon'ble Tribunal when the case is fixed for submission of written comments etc.

4. That the issues involved finally between the parties.

| Management side Signature | Union Side Signature |
|---|--|
| Sd/- | Sd/- |
| 1. (P.K. Roy) Dy. Personnel Manager. | 1. (Ram Janam Singh) Branch Secretary, R.C.M.S., Bhulanbarree Colliery |
| Sd/- | Sd/- |
| 2. (S.R.K. Rao) Personnel Officer. | 2. (Rama Shankar Singh) OBR, Bhulanbarree Colliery. Part of the Award |

S.O. 55.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron & Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(i)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 17 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron & Steel Company Limited, P. O. Bhaga, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen.—Shri S. Bose, Secretary Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 4th December, 1982

AWARD

By Order No. L-20012(277)/80-D. III(A) dated the 14th April, 1981, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Dis-

putes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act), referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of S/Shri S. H. Rahman, Ajit Mishra, Birendra Singh, Sovnath Yadav, Shama Tabroj, Jafar Khan, Shrinnath, K. K. Gupta, Shyamlal, Haripadu Tewari, Sarbjit Yadav, Akhtar Khan, Lukman Passi, Sabadeo Mishra, Raghupati, Hari Ram Yadav, Sachida Nand, Chandrika Singh, Ramesh and Hanu Bhuria, Heavy Tyndals of Noonodih-Jitpur Colliery, of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad, for payment of Category-IV wages from June, 1977 is justified? If so, to what relief are the said workmen entitled?"

2. The General Secretary of the Rashtriya Mazdoor Sangh, which has sponsored the cause of the concerned workmen, has filed written statement and rejoinder on behalf of the concerned workmen, and, similarly, the Area Manager of Noonodih-Jitpur Colliery has filed written statement and rejoinder on behalf of the management.

3. The case of the concerned workmen is that they, along-with several others, are permanent employees of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Company Limited, P. O. Bhaga, District Dhanbad since 1971 on the same or similar job equivalent to the job of Heavy Tyndals both on the surface as well as in the underground mines according to orders of the controlling authorities at the colliery level and, in accordance with the job performed by them regularly over the years they are entitled to receive Cat. IV rates of wages, whereas they are being paid different rate of wages of Cat. II or Cat. III, and thus they are being discriminated against by the management. They represented their case before the management for paying them Cat. IV rate of wages when a group of their co-workers were paid Cat. IV rate of wages with effect from June 1977 but the concerned workmen were left out. ~~Even though~~ It is indeed to receive justice from the hands of the management, the case of the workmen represented their case before Assistant Commissioner (Central), Dhanbad. But the entire proceedings ended in failure and this led to the non-referrence by the Central Government. On these grounds the workmen claim Cat. IV rate of wages with effect from June, 1977.

4. On the other hand, the case of the management is that the job description of "Tyndals" at Sl. No. 5 of Cat. IV (Skilled Junior) at page 46 of Appendix V of Vol-II of the Central Wage Board recommendations for the Coal Mining Industry, accepted by the Central Government with effect from 15-8-1967, vide Notification No. WB-16(5)/666 dated 21-7-1967 of the Government of India, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Deptt. of Labour & Employment), is as follows :

"Men generally employed in moving engineering stores, drums of oil and greases. Also responsible for erection, dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery."

According to the management, the concerned workmen do not move engineering stores, drums of oil or greases and they are also not called upon for erection, dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery. In fact, in Jitpur colliery there are 76 Tyndals in the engineering side and 32 Tyndals in the mining side which are much more than the number required in carrying on the work. So far as the concerned workmen are concerned they were deployed, if and when so required, in miscellaneous jobs. None of them has either the capacity or capability of doing job of Tyndal. At times their services are required in lowering timber/arches/girders etc. in underground. Timber lowering has always been done. Lowering of arches/girders is due to new technology. Such type of jobs which are all comparatively new developments are not covered by the job description in the Coal Awards or in the Wage Board recommendations. This is why the matter was referred to the Standardisation Committee of Joint Bipartite Committee for the Coal Industry (hereinafter referred to as IBCCI) which has been specially constituted to review and examine the reports of the different sub committees constituted by the IBCCI on new jobs and giving appropriate categories and preparation of job descriptions for underground mines and

also for miscellaneous sections such as workshop, excavation etc. as per clause 12-5-2 of the National Coal Wage Agreement (II) (hereinafter referred to as NCWA-II). So far as the IBCCI is concerned it has already standardised a number of jobs and also provided job descriptions. The type of job involved in the instant case has not so far been finalised but the management has already made a reference in this regard and the Standardisation Committee is already seized of the matter and decision is awaited soon. So far as NCWA-II is concerned it is a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act in as much as copies of the agreement, which is bipartite one, between several companies including M/s. Indian Iron and Steel Company Limited, representing the management, and several trade unions, including INTUC, to which the sponsoring union, the Rashtriya Mazdoor Sangh is affiliated, representing the workers, were duly forwarded to the appropriate authorities under Rule 58(4) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the Rules). Since the settlement is still subsisting and has not been terminated, no industrial dispute can be raised during the pendency of the settlement. This was pointed out to the conciliation officer, but he lost sight of the matter, and, without jurisdiction, proceeded with the conciliation proceedings and submitted a failure report to the Govt. of India recommending a reference to an Industrial Tribunal. The employers as also the workmen are bound by the decision of the Standardisation Committee as approved by the IBCCI and, therefore, in case this Tribunal proceeds with the reference and gives any findings, there may be a conflict of decision which is not warranted, apart from the fact that the employers as also the workmen have already selected their forum, and, therefore, the present reference is bad and not maintainable before the Tribunal.

5. Parties have led both oral and documentary evidence in support of their respective cases.

6. At the time of hearing there did not appear to be any difference or dispute between the parties regarding the type of work that the concerned workmen have been doing in Noonodih-Jitpur colliery. S. H. Rahman (WW-1), who is the only witness examined on behalf of the concerned workmen, has stated in his examination-in-chief that he was working in Noonodih-Jitpur colliery since 1974 and since June 1977 he was doing the work of un-loading rails from truck on which they are brought from Chasnala colliery and he carries them to the workshop of Noonodih-Jitpur colliery and other concerned workmen are also doing these jobs since 1977. He has further deposed that thereafter he and other concerned workmen get those rails cut to various sizes by the machine men of the workshop, and thereafter they carry those rail pieces of different sizes to the pit top of the colliery and thereafter some of the concerned workmen go down the mines with those rails in a case and inside the mine those rails are again un-loaded by some of the concerned workmen and taken to a place of storage, and similarly heavy gutters are also handled by the concerned workmen. He has further deposed that he and other concerned workmen also un-load arches which are brought from Chasnala colliery and take them inside the mine in the same manner and they also carry props, ventilation pipes and wooden sleepers inside the mines on case which are operated by electric lifts, and they also carry damaged and defective arches and pipes from inside the mine to the ground surface with the help of cages, and these are all the works which he and other concerned workmen do. His aforesaid evidence in the examination-in-chief regarding the types of work that he and other concerned workmen have been doing in Noonodih-Jitpur colliery has not been challenged by the management in his cross-examination, and, on behalf of the management, it has only been suggested in his cross-examination that the type of work about which he had deposed in his examination-in-chief are all work required to be done by general un-skilled mazdoors, which he has, of course, denied. A. K. Chatterjee (MW-1), who is an Asstt. Supdt. in Jitpur colliery, has also stated in his very examination-in-chief that the concerned workmen do the work of lowering timbers, cogging, sleepers, arches, girders and rails inside the mine from the surface level. In his cross-examination he has also admitted that heavy material such as arches, joist, rails etc. are brought from Chasnala colliery to Jitpur colliery by truck and the concerned workmen un-load those materials from truck and take them to the workshop for cutting the

rails to different required sizes and thereafter those materials are carried by the concerned workmen to the pit top and then they lower them down underground with the help of cages and they also un-load these materials from the cages and store them at the pit bottom and they also carry arches from the pit head to the underground in cages and un-load them at the pit bottom. His evidence in his examination-in-chief that the concerned workmen do not carry drums of oil or greases nor they are employed in erection or dismantling of structures or installation or withdrawal of machinery, has not been challenged on behalf of the workmen in his cross-examination.

7 From the aforesaid evidence adduced by the parties it would, thus, appear, as has already been stated above, that there is no dispute between the parties regarding the types of work that the concerned workmen have been doing at Noonodih-Jitpur colliery.

8 It is, however, the case of the management that the types of work which the concerned workmen are admittedly doing do not conform to the job description of Tyndals mentioned under item No 5 of Cat IV at page 46 of Appendix-V of Vol II of the Central Wage Board recommendations which has already been quoted above. The case of the management on this point is that since according to their own case and evidence the concerned workmen are not employed in moving drums of oil and greases nor are they responsible for erection, dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery, they cannot come under that category of Tyndals and their work being that of general unskilled mazdoors they have been put in Cat II or III as the case may be according to the nature of work that they are doing.

9 On the other hand it has been contended by Mr Bose appearing for the workmen that prior to the recommendations of the Central Coal Wage Board there was Mazumdar Award as confirmed by the Labour Appellate Tribunal and modified by Das Gupta Award according to which the job description of "Tyndal (Light)" for colliery under Item No 90 at page 77 of Appendix XI of Vol-II of the Mazumdar Award was "Men generally employed in moving engineering stores, drums of oil and greases etc", the job description of "Tyndal (Heavy)" as given in Item No 98 at page 78 was "A workman employed in moving heavy objects or in engineering erection work under the direction of Tyndal Supervisors or Jamadars", the job description of Tyndals (Heavy) for workshop under Item No W 29 at page 85 was "See job description for Colliery Tyndals. These men handle machinery at the workshop and also work at collieries from time to time, particularly in erection and dismantling work," and the job description of "Tyndal (Ordinary)" under Item No W 30 at the same page was "These men do general tyndals" work but are not usually employed on erection work requiring skill. They are mainly employed on the moving of stores etc and the loading and unloading of lorries', and under Appendix XII at page 88 Tyndals (Light) were placed under Cat IV and Tyndals (Heavy) were placed under Cat VI, but all types of tyndals whether in Cat IV or in Cat VI of the Mazumdar Award were put under one Cat IV under the Coal Wage Board recommendations when 10 categories of Mazumdar Award were compressed into 6 categories, and hence the concerned workmen who are atleast doing some of the jobs of Tyndals mentioned in the Mazumdar Award or jobs similar to that should be placed under Cat IV of the Wage Board recommendations as Tyndals.

10 The main contention raised by Mr T P Choudhury appearing for the management, however, was that since the work done by the concerned workmen do not in term conform to the job description of Tyndals mentioned under Item No 5 of Cat IV of Wage Board recommendations and since the use of girders and arches, which also the concerned workmen lower inside the mine, are new technics which have come into use round about the year 1972 or 1973 and consequently no reference about them are to be found in the job descriptions given either in the Mazumdar Award of the year 1956 or in the Wage Board recommendations of the year 1967 a reference was made by the management in the year 1980 by its letter dated 23.9.80 (Ext M-4) to JBCCI as per clause 12.7.2 of NCWA(II) to which agreement the management as well as the INTUC to which the concerned workmen's Union, the Rashtriya Colliery Maz-

door Sangh, is affiliated, are parties, and since that reference is still pending for consideration by the Standardisation Committee of JBCCI, the present reference by the Central Government to this Tribunal is incompetent as the said NCWA(II) is a settlement within the meaning of Sec 2(p) of the Industrial Disputes Act inasmuch as copies of the agreement which is a Bi-partite one was duly forwarded to the appropriate authorities under Rule 58(4) of the Rules by Memo No CSC/JBCCI/458 dated 13.8.1979 (Ext M-3) under the signature of Sri R S Murty (MW-2) who was formerly Director (Personnel) Central Coalfields Ltd and was a Member-Secretary of JBCCI, and who has proved the said Memo.

11 Mr Bose appearing for the union has, however, challenged the NCWA(II) being a settlement within the meaning of Sec 2(p) of the I D Act on the sole ground that the aforesaid forwarding memo (Ext, M-3) was signed only by the Member-Secretary, Sri R S Murty (MW 2) and it was not jointly signed by all the members of JBCCI although the requirement of Rule 58(4) of the Rules is that the parties to the settlement shall jointly send the copies thereof to the different authorities concerned. This was the only objection raised by Mr Bose to the aforesaid argument of Mr T P Choudhury.

12 It may, however, be mentioned that NCWA(II) is itself jointly signed by all the members of JBCCI and the aforesaid objection of Mr Bose is only regarding the aforesaid forwarding Memo No CSC/JBCCI/458 dated 13.8.79 (Ext M 3) under which copies of NCWA(II) were forwarded to the authorities concerned and which is also signed by Sri R S Murty, Member Secretary, but, which according to Mr Bose, should also have been signed by all the members of JBCCI. I may, however, mention here that the requirement of Rule 58(4) of Rules is only that the settlement arrived at between the employer and his workmen otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be sent by the parties to the settlement jointly to the different authorities concerned and not that its forwarding memo shall be jointly sent by them. In the present case the forwarding memo (Ext M-3) was signed by Sri R S Murty Member-Secretary of JBCCI, obviously on behalf of all the members constituting the Committee, and, consequently it could not but be said that it was sent jointly by them, and hence there was compliance of the aforesaid Rule 58(4) of the Rules and it was not necessary that the forwarding memo should also be signed by all the members constituting the committee when those members had already signed the NCWA(II).

13 Moreover, in a Division Bench decision of the Orissa High Court in the case of Kalinga Jute Products (Pvt.) Ltd. Vs Presiding Officer, Industrial Tribunal and others [1980 (I) LII 239], it has been held that the requirement of the rule that copies of the settlement shall be jointly sent is a requirement in excess of Sec 2(p) of the Act and it cannot be held, therefore, to be mandatory. In that decision a reference has also been made to Sec 18(1) of the Act which provides that a settlement arrived at by agreement between the employer and the workmen otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be binding on the parties to the settlement and also to Sec 19(1) of the Act which provides that such settlement shall come into operation on such date as is agreed upon by the parties to the dispute and if no date is agreed upon, on the date on which the memorandum of settlement is signed by the parties to the dispute and reading both these provisions together it has been further held in that decision that it is not the intention of law that the said operation is to be kept in abeyance until after a copy has been jointly sent, and viewed from this angle also requirement of joint sending is not mandatory so as to affect the validity of the settlement or its coming into operation. The rule of joint sending has therefore been held to be only directory, and not mandatory which should not be allowed to invalidate a settlement. In support of the aforesaid view a Supreme Court decision in the case of State of Madras Vs C P Saithy and another [(1953) (I) LII 174] has also been cited.

14 In view of my aforesaid finding that the sending of copies of NCWA(II) to the parties concerned under Memo No CSC/JBCCI/458 dated 13.8.79 by Sri R S Murty (MW-2) Member-Secretary of JBCCI, was joint sending by the members of JBCCI and there was full compliance of

the provisions of Rule 58(4) of the Rules, the aforesaid decision of the Orissa High Court need not in the present case be plesed into service to hold that NCWA(II) is a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act. But even without my aforesaid finding, NCWA(II) would be a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act in view of the aforesaid decision of the Orissa High Court according to which the requirement of joint sending of copies of the agreement to the authorities concerned is only directory and not mandatory and non-sending of it does not affect the validity of the settlement or its coming into operation. I, therefore, hold that in either view of the matter, NCWA(II) is a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act.

15. Clause 12.1.2 of the Agreement under Chapter XII at page 21 of NCWA(II) provides that this agreement would be in operation for a period of 4 years with effect from 1-1-79. According to the terms of the agreement, therefore it is to continue till 31-12-82. Sec. 19(2) of the Act provides that a settlement shall be binding for such period as is agreed upon by the parties, and shall continue to be binding on the parties after the expiry of the period aforesaid, until the expiry of two months from the date on which a notice in writing of an intention to terminate the settlement is given by one of the parties to the other party or parties to the settlement. Therefore the settlement under NCWA(II) will continue even after 31-12-82 and also thereafter until one or the other party gives written intimation of the intention to terminate the settlement and until expiry of two months from the date of such intention [See Shukla Manseta Industries Pvt. Ltd. Vs. Workmen, 1977 (II) LLJ. 339].

16. Clause 12.7.1 of NCWA(II) provides for a Standardisation Committee and it is agreed that with a view to examine and standardise different designations, job descriptions, disparities in service conditions among 19 different sets of employees including hours of work leaving for days, categorisation of jobs or whether there is obvious unity and also to examine such anomalies as may be brought to the notice of the Committee, a Standardisation Committee consisting of representatives of employees and representatives of the management shall be constituted. Clause 12.7.2 of the Agreement further provides that the functions of the Standardisation Committee shall, inter-alia, be to review and examine the reports of several sub-committees including the sub-committee B constituted by JBCCI on new jobs and categorisation and preparation of job description for old jobs (where they did not exist) for underground mines, and the first function of the Standardisation Committee would be to take up the unanimous recommendations of the sub-committees mentioned above with a view to co-ordinate them, resolve anomalies, if any, that may arise and recommend action for their implementation and it will thereafter examine those reports of the sub-committees where different opinions about the category to be awarded to specific jobs or any other differences of opinion have been expressed by representatives of the workers and managements, and to resolve the same. It is also the function of the Standardisation Committee to consolidate the job descriptions of different jobs available in different documents and also to examine all cases of anomalies and disparities in regard to the job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to its notice.

17. It was in pursuance to the aforesaid terms of the agreement of NCWA(II) that the management by its letter dated 23-9-80 (Ext. M-4) referred several cases to JBCCI for categorisation of new jobs which were created in different collieries after NCWA(I) including the following :—

"Material lowering gang.—This gang lowers materials like rails, girders, arches, timber etc. from surface to underground. They are mostly placed in Cat. II and they are demanding designation and category of tyndal. There is different jobs description of tyndal in wage board award."

In the aforesaid letter the management requested the JBCCI to take up the matter in the next Standardisation Committee meeting as the concerned employees were very much restive and approaching the management for their proper categorisation and raising industrial disputes and creating industrial relations problems. The Standardisation

Committee of JBCCI has not as yet given its decision on the aforesaid reference made by the management but is seized of the problem and a decision is expected. The Union of the concerned workmen which is affiliated to INTUC is bound by NCWA(II) which, as already held, is a settlement, and they having agreed that all cases of anomalies and disparities in regard to the job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to the notice of the Standardisation Committee shall be examined and resolved by the Standardisation Committee consisting of representatives of employees and representatives of the management, cannot raise any industrial dispute on that score to be decided by the Industrial Tribunal so long that settlement is in force and effect. In the case of Shukla Manseta Industries Pvt. Ltd. vs. Workmen [1977 (II) LLJ. 339], the Supreme Court has reiterated the legal position that where a settlement has been arrived at and has not been terminated in accordance with Sec. 19(2) of the Act any reference made by the Government of a dispute during the period of settlement will be invalid. The Punjab and Haryana High Court in the case of Atlas Cycle Industries Ltd. Vs. Industrial Tribunal, Haryana and others [1973 (I) LLJ. 182] has expressed a similar view that a matter covered by settlement cannot be subject matter of a reference during the currency of such settlement. The same view has been expressed by the Orissa High Court in the case of Kalinga Lite Products (Pvt.) Ltd. Vs. Presiding Officer, Industrial Tribunal and others [1980 (I) LLJ. 239].

18. Then there is another aspect of the matter. It may be argued on behalf of the workmen that NCWA (II) simply provides for constitution of a Standardisation Committee consisting of representatives of the employees and representatives of the management to examine and resolve all cases of anomalies and disparities in regard to the job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to the notice of the Standardisation Committee, but it does not per se settles the present dispute of the concerned workmen which has been referred to this Tribunal for adjudication and hence NCWA (II), even if it is held to be a settlement, does not debar this Tribunal from adjudicating the dispute in question. Though this argument was not advanced before me by Mr. Bose appearing for the workmen, I have considered it necessary to take care of that aspect of the matter also as it may be a possible argument on behalf of the workmen.

19. A similar question had been raised before the Punjab and Haryana High Court in the aforesaid case of Atlas Cycle Industries Ltd., Vs. Industrial Tribunal, Haryana and others [1973 (I) LLJ. 182]. In that case a general settlement had been made between the management and the workmen which provided that all matters in dispute arising from time to time between the management and the workmen shall be referred by either party to a settlement board consisting of five representatives of the workmen and five representatives of the management which will be presided over by an executive to be appointed by the management, and the settlement board will endeavour to take decision on the disputes referred to the board, but if unanimous decision is not possible in any case, the matter would be referred to the executive director/works director for his decision is not in case the decision of the executive works director is not acceptable to the workmen, it would be open to them to seek any remedy which may be available under any law in force. The point involved in that case was whether during the currency of such settlement the question whether the dismissal of a workman was proper or otherwise can be referred to the Industrial Tribunal at the instance of a workman without first exhausting the remedies provided under the settlement. The argument of the management was that the settlement makes it obligatory for the aggrieved workman to take advantage of the procedure and the machinery set up for amicable settlement of the dispute before resorting to legal remedies available to him under the Act. The Industrial Tribunal was, however, of the view that the power of the Government to make reference cannot be curtailed simply on the ground that the workman concerned did not take recourse to the procedure laid down in the settlement. It was urged by the Industrial Tribunal that, under sub-section (1) of Section (10) of the Act, the Government had statutory power to refer a dispute and all that is necessary is that an industrial dispute should exist or should be apprehended and, secondly, the Government should consider

to expedient to make a reference. It was, therefore, held by the Industrial Tribunal on that the validity of the reference cannot be challenged. It was against that decision of the Industrial Tribunal that the management had filed a writ petition in the High Court. In that case the main argument in the High Court advanced on behalf of the workmen was that the settlement was not a settlement qua-a-demand raising an industrial dispute and that the dispute was not covered by the settlement. The whole basis of this argument was that settlement must be with regard to an existing dispute. The argument was, however, negatived by the High Court on the ground that there can legitimately be a settlement between the parties providing for a reasonable and quick procedure saving the workmen as well as the management from unnecessary litigation which takes a very long time for the dispute to be finally settled in case the matter is referred to an Industrial Tribunal. Thus, the settlement with regard to the procedure cannot be said to be outside the purview of the "settlement" as defined in the Act on the ground that the same did not relate to an existing industrial dispute. So far as the argument advanced on behalf of the workmen that the dispute was not covered by the settlement is concerned, it was held by the High Court to have no force for the simple reason that the matter how the grievances of the workmen are to be settled in first instance, was specifically provided in the settlement. In that case the grievance of the workmen was that he was wrongly dismissed. That was certainly a matter which could be referred to a settlement board and if the workman did not find satisfaction with the decision either by the Settlement Board or the Works Director, as provided, it was open to him to proceed under the Act. For these reasons it was held that before exhausting the remedies as provided in the settlement, the workman could not approach the conciliation officer and the conciliation officer had no jurisdiction to go into the matter before the procedure laid down in the settlement had been followed, and, for the same reason the matter could not be referred to the Industrial Tribunal either. In the circumstance the writ application filed by the management was upheld and the decision of the Industrial Tribunal was quashed.

20. Relining on the aforesaid decision of the Punjab and Haryana High Court I, therefore, also negative the aforesaid possible argument referred in para 18 above which, though not advanced before me by Mr. Bose appearing for the workmen, could possibly be an argument on their behalf.

21. Finally, therefore, I hold that so long the NCWA(II), which has been held to be a settlement, is in force and effect which has provided for a Standardisation Committee consisting of representatives of employees and representatives of the management to examine and resolve all cases of anomalies and disparities in regard to job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to its notice, to which the management has already referred the dispute for decision and which is seized of the matter and the decision whereof is awaited, the present dispute cannot be referred to the Industrial Tribunal for adjudication, and hence the reference is held to be invalid. In that view of the matter I need not express any opinion on the merit of the dispute. In the circumstance of the case, however, there will be no order for cost.

Sd/-

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.
[No. I 20012(277)/80-D. III (A)]

S.O. 56.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Co. Limited Post Office Chasnala, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the
Industrial Disputes Act, 1947
Reference No 18 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Chasnala, District Dhanbad

AND
Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.
For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal

Dhanbad the 2nd December, 1982

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012(125)/80-D.III(A) dated 24-9-1980 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the demand of the workmen of Noonodih-Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Ltd, Post Office Bhaga, District Dhanbad that Sarvashri K. C. Nagpal, S. N. Tiwari and G. P. Singh should be promoted as Grade-I Clerk from the date their juniors were promoted is justified? If so, to what relief are the said workmen entitled?"

2 The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement dated 2-12-1982 has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.
(No. L-20012(125)/80-D.III(A))

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Reference No. 18 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s HISCO Ltd.,

AND
Their Workmen.

PETITION OF COMPROMISE

In the matter of adjudication above dispute both the parties have agreed to settle their differences amicably and after a number of discussions it has been agreed as follows :—

1. That the concerned workmen S/Shri K. C. Nagpal, S. N. Tiwary and G. P. Singh will be placed in clerical Grade I by the employers from the date of this compromise petition in terms of which an Award is to be given.
2. That the above named workmen shall be given notional seniority from the date the other persons namely S/Shri K. Prasad, K. P. Tiwary and others were placed in clerical Grade I i.e. from 1-4-79.
3. That the concerned workmen shall not be paid nor entitled to any back wages or arrears or any other financial benefits for the period from 1-4-79 till the date of Award.
4. That the concerned workmen shall be given fitment from 1-11-82 and annual increment in the new grade with effect from 1-3-83 as per provisions of NCWAII like those who were promoted earlier.
5. That both the parties agree that no claim/dispute and/or new interpretation will be made or given by either party in the context of above terms of the compromise petition, at any time in future.

That since the above terms of settlement forming the petition of compromise are fair and reasonable both the parties have jointly agreed and accepted the same, the compromise petition is filed before the Hon'ble Tribunal.

That both the parties, therefore, pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to record this compromise petition and give its Award in terms thereof and a copy of this compromise petition may be made a part of the Award.

For & on behalf of the Employers,
Sd/-

For & on behalf of the Workmen/
Union
Concerned Workmen.
1. K. C. Nagpal
2. S. N. Tiwari
3. G. P. Singh

Part of the Award.

ORDER

S.O. 57.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Central Hospital, Bhowra Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office, Jealgora District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 9th December 1982.

BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 3, DHANBAD

Reference No. 81/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Central Hospital, Bhowra Area of M/s. Bharat Coking Coal Ltd, P.O. Jealgora, Dist. Dhanbad

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workman—Shri S. Bose, Secretary R.C.M.S.

INDUSTRY : Coal.

STATE : Bihar.

Dated the 2nd December, 1982

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No L-20012-101/82-D.III(A) dated the 9th August, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workman of Jealgora Central Hospital, Bhowra Area of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jealgora, Dist. Dhanbad, that Shrimati Mithila Devi should be regularised on the post of Aya and paid wages as per the National Coal Wage Agreement is justified? If so, to what relief is the said worker entitled?"

2 On 29-11-1982 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.
Enc : Settlement.

Sd/-

J. N. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012/101/82-D.III(A)]

"MEMORANDUM OF SETTLEMENT"

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Representing Management | Representing Workmen |
|-------------------------|----------------------|

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Shri J.M. Gupta, Agent, Jealgora Colliery. | 1. Sri G.D. Pandey Secy. RCMS. |
| 2. Sri N.K.P. Sinha, P.M. Bhowra Area. | 2. Smt. Mithila Devi. |

SHORT RACITAL

An Industrial dispute was raised by RCMS over alleged denial of grade of Aya to Smt. Mithila Devi, PR worker of Jealgora Hospital. Smt. Mithila Devi was originally designated as wagon loader and placed in group III. Subsequently she was transferred to work at Jealdore hospital as unskilled mazdoor in Group I there she displayed as Aya since there was no job of PR unskilled mazdoor. The matter was discussed at length and mutually agreed by both the parties on the following terms of settlement:

1. Smt. Mithila Devi shall be designated as Aya and placed in grade II under Coal Mines Wage Board Recommendations. Her basic wages will be fixed under NEW Gr. II.

2. The dispute is finally decided and she shall not claim any back wages whatsoever.

3. The above agreement shall be effective from the date it is signed by both the parties.

4. A copy of agreement shall be sent to the concerned authority under Sub-Section 4 of Section 58 of Industrial Dispute Central Rules, 1957 for registration.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Representing Management | Representing Workman |
|-------------------------|----------------------|

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Sri J.M. Gupta, Agent, Jealgora Colliery | 1. Sri G. D. Pandey, Secy. RCMS. |
| 2. Sri N.K.P. Sinha, Personnel Manager, Bhowra Area. | 2. Smt. Mithila Devi. |

Witnesses:

1.
2.

New Delhi, the 17th December, 1982

S.O. 58.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bagdigi Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Londa, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 1 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bagdigi Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Londa, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 17th December, 1982

AWARD

By Order No. L-20012/160/80.D.III(A) dated the 24th December, 1980, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of the workmen of Bagdigi Colliery of Messrs, Bharat Coking Coal Limited, Post Office Londa, District Dhanbad that Shri Giyasuddin, Clerk Grade-II should be placed in Clerical Grade-I is justified ? If so, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The case of the concerned workman, Giyasuddin, is that he joined service at Bagdigi Colliery in June, 1963, and since 1973 he was placed as provident fund incharge and was being paid Clerical Grade-II wages. In 1976 and 1977 the management upgraded workman according to the nature of duties performed by each of them after taking their seniority into consideration. As section incharge of the provident fund he should have been placed in Clerical Grade-I from 1973, but the management deprived him from his legitimate claim and kept him in Clerical Grade-II. Thereupon he made representation to the management for considering his case and upgrading him from Clerical Grade-II to Grade-I, but to no effect. Thereafter the Union of the concerned workmen took up the matter with the management but when that also proved to be of no avail, the Union placed the dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad for conciliation which also ended in failure, and the Asstt. Labour Commissioner (C) submitted a failure report to the Central Government wherupon this reference has been made to this Tribunal for adjudication. On these grounds the claim of the concerned workmen is that he should be placed in Clerical Grade-I from 1973 with proper seniority and he should be paid the difference of wages.

3. The case of the management, on the other hand, is that the concerned workman joined at Bagdigi Colliery on 2-11-76 after being transferred from North Tisra Colliery where he worked from 20-7-76 to 1-11-76 as clerk and at the time of his transfer he was a provident fund clerk in

Grade-II. The Bagdigi colliery has man power strength of 2000 approximately and to deal with matters connected with provident fund, the management has engaged four provident fund clerks including the concerned workman, and the duties have been distributed amongst the four clerks. The concerned workmen does clerical works mainly connected with and incidental to forms A, M, H and W as prescribed under the Coal Mines Provident Fund Scheme. He handles the correspondence files pertaining to the provident fund matters. The other three clerks carry on duties connected with other forms, cards and returns and registers. All the four provident fund clerks have been placed in clerical Grade II according to Coal Wage Board recommendations and National Coal Wage Agreements. According to Coal Wage Board Scheme certain clerks like cashiers, store keepers, head clerks etc. are placed in Grade-II as well as in Grade-I, but rest of the clerks are placed in Grade-III and Grade-II. The maximum grade provided for a provident fund clerk is Grade-II. The head clerk (senior) is the controlling clerk of the office under whom provident fund clerks, bonus clerks, bill clerks, time keepers etc. work. When the head clerk (senior) is placed in Grade-I, it is absurd to place a provident fund clerk in the same grade. There was no post of provident fund incharge nor the concerned workman ever worked as section-incharge and there is also no rule for granting Grade-I to section-incharge. The management, however, considers the cases of all Grade-II clerks in the establishment for promotion to Grade-I to fill up the vacancies in Grade-I, and Departmental Promotion Committee has been constituted for the purpose, and the usual norms for promotion are seniority-cum-suitability. The Departmental Promotion Committee constituted in the year 1977 considered the case of the concerned workman for promotion to Grade-I along with others but did not recommend his case for promotion. On these grounds the contention of the management is that the concerned workman is not entitled to any relief.

4. It is, however, worthwhile to note that during the pendency of the present reference, the concerned workman has been, by management's Office Order No. GM:LA:PER:EST DPC-M.S.82/6513 dated 17-8-1982 (Ex. W-1), promoted from Grade-II to Grade-I with effect from 29-7-82 on the recommendation of Departmental Promotion Committee, and, therefore, the case of the concerned workman in the present reference is now confined to his claim for promotion from Grade-II to Grade-I from 1973 to 28-7-1982 on the sole ground that during that period he worked as provident fund incharge.

5. It is the admitted case of the parties that the concerned workman is working in the provident fund section of Bagdigi colliery. The case of the management, however, is that he is working there simply as provident fund clerk along with three other provident clerks and he has been rightly placed in Grade-II which is the grade provided for provident fund clerks under the heading "Clerical Staff Grading and Nomenclature" in Appendix VI at page 54 of Vol-II of the Coal Wage Board recommendations which has been approved by the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Dept. of Labour & Employment) by Resolution No. WB-16(S)/666 dated 21-7-1967 with effect from 15-8-1967 and that there is no post of provident fund incharge in the said colliery nor the concerned workman ever worked as provident fund incharge nor any post of provident fund incharge has been placed in Grade-I in the aforesaid Appendix VI. On the other hand, it is the case of the concerned workman that he was placed as provident fund incharge since 1973 and hence he should be placed in clerical Grade-I from 1973. The concerned workman Giyasuddin, who has examined himself as WW-1, has stated in his very examination-in-chief that once a written order was given by the management allotting duties to different clerks of the provident fund section including himself in the year 1977. In his cross-examination he has further stated that in the office order which was issued in the year 1977 it was mentioned that his duty will be to supervise the work of other clerks of the provident fund section but it was not mentioned therein that he would be incharge of the section and that office order might be in the file in his office and he might be able to show it to this Tribunal later on; but no such office order has ever been shown or filed. In his cross-examination he has further admitted that there is no order of the company appointing him as incharge of provident fund section nor any circular has been issued by the management to the effect that in every section there would be a section incharge who would be placed in Grade-I. At the end of his cross-examination he has again stated that the management never declared him in writing as section incharge of provident

fund section, but he has added that the management took from him the supervision work of the section which pertains to the duties of a section-incharge. No paper has, however, been filed to show that he did any supervisory duty in that section. In fact, his statement in his cross-examination is that he has been regularly filling up forms A, M, H and W under the Coal Mines Provident Fund Scheme and the other three clerks in the provident section similarly fill up other forms, returns and registers under Coal Mines Provident Fund Scheme. The position, therefore, is that there is neither any order of the management creating any post of provident fund incharge in the provident fund section nor there is any order appointing the concerned workman as provident fund incharge nor there is any evidence to show that the concerned workman supervised the work of other clerks of provident fund section, and, on the other hand, from the own evidence of the concerned workman it appears that he is working only as a clerk in the provident fund section as any other clerk in that section.

6. The only paper on which the concerned workman banks is a letter dated 9-12-1978 (Ext. W-2) written by the Superintendent, Bagdigi Colliery, to the Regional Commissioner Zone 'C', Coal Mines Provident Fund, Dhanbad, in which it has been stated "For verification of the declaration form 'A' we are sending our P.F. Sec. Incharge Md. Giyasuddin who will verify the age/date of birth of 8 workers said in previous letter and one Sri Hiraram Mahato a/c. No. C/222432." According to the concerned workman, Giyasuddin (WW-1), he was sent with this letter by the Superintendent, Bagdigi Colliery, to the office of the Regional Commissioner Zone 'C', Coal Mines Provident Fund, Dhanbad, for verification of declaration Form A which he did. He relies on that part of the letter in which he has been described as "P.F. Sec. Incharge". In that letter he might have been described as provident fund section incharge as, according to his own evidence, he was incharge of filling up Form A which was required to be verified in the office of the Regional Commissioner Zone 'C', and, in any case, simply because in the said letter he was described as provident fund section incharge he cannot become provident fund section incharge when there was neither any such post nor there was any order of the management appointing him as provident fund section incharge.

7. It is also worthwhile to mention that in the aforesaid "Clerical Staff Grading and Nomenclature" in Appendix VI at page 54 of Vol-II of Coal Wage Board recommendations there is no post of provident fund section incharge in Grade-I in which only some senior posts appear.

8. On the evidence on record, as discussed above, I, therefore hold that the concerned workman, Giyasuddin, never worked as section incharge of provident fund section nor he ever supervised the work of that section and in no view of the matter he is entitled to be placed in Grade-I from 1973 to 28-7-82 and to be paid difference of any back wages for that period i.e. prior to his getting the promotion from Grade-II to Grade-I in due course with effect from 29-7-82 on the recommendations of the Departmental Promotion Committee under management's letter dated 17-8-82 (Ext. W-1). The award is made accordingly. In the circumstance of the case there will be no order as to cost.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer

[No. L-20012/160/80-D.III(A)]

S.O. 59.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Badjna Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Nirshachatti, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 30/81

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Badjna Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Nirshachatti, Dist. Dhanbad

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers—None.

For the Workman—None

INDUSTRY : Coal.

STATE : Bihar

Dated, the 3rd December, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(64)/81-D.III(A) dated the 23rd June, 1981.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Badjna Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Mirshachatti, Dist. Dhanbad in not placing Shri Chandradeo Mishra in Clerical Grade-I as Loading Supervisor of Incharge with effect from the 1st May, 1973 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The present reference was registered by this Tribunal on 1-7-1981 and notices were issued to the parties. After several notices Sri T. P. Chowdhury Advocate for the management and Sri Bose, Advocate for the union appeared and on all most all the dates fixed in the case they took time on the ground that the matter is to be settled outside Court and that settlement will be filed shortly. For filing settlement or for filing written statements several adjournments were granted by the Court, but to no effect. On the last date it was submitted by the Advocate for the management that one chance more may be given to the parties either to file settlement or to file written statements. But inspite of the last chance also neither written statement or settlement has been filed in this case.

3. From the order-sheet it appears that the parties are not taking any interest in the Reference and it appears that there is no dispute between the parties.

4. In the circumstances a 'no dispute' award is passed.

J. N. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20012/64/81-D.III(A)]

S.O. 60.—In pursuance of section 17 of the industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Govindpur Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 24 of 1980

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the
I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Govindpur
Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited,
Post Office Sonardih, District Dhanbad and their
workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary,
Rastriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 30th November, 1982

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012(75)/80-D.III(A) dated 25th September, 1980 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

THE SCHEDULL

"Whether the demand of the workmen of Govindpur Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih District Dhanbad that Shri Shamsul Khan should be allowed to resume duty and regularised as car cleaner, with full wages for the period of his idleness is justified. If so, to what reliefs the said workman entitled."

2. The case of the concerned workman is, that he was employed as car cleaner, Area No. III from December, 1973 and worked continuously upto 13-9-75 when he was stopped from duty. The stoppage is said to have been done by the management without any reason and without issuing any notice. The workman was paid on voucher and in ordinary course his service should have been regularised with the passage of time, but since he approached the management to regularise him in the job, he was stopped from work. This action of the management is said to be illegal, arbitrary and an unfair labour practice. His further case is that he approached the local officers of the management who were pleased to forward his case to the Headquarter (Personnel) for absorption of the workman in the employment of M/s Bharat Coking Coal Limited. Thereafter the workman and his union made several efforts to settle the matter and ultimately when the management did not do anything the union raised an industrial dispute resulting into this reference for adjudication.

3. The plea taken by the management is that Shri Shamsul Khan was never a workmen and he was never a car cleaner. The relationship of employer and employee is denied. A point was raised that the area office of BCCL is not a mine and the concerned workman could not be said to be an employee of the mine so as to confer the jurisdiction of the Central Government to make this reference. The management wanted to decide the question of jurisdiction as preliminary point and after a hot contest it has been held by this Tribunal in a separate order dated 5-5-82 that the reference is maintainable. Ordinarily therefore the only question to be decided in this reference is as to whether the concerned workman Shri Shamsul Khan should be allowed to resume duty and regularised as car cleaner with full wages for the period of his idleness. On behalf of the management, however an argument has been advanced by Shri G. Prasad, Advocate that since in the evidence the concerned workman stated to be a car cleaner in Area No. I and the schedule of the reference says that he is a workman of Area No. III, this Tribunal cannot enlarge the scope of this reference to consider the case of the concerned workman. So the reference should be rejected on this ground alone. We have therefore to answer this reference in the light of the two points indicated above

4. I would like to first deal with the case of the management that the concerned workman could not get any relief because according to the workman he worked in Area No. I and the relief is sought against Area No. III. In the written statement of the workman the workman is said to be a car cleaner in Area No. III, Shri Shamsul Khan, WW. 1 in his evidence has said he was a khalasi doing the job of car cleaner in the office of the General Manager of the Area No. I at Sijua. He was doing this work from December, 1973 to September, 1975. His evidence further is that in 1974 he demanded to be made permanent and the Area Personnel Manager of that area prepared papers and sent the same to the headquarters for making his service permanent. He has said that in the meanwhile there was reorganisation of the areas and his area was shifted to Govindpur Area No. III. He has said that at the time of transfer of the area the management had stopped him from work. In his cross-examination he has said that Govindpur Area No. III is at a distance of 10 Kms. from Sijua and that he never worked in Govindpur Area No. III. From the evidence of WW. 1 it is clear that the concerned workman was working as a car cleaner and he was employed in Area No. I. On reorganisation the area where he was working was shifted to Area No. III, as a result of reorganisation. At the time of reorganisation he was stopped from work and so he did not work in Area No. III. An inference can be taken that had he continued to be in service his place of working would have been Govindpur Area No. III in normal course. Shri S. Bose, Advocate representing the workman has therefore argued that since the concerned workman would be still deemed to be in continuous service inspite of the action of the management in stopping him from work, the dispute could be raised only against Area No. III, and not area No. I. He has further argued that the plea of the management is absurd in view of the fact that had the schedule of the reference mentioned that the concerned workman was a workman in Area No. I, the management would have taken a plea that since the area where the concerned workman worked is now designated as Govindpur Area No. III the reference should be rejected on this score alone. In this connection the evidence of WW. 2 may be enforced who had said that till 1975 he was employed in Area No. I, Sijua as driver. This shows that sometime in the year 1975 there was reorganisation of areas and the then area No. I was reallocated to Govindpur Area No. III. Now this is a question of fact, and except for the evidence that I have quoted above, the management has not clarified the position with any evidence whatsoever, either oral or documentary. So we have only the evidence of WW. 1 who speaks about reorganisation and explains that Area No. I which was situated at Sijua has been shifted to Govindpur Area No. III, where he would be deemed to have continued inspite of his stoppage of work. This point therefore is concluded by a finding of fact that the concerned workman could seek relief only against Govindpur Area No. III and that the dispute was rightly raised against Area No. III. Shri Bose has further argued that since the management has no case whatsoever on merits of the case the management is simply showing technical objection to the case of the concerned workman to see that he could not succeed in his case. According to him the areas have been created by the owner M/s. Bharat Coking Coal Ltd. for the sake of administrative convenience and the areas therefore could not be regarded as separate establishments. On this ground alone Shri Bose has said that the objection taken by the management is not sustainable. I agree that since the areas have been reorganised from time to time by the headquarters of the BCCL, it could not be said that the establishments of the areas are separate establishments. In fact the establishments of the areas are part and parcel of the BCCL.

5. Having dispensed with the technical objection raised on behalf of the management, let us now consider the merits of the case as put forth by the management. The management has produced monthly and pay book register of Area No. I Sijua from June, 1974 to September, 1975. Nobody has come to prove this document. No positive entry in this book has been sought to be proved. In fact this register is a monthly attendance register and although in the heading of this register pay book is also mentioned, there is no entry to denote payment to the workers mentioned in the attendance register. It has been filed to show that the names of the concerned workman does not find place in this register. This register will show that it includes attendance of officers also and begins with Mr. R. J. Sinha General Manager in the Area No. I. This also includes the names of drivers, mafis and others. The name of WW. 2 the driver appears in this book.

Shri S. Bose has contended that this register mentions the names of only those workers and officers who are on the permanent roll of Area No. 1. According to him the concerned workman was employed on temporary basis and payment to him was made through vouchers. So there was ample reason for the management not to include his name in this register. Apart from this register no evidence has been adduced on behalf of the management. Shri G. Prasad Advocate has argued that since the concerned workman was never a workman of Area No. 1 or of BCCL, he could not produce any paper to prove this fact that he was never a workman. Shri Bose has pointed out that he filed a petition dated 18-11-81 calling for quite a number of documents from the management. Through the petition dated 18-11-81 the following documents were demanded :

- (a) Letter No. DYM/AR-30-III/183/11602 dated 14/19-7-76 from DPM Area No. III to Shri S. D. Pandey, DPM (IR) Karmik Bhawan with details of engagement of Shri Shamsul Khan, car cleaner.
- (b) Payment vouchers from December, 1973 to September, 1975 for payments made to Shri Shamsul Khan.
- (c) Petition dated 16-2-78 from Shri Shamsul Khan to the various authorities including :
 - (1) Chairman/Managing Director of BCCL.
 - (2) Director (Personnel) of BCCL.
 - (3) Director (T&P) of BCCL.
 - (4) Chief Personnel Manager, BCCL.

In this petition the workman made it clear that the aforesaid documents were necessary to prove his case. This Tribunal asked the management to produce those documents. The management replied by filing a petition dated 23-12-81 in which the management took the following pleas showing inability to produce the same.

1. The workman had not shown the relevancy of the document called for without affidavit.
2. The documents were not in the custody of the employer of Area No. III.
3. Under the Mines Act and Mines Rules the registers are not required to be maintained for more than a year.

6. It will appear that in the petition dated 18-11-81 item (a) is said to be a letter giving details of the engagement of Shri Shamsul Khan as car cleaner. The payment vouchers are relevant as shown by item (b) for the reason that the workman's case is that he was paid through vouchers. The management reply is that these documents could not be available in Area No. III and if available they were liable to be destroyed in course of a year. The management never says that these documents were already destroyed. At least item No. (a) is in Area No. III and is a letter in a particular file. It is not the case of the management that the whole file has been destroyed. Item No. (c) of the petition dated 18-11-81 is a petition dated 16-2-78. Copies of the petition dated 16-2-78 had been sent to various authorities, but none of them has been produced. This letter could have shown that the workman demanded from the management to be put on the job he was doing in the BCCL. There does not appear to be any reason why the management should not have produced this document called for. Shri Bose has pointed out in the course of his argument that the attempt of the management is to put hurdle in the way of the concerned workman to show that he was a workman of the BCCL as car cleaner. Shri Bose has further argued that since all the documents concerning his employment in BCCL as car cleaner could be with the BCCL the workman could not be expected to produce them in order to prove his case. The workman has done his best by calling for the documents from the custody of the management giving the fullest particulars possible to trace them out. But all that the management did was to show inability to produce them on one pretext or another which could not be sustainable in a court of law. It appears to be no doubt true a serious attempt is being made by the employer in this case to obstruct the workman in proving his case through legal methods. We have therefore no option but to

fall back upon whatever the evidence has been adduced in this case. The workman has examined himself as WW. 1 and says that he worked as car cleaner from December, 1973 to September 1975. He used to attend 7 vehicles being cars and jeeps and all these vehicles belonged to BCCL. He has said that he used to be paid through vouchers and he received Rs. 150 per month. He has been supported by Shri Nakul Mahato, WW. 2 who had been in the employment in BCCL since 1971, as a car driver. Till 1975 he was employed in Area No. 1, Sijua. He has said that there were 5 vehicles belonging to BCCL in Area No. 1. He has identified Shri Shamsul Khan the concerned workman in this court as a workman employed as car cleaner for 3 years during his time. The learned Advocate for the management has said that while WW. 1 has said that there were only 5 vehicles, WW. 2 has said that there were 7 vehicles in Area No. 1. He has also pointed out that the concerned workman in his evidence has said that his service was continuous, while WW. 2 says that the concerned workman worked for 3 years with certain gaps. The learned Advocate for the management has said that they were vital contradiction and for this reason the evidence of W.W. 1 and W.W. 2 should be rejected. I must say that these contradictions cannot be said to be vital for the simple reason that after a lapse of time there bound to be such discrepancies when witnesses depose from their memory. The vital question is as to whether the concerned workman was a car cleaner for a period of 3 years in Area No. 1, Sijua. On this point both WW. 1 and WW. 2 are consistent. Their evidence has not been rebutted by any counter evidence on behalf of the management. I have therefore to hold that the concerned workman Shri Shamsul Khan worked as car cleaner from December, 1973 to September, 1975 and was paid at the rate of Rs. 150 per month through vouchers. I have also to hold that after September, 1975 the management of BCCL stopped him from work. The evidence of WW. 1 is that in 1974 he had approached the Area Officers for making him permanent and the APM of the Area office had recommended his case to the headquarters office for making him permanent. In the meantime reorganisation of the Areas came and the area of the concerned workman was shifted to Govindpur Area No. III. It was at that time that he was made to sit idle without assigning any reason. Shri Bose has said that this is an unfair labour practice inasmuch as the concerned workman after serving for a period of 3 years should not have been stopped from work in such an arbitrary manner. Since we have come to a conclusion on the strength of evidence adduced in this case that the concerned workman was a car cleaner in the Area office, he should not have been stopped from work without assigning any reason or without serving him with any notice. It is objectionable on the part of the management that a car cleaner should be appointed on voucher when this job is clearly defined in the wage board recommendation. It is in category I which is the lowest paid workman in the colliery service. I wonder how a workman having worked for 3 years in his capacity as car cleaner could not be absorbed in category I on regular basis.

7. Shri G. Prasad, Advocate on behalf of the management has argued that the claim is belated because the dispute was raised in 1979 and he was stopped from work from September 1975. The simple case of the workman is that he had been approaching the various officers of the BCCL and for quite some time his union also made attempts with the management to see that he was put in employment. It cannot therefore be said to be a belated claim.

8. Having considered all aspects of the case I hold that the demand of the workmen of Govindpur Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office, Sonardih District Dhanbad that Shri Shamsul Khan should be allowed to resume duty and regularised as car cleaner with full wages for the period of his idleness is justified. Consequently, Shri Shamsul Khan, the concerned workman should be deemed to be in the service of the colliery w.e.f. 14-9-75 when he was stopped from work. He is also entitled to back wages and other emoluments w.e.f 14-9-75.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012/75/80.D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 61—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial

Tribunal, Hyderabad, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd. Bellampalli Division-I, and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th December 1982.

**BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD**

Industrial Dispute No. 8 of 1982

BETWEEN

**The Workmen of Singareni Collieries Company Limited
Bellampalli Division-I, Adilabad District. (A.P.).**

AND

**The Management of Singareni Collieries Company Limited,
Bellampalli Division-I, Adilabad District (A.P.)**

APPEARANCES :

None—for the Workmen.

Sri P. Venkateswara Rao, Senior Personnel Officer,
Bellampalli Division I—for the Management.

AWARD

The Government of India by order No. 21012 (14)/81-D.IV (B) dated 16-2-1982 referred this industrial dispute existing between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division I and their workmen for adjudication to this Industrial Tribunal:—

"Whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division I (AP) is justified in refusing to confirm Shri B. Achanna, General Mazdoor as Clerk Gr. II and to pay the difference of wages between the pay of Clerk Gr. II and the wages of Category I to Shri Achanna, General Mazdoor for the period he worked as Clerk from 4-1-75 to 30-7-78? If not to what relief is the workman entitled?"

(the name of the worker is wrongly described in the above order as R. Achanna. Hence the correct name R. Achanna is given in this award)

2. After registering the above industrial dispute in I.D. No. 8 of 1982, notices were issued to both the parties. After receipt of notices, the parties intimated to this Tribunal that the Industrial Disputes had been settled on 15-1-1982. Thereupon the parties were directed to file the settlement into the Tribunal. Several adjournments were granted to the parties for the above purposes. Ultimately the compromise petition in M.P. No. 183/82 was filed into this Tribunal on 20-10-1982 signed by the Management's representative, namely P. Venkateswara Rao, Senior Personnel Officer, Bellampalli Division I and the President, Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli, namely, S. Nagaiah Reddy for the Workmen. A memorandum of settlement arrived at between the parties on 15-1-1982 was enclosed to the above petition.

3. The following are the terms of settlement contained in the above memorandum of settlement:—

- (1) Shri R. Achanna shall also be considered for appointment as Clerk Gr. II along with other Graduate employees subject to his passing the Written Test/interview going to be held shortly for selection of Gr. II Clerks.
- (2) The Management agree to pay special allowance to Shri R. Achanna, at the rate of Rs. 60/- per month during the period from April 1976 to September, 1977.
- (3) The amount due to Shri R. Achanna, as per the item No. 2 of the said settlement, will be paid on or before 20th March, 1982.

- (4) The Union, therefore, agreed to withdraw the dispute pending before the Conciliation Machinery and Ministry of Labour, Government of India, and to treat the dispute as settled fully and finally.
- (5) Both the parties agree to submit this Memorandum of Settlement to the concerned Government Authorities as required under the Industrial Disputes Act Rules.
- (6) The parties shall send their implementation report on or before 30th March, 1982, failing which it will be treated that the settlement has been fully implemented.

4. As can be seen from the above memorandum of settlement, the present industrial dispute was settled between the Management and the workman on 15-1-1982 i.e., a month prior to the date of reference of the dispute to this Tribunal. Obviously for some reason or other, the above settlement was not brought to the notice of the Government of India, by the time the present reference was made to this Industrial Tribunal. As can be seen from the contents of the compromise petition, the terms of the settlement were also implemented by the Management. As per Paragraph 1 of the settlement, the workman, namely, R. Achanna had been considered, selected and appointed as Clerk, Gr. II by the Management. As per paragraphs 2 and 3 of the settlement, the Management had already paid the special allowance of Rs. 60.00 per month for the period from April, 1976 to September, 1977 before 20th March, 1982.

5. In view of the above facts, the compromise is recorded by me today. Therefore this award is passed in terms of the above settlement. Copies of the compromise petition and memorandum of settlement shall be appended to this award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 11th day of November, 1982.

Sd/-
Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

—NIL—

Sd/-
(Illegible)

Presiding Officer.

[No. L-20012/14/81-D.IV(B)]

S. S. MEHTA, Desk Officer.

**BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (C),
HYDERABAD**

I.D. No. 8 of 1982

BETWEEN

**The Management of Singareni Collieries Company Limited,
Bellampalli Division-I, Adilabad District (AP)**
...Management.

AND

**Workmen of Singareni Collieries Company Limited,
Bellampalli Division-I, Adilabad District (AP)**

..Workmen.

MEMO OF COMPROMISE

It is submitted that the parties have entered into a Memorandum of Settlement and thereby settled the dispute as follows:

1. As per para-1, of the Settlement, Shri R. Achanna, has, since been considered, selected and appointed as Clerk Gr. II.
2. As per para-2 and 3, the Management has already paid a special allowance of Rs. 60/- p.m. during the period from April, 1976 to September, 1977 before 20th March, 1982.

3. The Settlement arrived at could not be informed in time to the concerned authorities and hence, the dispute was referred for adjudication.
4. As per para-6, the implementation report on the Settlement has already been sent to the concerned authorities.
5. As per para-5, both the parties hereby submit this Memo of Settlement, in seven copies.

It is prayed that an award in terms of the Memorandum of Settlement filed herewith may please be passed.

Be pleased to consider.

Sd/-
For Management,
Sr. Personnel Officer,
Bellampalli Division I.
Sd/-
for Workmen
President.
Tandur Coal Mines Labour Union,
Bellampalli.

Memorandum of Settlement arrived at under Rule 58(4) of the I.D. Act, 1947, on 15-1-1982, at Bellampalli, between the management of the S.C. Company Limited and their workmen represented by the Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli, regarding alleged non-confirmation of Shri R. Achanna C.S.L., Boipalli No. 1 incline as Clerk Gr. II.

PARTIES PRESENT

Representing the Management :

Shri P. Krishnaji, Sr. Personnel Officer, the S.C. Company Limited, Bellampalli-504251.

Representing the Workmen :

Shri S. Nagaiah Reddy, President, TCML Union, Bellampalli-504251.

Short recital of the case

The President, T.C.M.L. Union, vide his letter No. 31(81) 49, dated 7-3-1981, raised an Industrial Disputes before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Hyderabad demanding that Shri R. Achanna, C.S.L., Boipalli No. 1 Incline should be confirmed as Clerk Gr. II and the difference of wages between Category-I and Clerk Gr. II should be paid from 21-1-1975 to 31-7-1978 stating that he worked as Clerk Grade-II during that period.

The Asstt. Labour Commissioner (Central), Hyderabad held conciliation proceedings on 30-9-1981. Since the Management and the Union could not come for an amicable settlement, over the dispute, the conciliation proceedings ended in failure. The Asstt. Labour Commissioner (C)/ Hyderabad, had submitted the failure of conciliation report to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. The Desk Officer, Government of India Ministry of Labour, New Delhi, had written a letter to the Secretary, Government of Andhra Pradesh, requesting the State Government to pursue the Management for an amicable settlement of the dispute or in the alternate to agree to the reference of the dispute for adjudication.

The Management held discussions again with the President, T.C.M.L. Union, over the entire dispute on 15-1-1982. During the discussions, it was explained that Shri R. Achanna was discharging the duties of a clerk intermittently, but not continuously for one year and three months. The Union was also informed that the Management is going to recruit some clerks shortly, and the case of Shri R. Achanna, C.S.L., Boipalli No. 1 Incline will also be considered for the post of Clerk Gr. II provided he is possessing required qualifications for the post of Clerk Gr. II and passes in the Test/Interview.

1085 GI/82—11.

After the discussions, the management and the Union have come to an agreement on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

- (1) Shri R. Achanna shall also be considered for appointment as Clerk Gr. II along with other Graduate employees subject to his passing the written Test/Interview going to be held shortly for selection of Gr. II Clerks.
- (2) The Management agree to pay special allowance to Shri R. Achanna, at the rate of Rs. 60 per month during the period from April 1976 to September 1977.
- (3) The amount due to Shri R. Achanna, as per the item No. 2 of the said settlement, will be paid on or before 20th March, 1982.
- (4) The Union, therefore, agreed to withdraw the dispute pending before the Conciliation Machinery and Ministry of Labour, Government of India, and to treat the dispute as settled fully and finally.
- (5) Both the parties agreed to submit this Memorandum of Settlement to the concerned Government Authorities as required under the Industrial Disputes Act Rules.
- (6) The parties shall send their implementation report on or before 30th March, 1982, failing which it will be treated that the settlement has been fully implemented.

SIGNATURES

Representing the Management : Representing the Workman :

Sd/-
(P. Krishnaji) Sd/-
(S. Nagaiah Reddy)

Witnesses :

Sd/-
(B.R.S. Naidu)
D.P.O., SC Co. Ltd., BPA
Sd/-
(T. P Muller George),
Head Clerk, Personnel Dept., BPA.

नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 1982

करो आ० 62--विस्थापित व्यवित (प्रतिकार तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा नमिनाडु सरकार के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (पुनर्वास) तथा उपसचिव (पुनर्वास) को, जैसा भी भासला हो, उसके अपने कर्तव्य-भार के अनिवार्य, नमिनाडु राज्य में मुश्किलों की भूमि तथा सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये, बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करते हैं।

[संख्या-1(19)/विषेष सेत्र/82-एज़०एत 2(क)]
महेन्द्र कुमार कंतल, अवृत्त सचिव

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 62.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Joint Secretary (Rehabilitation) and Deputy Sec-

rectary (Rehabilitation) as the case may be, in the Revenue Department, Government of Tamilnadu, as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the Compensation Post within the State of Tamil Nadu.

[No. 1(19)Spl.Cell/82-SS.II(A)]

M. K. KANSAL, Under Secy.

S.O. 63.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL: CALCUTTA

Reference No. 31 of 1979

PARTIES:

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers

Mr. D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen

Mr. Kamal Kumar Banerjee, Asstt. Secretary of the Union.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Port

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-32012/14/D.IV(A) dated 19th May, 1979 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in allowing Sri A. K. Mukherjee, U.D. Clerk, under the Chief Engineer to be superseded for the purpose of promotion to the post of Upper Division (Selection)? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The facts are simple. Sri A. K. Mukherjee was an U.D. clerk under the Chief Engineer of the CPT (Calcutta Port Trust). There was a vacancy in the year 1977 in the UD (Selection) post. Sri Mukherjee was superseded and instead Ajoy Kumar Guha Khasnabis who was also a U.D. clerk in the same department was promoted and appointed to the UD (Selection) post. It is admitted by both sides that the person who was senior was entitled to be appointed to that post. So the simple question is whether A. K. Khasnabis was senior to A. K. Mukherjee. I think he was.

3. Admittedly Sri Khasnabis was confirmed in the post of UD clerk in the Dock unit on 1st January 1963 but Sri Mukherjee was confirmed as UD clerk in the Calcutta unit on 23rd January 1963. Thus Khasnabis was confirmed ear-

lier. The date of seniority, in my opinion, should be determined by reference to the date of confirmation and not from the date of appointment in a particular grade or rank. It may be mentioned here that there were three units under the Port Development Wing (briefly, the PD Wing) under the Chief Engineer, (i) Calcutta unit, (ii) Dock unit and (iii) Head office unit. The PD wing was a temporary establishment. The UD (S) post was to be filled by the seniormost UD clerk from a combined list of all the three units. We are not concerned with the seniority of any UD clerk in any other particular unit. For the purpose of UD (S) post all the three units were to be considered as if one unit and the seniormost of them was to be appointed to the UD(S) post. Sri Ajoy Kumar Guha Khasnabis having been confirmed earlier must, therefore, be held to be senior. Rule 2 of the seniority rules framed by the CPT runs as under:

"When however a man is confirmed in a grade, he becomes senior to all other who have not been confirmed in that grade for purpose of promotion."

In the present case when Sri Ajoy Kumar Guha Khasnabis was confirmed, Sri Mukherjee had not been confirmed on that date and therefore Ajoy Kumar became senior to him.

4. The union argues that the seniority rules do not apply to the Chief Engineer's department. I do not agree. No separate rule has yet been framed for the department of the Chief Engineer in the CPT. The union itself in another written statement filed by them in Reference No. 11 of 1982 (Ex. M-3) in paragraph stated as follows:

"4. That all promotions of the workmen of CPT are done or governed by the seniority rules passed at the meeting of the erstwhile Commissioners for the Port of Calcutta on 8-5-57 under Resolution No. 473. In this connection copy of Secretary CPC's letter No. 7354 dated 2nd June, 1958 together with a copy of the report of the Committee set up to draw up rules for determining seniority of staff are enclosed marked with Annexure 'A' and 'A-1' and since then all promotions to the workmen of CPT were given as per said seniority rules."

On a perusal of the above it is clear that the union admitted the fact that the seniority rules in question governed all promotion of the workmen of the CPT.

5. The union next relied on Rule 1 of the said seniority rules. It runs as below:

"The seniority of a man in a grade should be determined on the basis of total length of his service in that grade or in an equivalent grade."

Suffice to say that this rule does not deal with a case of confirmation and therefore it is not applicable to the present case.

6. It is next contended on behalf of the union that Sri Mukherjee had officiated in the UD(S) post from 2-12-1953 to 1st February 1954 and this period of officiation should be counted in determining the length of service. In continuation of this submission it was further pointed out that Sri Mukherjee had been appointed as UD clerk earlier than Sri Ajoy Kumar Guha Khasnabis and from that point of view also the total length of service of Sri Mukherjee was more than that of Sri Khasnabis. In my opinion, the length of service has to be determined in a particular grade or rank in which the question of seniority arises and the period of another grade or rank cannot be taken into consideration. I am further of the opinion that in a case of confirmation the period of officiation can have no weightage and that seniority must be counted from the date of confirmation.

7. The union next submits that the existing seniority rules were amended by the erstwhile Commissioners for the Port of Calcutta (now Calcutta Port Trust) in the year 1973 by Resolution No. 1472 and by that amendment the seniority by confirmation had been ruled out. Suffice to say that these rules have not yet been approved by the Central Government and so they have absolutely no force.

8. The union next urged that according Annexure "E" (Ext. W 5) which is an observation of the Financial Advisor and Chief Accounts Officer to the effect that Sri Mukherjee was senior to Sri Ajoy Kumar, it should be held that Sri Mukherjee was senior to Ajoy Kumar. This observation was made on 26th November 1977. On this observation an endorsement was made by the Secretary to the effect that the Chief Engineer should see that observation and should send the papers to his office as early as possible. In my opinion, this observation is of no value. The FA and CAO thought that Sri Mukherjee had been appointed and confirmed as LD clerk earlier than Sri A. K. Guha Khasnabis and therefore he was senior. The observation is misconceived and exhibits ignorance of the rule as to seniority. I have already said that seniority has to be determined only by reference to the date of confirmation in the particular grade or rank in which the question arises. Here the question arise in the grade of UD clerk. Therefore nothing about the period as LD clerk can be considered. I may mention here that the Chief Engineer in his letter dated 20th September 1977 observed that Sri A. K. Guha Khasnabis was senior to Sri Mukherjee. That view in my opinion is correct.

9. The union next submitted that there was no combined list of seniority of the three units of the department of Chief Engineer. I think that this becomes a minor matter in view of the positive fact that A. K. Guha Khasnabis was confirmed earlier in the grade of UDC.

10. The Union next referred to Annexure C (Ext. W3) and Annexure D (Ext. W4) of their written statement. These two exhibits, in my opinion, are of no help to the union. Annexure C shows as to when certain clerks had been appointed in the Lower Division Clerk's post or Upper Division clerks post. This in my opinion is of no consequence in view of the discussions made above. Annexure D is in respect of the two clerks concerned, namely Sri Mukherjee and Sri Khasnabis. They have been shown as LD clerks as well as UD clerks with their dates of appointment confirmation and promotion. This also is of no importance in view of the discussions held. I have already mentioned the relevant dates for the purpose of determining the seniority. The contention thus has no force.

11. In the result, I hold that the management in relation to the CPT are justified in superseding Sri A. K. Mukherjee, UD clerk under the Chief Engineer and to promote Ajoy Kumar Guha Khasnabis in the post of Upper Division (Selection) Post in the department of the Chief Engineer. Sri A. K. Mukherjee, therefore, is not entitled to any relief.

Dated, Calcutta the 20th November, 1982.

M. P. SINH V, Presiding Officer
[No. L-32012/14/78-D-IV(A)]

New Delhi, the 17th December, 1982

S.O. 64.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA.

Reference No 45 of 1979

PARTIES .

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Sri D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Sri Asgher Ali, Vice-President of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port

AWARD

By Order No. L-32012(12)/78-D. IV(A) dated 12th July, 1979 the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the management in relation to Calcutta Port Trust are justified in imposing punishment by way of reduction of pay by two stages on Shri Mohiuddin, Loco Driver, under the Chief Mechanical Engineer on the charge of negligent and rash driving in November, 1975 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. On 20th July 1976 Mohiuddin, a Loco Driver was charged with misconduct inasmuch as he negligently and rashly drove engine No. D/51 on 3/4.11.75 and made a collision with the last wagon of the train carried by Engine No. 44 at 3 K. P. line causing damage to Loco No. D/51 and the wagon. Further, that said Shri Mohiuddin while on duty from 2206 hrs. On 3/4.11.75 failed to stop the engine D/51 at foul point, in spite of being cautioned by the Shunter Gunner on the basis of the report made by the Loco Foreman. He gave explanation on 31st July 1976 but the same was found not satisfactory. A domestic enquiry was held on 8th December 1976 by the Enquiry Officer Sri A. K. Sarkar who found him guilty of the charge. On receipt of the findings of the Enquiry Officer (Ext. M 5) the Chief Mechanical Engineer imposed the punishment as mentioned in the order of reference by his order dated 31st January 1977. His appeal therefrom was rejected by the Deputy Chairman.

3. According to the concerned workman (vide Ext. W1 dated 7 August 1976 and M3 dated 31st July 1976) he was asked to proceed to E J C by line No. 2 without any caution order, the level crossing was jammed up with vehicles in such a manner that it was not possible to know whether the line was clear, that the head-light of the engine became visible at the relevant time, that there was no stop signal and that the shunter gunner Jagu Tiwari who was with him for giving guidance did not ask him to stop. He denied the fact that he did not stop the engine in time. This could have properly be considered only when the person who were present with him in the engine would have been examined by the management. It appears that one shunter gunner and one member of the CISF were present at the time of accident. Non was examined. The management had filed several documents including the accident report and enquiry report (Ext. M 1) but these documents cannot show whether the concerned workman stopped or did not stop the engine in time or whether the headlight had become dim at the relevant time. These matters could prima facie be proved only by oral evidence of the two persons present in the engine at the time of accident. That evidence was available but the management did not bring them before the Enquiry Officer. Hence the documents are not of real assistance to the management for proving the charge against him. The whole enquiry was conducted only on one day namely 8th December 1976 simply on the basis of statement made by Mohiuddin.

4. The management contends that the departmental enquiry is valid because sufficient opportunity was given to the workman to defend himself. In my opinion that is not correct. Enquiry was held only on one day (8-12-76). Mohiuddin, the loco driver applied for adjournment to another date on the ground that his counsel was not available on that day due to his pre-engagement to some other work. No time was granted and enquiry was held in absence of the defence counsel. It may be pointed out that the management is bound to consider the representation made by the concerned

workman under the provisions of Rule 12 of the Calcutta Port Commissioners Employees' (Discipline and Appeal) Rules, 1964, briefly the 1965 Rules. The defence counsel could have placed before the enquiry officer the proper defence in an effective manner. There was, therefore, denial of reasonable and effective opportunity to the concerned workman and thus there was denial of justice too. The contention raised by the management thus has no force.

5. Mr. D. K. Mukherjee appearing for the management next contended that the holding of enquiry was not necessary for minor penalty under Rule 12 of the 1964 Rules. He pointed out that enquiry was necessary only when major penalty were imposed as contemplated in Rule 11 of 1964 Rules. Suffice to say that if the management adopts the procedure of enquiry it is not open to them to say that they are not bound by it even if the enquiry was not necessary. In the circumstances of this case the management is bound by that enquiry because it chose to adopt it. The enquiry held in this case is not based on any evidence. It is therefore perverse. If so, the order of punishment passed upon it must go.

6. Sri Ssgher Ali, appearing for the concerned workman, contended that during the departmental enquiry 10 or 11 questions were put to him and that being in the nature of cross-examining was not permissible in law. He also contended that the concerned should not have been examined prior to production of some evidence by the management. It is not necessary to go into this question because of the view expressed above.

7. In the result, my concluded award is that the management in relation to the Calcutta Port Trust were not justified in imposing punishment by way of reduction of pay by two stages on a charge of negligence and rash driving in November 1975, on Mohiuddin, the loco driver. I accordingly direct the management of the Calcutta Port Trust to pay back the amount which has been deducted to the concerned workman, namely Mohiuddin, loco driver.

Dated, Calcutta,
The 6th December, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[N. L-32012/12/78-D. IV (A)]

S.O. 63.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Salgaokar Engineers Private Limited, Vesco-da-Goa and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2/42 of 1982

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of M/s. Salgaonkar Engineers Pvt Ltd., Vasco-da-Gama, Goa.

AND
Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—No appearance

For the workmen—No appearance

INDUSTRY : Port and Docks STATE : Goa, Daman and Diu

Bombay, the 8th November, 1982

AWARD

In their letter No. L-36012(3)/82-D.IV(A) dated 1-10-1982 the Central Government have referred the following dispute

for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Messrs Salgaokar Engineers Private Limited in retrenching with effect from 9-6-1982 the 62 workmen (whose names are mentioned in the annexes) employed in transhipper "m.v. Gosalia Prospect" is justified? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

ANNEXURE

S. No. Name

1. Shri J. S. Fernandes
2. " Pralhad Manirekar
3. " Keshav Rane
4. " Gurunath Kochrekar
5. " Diogo Severes
6. " Vinayak Sawant
7. " Joaquim D'Costa
8. " Caetano Pereira
9. " Milagres Rodrigues
10. " Shaikh Hassan
11. " Kubraab Iddelgi
12. " Manial Saraj
13. " Mohidinsab Gulbarga
14. " Mathaye Chowan
15. " Kasimsah Gulbarga
16. " Shivlingappa Koonreddi
17. " K. B. Mathel
18. " Usman Khan
19. " Dattatraya B. Shirke
20. " Mayappa Harijan
21. " Hanumantha Muthatl
22. " Sabanna U. Narsonagi
23. " Hanumantha Gangur
24. " Kechappa Harijan
25. " Apanna D. Guledar
26. " Amarappa Wallihar
27. " Shivlingappa Sarur
28. " Rajput Pal
29. " Pyarelal Bindh
30. " Claram Saroj
31. " Parasnath Bindh
32. " Baijanath Bindh
33. " Rammahech Bindh
34. " Ramprish Chawan
35. " Mohanlal Bindh
36. " Gajraj Bindh
37. " Gulraj Chowan
38. " Dikhi Bindh
39. " Thakur Chowan
40. " Ramdhani Dusad
41. " Rambachan Bindh
42. " Brijlal Bindh
43. " Chandeshwar Chowan
44. " Ankush Omkhande
45. " Madhukant Naik
46. " Antonio Antao
47. " Mahadeo Shet Gaonkar
48. " P. R. L. Trindade
49. " Mohan Kavlekar
50. " Chandrakant Parab
51. " Sudhakar Rane
52. " Michal Rodrigues
53. " Gopinath Khorjuvenkar
54. " Philip Vaz
55. " Babuso Amonkar
56. " J. D. Sequira
57. " Shantanu Marajkar
58. " Yeshwant Naik

[भाग II—प्रावधान 3(ii)]

. भारत का याज्ञवल : जनवरी 1, 1983/पृष्ठ 11, 1904

S. No. . Name

59. Shri Manohar Kanoji
 60. " Narsinha Mukkaikar
 61. " Manual Fernandes
 62. " Shamsuddin Shah

2. As is evident the dispute relates to the alleged retrenchment of 62 workmen from the services of the Respondent Company. During the pendency of the present reference, however, the matter seems to have been mutually negotiated whereby the parties namely the Goa, Mining Labour Welfare Union who espoused the cause of these 62 workmen and the management have arrived at certain terms embodied in the terms of settlement, on the strength of which there is a request to pass an award by both the parties. I have perused the terms of the settlement whereby I find that out of 62 workmen 52 have been agreed to be reinstated with certain monetary benefits while the remaining 10 workmen who stand retrenched from 9-6-1982 are to get additional amount equivalent to 75 per cent of the total amount of retrenchment compensation and gratuity payable to them under the notice of retrenchment. These payments were to be made by 30-9-1982 in full and final settlement to the retrenched workmen.

3. It is true that out of 62 workmen 10 workmen remained out of service but then having regard to the fact that a major portion of the workmen is agreed to be reinstated and since the Union who has espoused the cause have found the settlement fair and reasonable whereby the dispute has been brought to an end, I endorse the settlement, hold it to be fair and reasonable and the dispute therefore does not survive.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-36012/3/82-D. IV(A)]

S.O. 66.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL :

CALCUTTA

Reference No. 42 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. D. K. Mukherjee Industrial Relation Officer.

On behalf of Workmen—M/s. Asgher Ali, Vice-President, National Union of Waterfront Workers.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Port

AWARD

By Order No. L-32012/4/80-D.IV(A) dated 7th June, 1980 the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in not confirming Shri Sadhan Chandra Mondal, Lascar, U.R.R. Party, Falta with effect from 1st August, 1977 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. When the case was taken up for hearing, the parties filed a petition stating that the matters have been settled amicably between the parties on the terms embodied in the said petition and prayed that an award be passed in terms of the said compromise petition. I have gone through the terms of settlement and I am satisfied that the terms are fair and reasonable. I therefore accept the same and pass an award in terms of the said compromise petition which will form part of this Award as Annexure "A".

Dated, Calcutta,

The 4th December, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

In the matter of Reference No. 42 of 1980

AND

In the matter of the Government of India, Ministry of Labour Order No. L-32012/4/80-D.IV(A) dated 7-6-1980.

AND

In the matter of Notice No. Ref. 42/80/641 dated 18/19-7-1980 issued by the Secretary to the Court, Central Government Industrial Tribunal, Calcutta.

BETWEEN

The employers in relation to the management of the Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their Workmen

Represented by National Union of Waterfront Workers, 15, Coal Dock Road, Calcutta-700043.

Humble petition of the applicants, employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and the workmen represented by the National Union of Waterfront Workers (hereinafter referred to as the "Board" and the "Union" respectively in this matter).

Most Respectfully Sheweth :

1. That your petitioners submit that the Government of India, Ministry of Labour under Order No. L-32012/4/80-D.IV(A) dated 7-6-1980, referred to the Hon'ble Tribunal the dispute in respect of the matters specified in the Schedule below :

"THE SCHEDULE

Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in not confirming Shri Sadhan Chandra Mondal, Lascar, U.R.R. Party, Falta with effect from 1st August, 1977 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

2. That your petitioners state that the Written Statement on behalf of the "Board" was filed before the Hon'ble Tribunal on 29-8-1980 and the Written Statement on behalf of the "Union" was submitted on 30-8-1980. The case is now fixed for pre-emptory hearing on 3-12-1982.

3. That your petitioners state that meanwhile the matter has been further discussed between the parties to the dispute

and it has been voluntarily agreed that the concerned workmen in the dispute, who are named below, be confirmed with effect from the dates shown against each and be adjudged the inter se seniority position amongst them in the cadre of Lascare under the Upper Reaches Research Station, Phalta, Chief Hydraulic Engineer's Department, in the order mentioned herein :

| Order in Seniority | Name | Designation | Date of confirmation in the post of Lascar in U.R.R.S. Phalta | |
|--------------------|---------------------------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Shri Santu Ranjan Purkait | Temporary Lascar | 29-9-1980 | |
| 2. | Shri Samad Ali | Temporary Lascar | 30-9-1980 | |
| 3. | Shri Sadhan Chandra | Temporary Lascar | 1-10-1980 | |

4. That your petitioners submit that the above reference before the Hon'ble Tribunal may kindly be disposed of in terms of the above compromise.

Under the above circumstances, your petitioners most humbly pray that your Honour would be graciously pleased to consider the matter in terms of the above settlement and give an award accordingly.

And for this, your petitioners as in duty bound shall ever pray.

Sd./-
I.R.O.
Calcutta Port Trust

Sd. /-
Vice-President
National Union of Waterfront Workers

Witness :

1. Sd./-
2. Sd./-

1. Sd. /-
2. Sd. /-

Calcutta,
Dated this the 3rd Day of December 1982.

M P. Singh, Presiding Officer
[No. L-32012/4/80-D. IV(A)]
T. B. SITARAMAN, Desk Officer

New Delhi, the 16th December, 1982

S.O. 67.—In accordance with section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, of the Central Government, the Central Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Calcutta, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 43 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank, Calcutta,

AND
Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. Rameswar Singh, Law Officer

On behalf of Workmen—Mr. R. L. Singh, General Secretary of the Union.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Banking.

AWARD

By Order No. L-12012/48/80-D.II.A dated 29th October, 1981 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in relation to its Biplabi Rash Behari Basu Road, Calcutta Branch, in imposing the punishment of stoppage of three increments and debarring with effect from 25th March, 1978 for promotion to clerical cadre of Shri G. P. Trivedi, Peon is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The terms of reference show that two kinds of punishment were imposed on the peon G. P. Trivedi: (i) stoppage of three increments and (ii) debarring him with effect from 25th March, 1978 from promotion to clerical cadre (vide Exts. M-10 and M-11). The question is whether this action of the management is justified? The main facts of the case are admitted and are simple. G. P. Trivedi joined the service of the Punjab National Bank, Biplabi Rash Behari Bose Road, Calcutta (briefly, the bank) as a probationer peon on 20th April, 1967. At the time of joining he declared that his educational qualification was VIII class pass and he also produced certificate exhibit M-2 to that effect. In fact he was a matriculate at that time but he did not disclose this fact then. In the year 1974 he informed (vide letter Ext. W-1—exhibit M-4) the bank that he was a matriculate and he had passed the Matriculation examination in the year 1961. He produced a high school certificate, Ext. M-5. Thereafter he began to make representation requesting the bank to give him chance of officiating in the vacant post of a clerk. He made three such representations in 1974 (Exhibits W-1, W-2 and W-3) and two representations in 1975 (Exts. W-4 and W-5). The General Secretary of the Union also wrote for him to the management. On 25th October, 1976 the management issued a chargesheet to him asking him to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him for the false declaration as to his educational qualification at the time of joining his service as a probationer peon. In the chargesheet it was mentioned, "The bank as a matter of policy does not employ over-qualified persons (i.e. those who have passed the matriculation—higher secondary examination) in subordinate cadre. Thereafter the bank held the enquiry which started on 7th January, 1977 and concluded on 21st June, 1977. The Enquiry Officer's report is exhibit M-8. The Enquiry Officer Mr. G. S. Burmrah found as follows :

- (i) It is established beyond doubt that Sri Trivedi who passed matriculation examination in 1961, joined the services of the Bank in April, 1967, informed the Bank at the time of his appointment that he had passed Junior High School Examination. In this way he suppressed his higher qualification which is a material fact;
- (ii) The above conduct on the part of Sri Trivedi although not covered in the list of gross mis-conducts under the Bipartite Settlement of 1966 is a prima facie gross misconduct.
- (iii) From the evidence adduced by the management representative of the Bank, it could not be established, on the basis of documentary proof, that in the year 1967 (when Sri Trivedi joined the services of the Bank) as per policy the Bank was not appointing matriculates or higher secondary passed candidates in subordinate cadre;
- (iv) It appears that there are cases in the Bank wherein matriculates or higher secondary passed candidates have been appointed in subordinate cadre.

While above may be the correct position, in the case of Sri Trivedi what has been established beyond doubt is that he had suppressed his educational qualification which was a material fact.

This leads to a doubt that Sri Trivedi at the time of the appointment in the Bank service must have been aware of the fact that his higher qualification might come in his way in appointment in the Bank in subordinate cadre. He further declared

his qualification as Junior High School pass only although he had passed matriculation much before his joining the Bank service."

On receipt of the enquiry report the management imposed the punishment as stated above on the ground of concealment of a material fact which was considered to be gross misconduct.

3. In my opinion, though the Bank was empowered to impose the punishment of stoppage of increment, it was not justified to do so in the facts and circumstances of this case. It is true that neither in the chargesheet (Ext. W-7) nor in the enquiry report (Ext. M-8) nor in the order of proposed punishment (Ext. M-10) it was mentioned as to what administrative order of the management or what clause of the bipartite settlement of 1966 was contravened by Sri Trivedi but the central fact remains that Shri Trivedi concealed a material fact at the time of his entry into service in the year 1967. The management has pointed out that the bank had issued a circular Ext. M-9 dated 16th May, 1973 which was to the effect that a person giving false declaration about his educational qualification should be discharged from service. This circular, however, was not in existence in 1967 when Trivedi joined his service. It was argued on behalf of the workman that the Enquiry Officer has found that the bank has failed to substantiate that in the year 1967 when Trivedi joined the service of the bank its policy was that matriculates will not be appointed as a candidate in subordinate cadre. That is correct. Admittedly at the time of the chargesheet and onwards there was the circular of 1973 in existence under which such person could be discharged for making false declaration as to his qualification. So irrespective of the Bank's policy regarding non-appointment of matriculates as peons Sri Trivedi could be punished. It was argued by the Union that the bank itself had appointed several matriculates as peons and that the bank did not produce the service records of 25 clerks as demanded by Sri Trivedi which could have shown that matriculates had been appointed as peons by the bank. Even if that be so, it is no ground to exonerate him from liability for his misconduct. It was next urged by the workmen that the act of Sri Trivedi was not misconduct as per provisions of the Bipartite Settlement of 1966. Suffice to say that an act can be misconduct outside the settlement. Any way, the punishment of stoppage of increment cannot be sustained in view of the Bank's own conduct in appointing Matriculates as peons and also in view of the fact that its alleged policy of non-appointment of over qualified persons was not established.

4. So far as the second punishment of debarring him from officiating promotion is concerned, it was confined only to two years with effect from 25-3-1978 which ended on 25th March, 1980 (vide circular Ext. M-14 dated 29th January, 1977 and Ext. M-15 dated 30th August, 1978). Sri Trivedi is now admittedly eligible for officiation and promotion. It may also be noticed that officiation or promotion is primarily a management function. No employee has a right to officiate or to be promoted. Sri Trivedi can have no grievance in this behalf. He can have no right to force the management to promote him to a higher post unless any rule or agreement permits it. After all he did conceal a material fact regarding his educational qualification at the time of joining his service. That fact on his part cannot be called fair. In my opinion it amounts to misconduct.

5. After having considered the submissions of the parties and the facts and circumstances of the case I come to the conclusion that the punishment of stoppage of increment imposed upon Sri G. P. Trivedi, Peon by the management is not justified and it ought to be set aside. It is accordingly set aside. As regards the second punishment of debarring him from promotion, I am of opinion that the action of the management in this behalf is justified. Sri Trivedi is, therefore, entitled to get relief in part. The management is directed to pay all his legal dues respecting the increment as may be permissible as per rules of the management.

This is my award.

Dated, Calcutta,

M. P. SINGH, Presiding Officer

The 16th November, 1982.

[No. L-12012(48)/80-D.II(A)]

New Delhi, the 6th December, 1982

3 O. 63.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India Bombay, and their workman, which was received by the Central Government on the 26th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-23 of 1978

PARTIES:

Employers in relation to Union Bank of India, Bombay.

AND

Their Workman.

APPEARANCES:

For the employer—Mr. F. D. Damania, Advocate.

For the workman—Mr. M. S. Udeshi, Advocate

INDUSTRY : Banking.

STATE : Maharashtra.

Bombay, the 30th day of October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-12012/48/78-D.II.A dated 23/27th November, 1978, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India, Bombay, and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Union Bank of India, Bombay, in terminating the services of Shrimati N. P. Bhisma, Special Assistant with effect from 1st October, 1976 is legal and justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The workman, Mrs. N. P. Bhisma, joined the Bank on 10th June, 1957 as a Clerk. At the relevant time the workman was attached to Prabhadevi Branch of the Bank as a Special Assistant. The services of the workman were terminated by the employer-Bank on 1st October, 1976 purporting to do so under paragraph 522.1 of the Sastry Award. The workman alleged that the action of the Bank in terminating her services as above was wrongful, illegal and inequitable, for the reasons mentioned in the statement of claim. The workman, therefore, claimed reinstatement with full back wages and continuity of service.

3. The employer Bank by its written statement dated 26th July, 1979 maintained that its action of terminating the services of the workman was perfectly proper and justified.

4. It appears that the grievance of the Bank was that while the workman was working in the Bank, it was observed, that she was highly irregular in her attendance and she was in the habit of frequently remaining absent without prior permission and/or justifiable grounds or reasons causing considerable inconvenience to whichever branch she was posted. It also appears from the document produced in this reference that it was the case of the Bank that she had been advised in various memoranda to improve her attendance and in spite of that she did not improve.

5. It appears that the talks of settlement were going on between the parties and finally on 8th October, 1982 a settlement was arrived at between them. The terms of the settlement signed by both the parties have been placed on record where under by way of all amounts payable to the workman from the date of her termination till 8th October,

1982, the Bank offered to pay and the workman agreed to receive a sum of Rs. 52,586.10 less an amount of Rs. 977 being income-tax payable on the said sum. The break up of this amount has been given in the settlement. In view of this payment the workman has given up her claim for reinstatement in the service of the Bank as also her claim for back wages. As desired by the workman the employer has paid to the workman at the time of filing the present consent terms before this Tribunal a sum of Rs. 51,609.10 by pay order drawn on Union Bank of India, Bombay Main Branch in favour of the workman's Advocate on record, Mr. M. S. Udeshi.

6. The settlement was filed before this Tribunal on 23rd October, 1982. It is duly signed by the parties themselves and their Advocates. I find the settlement to be just and fair.

7. I, therefore, pass an award in terms of the settlement annexed to this award. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer
[No. L-12012(48)/78-D. II(A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT No. 23 of 1978

Smt. N. P. Bhishma ... Workman

Versus

Union Bank of India ... Employer

MAY IT PLEASE THE HONOURABLE TRIBUNAL

1. The workman Smt. N. P. Bhishma and the employer, Union Bank of India, have settled their dispute referred to this Hon'ble Tribunal under the above Reference as per the terms of Settlement signed by them today.

2. Both the parties agree that the said Settlement is fair and proper. The Bank has today made payment to the Advocate for the workman of a sum of Rs. 51,609.10, which is the net amount payable after deducting a sum of Rs. 977 from the total amount of Rs. 52,586.10 payable under the terms of the Settlement. The workman admits having received the said amount.

3. In view of the aforesaid, both the parties jointly apply to this Hon'ble Tribunal to dispose of the above Reference in accordance with the terms of Settlement filed before this Hon'ble Tribunal.

Dated at Bombay this 8th day of October, 1982.

(M. S. UDESHI)

Advocate for the Workman.

(Firoze Darasha Damania)

Advocate for Union Bank of India.

N. P. BHISHMA,
Workman above named.

Sd/-

For Union Bank of India
Superintendent.

Sd/-

(Married daughter of
Mrs. N. P. Bhishma)

PRESENT :

Mr. M. S. Udeshi—Advocate for workman.

Smt. Vordene Rana, married daughter of workman—
present for workman.

Mr. S. K. Talsoma Advocate holding for Mr. F. D. Damania, Mr. Udeshi Advocate for workman says that the Bank has issued payee account pay order in the name of

Advocate for the workman in terms of column 7 of the consent terms; and as stated in the application.

Settlement appears to be fair & just. Award in terms of settlement.

23-10-1982.

Sd/-

for Central Tribunal

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT No. 23 of 1979

Smt. N. P. Bhishma ... Workman

Versus

Union Bank of India ... Employer

TERMS OF SETTLEMENT

With a view to resolve the dispute amicably and as a gesture of goodwill, the Union Bank of India (hereinafter referred to as 'the bank') agrees to settle the case of Smt. N. P. Bhishma (hereinafter referred to as 'the workman').

2. By way of all amounts payable to the workman for the period from 1st October, 1976 till 8th October, 1982 either by way of wages/leave wages/bonus/ex-gratia payment or allowances, perquisites and privileges, the Bank agrees to pay the workman and the said workman agrees to receive a sum of Rs. 52,586.10 Less an amount of Rs. 977.00 being income tax payable on the said sum. The break-up of Rs. 52,586.10 is as under:—

| | |
|--|---------------|
| (a) Encashment of 30 days privilege leave | Rs. 2,535.00 |
| (b) Retrenchment compensation for 25 years @ 15 days salary for each year of service | Rs. 31,687.50 |
| (c) Employer's Provident Fund Contribution from 1-10-1976 to 8-10-1982 | Rs. 5,647.90 |
| (d) Gratuity on the basis of wages as on 8-10-1982 Entitlement to Gratuity | Rs. 18,195.00 |
| Less : Already paid at the time of Abandonment of service | Rs. 8,565.00 |
| Total amount of Gratuity to be paid... | Rs. 9,630.00 |
| (e) 3 months notice pay on the basis of wages as on 8-10-1982 | Rs. 7,505.00 |
| Less : Notice pay paid at the time of terminating her services | Rs. 4,419.30 |
| | Rs. 3,085.70 |
| | Rs. 52,586.10 |

(Rupees Fifty two thousand Five hundred Eighty six and Paise Ten only)

3. The aforesaid amounts have been calculated on the basis of the salary the employee would have drawn had she been in the service of the Bank as on date and the workman agrees to the settlement arrived at in clause 2 above.

4. In view of the above, the workman hereby gives up her claim for reinstatement in the service of the Bank as also her claim for back wages from 1st October, 1976 to 8th October, 1982.

5. Income Tax to the tune of Rs. 977.00 is deducted from the full amount and therefore, the balance amount of Rs. 51,609.10 only is payable to the workman and the workman agrees to receive the amount of Rs. 51,609.10 by way of settlement.

6. The workman hereby declares that on receipt of the said sum of Rs. 51,609.10 she does not and will not have any claim whatever against the employer.

7. As desired by the workman, the employer has paid to the workman at the time of filing the present consent terms, a sum of Rs. 51,609.10 arrived at in clause 5 above, by pay order No. 043586 drawn on Union Bank of India, Bombay Main Branch, dated the 5th October, 1982 favouring the workman's advocate on record in the above matter viz. Shri M. S. Udeshi.

8. The parties agree to bear their own costs of the above reference proceedings.

Dated at Bombay this day of October, 1982.

Sd/-

(M. S. Udeshi)

Advocate for Workman

Sd/-

(Firoze Darasha Damania)

Advocate for

Union Bank of India.

Sd/-

(N. P. Bhishma)

Workman above named

Mrs. Vandana Raman

(married daughter of Mrs. N. P. Bhishma)
For Union Bank of India

Sd/-

Superintendent

SO 69—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Maharashtra, and their workman, which was received by the Central Government on the 26th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-31 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to State Bank of India

AND

Their workmen

APPARANCES :

For the employer—Mr. G. G. Modak, Advocate.

For State Bank of India & Subsidiary Bank Employees' Association—Mr. R. Rajan Pillai, Advocate.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 29th day of October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No I-12011/17/80-D.IIA dated 18th December, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

1085 GI/82-12

SCHEDULE

"Whether the management of State Bank of India, Chief Regional Manager, Nagpur, is justified in denying overtime claims to S/Shri Laware, Ingle and Deshmukh, Godown Watchmen of Khamgaon Branch during the period from April, 1969 to December, 1972 ? If not, to what relief they are entitled to?"

2. The State Bank of India has got a branch at Khamgaon. The three workmen mentioned in the schedule set out above were working as Godown Watchmen at Khamgaon branch during the period from April, 1969 to December, 1972. It is not disputed that it is an establishment registered under the Bombay Shops and Establishments Act, 1948 (hereinafter referred to as the "Shops Act"). The provisions of the Shops Act are, therefore, applicable to Khamgaon branch of the State Bank of India.

3. The three watchmen were deputed by the employer-Bank for work as detailed below :

(i) M. G. Laware was deputed to work as a Watchman of the Godown of M/s. Bhuidas Karsandas & Co.;

(ii) D. J. Ingle was deputed to the Godown of M/s. Thunjunwala & Co.; and

(iii) S. R. Deshmukh was deputed to M/s. Thunjunwala Rolling Mills and Engineering Works."

These workmen were required to work at the godowns of the aforesaid concerns for the relevant period. It is the case of the workmen that they were required to perform 12 hours duty. According to them, they were required to work overtime for four hours a day. The workmen claimed that the total amount due to them on account of overtime wages was as follows :

(i) Laware : Rs. 12,001.81.

(ii) S. R. Deshmukh : Rs. 12,568.58.

(iii) D. J. Ingle : Rs. 10,897.78".

However, the Bank did not make the payment to them for overtime wages. They alleged that the godowns where they were detailed to work were under the Municipal limits of Khamgaon and the provisions of the Shops Act are, therefore, applicable. They contended in their statement of claim that the factum of performance of 12 hours work per day is not disputed by the Bank. They, therefore, prayed that this Tribunal be pleased to pass an award granting them the relief in respect of the overtime wages as claimed.

4. In the written statement filed on behalf of the Bank it was admitted that the provisions of the Shops Act are applicable. It was, however, pleaded that as laid down in paragraph 195 of the Labour Appellate Tribunal's decision, a godown watchman has no fixed hours of work and is not required to sign the Attendance Register in the office of the Bank. It was, therefore, denied that the workmen are entitled to overtime wages as claimed. It was contended that these workmen are entitled to godown allowance as provided in clause 512 of Chapter-V of the award of the Labour Appellate Tribunal. They are paid an allowance of Rs. 8 each. It was, therefore, alleged that there could not be any question of these workmen having performed the duties in excess of their prescribed period and/or their being entitled to claim overtime allowance. It was denied that they had admitted the factum of performance of overtime by these workmen. It was pleaded that under item 14 of Schedule II of the Shops Act these workmen are exempted from the operation of certain sections of the Shops Act which included Section 14 of that Act. It was, therefore, submitted that no overtime wages are payable to the workmen and the reference be disposed of accordingly.

5. It is not in dispute that the Shops Act is applicable to the establishment viz., the Khamgaon branch of the State Bank of India where the workmen worked. Reliance is, however, placed upon Section 14 read with Section 4 of the Shops Act. It is pointed out for the Bank that under item No. 14 of Schedule II of the Shops Act the workmen are

excluded from the provisions of Section 14 of the Shops Act. Section 14(1) provides :—

"Subject to the provisions of this Act, no employee shall be required or allowed to work in any shop or commercial establishment for more than nine hours in any day and forty-eight hours in any week."

It is argued on the basis of this provision read with item No. 14 in Schedule II of the Shops Act that the provisions regarding hours of work as mentioned in Section 14(1) of the Shops Act are not applicable to the case of workmen. The argument is that the workmen may be made to work for more than the hours of work specified in the said section and because of the exemption they will not be entitled to claim overtime wages under Section 63 of the Shops Act.

6. Mr. Pillai, the learned counsel for the Union, submitted that exemption granted under item No. 14 of Schedule II of the Shops Act will not be available to the Bank for resisting the claim for overtime work. In support of this submission, he relied upon the decision of the Division Bench of the Bombay High Court in the case of Penambur Vishnumurti Narayan Upadhyaya v. C. P. Fernandes (Vol. 58 B.L.R. 1956 p. 799). That was a case where the employee of a bakery, who was a deliveryman whose work was to deliver bread and loaves prepared by the bakery to its customers, applied under Section 63 of the Shops Act for payment of overtime wages. A contention was raised on behalf of the bakery that under Schedule II, item 8 of the Shops Act the prohibition contained in Section 14 of the Shops Act, prohibiting the employer from making the employee work beyond the limit of hours prescribed therein was removed as regards deliveryman. It was held that in spite of the above provision, if the employee established that he had worked overtime in any particular work, he was entitled to overtime wages as provided in Section 63 of the Act. Their Lordships observed :—

"It is erroneous to assume that because an establishment is exempted from the provisions of S. 14 and because there is no limit of work laid down with regard to that establishment under S. 14, therefore there is no limit of hours of work applying to that establishment as far as Section 63 is concerned. The limit of work for the purpose of S. 14 is entirely different from the limit of work laid down by the legislature for the purpose of Section 63. Whereas the limit of work for the purpose of S. 14 is laid down in order to prohibit the employer from requiring an employee to make him work beyond the limit, the limit of work laid down for the purpose of Section 63 is purely for the purpose of computing overtime wages. In our opinion, therefore, if the employee in this case establishes that he has worked overtime in any particular week he would be entitled to overtime wages as provided by Section 63."

It was further observed in this decision that the authority below was in error in taking the view that because there was no limit of work with regard to a particular establishment under Section 14, therefore, there would be no limit of work under Section 63 and the establishment could make an employee work for any length of time without paying him overtime wages. This decision is a complete answer to the argument that in view of the entry No. 14 in Schedule II of the Shops Act the employee cannot claim overtime for the overtime work under the provisions of Section 63 of the Shops Act. It must, however, be noted that item 14 in Schedule II of the Shops Act, does not say that the provisions in Section 63 also are not applicable to the employees of the establishments mentioned in item No. 14.

7. It will, therefore, have to be held that the workmen i.e. the three watchmen in this reference are entitled to overtime wages by virtue of the provisions in Section 63 of the Shops Act.

8. Mr. Modak, the learned counsel for the Bank, referred to the agreement dated 31st March, 1967, between the State Bank of India and its Workmen represented by the All India State Bank of India Staff Federation. Para 5.12 therein provides :—

GODOWN ALLOWANCE

Godown Keepers and Godown Watchmen to whom the provisions regarding hours of work and overtime do not apply and who were excluded by the Labour Appellate Tribunal in paragraphs 194 and 195 of its Decision dated 28th April 1954 shall be paid a Godown Allowance of Rs. 25 per month if he is a Godown Keeper and Rs. 15 per month if he is a Godown Watchman."

Relying upon this provision it is contended for the Bank that the Godown Watchmen are not entitled to overtime wages, but to Godown Allowance only. However, it is made clear in the said paragraph itself that the provisions regarding payment of Godown Allowance will be applicable to Godown Keepers and Godown Watchmen to whom the provisions regarding hours of work and overtime do not apply. Now, obviously under the provisions of the Shops Act, the Godown Watchmen, who are working within the Municipal limits, would be entitled to overtime wages, if their hours of work exceed the prescribed limit. This para, therefore, is of no avail to the Bank. Even though under item No. 14 of Schedule II to the Shops Act, there is exemption in the case of Godown Watchmen in respect of the provisions mentioned in column 3 of item No. 14, there is no exemption in their case in respect of the provisions in Section 63 of the Shops Act. The provisions in Section 63 of the Shops Act will be available to these Godown Watchmen for claiming wages for overtime work. Under Section 63(1) of the Shops Act they shall be entitled, in respect of the overtime work, to wages at the rate of 1½ times their ordinary rate of wages.

9. A notice was given on 13th August, 1982 by the Association, who espoused the case of workmen to the Bank to produce certain documents. The Bank has now produced the documents as per that notice. One of the documents produced is a letter written by the Branch Manager, Khamgon Branch on 26th April, 1973 to the Regional Manager, State Bank of India, Bombay. In that letter there is clear admission that the three Watchmen have put in overtime work and overtime pay as claimed by them is payable to them. In fact the Branch Manager had sought the permission of the Regional Manager to make payment for the overtime work as claimed by the three Godown Watchmen in their statement of claim.

10. I, therefore, find that the management of the State Bank of India, Chief Regional Manager, Nagpur, is not justified in denying overtime claims to the three Godown Watchmen, Aware, Ingle and Deshmukh. They are entitled to overtime wages as provided in Section 63 of the Shops Act, 1948.

11. My award accordingly. No order as to costs

M. D. KAMBIL, Presiding Officer

[No. 1-12012(48)/78-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1982

का० आ० 70--केन्द्रीय मरकार, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 10 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्त वित्त पोषित अपने किया कलापों का बृत देने हुए उम् वर्ष के लेखा विवरण के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है :—

गामन्य --चूना-पत्थर प्रीर डोलोमाइट खान थम कल्याण निधि, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) के अधीन गठित की गई श्री जिसमे किसी खान में उत्पादित उन्ने चूना

पत्थर और डालामाइट पर, जिनमा चूना पत्थर और डोलोमाइट खाना में तियोजित वार्षिकों के उत्पादन की अविवरित करने के लिए। —

- (1) फिसी कारखाने के अविष्टानों का प्रकाय किया जाता है या अन्यथा व्ययन किया जाता है,
- (2) ऐसी खाने के स्थानीय द्वारा मॉस्ट, लोहा या इसके निर्माण में फिसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

यथास्थिति चूना पत्थर या डोलोमाइट पर एक स्पष्ट प्रति मीट्रिक टन में प्रतिधिक दर से उत्पादन जुल्के के उद्घरण और सग्रहण की अवस्था की गई है। इन सभी उद्घरण की वास्तविक दर बोम पंग प्रति मीट्रो टन है। उपकरण के ग्राम मुख्यतः लाहौर राज्य और स्वच्छता में सुधार चिकित्सा सुविधाओं की अवस्था, शावान और पोषण क्षमताओं, आदि ते लिए प्रार्थित नहावना देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

2 प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, उत्तरी राज्यों और सभी जास्ति क्षेत्र गोंदा और दिल्ली को जिसमें देश की चूना पत्थर और डोलोमाइट खान है, पात्र क्षेत्रों में बोटा गया है और इन क्षेत्रों के कल्याण आयुक्तों का इस अविनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों का लागू करने के लिए कल्याण और उपकरण आयुक्तों के सभ में नियुक्त किया गया है। क्षेत्रों का आवान इस प्राप्त किया गया है। —

| क्रमांक | अधिकारी नाम | मुक्यालय | उनके क्षेत्राधिकार में विनाम |
|---------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | कल्याण आयुक्त, जबलपुर | उत्तर क्षेत्र वाले राज्य | अम मन्त्रालय, |
| | थम मन्त्रालय, | | भारत सरकार |
| | जबलपुर। | | |
| 2. | कल्याण आयुक्त, भूवनेश्वर | उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, | मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और |
| | थम मन्त्रालय, | | मध्यांशुमित्र क्षेत्र गोंदा। |
| | भारत सरकार | | |
| | भूवनेश्वर। | | |
| 3. | कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद | बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू | |
| | थम मन्त्रालय, | आर कर्मी और सघ- | |
| | भारत सरकार | गांधीनगर क्षेत्र दिल्ली | |
| | इलाहाबाद। | | |
| 4. | कल्याण आयुक्त, भीलावडा | गाजियान, गुजरात, | |
| | थम मन्त्रालय, | हरियाणा, पंजाब और | |
| | भारत सरकार, | हिमाचल प्रदेश। | |
| | भीलावडा। | | |
| 5. | कल्याण आयुक्त, बगलौर | तमिलनाडु, कर्नाटक और | |
| | थम आयुक्त, | अन्ध्र प्रदेश | |
| | भारत सरकार, | | |
| | बगलौर। | | |

लोटारा प्रांत वालों द्वारा जाने के अस्तित्व के लिए विविध राज्यों में विविध विवरित करना चाहिए।

(f) स्थान

3. 1 यहाँ से स्थान 12 आयुर्वेदिक और 14 एलो-टोन की अवधारणों के अवावा, आलाच्य अवधि के दीर्घन चार और अधिकारया जूनगढ़ (राजस्थान) विस्तृद्वारा (राजस्थान), माताल (हिमाचल प्रदेश) और लहेरी (राजस्थान), में एक एक का मजुरी दी गई। इन अधिकारयों में 2,53 लाख से अधिक गर्भी लाभ उठाते हैं।

3. 2 यात्रोंवाले वार्षिक दीर्घ खान प्रबन्धनों के लिए यहाँ यात्रा अनुशासन भी मंजूर किए गए। —

| | | |
|-----|--------------------|-------------------|
| (a) | प्रमूलेष वैत | 2,37,000 रुपये |
| (b) | एक्स्प्रेस मध्यांश | — |
| (c) | यथा अवश्याल | |
| | उत्तरग | 1,30,409 36 रुपये |

3. 3 वागड़ अम गम्भीर दुर्घटना याजना के अन्तर्गत 22 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त दुआरा और 17 नवेदिक के रायियों का डवाज़ किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में नवेदिक से पीछित रायियों के लिए 41 पलग वर्तित किए गए।

शिक्षा

4. कूना-पत्थर और डालामाइट थर्मिका के पुत्रा और पुत्रियों का छात्रवृत्तिया देने की याजना के अन्तर्गत 1776 छात्रों का छात्रवृत्तियों के स्कूल में 1,33,055 रुपये की रायि का भुगतान किया गया। इनमें से भीतवाडा क्षेत्र के 336, ब्रह्मनौर क्षेत्र के 17, जबलपुर क्षेत्र के 297, भुवनेश्वर क्षेत्र के 16 और इलाहाबाद क्षेत्र के 110 छात्र थे।

आवाम

5. वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान टाडा-1 अवाम याजना के अन्तर्गत 646 मकानों का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई और रियोटाइटिंग वर्ष के दौरान 132 मकानों का निर्माण किया जा चुका था और ग्रामा मसान वनाओं योजना के अन्तर्गत 130 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई और 1981-82 के दौरान 27 मकानों का निर्माण पूरा किया गया।

मनोरंजन

6. आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 9 मिनेमा प्रोजेक्टरों और 8 रेडियो सैटों की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी गई।

6. 1 इसके अन्तर्गत, विभिन्न प्रबन्धनों द्वारा चवाए जा रहे कल्याण केन्द्रों का 1629 80 रुपये की सहायता अनुदान की मजूरी दी गई और विभिन्न क्षेत्रों में दूरभासेटों, सामाजिक तथा सास्कृतिक कार्यकलापों के लिए 56,207.44 रुपये की रायि मजूरी दी गई।

जल प्रदाय :

7. रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, जल प्रदाय स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खानों के प्रबंधतात् को 14,68,026 रुपए को अन्तिम किशत स्वीकृत की गई।

8. वर्ष 1981-82 का लेखा विवरण

| | ₹ |
|------------------------------|----------------|
| 1-4-81 को अथशेष | 1,80,25,796.00 |
| 1981-82 के दौरान प्राप्तियां | 66,361.22 |
| घटय | 41,33,843 |
| 31-3-1982 को अन्तशेष | 2,05,52,975.00 |

[सं. जैड-16016/1/82-एम० वी/डब्ल्यू II]

टो० डॉ० सलहोत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 1982

S.O. 70.—In pursuance of section 10 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), the Central Government hereby publishes the following report giving an account of its activities financed under the said Act during the financial year 1981-82 together with the statement of accounts of that year :—

General—The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) which provides for the levy and collection of cess at a rate not exceeding one rupee per metric tonne on so much of Limestone and Dolomite produced in any mine,

- (i) as is sold or otherwise disposed to the occupier of any factory, or
- (ii) as is used by the owner of such mine for any purpose in connection with the manufacture of cement, iron or steel,

to promote the welfare of the persons employed in limestone and dolomite mines. The actual rate of levy presently is twenty paise per metric tonne. The proceeds of the cess are being utilised mainly for the improvement of public health and sanitation, provision of medical facilities, subsidy on housing and programmes of nutrition etc.

2. For administrative convenience, the nineteen States and Union Territories of Goa and of Delhi which have Limestone and dolomite mines in the country, have been grouped into five regions and the Welfare Commissioners of the areas have been appointed as Welfare and Cess Commissioners for the enforcement of the Act and Rules framed thereunder.

The allocation of the region is as under:—

| Sl. No. | Designation of the Officer | Headquarters | Name of the States and their jurisdiction |
|---------|---|---|---|
| 1. | Welfare Commissioner, Jabalpur Ministry of Labour, Government of India, Jabalpur. | Madhya Pradesh, Maharashtra and Union Territory of Goa. | |
| 2. | Welfare Commissioner, Bhubaneswar Ministry of Labour, Government of India Bhubaneswar. | Orissa, West Bengal Assam and Meghalaya | |
| 3. | Welfare Commissioner, Allahabad Government of India, Ministry of Labour, Allahabad. | Bihar, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir and Union Territory of Delhi | |
| 4. | Welfare Commissioner, Bhilwara Ministry of Labour, Government of India, Bhilwara. | Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab and Himachal Pradesh. | |

5. Welfare Commissioner, Bangalore
Ministry of Labour
Government of India

Bangalore

Tamil Nadu, Karanataka and Andhra Pradesh.

The following welfare facilities have been provided to Lime stone and Dolomite Mines workers:—

A. HEALTH Besides 12 Ayurvedic and 14 Allopathic dispensaries established earlier, four more dispensaries one each at Junagarh (Rajasthan), Chittorgarh (Rajasthan), Manal (H.P.) and Lahori (Rajasthan) were sanctioned during the year under report. These dispensaries serve more than 2.53 lakhs patients.

3.2 Grant in aid for the following purposes were also sanctioned to the mine managements during the year under report:—

| | |
|-------------------------------|----------------|
| (a) Ambulance | R. 2,37,000 |
| (b) Chest Screening Machine | *.. |
| (c) Other Hospital Equipments | R. 1,30,409,56 |

3.3. 22 persons were provided benefits under Fatal benefit and serious accident Scheme and 17 patients were treated for Tuberculosis 41 beds were reserved for T.B. patients in different regions.

EDUCATION:—

Under the scheme of award of scholarships to sons and daughters of limestone and dolomite workers, an amount of Rs. 1,33,055 lakhs was paid as scholarships to 1776 students. Out of these 336 were in Bhilwara, 17 in Bangalore, 297 in Jabalpur and 16 in Bhubaneswar and 110 in Allahabad.

HOUSING:

5. During financial year 1981-1982, 646 houses were sanctioned under Type I Housing Scheme, 132 houses were constructed during the year under report and 130 houses were sanctioned under Build Your Own House Scheme and 27 houses have been completed during 1981-1982.

RECREATION:

During the year under review 9 cinema projectors and 8 Radio Sets were sanctioned for providing at different places.

6.1 In addition, grants-in-aid amounting to Rs. 1629-80 was sanctioned to the Welfare Centres maintained by the different managements and an amounts of Rs. 56,207.44 was sanctioned for tournaments, social and cultural activities in different regions.

WATER SUPPLY:

7. During the period under report for water supply scheme a final instalment amounting to Rs. 14,68,026 was sanctioned to the management of different quaries in different regions.

8. Statement of account for year 1981-1982

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Opening Balance as on 1-4-1981 | Rs. 1,80,25,796.00 |
| Receipts during 1981-1982 | Rs. 66,361.22 |
| Expenditure | Rs. 41,33,843 |
| Crossing balance as on 31-3-1982 | Rs. 2,05,53,975.00 |

[F. No. Z-16016/1/82-M.V.W.II]
T.D.SALHOTRA, Under Secy.

बाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983

का. आ. 71.—नियर्यात (क्वालिटी नियवण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त इच्छितयों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एसेंडवार मैटर्स पॉस्ट मोरटर (इंडिया) प्रा. लि. 53-1-16, मकावाई सेट, जगन्नाथपुर, काकीनाड़-2, को नियन्त्रित मदों के भ्रमीकरण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के तिए मान्यता देती है।

1 तेल रहित चावन की भूसी और

2 हड्डी का चूरा, चूर और भीग।

[म 5(3)/82-ई आई एड ई पी]

MINISTRY OF COMMFRCE

New Delhi, the 1st January, 1982

S.O. 71.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of one year M/s. Pest-Mortem (India) Pvt Ltd, 53 1-16, Mekavai St, Jagannathpur, Kakinada 2, as an agency for the fumigation of following items—

- 1 De oiled Rice Bran, and
- 2 Crushed Bones, Hooves and Horns

[No 5(3)/82-EI&EP]

आधेश

का. आ. 72—भारत के नियर्यात व्यापार के विकास के लिए प्रेशर कुकरों का नियर्यात से पूर्व क्वालिटी नियवण और निरीक्षण के अधीन लाने के नियंत्रित प्रमाण, नियर्यात (क्वालिटी नियवण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अवधारनसार भारत सरकार के बाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का. आ. 2387 तारीख 26 जून, 1982 के अधीन भारत के गजपत, भाग 2, खड़-3, उप-खड़ (ii) तारीख 26 जून 1982 में प्रकाशित किए गए थे,

ओर उक्त आदेश के गजपत में प्रकाशित हाल के वैनालीस दिन का भीतर उन सभी व्यक्तियों में आवश्यक और मुक्ताव मार्गे गए थे जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी,

ओर उक्त राजपत्र की प्रतिया जनता का 12 जुलाई, 1982 को उत्तरदाता दी गई थी,

और केंद्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप प्रमाणव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और शुल्कों पर विचार कर लिया है।

अत अब, केंद्रीय सरकार, नियर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करते के पश्चात अपनी यह शब्द होने पर कि भारत के नियर्यात व्यापार के विकास में तिए ऐसा करना आवश्यक और समीचित है नियर्यात (क्वालिटी नियवण

प्रारंभिक नियर्यात) अधिनियम 1963 (1963 का 21) के धारा 6 द्वारा प्रदत्त अनुमति का प्रयाग तरत हुा—

- (1) अधिसूचित करनी है कि प्रेशर कुकर नियर्यात से पूर्व निरीक्षण के अधीन होने,
- (2) प्रेशर कुकर नियर्यात (निरीक्षण) नियम, 1963 के अनुसार निरीक्षण के प्रवार के स्थान में फिराइट करनी है जो नियर्यात से पूर्व ऐसे प्रेशर कुकर का लाग नामा
- (3) गट्टीव और अतराइटीव मानकों तथा नियर्यात नियवण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य नियमों के मानकों का प्रेशर कुकरों ने नियम भान्त निनिदणों के स्थान में मान्यता देती है जथा
- (4) अनराइटीव व्यापार के दीगल प्रेशर कुकरों के नियर्यात को तब तक प्रतिपिछ़ वर्ती है जब तक कि उनके गाव नियर्यात (क्वालिटी नियवण और निरीक्षण) अधिनियम, 1964 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन गरपित या मान्यता प्राप्त अभिकरण से भी एक द्वारा जारी किया गया इस आवश्यकीय प्रभाव-पद्धति हो तो कि प्रेशर कुकर का प्रयोग इसके निरीक्षण से सबवित शर्तों का प्रयोग वर्ता है तब नियर्यात याप्त है।

2 इस आदेश की काई भी बात भू-सामान, भूमुद्दी सामग्र्या वायु मार्ग द्वारा किये गये प्रेशर कुकर के वास्तविक नमूना के नियर्यात पर लागू नहीं होती।

3 इस आदेश में 'प्रेशर कुकर' से 4 लीटर से लकर 22 लीटर तक की धरिता वाला ऐसा काई दाव-पाप पाल अभिप्रेत है जिसका प्रयोग बाहरी उपभोग में होता है जिसमें 10 लिलाग्राम एफ/सेटी भीटर 2 का वार्षिकरण बायप दाव बनाये रखने की असता होती है।

4 यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[म 6(9)/81-ई आई एड ई पी०)]

ORDER

S.O. 72—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Pressure Cookers to quality control and inspection prior to export were published as required by sub rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 26th June, 1982, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No S.O. 2287 dated 26th June, 1982,

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said Order in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th July, 1982,

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft proposal have been considered by the Central Government;

Now, therefore, the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), hereby—

- (1) notifies that the Pressure Cookers shall be subject to inspection prior to export;
- (2) specifies the type of inspection in accordance with the export of Pressure Cookers (Inspection) Rules, 1983 as the type of inspection which would be applied to such Pressure Cookers prior to export;
- (3) recognises National and International Standards, and standards of other Bodies recognised by Export Inspection Council as the standard specifications for the Pressure Cookers; and
- (4) prohibits the export in the course of International Trade of Pressure Cookers unless the same is accompanied by a certificate issued by any one of the Agencies recognised or established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of Pressure Cookers satisfies the conditions relating to its inspection and is exportworthy.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of bona fide samples of the Pressure Cookers.

3. In this Order, "Pressure Cookers" means any pressure cooking vessel of capacity from 4 litres upto and including 22 litres for use with external heat sources capable of maintaining working steam pressure of 1.0 kgf/cm².

4. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 6(9)/81-LI&FP]

का० अं० 73.—केन्द्रीय सरकार, नियंत्रण (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्ननिचित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) सक्षिप्त नाम और प्रारम्भः—इन नियमों का सक्षिप्त नाम प्रेशर कुकर नियंत्रण (निरीक्षण) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:—इन नियमों में, जब तक कि मंदभ में अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) "अधिनियम" से नियंत्रण (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सुम्वई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से या मान्यता प्राप्त कोई संगठन अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "प्रेशर कुकर" से 4 लीटर से लेकर 22 लीटर तक की धारिता वाला ऐसा कोई दाब-पाक पाव अभिप्रेत है जिसका प्रयोग बाहरी उपमा से होता है जिसमें 1.0 किलोग्राम एफ/सेटीमीटर का

कार्यकरण दाब बनाये रखने की क्षमता होती है।

3. निरीक्षण का आधार नया प्रक्रिया—(1) नियंत्रण के लिये आगवित प्रेशर कुकर को निरीक्षण यह देखने के विचार में किया जायेगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियंत्रित देशों के अनुरूप है अर्थात् राष्ट्रीय और अनराष्ट्रीय मानक तथा नियंत्रित नियंत्रण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य नियंत्रण के मानक, प्रेशर कुकरों के लिये मानक नियंत्रित देशों के रूप में।

शा तो :

(क) यह मुनिश्चित करके कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दोनों नियम 3 के उप-नियम 2 (क) के मध्यीन उपावंध-1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण ट्रिलों का प्रयोग किया गया है।

(ख) नियम 3 के उप-नियम 2 (ख) के अनुसार किये गये निरीक्षण के आधार पर,

या

(ग) दोनों के द्वारा।

(2) प्रेशर कुकरों के निरीक्षण के लिये निरीक्षण की निम्नलिखित स्कीमों में से कोई एक स्कीम या दोनों स्कीमों अपनाई जायेगी, अर्थात्—

(क) प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण :—

(i) कोई भी विनिर्माण एकक जिसके पास उपावंध-1 के अनुसार प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है, अभिकरण के निकटसम वायलिय को आवेदन करेगा।

(ii) नियंत्रित निरीक्षण अभिकरण विनिर्माण एकक में जाने का प्रब्रथ करेगा तथा यह नियंत्रित करेगा कि उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण पद्धति सतोषजनक रूप के कार्य कर रही है।

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण.—

कोई भी विनिर्माण एकक खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करना तो वह अपने नियंत्रित किये जाने वाले परेषणों का किसी भी अभिकरण को निरीक्षण के लिये देगा जो यह मुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नियंत्रित देशों के अनुरूप है।

(3) निम्नलिखित प्रक्रिया प्रेशर कुकरों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिये अपनाई जायेगी, अर्थात्—

(i) प्रेशर कुकरों के नियंत्रित करने का इच्छुक कोई नियातकारी अपने ऐसा करने के आशय की सूचना

विवित स्पष्ट में देगा और उसी सुनता के समय एम नियंत्रित भौमिका नियंत्रित सरिदा भौमी भौमी नक्तीकी विनिर्देशों का विवरण देते हुए विनिर्देशों का घाषणा पत्र इसी भी अभिकरण का देगा जिससे यह उपनियम (2) के खड़ (क) या खड़ (ख) पा दोनों लंडों के अन्मान निर्णय कर सके।

- (ii) वह उसी समय सूचना की एवं प्रति नियोक्ता के लिये परिपद के कार्यान्वय देगा।
- (iii) उपनियम (2) के खड़ (क) के अनुमोदित एहसास व्यापार विनियोग उत्पादों के नियंत्रित एवं नियंत्रित उत्पादों के नियंत्रित एवं नियंत्रित उत्पादों के नियंत्रित आण्डिन एम भौमी सुचना के साथ यह भी घाषणा करेगा कि नियंत्रित के लिये आण्डिन प्रेशर कुकरों का विनियोग उपावध-1 में अधिकारित नामिटी नियवण का प्रयाग करके किया गया है और परेशण इस प्रयोजन के लिये अविनियम की घाग 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- (iv) खड़ (iii) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा विनियोग के परिमाण में परेशण के भेजे जाने से कम से कम 3 दिन पहले परिपद तथा अभिकरण के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये।
- (v) नियंत्रित अभिकरण का परेशण पर लगाये जाने वाले पहलान चिन्ह भी देगा।
- (vi) खड़ (ii) या खड़ (iii) के अधीन भौमी तथा घोषणा प्राप्त होते पर अभिकरण--
 - (क) उपनियम (2) के खड़ (क) के अधीन अनुमोदित एककों द्वारा विनियोग उत्पादों का नियंत्रित बोक्ता करने वाले नियंत्रित की दणा में अभूत यह समाधान कर लेने पर कि विनियोग की प्रक्रिया के दौरान एक न उपावध-1 के अधीन दिये गये पर्याप्त नामिटी नियवणों का प्रयाग किया है और उपावध में परिपद व्यापार जारी किये गये निदेशा, यदि कोई हो, का पालन किया है तो यह तीन दिन के भीतर यह घाषणा करने हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि प्रेशर कुकरों का परेशण नियंत्रित योग्य है। तथापि अभिकरण कालिक नियोक्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि विनियोग परिमाणों पर पर्याप्त नियश्वरणों का प्रयाग किया गया है तथा उत्पाद मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसृप्त है, और
 - (ख) उपनियम (2) के खड़ (ख) के अधीन आने वाले एककों द्वारा विनियोग उत्पादों

का नियंत्रित बने वाले नियंत्रित की इसे में प्रेशर कुकरों तो नियंत्रित यह सुनिश्चित भौमी व्यापार से उत्पाद उप विनियोग के लिये मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसृप्त है।

- (vii) (i) जब कभी अभिकरण द्वारा घोषा की जाये तो नियंत्रित की नियंत्रित प्रेशर गे ने प्रेशर कुकरों के नमूने विनियोग भौमी परेशण के लिये नियुक्त देगा। तथापि, ऐसे नमूने विनियोग करने के पासात् अभिकरण द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे।
- (ii) नियोग वी समाप्ति से पश्चात् अभिकरण परेशण में पैकेजों की इस रीति में 3 अन्दर पैक उत्पाद किया यह गुनियित होता जाये कि गुहरवद पैकों में हरतक्षेप नहीं किया जा सकता है।
- (iii) परेशण अस्वीकृत दो जाने की दणा में, यदि नियोक्ता गेगा चाहे तो अभिकरण परेशण वो महरवद नहीं होता।
- (iv) ऐसे मामला में, तथापि, नियंत्रित की अस्वीकृति के विश्व अर्थात् बरने का हक्कार नहीं होता।
- (v) यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि प्रेशर कुकरों का परेशण इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं का पूरा करना है तो वह नियोक्ता की समाप्ति के सात दिन के भीतर नियंत्रित की वह घोषणा करने हुए, प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेशण नियंत्रित योग्य है।
- परन्तु जहा अभिकरण का समाधान नहीं हो पाता है वह उक्त सात दिनों की उक्त अनुधि के भीतर उसके लिये रामण देते हुए अस्वीकृत-पत्र जारी करेगा।
- । मान्यता प्राप्त चिन्ह का चिपकाना और उसका प्रतिक्रिया--
- भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 वा 36) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955 के उपबध प्रेशर कुकरों पर नियंत्रित से पूर्व मान्यता प्राप्त चिन्ह प्रेशर कुकरों की प्रक्रिया के माध्यम से यथा संभव लाग होगे तथा दो त्रितीय चिन्ह, प्रेशर कुकरों की नियंत्रित अवीन कोई भी नियोक्ता नहीं किया जायेगा।
- 5 नियोक्ता का स्थान -इन नियमों के अधीन नियोक्ता विनियोग का या अन्य परिमाणों पर किया जायेगा जहा परीक्षण और नियोक्ता के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

6. निरीक्षण शुल्क नियतिकर्ता, अधिकरण को निरीक्षण कीम निम्न प्रकार देगा।

प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपये (बीम रुपये) के अधीन रहने हए।

- (1) अनुमोदित प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण एकको द्वारा नियति के लिए विनिर्मित और आशयित तथा नियम 3 के उप-नियम (1) (2) और (4) के आधार पर निरीक्षण करने के लिए बस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2% की दर से।
- (2) अनुमोदित प्रक्रियागत त्वालिटी नियंत्रण एकको द्वारा विनिर्मित और व्यापारी नियतिकर्ताओं द्वारा नियति के लिए आशयित तथा नियम 3 के उप-नियम (4) के आधार पर निरीक्षण के लिए विनिर्मित बस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.3% की दर से।
- (3) व्यापारी नियतिकर्ताओं द्वारा नियति के लिए आशयित तथा नियम 3 के उप-नियम (3) के आधार पर निरीक्षण के लिए विनिर्मित बस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4% की दर से।
- (4) गज्यों या मंध गज्य क्षेत्रों की संवधित सरकारों के पास लवु उत्तरांग विनिर्माण एककों के रूप में रजिस्ट्रीकूट विनिर्माताओं द्वारा नियति के लिए आशयित बस्तुओं और नियम 3 के उप-नियम (1), (2) परा (3) के आधार पर निरीक्षण करने के लिए आशयित बस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.18% तथा 0.36% की दर से।

7. अपील:

- (1) नियम 3 के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के इकार ने व्यक्ति उमके द्वारा ऐसे इकार की यूनन। प्राप्त होने के इस दिनों के भीतर कम में कम तीन व्यक्तियों के विशेषज्ञ पैनल को जो केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किया जा सके, अपील कर सकेगा।
- (2) विशेषज्ञ पैनल की कुल सदस्यां संख्या में से कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
- (3) पैनल की गणरूपति तीन में होंगी।
- (4) अपील, प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

उपांध-1

प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण :

नियति के लिए आशयित प्रेशर कुररों की क्वालिटी विनिर्माता द्वारा, उपांध-2 में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों

पर, विनिर्माण के विभिन्न प्रकारों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके निश्चिन की जाएगी।

- 1 क्रम की गयी सामग्री तथा संघटकों सह नियंत्रण।
- (क) विनिर्माता प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री या संघटकों की विशेषताओं तथा महायताओं सहित त्रिभूत विमाओं को समाविष्ट करने द्वारा, क्रम विनिर्देश अधिकरित करेगा।
- (ख) स्थीरत परेषणों के माथ या नो अथ विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संतुष्टि करने द्वारा उत्पादक का परीक्षण प्रमाणपत्र होगा या ऐसे परीक्षण प्रमाण-पत्र के न होने पर, क्रम विनिर्देशों से इसकी अनुलग्न की जांच करने के लिए प्रत्येक परेषण में से नमूनों की नियमित जांच की जाएगी। उत्पादक के परीक्षण प्रमाण-पत्र की शुद्धता भव्यापिन करने के लिए पांच परेषणों में से कम से कम एक पुनः जांच की जाएगी।
- (ग) आने वाले परेषणों का निरीक्षण और परीक्षण, मांखियकी नमूना योजना के अनुसार क्रम विनिर्देशों से अनुस्पन्दन सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
- (घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत और अस्वीकृत माल या संघटकों के पृथक्करण के लिए तथा अस्वीकृत माल या संघटकों के निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतिया अपनाई जाएगी।
- (ङ) उपरोक्त नियंत्रण के मंद्र में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप में रखा जाएगा।

प्रक्रिया नियंत्रण :

- (क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए द्वयोर्वार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकरित करेगा।
- (ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकरित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपस्कर या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।
- (ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा।

3. उत्पाद नियंत्रण :

- (क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिए विनिर्माता के पास या ता अपनी परीक्षण सुविधाधां होंगी या उमकी पहुच वहां तक होंगी जहां ऐसी सुविधाधां विद्यमान है। उमके लिए पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा।
- (ख) परीक्षण के लिए नमूना (जहां कहीं भी अपेक्षित हो) अभिलेखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(ग) प्रत्येक समुच्चय को जांच अधिकथित निरीक्षण जांच सूची के अनुसार की जाएगी।

4. माप-पद्धति नियंत्रण :

उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त गेजों तथा उपकरणों की कालिक जांच या उनका अनुसंशोधन किया जाएगा तथा अभिलेख, वृत्त कार्ड के रूप में रखे जाएंगे।

5. गरिमण नियंत्रण :

- (क) उत्पाद को योसमी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माता द्वारा व्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।
- (ख) उत्पाद भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी प्रकार से परिरक्षित रखा जाएगा।

6. पैकिंग नियंत्रण :

उपयुक्त उत्पाद की पैकिंग के लिए विनिर्देश अधिकथित किया जाएगा।

उपांत्ति 2

नियंत्रण के स्तर

| क्रम संख्यात्मक | निरीक्षण/परीक्षण की विशेषताएं | प्रयोक्ता | नमूना आकार | लॉट आकार |
|---|---|---|--------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. क्षय की गयी सामग्री और संषटक | | | | |
| (क) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी प्रयोजन के लिए मान्यता - और फिनिश सहित) | प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | प्रत्येक | — | — |
| (ख) सह्यताओं सहित विमाएं | | | | |
| (1) सबसे मुळ्य | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर निश्चित किया जाएगा | प्रत्येक लॉट | — |
| (2) अन्य | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | यथोक्त | प्रत्येक लॉट | — |
| (ग) अन्य कोई प्रयोक्ता | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | यथोक्त | प्रत्येक लॉट | — |
| 2. विनिर्मित संषटक तथा उप समुच्चय | | | | |
| (क) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी और फिनिश सहित) | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | प्रत्येक | — | — |
| (ख) सह्यताओं सहित विमाएं | | | | |
| (1) सबसे मुळ्य | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | अभिलेखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा। | प्रत्येक लॉट | — |
| (2) अन्य | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | अभिलेखित अन्वेषण के आधार यथोक्त पर निश्चित किया जाएगा। | प्रत्येक लॉट | — |
| 3. समुच्चय | | | | |
| (क) कारीगरी और फिनिश | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त | प्रत्येक | — | — |
| (ख) परीक्षण | मानक विनिर्देशों के अनुसार | | | |
| (1) अमत्ता परीक्षण | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | दो हुए कुकरों के लिए 50 कुकरों में से एक और पिट्ठा लोहे के कुकरों या इसके भाग के लिए प्रति 500 कुकरों में से एक | — | — |
| (2) बायु दाब परीक्षण | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | प्रत्येक | — | — |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|--|--|-------------------|
| | | (3) प्रूफ दाब परीक्षण | | |
| | (क) ढले हुए कुकरों के लिए (ख) कुकरों के लिए पिटवां लोहे के | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | (1) प्रति माह 2000 नगों कुल उत्पादन का 4% तक के उत्पादन के लिए (2) प्रति माह 2001 से 10,000 नगों तक के उत्पादन के लिए (3) प्रति माह 10,000 नगों कुल उत्पादन का 1% से अधिक उत्पादन के लिए | |
| | (4) दाब नियंत्रण युक्ति के निए प्रचालन परीक्षण | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | (क) प्रति माह 2000 नगों कुल उत्पादन का 10% तक के उत्पादन के लिए (ख) प्रति माह 2001 से 10,000 नगों तक के उत्पादन के लिए (ग) प्रति माह 10,000 नगों कुल उत्पादन का 2% से अधिक उत्पादन के लिए | |
| | (5) सरका दाब विभाजन यंत्र के लिए परीक्षण | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | | कुल उत्पादन का 1% |
| | (6) विस्फोट दाब परीक्षण | | | |
| | (क) ढले हुए कुकरों के लिए प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | | प्रति 100 कुकरों में से एक | |
| | (ख) कुकरों के लिए पिटवां लोहे के | | (1) प्रति माह 2000 नगों तक के उत्पादन के लिए प्रत्येक 500 कुकरों में से एक (2) प्रति माह 2001 नगों और 10,000 नगों तक के उत्पादन के लिए प्रत्येक 700 कुकरों में से एक (3) प्रति माह 10,000 नगों से अधिक उत्पादन के लिए प्रत्येक 1000 कुकरों में से एक | |
| | (7) दाब के अधीन (जहाँ कहीं लागू हो) ढक्कन को हटाने के लिए परीक्षण | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | प्रति 500 कुकरों में से एक | -- |
| | (8) स्प्रिग भारित सरचना के लिए परीक्षण (जहाँ कहीं लागू हो) | प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार | प्रति 100 कुकरों में से एक | -- |

S.O. 73.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (i) Short title and commencement.—These rules may be called the Export of Pressure Cookers (Inspection) Rules, 1983.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963);

(b) "Agency" means any of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras or any other organisation recognised by the Central Government under section 7 of the Act;

(c) "Pressure Cooker" means any pressure cooking vessel of capacity from 4 litres upto and including 22 litres for use with external heat sources capable of maintaining working steam pressure of 1.0 kgf/cm².

3. Basis and procedure of inspection.—(1) Inspection of Pressure Cookers intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act i.e. National and International Standards and standards of other bodies recognised by Export Inspection Council, as the standard specifications for the Pressure Cookers.

either

(a) by ensuring that during the process of manufacture the inprocess quality control drills as specified in Annexure-I, under sub-rule 2(a) of rule 3 have been exercised;

or

(b) on the basis of inspection carried out in accordance with sub-rule 2(b) of rule 3;

or

(c) by both.

(2) Any one or both of the following schemes of inspection shall be adopted for pressure cookers, namely:—

(a) Inprocess Quality Control:—

(i) Any manufacturing unit having adequate in process quality control as per Annexure I shall apply to the nearest office of the Agency.

(ii) Export Inspection Agency shall then arrange a visit to the manufacturing unit and assess as to whether an effective inprocess quality control system is operating satisfactorily.

(b) Consignment-wise inspection.—Any manufacturing unit not satisfying the requirements specified in clause (a) shall offer to any agency their export consignments for inspection which shall be done to ensure that the products manufactured by it conforms to the specifications recognised by Central Government under section 6 of the Act.

(3) The following procedure shall be followed for inspection and certification of pressure cookers, namely:—

(i) Any exporter intending to export pressure cookers shall give intimation in writing of his intention so to do and submit alongwith such intimation a declaration of the specifications giving details of all technical characteristics as stipulated in the Export contract relating to such export to any of the Agencies to enable it to carry out inspection in

accordance with clause (a) or clause (b) or both the clauses of sub-rule (2).

(ii) He shall at the same time endorse a copy of such intimation for inspection to the office of the Council.

(iii) For export of products manufactured by units approved under clause (a) of sub-rule (2) the exporter shall also submit alongwith such intimation a declaration that the pressure cookers intended for export has been manufactured by exercising quality control as laid down in Annexure I and the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised under section 6 of the Act for this purpose.

(iv) Every intimation and declaration under clause (iii) shall reach the office for the Agency and the Council not less than 3 days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(v) The exporter shall also furnish to the Agency the identification marks applied on the consignment.

(vi) On receipt of the intimation and declaration under clause (ii) or clause (iii), the Agency—

(a) in the case of an exporter exporting products manufactured by units approved under clause (a) of sub-rule (2) on satisfying itself that during the process of manufacture the unit has exercised adequate quality control as provided under Annexure I and followed the instructions, if any, issued by the Council in this regard, shall within three days issue a certificate declaring the consignment of pressure cookers as export worthy. However, the Agency shall ensure thorough periodic inspections that adequate controls are exercised at the manufacturing premises, and products conform to the recognised specification; and

(b) in case of exporter exporting products manufactured by units falling under clause (b) sub-rule (2) shall carry out inspection of pressure cookers with a view to ensuring that the product conforms to the specifications recognised for the purpose.

(vii) (a) The exporter shall supply free of charge for inspection and testing samples of pressure cookers from export consignment as and when required by the Agency. Such samples, however, shall be returned by the Agency after the inspection is done.

(b) After completion of inspection the Agency shall immediately seal packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(c) In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency.

(d) In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(viii) If the Agency is satisfied that the consignment of pressure cookers complies with the requirement under these rules it shall within seven days of completion of inspection issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is export-worthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days issue rejection letter communicating the reasons therefor.

4. Affixation of recognised mark and procedure therefor.—The provisions of the Indian Standard Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standard Institution (Certification Marks) Regulation, 1955,

shall, so far as may, apply in relation to the procedure of affixation of the recognised marks or seal on pressure cookers prior to export and pressure cookers so marked, shall not be subjected to any inspection under rule 3.

5. Place of Inspection.—Inspection under these rules shall be carried out at the manufacturer or other premises where adequate testing and inspection facilities are available.

6. Inspection fee.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under : subject to a minimum of Rs. 20 (Rupees Twenty only) per consignment :

- (i) at the rate of 0.2 per cent of fob value of goods manufactured and intended for export by approved in-process quality control units and for inspection on the basis of sub-rules (i), (ii) and (iv) respectively of rule 3 ;
- (ii) at the rate of 0.3 per cent of fob value of the goods manufactured by approved in-process quality control units and intended for export by merchant exporters and for inspection on the basis of sub-rule (iv) of rule 3 ;
- (iii) at the rate of 0.4 per cent of fob value of the goods intended for export by merchant exporters and for inspection on the basis of sub-rule (iii) of rule 3 .
- (iv) at the rate of 0.18 per cent and 0.36 per cent of f.o.b. value of the goods manufactured and intended for export by manufacturers registered as small scale manufacturing units with the concerned government of States or Union Territories and for inspection on the basis of sub-rules (i), (ii) and (iii) respectively of rule 3 .

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under rule 3 may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of Experts consisting of not less than three persons that may be constituted by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-thirds of non-official of the total membership of the panel of Experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE I

Inprocess Quality Control :

The quality of the pressure cookers intended for export shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, at the levels of control specified in Annexure-II.

1. Bought out materials and components control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of mate-

rials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

- (b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificate corroborating the requirements of the purchase specifications or in the absence of such test certificates, a samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counter-checked at least once in five consignments to verify the correctness.
- (c) The incoming consignments shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications, against statistical sampling plans.
- (d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and for disposal of rejected materials or components.
- (e) Adequate records in respect of the above mentioned control shall be systematically maintained.

2. Process Control :

- (a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacture.
- (b) Equipment or instruments facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process/specifications.
- (c) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls exercised during the process of manufacture.

3. Product Control :

- (a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specifications. Adequate records thereof shall be maintained.
- (b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.
- (c) Each and every assembly shall be checked against laid down inspection check list.

4. Metrological Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

5. Preservation Control :

- (a) A detailed specification shall be laid down by manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.
- (b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control.—A specification shall be laid down for packing the aforesaid products.

ANNEXURE II LEVELS OF CONTROL

| Sl. No. | Particulars of Inspection/Test | Requirement | Sample Size | Lot size |
|------------|--|---|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. (a) | Bought out materials and components As per standard specification Visual inspection (including workmanship and finish) | recognised for the purpose. | Each. | — |
| (b) | Dimensions with tolerances (i) Critical | As per standard specification recognised for the purpose. | To be fixed on the basis of recorded investigation. | Each lot. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|--|--|--|-----------|
| | (ii) Others | As per standard specification recognised for the purpose. | To be fixed on the basis of recorded investigation. | Each lot. |
| | (c) Any other requirement | As per standard specification recognised for the purpose. | To be fixed on the basis of recorded investigation. | Each lot. |
| 2. Manufactured components and sub-assembly | | | | |
| | (a) Visual inspection (including workmanship and finish) | As per standard specification recognised for the purpose. | Each | — |
| | (b) Dimensions with tolerances | | | |
| | (i) Critical | As per standard specification recognised for the purpose. | To be fixed on the basis of recorded investigation. | Each lot. |
| | (ii) Others | As per standard specification recognised for the purpose. | To be fixed on the basis of recorded investigation. | — |
| 3. Assembly | | | | |
| | (a) Workmanship and finish | As per standard specification recognised for the purpose. | Each. | — |
| | (b) Tests | | | |
| | (i) Capacity test | As per standard specification recognised for the purpose. | One in every 50 cookers for cast cookers and one in every 500 and part thereof for wrought cookers. | — |
| | (ii) Air Pressure Test | As per standard specification recognised for the purpose. | Each | — |
| | (iii) Proof Pressure Test | | | |
| | (a) for cast cookers | As per standard specification recognised for the purpose. | Each | — |
| | (b) for wrought cookers | As per standard specification recognised for the purpose. | (1) for production upto 2000 pcs. per month. 4 % of the total production. (2) For production between 2001 and 10000 pcs. per month. 2 % of the total production. (3) For production above 10000 pcs. per month. 1 % of the total production. | — |
| | (iv) Operating test for pressure regulating device. | As per standard specification recognised for the purpose. | (a) For production upto 2000 pcs. per month. 10% of the total production. (b) For production between 2001 and 10000 pcs' per month. 5% of the total production. (c) For production above 10000 pcs. per month. 2% of the total production. | — |
| | (v) Test for safety pressure relief device. | As per standard specification recognised for the purpose. | 1% of the total production. | — |
| | (vi) Bursting pressure test | | | |
| | (a) for cast cookers. | As per standard specification recognised for the purpose. | One in every 100 Cookers. *(1) For production upto 2000 pcs. per month. One in every 500 cookers. | — |
| | (b) for wrought cookers. | *As per standard specification recognised for the purpose. | (2) For production between 2001 pcs. and 10000 pcs. One in every 700 cookers. (3) For production above 10000 pcs. per month. One in every 1000 cookers. | — |
| | (vii) Test for removal of lid under pressure (wherever applicable) | As per standard specification recognised for the purpose. | One in every 500 cookers | — |
| | (viii) Test for spring loaded mechanism (wherever applicable). | As per standard specification recognised for the purpose. | One in every 100 cookers. | — |

का० आ० 74.—नियर्ति (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 3 के साथ पठित नियर्ति क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, 1 जानवरी, 1983 से एक वर्ष की अवधि के लिए श्री एस० अबिद हुसैन, अर्ड० ए० एस० वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), को नियर्ति नियंत्रण परिषद् के अधीन के रूप में तथा नियन्त्रित को सदस्यों के रूप में इतद्वारा नियुक्त करती है:—

1. निदेशक, निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण नियर्ति नियंत्रण परिषद्, नई दिल्ली—सदस्य सचिव।
 2. महानिदेशक, भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली।
 3. भारत सरकार के कृषि विभाग सलाहकार।
 4. महानिदेशक, वाणिज्यक जातगती तथा ग्रंकसंकलन, कलकत्ता।
 5. सचिव (तकनीकी विकास) उद्योग मंत्रालय।
 6. कु० रोमा मजूमदार, अल्प संचेतन, वाणिज्य मंत्रालय।
 7. अध्यक्ष, लघु उद्योग संघ फेडरेशन।
 8. अध्यक्ष, सुदूरी खाद्य नियान्ति संघ, कोवीत।
 9. अध्यक्ष, चमड़ी नियर्ति संवर्धन परिषद् मद्रास।
 10. अध्यक्ष, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन।
 11. विकास आयुक्त, लघु उद्योग।
 12. कार्यकारी निदेशक, इंजीनियरिंग नियर्ति संवर्धन परिषद्।
 13. माइटोडे प्र० लि० बंगलोर, (मद्रास, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम्)।
 14. मैसर्स डा० रमन सी० अमीन के डा० रमन सी० अमीन, वर्मई।
 15. महानिदेशक, नेशनल टेस्ट हाउस, कलकत्ता।
- [फा० नं० 3/94/75-ई० अर्ड० ए० ए० पी०]

सी. बी. कुररेती, निदेशक

S.O. 74.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri S. Abid Hussain, IAS Commerce Secretary, Ministry of Commerce (Department of Commerce) as Chairman and nominates the following as Members of the Export Inspection Council for a period of one year with effect from 1st January, 1983.

1. Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council, New Delhi—Member Secretary.
2. Director General of Indian Standards Institution, New Delhi.
3. Agricultural Marketing Advisor of the Government of India.

4. Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
5. Secretary (Technical Development) Ministry of Industry, New Delhi.
6. Km. Roma Mazumdar, Additional Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi.
7. President, Federation of Association of Small Industries.
8. President, Seafood Exporters Association, Cochin.
9. Chairman, Leather Export Promotion Council, Madras.
10. Chairman, Indian Jute Mills Association.
11. Development Commissioner, Small Scale Industries.
12. Executive Director, Engineering Export Promotion Council.
13. Mysodet Pvt. Ltd., Bangalore, (Madras, Vijayawada, Visakhapatnam).
14. Dr. Raman C. Amin of M/s Dr. Raman C. Amin Bombay.
15. Director General, National Test House, Calcutta.

[F. No. 3(94)/75 EI&EP]
C. B. KUKRETI, Jr. Director

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1982

का०आ० 75—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एजड्डारा श्री एन० रामादुराई को, जो हाल में नियंत्रक, लाइसेंसिंग के पद पर थे, 1 जून 1982 के पूर्वान्ह से नियमित आधार पर सचिव, चाय बोर्ड, के पद पर नियुक्त करती है।

[सं० के० 12013(1)/82-प्लांट (ए)]
पी०एस० रंधारा, अधर सचिव

New Delhi, the 6th November, 1982

"S.O. 75.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) the Central Government hereby appoints Shri N. Ramadurai, lately Controller of Licensing as Secretary, Tea Board on regular basis with effect from the forenoon of the 1st June, 1982.

[No. K-12013(1)/82-Plant. A]

P. S. RANDHAWA, Under Secy.

(दैश्वटाइल विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

का०आ० 76—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य श्री शिरोमणि शर्मा, विकास आयुक्त, हथकारघा को आंर आगे आदेश होने तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा०सं० 25012/11/82-रेशम]

(Department of Textiles)

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Shiromani Sharma, Development Commissioner for Handlooms a member of the Central Silk Board as Vice-Chairman of the Central Silk Board until further orders.

[F. No. 25012/11/82-Silk]

कांग्रेस 77.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (टैक्सटाइल विभाग) की अधिमूलन सं. कांग्रेस 2234, तारीख 24 अप्रैल, 1982 को निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम में,—

(1) मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

“1. श्री शिरोमणि शर्मा, अधिनियम की धारा विकास शायुक्त (हथकरघा), 4(3)(ख) के अधीन टैक्सटाइल विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत नामनिर्देशित।”; सरकार।

(2) मद 16 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

“16. रेख उत्पादन और रेशम बूनाई निदेशक, पश्चिमी बंगाल सरकार, 45, गणेश चन्द्र एवेन्यू, फलकला। 16क. श्री छोटे सी. जोगदार, भूपूर्व संसद् सदस्य, डा० मालदा-732101 जिला मालदा, (पश्चिमी बंगाल)।

अधिनियम की धारा 4(3)(च) के अधीन पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नामनिर्देशित।”

(3) मद 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

“30. कु० कल्पाणी चौधरी, उप-सचिव, टैक्सटाइल विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।

अधिनियम की धारा 4(3)(आ) के अधीन केन्द्रीय राजकार द्वारा नामनिर्देशित।”

[फा०सं. 25012/11/82-रेशम]

के० चौधरी, उप-सचिव

S.O. 77.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes, the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Deputyagent of Textiles) No. S. O. 2234, dated the 24th April, 1982, namely:—

In the said notification, —

(i) for item 1 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“1. Shri Shiromani Sharma; Nominated by the Development Commissioner Central Government (Handlooms), Department under section 4(3)(b) of Textile”, Ministry of Com. of the Act.”; mere, Government of India.

(ii) for item 16 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

| | |
|--|---|
| <p>“16. Director of Sericulture and Silk Weaving, Government of West Bengal, 45, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.</p> <p>16A. Shri D.C. Jordon, Esq.M.P., P.O. Mail 11-732101, District Mail 11, (West Bengal)</p> | <p>Nominated by the Government of West Bengal under section 4(3)(f) of the Act.”;</p> |
|--|---|

(iii) for item 30 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

“30. Km. Kalyani Chaudhuri, Nominated by the Deputy Secretary, Central Government Department of Textiles, under section 4(1)(j) Ministry of Commerce, of the Act.”; Government of India

[F. No. 25012/11/82-Silk]

K. CHAUDHURY, D.J. Secy.

(मुख्य-नियंत्रण, आवात-निर्वात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 14 दिसंबर, 1982

कांग्रेस 78-जनवरी आर० एस० राठोड़, 15 कुमारु हृदौर, मार्फत 56 ए पी पी को विकलांगों के लिये विशेष उत्करण युक्त एक मात्रू डीजल कार 1588 सी०सी० के आयत के लिये 65000 रुपये मूल्य का एक आवात लाइसेंस स० पी०/एफ०/2028719, दिनांक 5-9-81 प्रदान किया गया था।

2. आवेदक ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है फि मूल प्रति उनसे यो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा क्रितिमय नियवण प्रति किसी भी सीमांशुलक प्राधिकारी के पास पजीबत नहीं कराई गई थी अतः आयात लाइसेंस के मूल्य का विलक्षण भी उपर्योग नहीं हुआ है।

3. अपने नक्के के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने शपथ आयुक्त, दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि आयात

लाइसेंस सं० पी०/एफ०/2028719, दिनांक 5-9-81 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति आवेदक से खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है। समय-नमय पर यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(सी०सी०) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वेश्वी आर० एम० राठौड़ के नाम में जारी किये गये उपर्युक्त लाइसेंस सं० पी०/एफ०/2028719 दिनांक 5-9-81 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति श्री आर०/एस० राठौड़ को अनुग्रह से जारी की जा रही है।

[मि० सं० एफ०-48/81-82/बी०एल०एस०]
ज० पी० सिंघल, उप मुख्य-नियंत्रक,
आयात-नियंत्रित

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 14th December, 1982

S.O. 78.—Mr. R. S. Rathore, 15 Kumaon, Indore, C/o 56 APO was granted an Import Licence No. P/F/2028719 dated 5th September, 1981 for Rs. 65,000 only for the import of one Golf Diesel Car 1588 CC fitted with Special Equipment for disabled.

2. The applicant has applied for issue of a Duplicate copy of Exchange Control Copy of the above mentioned Import Licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the Licence has been lost. It has further been stated that the original Exchange control copy of the Licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of the Import Licence has not been utilised at all.

3. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit, duly sworn before the Oath Commissioner, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Copy of the Import Licence No. P/F/2028719 dated 5th September, 1981 has been lost or misplaced by the applicant. In exercise of powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import Control Order 1955 dated 7th December, 1955, as amended from time to time, the said original Exchange Control copy of Licence No. P/F/2028719 dated 5th September 1981 issued to Mr. R. S. Rathore is hereby cancelled.

4. A duplicate copy of the Exchange Control Copy of the Import Licence is being issued to Mr. R. S. Rathore separately.

[F. No. F-48/81-82/BLS]
J. P. SINGHAL, Dy. Chief Controller,
Imports & Exports.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा
नियंत्रित का कार्यालय)

मद्रास, 21 अगस्त, 1982

का० आ० 79.—सर्वेश्वी नवरत्न जैनरल प्राइवेट्स, नम्बर-139, एन० एस० सी० बीस रोड, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936064-सी०-एकसएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाण-पत्र करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाण-पत्र के अवास्तविकता के बारे में विष्वास करने

का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को अधिकतगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने अधिकतगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं हस्तात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी नवरत्न जैनरल प्राइवेट्स, नम्बर 139, एन० एस० सी० बीस रोड, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936064-सी०-एकसएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-1982 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या शीएफ-1203-एएम-82-एय०-3]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports.)

ORDER

Madras, the 21st August, 1982

S.O. 79.—M/s. Navarathan General Products, No. 139, N.S.C. Bose Road, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1936064/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936064/C/XX/82/M/81, dated 6-3-1982 issued to M/s. Navarathan General Products, No. 139, N.S.C. Bose Road, Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1203/AM. 82/AU. III]

का० आ० 80.—सर्वेश्वी संगवी स्टोर्स, नम्बर 14 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936061-सी०-एकसएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाण-पत्र करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाण-पत्र के अवास्तविकता के बारे में विष्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982

को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री संगवी स्टोर्स, नम्बर 14, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936061-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ-1195-एम-82-एयू 3]

S.O. 80.—M/s. Sangvi Stores, No. 14, Narayana Mudali Street, Madras-600001 were granted a licence No. PZ/1936061/C/XX/82/M/81, dated 6-3-1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 91(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. PZ/1936061/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 issued to M/s. Sangvi Stores, No. 14, Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1195/AM.82/AU.III]

का० आ० 81.—सर्वश्री राकेश एनटरप्राइज़स नम्बर 136, एन० एस० सी० बोस रोड, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936091-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राकेश एनटरप्राइज़स नम्बर 136, एन० एस० सी० बोस रोड, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च, 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936091-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ-1245-एम/82-एयू 3]

S.O. 81.—M/s. Rakesh Enterprises, No. 136, N.S.C Bose Road, Madras-600001 were granted a licence No. PZ/1936091/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 91(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. PZ/1936091/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982, issued to M/s. Rakesh Enterprises, No. 136, N.S.C. Bose Road, Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1245/AM.82/AU.III]

का० आ० 82.—सर्वश्री वीनस कारपोरेशन, नम्बर 64, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936002-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वीनस कारपोरेशन नम्बर 64 नारायण मुदली

स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936002-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद द्वारा रद्द करता है।

[संख्या : डीएफ-1106-एएम-82-एयु 3]

S.O. 82.—M/s Venus Corporation No. 64 Narayana Mudali Street Madras-600001 were granted a licence No. P[Z] 1936002[C]XX/82/M/81, dated 3-3-1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P[Z]1936002[C]XX/82/M/81, dt. 3-3-1982 issued to M/s. Venus Corporation 64 Narayana Mudali Street Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. FP. 1106/AM. 82/AU.III]

का. आ. 83.—सर्वश्री राजेश कापोरेशन, संख्या 57, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935855-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिलाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजेश कापोरेशन, संख्या 57, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935855-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-884-एएम 82-एयु 3]

S.O. 83.—M/s. Rajesh Corporation, No. 57, Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a Licence No P[Z] 1935855/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P[Z]1935855[C]XX/82/M/81 dt. 19-2-82 issued to M/s. Rajesh Corporation, No. 57, Narayana Mudali Street, Madras-600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/884/AM. 82/AU. III]

मद्रास, 2 सितम्बर, 1982

का. आ. 84.—सर्वश्री गौतम द्रेडस 77, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935857-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिलाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी न जाने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री गौतम द्रेडस, 77, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को अप्रैल-मार्च, 1982 अवधि के लिये रुपये 10,000 तक जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935857-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-1982 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-883-एएम-82-एयु 3]

Madras, 2nd September, 1982

S.O. 84.—M/s. Goutham Traders, 77, Narayana Mudali St., Madras-600001 were granted a licence No. P[Z]1935857/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935857/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Goutham Traders, 77 Narayana Mudali St., Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/883/AM. 82/AU. III]

का० धा० 85—सर्वथी महेश्वरी एजन्सीज, 135, एन० एस० सी० बी० बो० रोड़, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों के आयात करने के लिये आयात लाइसेंस मंख्या पी-इजट-1936007-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र ने श्रूत्वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अब आमले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वथी महेश्वरी एजन्सीज, 135, एन० एस० सी० बो० बो० रोड़, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936007-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1103-एएम-82-एय०-3]

S.O. 85.—M/s. Maheswari Agencies 135, M.S.C. Bose Road, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936007/C/XX/82/M/81, dated 3-2-82, for import of Dry fruits of Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Imports Licence No. P/Z/1936007/C/XX/82/M/81 dated 3-2-82 issued to M/s. Maheswari Agencies, 135, N.S.C. Bose Road Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1103/AM. 82/AU. III]

का० धा० 86—सर्वथी वी०जी० प्राविजन्स, संख्या-11, तनिकाचल मुदली स्ट्रोट, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रावान लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936003-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 को धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वथी वी०जी० प्राविजन्स, संख्या-11, तनिकाचल मुदली स्ट्रोट, मद्रास-21 को, अप्रैल-मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936003-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-32 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1107-एएम 82-एय०-3]

S.O. 86.—M/s. V. G. Provisions, No. 11, Thanigachala Mudali Street, Madras-21 were granted a licence No. P/Z/1936003/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936003/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 issued to M/s. V. G. Provisions, No. 11 Thanigachala Mudali Street, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1107/AM. 82/AU. III]

आवेदन

का० आ० 87.—सर्वश्री शांति एजेन्सी, 5/17, जेनरल कालन्स रोड़, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या इचट-1935996-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रभाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रभाणपत्र के अवस्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण वक्ताओं नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रभाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री शान्ति एजेन्सी, 5/17, जेनरल कालन्स रोड़, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इचट-1935996-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ-1076-एम-82-एयू 3]

S.O. 87.—M/s. Santhi Agency, 5/17, General Collensroad, Madras-600012, were granted a Licence No. P/Z/1935996[C/XX/82/M/81] dated 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Import (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935996/C/XX/82/M/81 dated 2-3-82 issued to M/s. Santhi Agency, 5/17, General Collers Road, Madras-600012, for import Dry Fruit for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/1076/AM. 82/AU. III]

का०आ० 88.—सर्वश्री वर्मा ट्रेडर्स, 92, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी इचट-1936065-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

1936059-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रभाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रभाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गला सनदी लेखापाल प्रभाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है श्रीर एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए सर्वश्री वर्मा ट्रेडर्स, 92, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 को प्रबंधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इचट-1936059-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ-1181-एम-82-एयू 3]

S.O. 88.—M/s. Varma Tradeis, 92 Narayana Mudali Street, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936059/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936059/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 issued to M/s. Varma Tradeis, 92 Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1181/AM. 82/AU. III]

का०आ० 89.—सर्वश्री रामदेव जेनरल स्टोर्स, 21, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी इचट-1936065-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व प्राप्त के प्रभाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया

है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सन्दर्भ लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री रामदेव जेनरल स्टोर्स, 21 नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि कर लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-डब्ल्यू 19°6065-सी-एक्सएक्स 82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1204-एम-82-एय३]

S.O. 89.—M/s. Ramadev General Stores, 21, Narayana Mudali Street, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936065/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Import (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936065/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Ramadev General Stores, 21, Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1204/AM. 82/AU. III]

कांग्रेस 90.—सर्वश्री नवीन जेनरल स्टोर्स, 49 पेरियार रोड़, पार्टी, मद्रास-50 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी इड-1936067-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सन्दर्भ लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सन्दर्भ लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सन्दर्भ लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री नवीन जेनरल स्टोर्स, 49, पेरियार रोड़, पार्टी मद्रास-50 को, अप्रैल मार्च 1982 की अवधि के लिए रु 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी इड-1936067-सी-एक्सएक्स 82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1202-एम 82-एय३]

S.O. 90.—M/s. Naveen General Stores, 49, Periar Road, Padi, Madras-50 were granted a Licence No. P/Z/1936067/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licencing holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936067/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Naveen General Stores, 49, Periar Road, Padi, Madras-50 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

. [F. No. DF/1202/AM. 82/AU. III]

कांग्रेस 91.—सर्वश्री भोइदी न स्टोर्स, 39 मेडल्स स्ट्रीट, बैप्पोरी, मद्रास-600007 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी इड-1935913-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सन्दर्भ लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सन्दर्भ लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोइदीन स्टोर्स, 39, मेड्रास स्ट्रीट, वेपरी, मद्रास-7 को, अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935913-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-951-एएम-82-एयू 3]

S.O. 91.—M/s. Moideen Stores, 39, Maddax Street, Vepery, Madras-600007 were granted a Licence No. P/Z/1935913/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935913/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 issued to M/s. Moideen Stores, 39, Maddax Street, Vepery, Madras-7 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/951/AM82/AU-III]

का० आ० 92.—सर्वको लक्ष्य स्टोर्स, 12, सुब्बराय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास -12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी- इजट-1936096-सी- एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताया कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सनुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री लक्ष्य स्टोर्स 12 सुब्बराय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी

किये गये लाइसेंस संख्या पी इजट-1936096-सी- एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ-1263-एएम-82-एयू 3]

S.O. 92.—M/s. Lucky Stores, 12 Subbaraya Chetty St., Madras-12 were granted a Licence No. P/Z/1936096/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936096/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Lucky Stores, 12 Subbaraya Chetty Street, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1263/AM. 82/AU. III]

का० आ० 93.—सर्वश्री धनलक्ष्मी स्टोर्स, 49, नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी- इजट-1936097-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया जारी किया गया था कि 25-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सनुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री धनलक्ष्मी स्टोर्स 49 नारायण मुदला स्ट्रीट मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी- इजट-1936087-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1246-एएम-82-एयू-3]

S.O. 93.—M/s. Dhannalakshmi Stores, 49, Narayanan Mudali Street, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936097/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936087/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Dhanalakshmi Stores, 49, Narayana Mudali St., Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DE/1246/AM. 82/AU. III]

का० आ० 94—सर्वश्री महेश कुमार प्राविजन स्टोर्स, 47, नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-600001 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी-इजट-1936009-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 को धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोहन कुमार प्राविजन स्टोर्स, 47, नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी-इजट-1936009-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1100-एएम-82-एयू-3]

S.O. 94.—M/s. Mahesh Kumar Provision Stores, 47, Narayana Mudali St., Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1936009/C/XX/82/81 dated 3-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not

genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936009/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 issued to M/s. Mahesh Kumar Provision Stores, 47, Narayana Mudali St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1100/AM. 82/AU. III]

का० आ० 95—सर्वश्री कृष्ण ट्रेडर्स, 18 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी-इजट-1936063-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किय गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा, 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कृष्ण ट्रेडर्स, 18 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी-इजट-1936063-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1196-एएम-82-एयू-3]

S.O. 95.—M/s. Krishna Traders, 18, Narayana Mudali St., Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936063/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied

that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/193603/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Krishna Traders, 18, Narayana Mudali St., Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1196/AM. '82/AU. III]

का० आ० 96.—सर्वश्री महिपाल एन्टरप्राइजेस, 22, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी-इजट 193608-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्थाविकाता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने भास्ते को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने की एक पश्चीम निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) अधिकारी, 1955 को धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री महिपाल एन्टरप्राइजेस, 22, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी-इजट 1936068-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1202 (ए)-एम-82-एयू 3]

S.O. 96.—M/s. Mahipal Enterprises, 22, Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1936068/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As, there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936068/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82, issued to M/s. Mahipal Enterprises, 22, Narayana Mudali, Street, Madras-1, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/1202(a)/AM. 82/AU. III]

का० आ० 97—सर्वश्री मूर्ति प्राविजन स्टोर्स, संख्या 1, पोन्नपन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आगामी लाईसेंस संख्या पी-इजट -1936110-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्थाविकाता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने भास्ते को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने की एक पश्चीम निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) अधिकारी, 1955 को धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मूर्ति प्राविजन स्टोर्स, संख्या-1, पोन्नपन स्ट्रीट मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी-इजट 1936110-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1260-एएम-82-एयू 3]

S.O. 97.—M/s. Moorthy Provision Stores, No. 1, Ponnappan Street Madras-12 were granted a licence No. P/Z/1936110/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936110/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Moorthy Provision Stores No. 1 Ponnappan Street Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. PF/1260/AM. 82/AU. III]

का० आ० 98.—सर्वश्री मदन ट्रेइर्स, 8, एडपालयम स्ट्रीट, मद्रास-600003 को रुपये 10000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी-इजट-1936037-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मदन ट्रेडर्स, 8, एडपालयम स्ट्रीट, मद्रास-600003 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936037-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्वारा रद्द करना हूँ।

[संख्या : डी एफ- 1174-ए एम 82-एयू 3]

S.O. 98.—M/s. Madan Traders, 8, Edapalayam Street, Madras-600003 were granted a licence No. P/Z/1936037/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936037/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 issued to M/s. Madan Traders, 8, Edapalayam Street, Madras-600003 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1174/AM. 82/AU. III]

का० आ० 99.—सर्वश्री पोनमणी मटोर्स, 43 टांक बांड रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935881-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री पोनमणी मटोर्स, 43, टांक बांड रोड, मद्रास-600012 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935881-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी-एफ-912-एम 82-एयू 3]

S.O. 99.—M/s. Ponmani Stores, No. 43, Tank Band Road, Madras-600002 were granted a Licence No. P/Z/1935881/C/XX/82/M/81, dt. 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935881/C/XX/82/M/81, dt. 22-2-82 issued to M/s. Ponmani Stores, No. 43, Tank Band Road, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/912/AM.82/AU.III]

का० आ० 100.—सर्वश्री जयलक्ष्मी मटोर्स 12, तुलसी नायबकल स्ट्रीट, मद्रास-600012 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935904-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जयलक्ष्मी स्टोर्स, 12, तुलसी नायककल स्ट्रीट मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935904-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी-एफ-935-एम-82-एयू 3]

S.O. 100.—M/s. Jayalakshmi Stores, 12, Thulasi Naicken Street, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/193-5904/C/XX/82/M/81, dated 24-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935904/C/XX/82/M/81 dated 24-2-82 issued to M/s. Jayalakshmi Stores, 12, Thulasi Naicken Street, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/935/AM.82/AU.III]

का० आ० 101:—सर्वश्री बैंकटरमण प्राविजन स्टोर्स, 52, संजीवरायन कोयिल स्ट्रीट, मद्रास-21 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935912-सी-एक्सएक्स-82-एम 81 दिनांक 25-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण वताओं नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेना हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री बैंकटरमण प्राविजन स्टोर्स, 52, संजीवरायन कोयिल स्ट्रीट, मद्रास-21 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935912-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी-एफ-949-एम-82-एयू 3]

S.O. 101.—M/s. Sri Venkataramana Provision Stores, 52, Sanjevarayan Koil Street, Madras-21 were granted a Licence No. P/Z/1935912/C/XX/82/M/81, dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935912/C/XX/82/M/81, dated 25-2-82 issued to M/s. Sri Venkataramana Provision Stores, 52, Sanjevarayan Koil Street, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/949/AM 82/AU.III]

का० आ० 102:—सर्वश्री रमेश एण्ड प्राविजन स्टोर्स, 38, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936058-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण वताओं नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेना हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रमेश एण्ड प्राविजन स्टोर्स, 38, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए

जारी किये गये नाइसेंस मध्या पो-इंजट-1936058-सी-एस-एस-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 का एन्ड्रायर रद्द करता है।

[संख्या डी एफ-1180-एम-82-एयू 3]

S.O. 102.—M/s Ramesh and Provision Stores, 38, Narayana Mudali Street Madras were granted a Licence No. P[Z] 1936058[C]XX|82|M|81, dt. 5-3-1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P[Z]1936058[C]XX|82|M|81, dt. 5-3-1982 issued to M/s Ramesh and Provision Stores 38, Narayana Mudali Street Madras for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF|1180|AM.82|AU.III]

का० आ० 103.—रवंशी लक्ष्मी प्राविजन स्टोर्स, 24, सेव्यपेक्षमान कोइल स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात बताने के लिए आयात नाइसेंस मध्या पी-इंजट-1936112-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त नाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास बताने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नाटिम जारी किया गया था कि 25-6-1982 का व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया नाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात ने संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त नाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा नाइसेंस ही रद्द करने की एकाधीन निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955, की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्रान्ति नाइसेंस प्राविजन रटोर्स, 24, सेव्यपेक्षमान कोइल स्ट्रीट, मद्रास-12 की अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये नाइसेंस मध्या पी-इंजट-1936112-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1267-एम-82-एयू 3]

S.O. 103.—M/s Lakshmi Provision Stores, 24, Solva Perumal Koil Street, Madras, 12 were granted a Licence No. P[Z] 1936112[C]XX|82|M|81, dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P[Z]1936112[C]XX|82|M|81, dated 6-3-82 issued to M/s Lakshmi Provision Stores, 24, Solva Perumal Koil Street, Madras, 12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF|1265|AM.82|AU.III]

का० आ० 104.—पर्वथी तगम स्टोर, 20, न्यू स्ट्रीट, ओट्टेरी, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात नाइसेंस संख्या पी-इंजट-1936119-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त नाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास बताने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नाटिम जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया था। लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त नाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा नाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के प्रत्यंत प्रदत्त प्रतिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्रान्ति नाइसेंस स्टोर, 20, न्यू स्ट्रीट, ओट्टेरी, मद्रास-600012 का प्रत्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये नाइसेंस संख्या पी-इंजट-1936119-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1267-एम-82-एयू 3]

S.O. 104.—Thangam Store, 20, New Street, Otteri, Madras-600012 were granted a Licence No. P[Z]1936119[C]XX|82|M|81, dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken

to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936119/C/XX/82/M/81, dated 6-3-82 issued to M/s. Thangam Stores, 20, New Street, Ottori, Madras-600 012, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1267/AM.82/AU.III]

का० था० 105.—सर्वश्री महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेज, 51, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस तंख्या पी-जे-1935917-सी-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणात्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणात्र के अवस्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नाटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 का अक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अबने मामले को साध करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेज, 51 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये लाइसेंस संख्या पी-जे-1936006-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1105-एम 82-एयू 3]

S.O. 105.—M/s. Mahalakshmi Enterprises, 51, Narayana Mudali Street, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1936006/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 25-6-1982. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936006/C/XX/82/

M/81 date 3-3-82 issued to M/s. Mahalakshmi Enterprises, 51, Narayana Mudali Street, Madras-600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1105/AM. 82/AU. III]

मद्रास, 15 अक्टूबर, 1982

का० था० 106.—सर्वश्री स्वामी एन्टरप्राइजेज, 184, सैडनामस रोड, मद्रास-600112 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जे-1935917-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवस्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नाटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री स्वामी एन्टरप्राइजेज, 184, सैडनामस रोड, मद्रास-600112 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जे-1935917-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-955-एम 82-एयू 3]

Madras, 15th October, 1982

S.O. 106.—M/s. Swamy Enterprises, 184, Sydenhams Road, Madras-600 112 were granted a Licence No. P/Z/1935917/C/XX/M/81 dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above Import Licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935917/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 issued to M/s. Swamy Enterprises, 184, Sydenhams Road, Madras-600 112 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/955/AM. 82/AU. III]

का० आ० 107.—सर्वश्री बालाजी प्राविजन स्टोर्स, संख्या 38, डी मेल्लोम रोड, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात नाइसेम संख्या पी-जे-ड-1935934-सी एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 29-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री बालाजी प्राविजन स्टोर्स, संख्या 38, डीमेल्लोस रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये नाइसेम संख्या पी-जे-ड-1935934-सी-एक्स-एक्स-82 एम-81 दिनांक 29-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी एफ-982-ए एम 82-एयू 3]

S.O. 107.—M/s. Balaji Provision Stores, No. 38, Demellos Road, Madras-12 were granted a Licence No P/Z/1935934/C/XX/M/81 dated 29-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1935934/C/XX/M/81 dated 29-2-82 issued to M/s. Balaji Provision Stores, No. 38, Demellos Road, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1983 period.

IF. No. DF/982/AM. 82/AU. III

का०आ० 108.—सर्वश्री अशोक ट्रेडर्स, 3, केशव ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600003 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात नाइसेम संख्या पी-जे-ड-1936053-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक पक्षीय निर्णय² लेता हूं।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री अशोक ट्रेडर्स, 3, केशव ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600003 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1936053-सी-एक्स-एक्स-82 एम-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी एफ-1178-ए एम 82-ए यू 3]

S.O. 108.—M/s. Ashok Traders, 3, Kesava Iyer Street, Madras-600 003 were granted a Licence No. P/Z/1936053/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1936053/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 issued to M/s. Ashok Traders, 3 Kesava Iyer Street, Madras-600 003, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

IF. No. DF/1178/AM. 82/AU. III

का०आ० 109.—सर्वश्री श्रीनीवासा स्टोर्स, संख्या 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात नाइसेम संख्या पी-जे-ड-1935895-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी

किया गया। लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की पांग पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्रीनीवासा स्टार्स, संख्या 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 का अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1935895-सी-एकम-एकम-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डीएफ/859/ए एम 82/ए पू 3]

S.O. 109.—M/s. Srinivasa Stores, No. 32, Kasi Chetty Street, Madras-600 001 were granted a licence No. P/Z/1935895/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by production a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935895/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 issued to M/s. Srinivasa Stores, No. 32, Kasi Chetty Street, Madras-600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[No. DF/859/AM. 82/AU. III]

का०आ० 110.—सर्वश्री नरेन्द्रा कार्पोरेशन, 14, तोलमिगम स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1935864-सी-एकस-82-एम-81 दिनांक 23-9-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उग प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस का रद्द करने की एकाज्ञा दिये जाते हैं।

किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नरेन्द्रा कार्पोरेशन, 14, तोलमिगम स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1935864-सी-एकस एकम-82-एम-81 दिनांक 23-9-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[मंदा० दो एफ-894-एन एम 82-ए पू 3]

S.O. 110.—M/s. Narendra Corporation, 14-Tholasingam Street, Madras-600 001, were granted a Licence No. P/Z/1935864/C/XX/82/M/81 dated 23-9-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935864/C/XX/82/M/81 dated 23-9-82 issued to M/s. Narendra Corporation, 14, Tholasingam Street, Madras-600 001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March 1982 period.

[F. No. DF/894/AM. 82/AU. III]

का०आ० 111.—सर्वश्री प्रकाशमल भारत कुमार, 73, नारायण मृदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1935687 सी-एकस-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा मूत्रपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 का व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले का स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस का रद्द करने की एकाज्ञा दिये जाते हैं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए,

सर्वश्री प्रकाशमल भारत कुमार, 73, नरायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मंख्या पर, जे-ड-1935867 सो-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 का एन्टद्वारा रद्द करता है।

[सं. डीएफ 895 एम-एम-82-एयू 3]

S.O. 111.—Prakashmal Kharat Kumar, 73, Narayana Mudali Street, Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935867/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935867/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Prakashmal Bharat Kumar, 73, Narayana Mudali Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March 1982 period.

[No. DF/895/AM. 82/AU. III]

कांगड़ा-112—सर्वश्री बांबे ट्रेडर्स 6 कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास 1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1936056 सो-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापात्र द्वारा भूतरूप आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवासन्विकास के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी में वह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी। कथा गत था कि 20-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारा किया गया लाइसेंस क्या न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न याने के कारण, इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापात्र प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एन्टद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेगा है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बांबे ट्रेडर्स, 6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-655551 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,055 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1636056-सो-एक्स-एक्स-82-ए-म-81 दिनांक 5-3-1982 का एन्टद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं. डीएफ-1177-एम-82-एयू 3]

S.O. 112.—M/s. Bombay Traders, 6, Kasi Chetty Street, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1936056/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936056/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 issued to M/s. Bombay Traders, 6, Kasi Chetty Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[No. DF/1177/AM. 82/AU. III]

कांगड़ा-113—सुरेन्द्र एन्टरप्राइजेस, 58, नरायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1935856-सो-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापात्र द्वारा भूतरूप आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवासन्विकास के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में एक पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 का अवक्तन-गत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारा किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अतः मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न ग्राने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापात्र प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एन्टद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक त्रिपुरारी निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सुरेन्द्र एन्टरप्राइजेस, 67, नरायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जे-ड-1935856-सो-एक्स-एक्स-82-ए-म-81 दिनांक 19-2-82 का एन्टद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं. डीएफ-891-एम-82-एयू]

S.O. 113.—M/s. Surendra Enterprises, 67, Narayana Mudali Street Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935856/C/XX/82/M/81 dt. 19-2-82 for import of dry fruits for Rs. 10000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to

cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82 As the Party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955 hereby cancel the import licence no. P/Z/1935875/C/XX/82/M/81 dt. 19-2-82 issued to M/s. Suiendra Enterprises 87 Narayana Mudali Street-Madras 600 001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/891/AM. 82/AU. III]

मद्रास, 3 नवम्बर, 1982

का०ग्रा० 1140—सर्वश्री मंजू सेल्स कारपोरेशन, संख्या- 11, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935875-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सुनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिवार्ड देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सुनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) भारत 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदर्शन अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री मंजू सेल्स कारपोरेशन, संख्या-11, कासी चेट्टी लेन, मद्रास 600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935875-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० झी एफ-913-एम 82-एय० 3]

Madras, the 3rd November, 1982

S.O. 114.—M/s. Manju Sales Corporation, No. 11, Kasi Chetty Lane, Madras. 1 were granted a licence No. P/Z/1935875/C/XX/M/81 dt. 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82 As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935875/C/XX/82/M/81 dt. 22-2-82 issued to M/s. Manju Sales Corporation, No. 11, Kasi Chetty Lane, Madras-600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/913/AM. 82/AU. III.]

का०ग्रा० 1150—सर्वश्री युनैटेड मेल्स कारपोरेशन, 32, स्ट्रॉटन मुथ्या मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935910-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सुनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिवार्ड देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सुनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) भारत 1955 की धारा 9(1) (ग) के अन्तर्गत प्रदर्शन अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री युनैटेड सेल्स कारपोरेशन, संख्या- 32, स्ट्रॉटन मुथ्या मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,005 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935910-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डीएफ/934/ए एम 82 एय० 3]

S.O. 115.—M/s. United Sales Corporation, 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1935910/C/XX/82/M/81 dated 24-2-82 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82 As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935910/C/XX/82/M/81 dt. 24-2-82 issued to M/s. United Sales Corporation No. 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras-1 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/934/AM. 82/AU. III.]

का०या० 116;—सर्वथी यमुना ट्रेडिंग कम्पनी 32 स्ट्रॉटन मुथया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को एप्रैल 10,000 रुपये का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस मंख्या पी-इजट-1935890-ती-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखाभाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-1982 को अधिकारी सुनवाई का शब्दार्थ देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इच्छा से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गत 1 जूनी लेखाभाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एवं द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लिया हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(a) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वथी यमुना ट्रेडिंग कम्पनी 32, स्ट्रॉटन मुथया मुदली स्ट्रीट मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए एप्रैल 10,000 रुपये का सूखे कलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस पी-इजट-1935890-ती-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 को एवं द्वारा रद्द करता हूँ।

[सं डी-एफ-9 27-एम-82-एयू 3]

S.O. 116.—M/s. Yamuna Trading Co., No. 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras-600001 were granted a licence No. PZ/1935935/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. PZ/1935935/C/XX/82/M/81 dt. 23-2-82 issued to M/s. Yamuna Trading Co., 32, strotten Muthia Mudali St., Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March'82 period.

[No. DF/927/AM. 82/AU. III]

का०या० 117;—सर्वथी अजंता ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या 24, रेडी रामन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को एप्रैल 10,000 रुपये कलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मंख्या पी-इजट-1935876-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 27-2-1982 जारी किया गया था।

1085 GI/82-16.

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखाभाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-1982 को अधिकारी सुनवाई का शब्दार्थ देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इच्छा से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गत 1 जूनी लेखाभाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एवं द्वारा लाइसेंस रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लिया हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 6(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वथी यमुना ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-34, रेडी रामन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए एप्रैल 10,000 रुपये कलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस सं. पी-इजट-1935935-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 27-2-82 को एवं द्वारा रद्द करता हूँ।

[सं डी-एफ-9 27-एम-82-एयू 3]

S.O. 117.—M/s. Ajantha Trading Co. No. 34, Reddy Raman St. Madras-600001, were granted a licence No. PZ/1935935/C/XX/82/M/81 dated 27-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import licensee has been obtained by fraudulent mean, and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. PZ/1935935/C/XX/82/M/81 dated 27-2-82 issued to M/s. Ajantha Trading Co., No. 34 Reddy Raman St., Madras, 600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 Period.

[No. DF/980/AM. 82/AU. III]

का०या० 118—सर्वथी जास्ती ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-4, तम्ब नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को एप्रैल 10,000 रुपये कलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मंख्या पी-इजट-1935876-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखाभाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को अधिकारी सुनवाई का शब्दार्थ देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले

को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जोती ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-4, तम्भ नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935876-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-914-एम 82-एयू 3]

S.O. 118.—M/s. Jothi Trading Co., No. 4, Thambu Naicken Street, Madras-600 001, were granted a Licence No. P/Z/1935876/C/XX/82/M/81 dt.—22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935876/C/XX/82/M/81 dt. 22-2-82 issued to M/s. Jothi Trading Co., No. 4, Thanbu Naicken Street, Madras-600 001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/914/AM. 82/AU. III.]

का०ग्रा० 119—सर्वश्री सरस्वती एम्पोरियम, 5, अयलूर मुल्तैया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-193586-S-सी-एक्सएक्स-81-एम-81 दिनांक 17 12 81 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सरस्वती एम्पोरियम, 5, अयलूर मुल्तैया मुदली

स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935686-सी-एक्सएक्स-81-एम-81 दिनांक 17-12-81 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-668-एएम/82-एयू 3]

S.O. 119.—M/s. Saraswathi Emporium, 5, Ayalur Muthiah Mudali Street, Madras—600 001 were granted a Licence No. P/Z/1935686/C/XX/81/M/81 dated 17-12-81 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As, the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935686/C/XX/81/M/81 dated 17-12-81 issued to M/s. Saraswathi Emporium, 5, Ayalur Muthiah Mudali Street, Madras—600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/668/AM/82/AU. III]

का०ग्रा० 120—सर्वश्री लालबाणी प्रोविजन ट्रेडर्स, 26, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी-इजट-1935833-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री लालबाणी प्रोविजन ट्रेडर्स, 26, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935833-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-846-एएम 82-एयू 3]

S.O. 120.—M/s. Lalwani Provision Traders, 26-Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935833/C/XX/82/M/81 dt. 16-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import Licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935833/C/XX/82/M/81-dt. 16-2-82 issued to M/s. Lalwani Provision Traders, 26, Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/846/AM. 82/AU. III.]

का०ग्रा० 121.—सर्वेशी पारमार प्राविजन स्टोर, 89, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935835-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस ध्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी पारमार प्राविजन स्टोर, 89, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935835-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-849-एम 82-एयू 3]

S.O. 121.—M/s. Parmar Provision Store, 89, Narayana Mudali St. Madras-1, were granted a licence No. P/Z/1935835/C/XX/82/M/81 dated 16-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the Party did not turn up for a personal Hearing

to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935835/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Parmar Provision Store 89, Narayana Mudali Street, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 Period.

[No. DF/849/AM. 82/AU. III.]

का०ग्रा० 122.—सर्वेशी यूनिवर्सल ट्रेडर्स, 20 कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935838-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त साइरेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने से पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस ध्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस दात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी यूनिवर्सल ट्रेडर्स, 20, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल—मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935838-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-853-एम-82-एयू 3]

S.O. 122.—M/s. Universal Traders, 20, Kasi Chetty St., Madras; 600001 were granted a Licence No. P/Z/1935838/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935838/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Universal Traders, 20, Kasi Chetty St., Madras, 1, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/853/AM. 82/AU. III]

का० आ० 123.—सर्वेशी रवीं ट्रेडर्स, 383, कोन्नूर हाई रोड, मद्रास-600012 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी० इजट-1935826-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 12-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण दत्तात्रो नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया था लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी रवीं ट्रेडर्स, 383, कोन्नूर हाई रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए, रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935826-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 12-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : शी एफ०-834-ए एम 82-ए यु 3]

S.O. 123.—M/s. Ravi Traders, 383, Konnur High Road, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935826/C/XX/82/M/81 dated 12-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935826/C/XX/82/M/81 dated 12-2-82 issued to M/s. Ravi Trade's 383, Konnur High Road, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/834/AM. 82/AU. III]

का० आ० 124.—सर्वेशी मंजू ट्रेडिंग कम्पनी, 25, आदियप्प नाइक्कन रट्टीट, मद्रास-600001 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट-1935687-सी-एक्सएक्स० 82-एम०-81 दिनांक 17-12-81 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण दत्तात्रो नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया था लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने के एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी मंजू ट्रेडिंग कम्पनी, 25, आदियप्प नाइक्कन रट्टीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935687-सी-एक्सएक्स० 82-एम०-81 दिनांक 17-12-81 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[मंजू : डो एक० 667-ए एम 82-ए यु 3]

S.O. 124.—M/s. Manju Trading Company 25, Audiappa Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935826/C/Z/1935687/C/XX/82/M/81 dated 17-12-81 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935687/C/XX/82/M/81 dated 17-12-81 issued to M/s. Manju Trading Co., 25, Audiappa Naicker St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 periods.

[No. DF/667/AM. 82/AU. III]

का० आ० 125.—सर्वेशी लक्ष्मी ट्रेडर्स, 25, वेस्ट कन्नमंडवम रोड, रायपुरम, मद्रास-600013 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट-1935789-सी-एक्सएक्स० 82-एम०-81 दिनांक 4-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से वह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदों लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों वा प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी श्री सद्मी देवर्स, 25, वेस्ट कलमांडपम रोड, रायपुरम, मद्रास 13 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पर्स-इजट-1935789 सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : श्री एफ० 798-ए एम 82-ए यु 3]

S.O. 125.—M/s. Shri Lakshmi Traders, 25, West Kalamandapam Road, Royapuram, Madras-600013, were granted a Licence No. P/Z/1935789/C/XX/82/M/81 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935789/C/XX/82/M/81 dt. 4-3-82 issued to M/s. Shri Lakshmi Traders, 25, West Kalamandapam, Road, Rayapuram, Madras-600013 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/798/AM.82/AU.III.]

का० श्रा० 126.—सर्वेश्वी रेनुका एड कम्पनी, 12, कासी चेट्टी स्टोर, मद्रास-600001 को वह रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935668-सी-एक्सएक्स-82-एम० 81 दिनांक 7-12-81 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से वह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदों लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदों लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी रेनुका एड कम्पनी, 12, कासी चेट्टी स्टोर, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935668-पी० एक्स० एक्स० 82-एम० 81 दिनांक 7-12-81 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

. [संख्या . श्री एफ० 658-ए एम 82-ए यु 3]

S.O. 126.—M/s. Renuka & Co., 12, Kasi Chetty Street Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935668/C/XX/81/M/81 dated 7-12-81 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means for April—March, 1982 period.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935688/C/XX/81/M/81 dated 7-12-81 issued to M/s. Renuka & Co., 12, Kasi Chetty Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 Period.

[No. DF/658/AM.82/AU.III]

का० का० 127.—सर्वेश्वी श्री जयलक्ष्मी स्टोर्स, संख्या-9 कृष्ण ऐपर स्टोर, मद्रास-1 को रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935891-सी० एक्स० एक्स० 82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के प्रवासत्रिता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से वह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई प्रत्यक्ष देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदों लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी श्री जयलक्ष्मी स्टोर्स, संख्या-9, क्रष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी०इजट० 1935891-सी० एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 23-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या: डी एफ-926-ए एम 82- एय० 3]

S.O. 127—M/s. Sree Jayalakshmi Stores, No. 9, Krishna Iyer St., Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1935891/C/XX/82/M/81, dated 23-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1935891/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 issue to M/s. Sree Jayalakshmi Stores No. 9, Krishna Iyer St., Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/926/AM.82/AU.III.]

का०आ० 128.—सर्वेश्वी गोल्डन ट्रेडर्स, 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०इजट०-1935840-सी० एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विवाद करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण वताओं नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को अविक्तगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मापदण्डों को स्पष्ट करने अविक्तगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी गोल्डन ट्रेडर्स, 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी०इजट० 193778-सी०एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 4-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

संख्या पी० इजट० 1935840-सी०एक्स-एक्स० 82-एम०-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ- 862-ए एम 82- ए य० 3]

S.O. 128.—M/s. Golden Traders, 322, Kasi Chetty Street, Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/1935840[C]XX/82/M/81 dt. 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935840[C]XX/82/M/81 dt. 17-2-82 issued to M/s. Golden Traders, 32, Kasi Chetty Street, Madras-600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[INo. DF/862/AM.82/AU.III]

का०आ० 129.—सर्वेश्वी विजया ट्रेडर्स, 37, एम०एस० कोइल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०इजट०-1935788-सी०एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 4-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त नाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण वताओं नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को अविक्तगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मापदण्डों को स्पष्ट करने अविक्तगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी विजया ट्रेडर्स, 37, एम०एस० कोइल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०इजट० 193778-सी०एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 4-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी०एफ०-802-ए०एम० 82-ए०य०३]

S.O. 129.—M/s. Vijaya Traders, 37, M. S. Koil Street, Royapuram, Madras-13 were granted a licence No. P/Z/1935788[C]XX|82|m|81 dt. 4-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports Control Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935788[C]XX|82|m|81 dt. 4-2-82 issued to M/s. Vijaya Traders, No. 37, M. S. Koil Street, Madras-13 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/802/AM.82/AU.III]

का० शा० 130.—सर्वश्री मनोज एन्टरप्राइज्यू, संख्या-7, तम्मू नाइकन रुटी, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए प्रायात लाइसेंस संख्या पी.इ.जे.टॉ. 1935909-सी.एक्स.एक्स. 82-एम. 81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिवार्ड हेने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को अक्षितगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस वर्षों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने अक्षितगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गवर्नर सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एन्टरप्राइज्यू को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मनोज एन्टरप्राइज्यू, संख्या-7, तम्मू नाइकन रुटी, मद्रास-600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.इ.जे.टॉ. 1935909-सी.एक्स.एक्स. 82-एम. 81 दिनांक 24-2-82 को एन्टरप्राइज्यू रद्द करता हूँ।

[संख्या डॉ. एफ०. 936-ए० एम० 82-ए० य०-3]

S.O. 130.—M/s. Manoj Enterprises, No 7 Thambu Naikon St., Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935909|C|XX|82|M|81 dated 24-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a

Personal Hearing on 15-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935909|C|XX|82|M|81 dated 24-2-82 issued to M/s. Manoj Enterprises, No. 7. Thambu Naik St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/936/AM.82/AU.III]

का० शा० 131.—सर्वश्री डाइमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-7-7, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.इ.जे.टॉ. 1935936-सी.एक्स.एक्स. 82-एम०-81 दिनांक 27-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिवार्ड हेने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को अक्षितगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस वर्षों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने अक्षितगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से मनुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एन्टरप्राइज्यू लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री डाइमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-7, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.इ.जे.टॉ. 1935936-सी.एक्स.एक्स. 82-एम०-81 दिनांक 27-2-82 को एन्टरप्राइज्यू रद्द करता हूँ।

[संख्या डॉ. एफ०. 936-ए० एम० 82-ए० य०-3]

S.O. 131.—M/s. Diamond Trading Co., No. 7, Kasi Chetty Lane, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935936|C|XX|82|m|81 dated 27-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935936|C|XX|82|m|81 dated 27-2-82 issued to M/s. Diamond Trading Co., No. 7, Kasi Chetty Lane, Madras for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. PF/986/AM.82/AU.III]

का० आ० 132.—सर्वश्री गुडविल एन्टरप्राइजेज, 9, कृष्ण एयर स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1935854-सी.एक्स एम्स-82-एम-81। दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस अयों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गुडविल एन्टरप्राइजेज, 9, कृष्ण एयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1935854-सी.एक्स एम्स. 82-एम. 81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संलग्न : डी० एफ०-889-ए० एम०-82-ए० य०-३]

S.O. 132.—M/s. Goodwill Enterprises, 9, Krishna Iyer Street, Madras-1, were granted a Licence No. P/Z/1935854 for C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935854/C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 issued M/s. Goodwill Enterprises, Madras-600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/889/AM.82/AU.III]

का० आ० 133.—सर्वश्री सैयमा मालिगै संख्या-12, डी मैलोस रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1936098-सी.एक्स एम्स. 82-एम. 81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस वर्षों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री सैयमा मालिगै, संख्या-12, डी मैलोस रोड, मद्रास-600012 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1936098-सी.एक्स एम्स. 82-एम. 81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संलग्न : डी० एफ०-1248/ए० एम० 82-ए० य०-३]

S.O. 133.—M/s. Syama Maligai, No. 12, Demelows Road, Madras-600012, were granted a Licence No. P/Z/1936093/C/XX/82/M/81, dt. 6-3-82 for Import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936093/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 issued to M/s. Syama Maligai, No. 12, Demelows Road, Madras-12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982, period.

[F. No. DF/1248/AM.82/AU.III]

मद्रास, 9 नवम्बर, 1982

का० आ० 134.—सर्वश्री रघुवीर एजेन्सीस, संख्या 3/14, काशी चैटी स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 193580-सी.एक्स एम्स. 82-एम. 81 दिनांक 5-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का

कारण दिखाई दें थे, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 वो उपर्युक्त मुनबाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनबाई ने लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री राधोर एजेंसीम, संख्या 3/11, कासी चौटी स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल—मार्च 1982 की प्रतिविधि द्वारा लिए रखे 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी विधे गये लाइसेंस संख्या पो-जेड-1935809-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डीएफ-805-एम-82-एय-3]

ORDER

Madras, the 9th November, 1982

S.O. 134.—M/s. Rathore Agencies, No. 3/14, Kasi Chetty St., Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1935809/C/XX/82/M/81, dated 5-2-82, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence was been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935809/C/XX/82/M/81 dated 5-2-82 issued to M/s. Rathore Agencies, No. 3/14, Kasi Chetty St., Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/805/AM.82/AU.III]

कांग्रेस 135—सर्वश्री बालाजी स्टोर, संख्या-2, गमनाइकन स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रखे 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पो-जेड-1935836-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में ये विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत मुनबाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारा रहना गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनबाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूं।

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनबाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बालाजी स्टोर, संख्या-2 रामनाइकन स्ट्रीट रायपुरम, मद्रास-13 को, अप्रैल—मार्च 1982 की प्रवधि के लिए रखे 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935836-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या: डीएफ-850-एम-82-एय-3]

S.O. 135—M/s. Balagi Store, No. 2, Ramanaicken Street, Royapuram, Madras-600013 were granted a Licence No. P/Z/1935836/C/XA/82/M/81 dated 16-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935836/C/XX/82/M/81 dt. 16-2-82 issued to M/s. Balaji store, No. 2, Ramanaicken street, Madras-13, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/850/AM.82/AU.III]

कांग्रेस 136—सर्वश्री बालमुरुगन मालिगै स्टोर, संख्या-5, केंद्र गोड, मद्रास-600012 को रखे 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पो-जेड-1935844-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में ये विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 हो व्यक्तिगत सुनबाई को अवसर देने के पश्चात् उनको जारा रहना गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनबाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदन अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री बालमृतम मलिगी स्टोर्स, मद्रास-5, को राम रोड, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मर्यादा पी-डब्ल्यू-1935884-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 का प्रतिवारा रद्द करता है।

[संख्या : डीएफ-897-एम-82-एम-3]

S.O. 136.—M/s. Balamurugan Maligai Stores, No. 5, K.H. Road, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935884/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1935884/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Balamurugan Maligai Store, No. 5, K. H. Road, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F No DF/897/AM 82/AU III]

का० घा० 137—सर्वश्री राजेश्वरी प्राविजनक स्टोर्स, संख्या-44, डी-मेल्लोम रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-डब्ल्यू-1935883-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस गलत लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अन्तर्भुक्तता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी ने यह पूछते हुए एक भारण बतायी नींटिम जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं हम बात से मतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत गलत लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस का रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदन अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री राजेश्वरी प्राविजनक स्टोर्स, 44, डी-मेल्लोम रोड, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 का अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए

जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-डब्ल्यू-1935883-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को प्रतिवारा रद्द करता है।

[संख्या : डीएफ-898-एम 82-एयू 3]

S.O. 137.—M/s. Rajeswari Provisions Stores, No. 44, Demellos Road, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935883/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine a Show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing No 29-10-82. As the party did not turn up for Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935883/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Rajeswari Provisions Stores, 44 Demellos Road, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period

[No. DF/898/AM-82/AU. III]

का० घा० 138.—सर्वश्री बाणी प्राविजनक 7 जी० ए० रोड, मद्रास 600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-डब्ल्यू-1935879-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्थिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी ने यह पूछते हुए एक भारण बतायी नींटिम जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया नाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं हम बात से मतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत गलत लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदन अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री बाणी प्राविजनक, 7, जी० ए० रोड, मद्रास-600021 को, अप्रैल-मार्च, 1982 का अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-डब्ल्यू-1935879-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को प्रतिवारा रद्द करता है।

[संख्या : डीएफ-905-एम 82-एयू 3] ।

S.O. 138.—M/s. Vani Provisions, 7 G.A. Road, Madras-600021 were granted a Licence No. P/Z/1935879/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935879/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Vani Provisions, 7, G.A. Road, Madras-600021 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/905/AM-82/AU. III]

का० आ० 139.—सर्वश्री तिरुमुरुगन प्राविजन स्टोर्स, 21, मन्त्रीयप्पा मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को रु 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मंख्या पी-इजट-1935880-मी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस ननदो लेखापाल द्वारा भूत्यूर्ब आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के प्रवासनिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में वह पछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवमर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने भासने को व्यष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गवन ननदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री तिरुमुरुगन प्राविजन स्टोर्स, 21, मन्त्रीयप्पा मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मंख्या पी-इजट-1935880-मी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 का एतद्वारा रद्द करता हूं।

[मंख्या : डीएफ-911-एम० 82-एय० 3]

S.O. 139.—M/s. Thirumurugan Provision Stores, 21, Sugthiappa Mudali St., Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935880/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was

not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935880/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Thirumurugan Provision Stores, 21, Sugthiappa Mudali Street, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[No. DF/911/AM 82/AU. III]

का० आ० 140.—सर्वश्री रूप ट्रेडिंग कम्पनी, 51, कुट्टितम्पिरान स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936106-मी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूत्यूर्ब आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पृष्ठे हुए एक सारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवमर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने भासने को व्यष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गवन ननदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रूप ट्रेडिंग कम्पनी, 51, कुट्टितम्पिरान स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मंख्या पी-इजट-1936106-मी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 का एतद्वारा रद्द करता हूं।

[मंख्या : डीएफ-1259-एम० 82-एय० 3]

S.O. 140.—M/s. Roop Trading Company, 51, Kuttuthiram St., Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1936106/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936106/C/XX/82[M]81 dated 6-3-82 issued to M/s Roop Trading Company, 51, Kuttithambitan St., Madras for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March 1982 period

[No. DF/1259/AM. 82/AU. III]

का० आ० 141.—सर्वश्री श्री कनगदुर्ग जेनरल स्टोर्स 16, नमासिवायम चेट्टी लेन, मद्रास-600021 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आदात लाइसेंस मख्या पी०-इजट-1935877-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करन की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री कनगदुर्ग जेनरल स्टोर्स 16 नमासिवायम चेट्टी लेन, मद्रास-21 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935877-सी०-एक्स एक्स-82-एम०-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[मख्या : डीएफ-910-एम 82-एम 3]

S.O. 141.—M/s. Sri Kanagadurga General Stores, 16, Namashivayam Chetty Lane, Madras-600021 were granted a Licence No. P/Z/1935877/C/XX/82[M]81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935877/C/XX/82[M]81 dated 22-2-82 issued to M/s. Sri Kanagadurga General Stores, 16, Namashivayam Chetty Lane, Madras 21 for import of dry fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/910/AM. 82/AU. III]

का० आ० 142.—सर्वश्री निमल ट्रेडिंग कम्पनी, सच्चा 27, स्ट्रॉटन मुथ्या मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 वा रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935878-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आधार के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस ब्याही न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नामदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करन की एक-पक्षीय निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री निमल ट्रेडिंग कम्पनी संख्या-27, स्ट्रॉटन मुथ्या मुदला स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935878-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता है।

[मख्या : डीएफ-909-एम 82/बाय० 3]

S.O. 142.—M/s. Nirmal Trading Co. No 27 Stroffen Mathia Mudali Street, Madras-600001 were granted a Licence No P/Z/1935878/C/XX/82[M]81 dated 22-2-82 for import of Div fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I was satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1935878/C/XX/82[M]81 dated 22-2-82 issued to M/s. Nirmal Trading Co. No. 27, Stroffen Mathia Mudali street, Madras 600001 for import of Dry fruit for Rs. 10,000 for April—March 1982 period

[No. DF/909/AM '82/AU. III]

का० आ० 143.—सर्वश्री श्री उमा जेनरल स्टोर्स, संख्या-68, जी० ए० रोड मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935885-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उर्ध्वक लाइसेंस पर्याप्त लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने गे, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से मंतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पर्याय निर्णय लेता हूं।

मैं, प्रायात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री उमा जेनरल स्टोर्स, संख्या-68, जी० ए० रोड, मद्रास-600021 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935885-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[मध्या : डीएफ-899-एम/82-एयु 3]

S.O. 143.—M/s. Sri Uma General Stores, No. 68, G.A. Road, Madras-600 021 were granted a Licence No P/Z/1935885/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935885/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Sri Uma General Stores, No. 68, G.A. Road Madras-600 021 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/899/AM. 82/AU. III]

का० आ० 144.—सर्वश्री मैर्कुरी ट्रेडर्स, संख्या-32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936102-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस भनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से मंतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मैर्कुरी ट्रेडर्स, संख्या-32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936102-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[मध्या : डीएफ/1269 / एम 82/एयु 3]

S.O. 144.—M/s. Mercury Traders, No. 32, Kasi Chetty St., Madras-600 001 were granted a Licence No. P/Z/1936102/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936102/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Mercury Traders, No. 32, Kasi Chetty St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1269/AM. 82/AU. III]

का० आ० 145.—सर्वश्री गायत्री प्रमोरियम, संख्या-41, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935779-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के

कारण, मैं इस बात से सतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी नेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एनद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गायत्री एम्पोरियम, मध्या-41, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-1 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि ले लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935779-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 को एनद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-788-एम-82-एयू 3]

S.O. 145.—M/s. Gayatri Emporium, No. 41, Kasi Chetty Lanc, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935779/C/XX/82/M/81, dt. 1-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past import; which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935779/C/XX/82/M/81 dt. 1-2-82, issued to M/s. Gayatri Emporium, No. 41, Kasi Chetty Lanc, Madras. 1, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982-period.

[F. No. DF/788/AM. 82/AU.III.]

कांग्रेस 145.—सर्वश्री बालाजी केमिकल्स, संख्या-6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935805-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी नेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नाटिन जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत मुनबाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनबाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी नेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एनद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए,

सर्वश्री बालाजी केमिकल्स, संख्या-6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935805-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 का एनद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ-806-एम 82-एयू 3]

S.O. 146.—M/s. Balaji Chemicals, No. 6, Kasi Chetty St, Madras. 600001 were granted a Licence No. P/Z/1935805/C/XX/82/M/81 dated 5-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935805/C/XX/82/M/81 dated 5-2-82 issued to M/s. Balaji Chemicals No. 6, Kasi Chetty St, Madras. 600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No : DF/806/AM. 82/AU. III.]

कांग्रेस 147.—सर्वश्री श्री रामा ट्रेडर्स, 15, नामसिवाय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935882-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी नेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नाटिन जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत मुनबाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनबाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी नेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एनद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री रामा ट्रेडर्स, 15 नामसिवाय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600021 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935882-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एनद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ-900-एम 82-एयू 3]

S.O. 147.—M/s. Sri Rama Traders 15, Namasivaya Chetty St Madras 600021 were granted a Licence No. P/Z/1935882/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935882/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Sri Rama Traders 15, Namasivaya Chetty St., Madras, 600021 for import of Dry Fruits for Rs 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/900/AM. 82/AU. III.]

मद्रास, 15 अक्टूबर, 1982

कांगड़ा 148.—सर्वश्री स्वस्टीक ट्रेडिंग कम्पनी मंड्या 32 स्ट्राटन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मंड्या पी-इजट-1935839-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस करने लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवाक्षिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ तो टिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने का कारण में इस बात से मतुपुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लिता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री स्वस्टीक ट्रेडिंग कम्पनी, मंड्या-32, स्ट्राटन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल—मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस सख्ता पी-इजट-1935852-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[स० डॉ एफ-855-एम 82-एयू-3]

Madras, the 15th November, 1982

S.O. 148.—M/s. Swastik Trading Co., No. 32, Strotten Muthia Mudali Street, Madras-600091 were granted a licence No. P/Z/1935839/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was

not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935839/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Swastik Trading Co., 32, Strotten Muthia Mudali Street, Madras-600091 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/855/AM. 82/AU. III.]

कांगड़ा 149.—149 सर्वश्री वर्दमान ट्रेडर्स, 37, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी-इजट-1935852-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवाक्षिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ तो टिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लिता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वर्दमान ट्रेडर्स, 37, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 को अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935852-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[स० डॉ एफ-874-एम 82-एयू-3]

S.O. 149.—M/s. Vardhman Traders, 37, Narayana Mudali Street, Madras, 600091 were granted a license No. P/Z/1935852/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby

cancel the import licence No. P/Z/1935852/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 issued to M/s. Vardhman Traders, 37, Narayana Mudali Street, Madras, 600 001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/874/AM. 82/AU. III]

का०आ० 150.—सर्वश्री सुरेश ट्रेडर्स, 11, कासी चेटी स्ट्रीट, मद्रास 600001 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936046-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अधास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से मंतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सुरेश ट्रेडर्स, 11, कासी चेटी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936046-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डॉ एफ-1173-एम 82-एय० 3]

S.O. 150.—M/s. Suresh Traders, 11 Kasi Chetty St., Madras-600 001 were granted a Licence No. P/Z/1936046/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1982, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936046/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 issued to M/s. Suresh Traders, 11 Kasi Chetty Street, Madras—600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1173/AM. 82/AU. III]

का०आ० 151.—सर्वश्री नारेश्वरा प्राविजन्स, संख्या-29, ठुलसी नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936044-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस भनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवापनिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नारेश्वरा प्राविजन्स, संख्या-29, ठुलसी नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936044-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डॉ एफ-1170-एम 82-एय० 3]

S.O. 151.—M/s. Nageshwara Provisions, No. 29, Thulasi Naicker Street, Madras-12, were granted a Licence No. P/Z/1936044/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1982, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936044/C/XX/82/M/81, dated 4th March, 1982 issued to M/s. Nageshwara Provisions, No. 29-Thulasi Naicker Street, Madras-12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/1170/AM. 82/AU.III]

का०आ० 152.—सर्वश्री रामराम ट्रेडर्स, 19, थाना स्ट्रीट ब्रेपेरी, मद्रास-7 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935900-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 21-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रोसरी ट्रेडर्स 19, थाना स्ट्रीट, वेपरेरी, मद्रास-7 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935900-सी-एक्स-82-एम-81 दिनांक 21-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या ई-एफ-944-एम 82-एयू 3]

S.O. 152.—M/s. Rosary Traders, 19, Thana Street, Vepery, Madras-7, were granted a Licence No. P/Z/1935900/C/XX/82/M/81 dated 21st February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935900/C/XX/82/M/81 dated 21st February, 1982 issued to M/s. Rosary Traders, No. 19, Thana Street, Vepery, Madras-7 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/944/AM. 82/AU.III]

का०प्रा० 153.—सर्वश्री कमलेश ट्रेडर्स, संख्या-4, तोलसिंगम स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935868-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कमलेश ट्रेडर्स, संख्या-4, तोलसिंगम स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935868-सी एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या ई-एफ-896-एम 82-एयू 3]

S.O. 153.—M/s. Kamlesh Traders No. 4, Tholasingam street, Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935868/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 23rd September, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935868/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 issued to M/s. Kamlesh Traders No. 4, Tholasingam Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/896/AM. 82/AU. III]

का०प्रा० 154.—सर्वश्री कोटी स्टोर्स 34/2, ई मेल्लोस रोड, मद्रास-12 को -रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935902-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार

पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कोटी स्टोर्स, 34/2, डी गेल्लोस रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935902-सी-एस एक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-945-एम 82-एयू 3]

S.O. 154.—M/s. Koti Stores, 34/2, Demelows Road, Madras-12 were granted a licence No P/Z/1935902/C/XX/82/M/81 dated 24th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935902/C/XX/82/M/81 dated 24th February, 1982 issued to M/s. Koti Stores, 34/2, Demelows Road Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/945/AM. 82/AU.III]

का० आ० 155.—सर्वश्री नाडार मालीगी, 25, पेरिय नम्बरी मुदली स्ट्रीट, मद्रास-7 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट-1935888-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण शिवाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नौंचिन जारी किया गया था कि 22-7-82 को अधिकारित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपनी मामले को स्पष्ट करने अधिकारित सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं हम बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नाडार मालीगी, 25, पेरिय नम्बरी मुदली स्ट्रीट, मद्रास-7 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रूपये

10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1934888-सी एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-7-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-922-ए एम 82-एयू 3]

S.O. 155.—M/s. Nadar Maligai, 25, Peria Thambi Mudali St., Madras-7, were granted a Licence No. P/Z/1935888/C/XX/82/M/81 dated 23rd February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935888/C/XX/82/M/81 dated 22nd July, 1982 issued to M/s. Nadar Maligai, 25, Peria Thambi Mudali St., Madras-7 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/922/AM. 82/AU.III]

का० आ० 156.—सर्वश्री मुथा जेनरल ट्रेडर्स, संख्या 3, तम्बू नाड कॉन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट-1935837-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मानदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिवाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नौंचिन जारी किया गया था कि 24-9-82 को अधिकारित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले का स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं हम बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मुथा जेनरल ट्रेडर्स, मुथा-3, तम्बू नाड कॉन स्ट्रीट, मद्रास 600001 को अप्रैल, मार्च, 1982 को अद्वितीय के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935837-सी०-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-854-ए०एम० 82-एय० 3]

S.O. 156.—M/s. Mutha General Traders, No. 3, Thambu Naicken Street, Madras-60001 were granted a Licence No. P/Z/1935837/C/XX/82/M/81, dated 17th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24th September, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935837/C/XX/82/M/81 dated 17th February, 1982 issued to M/s. Mutha General Traders No. 3, Thambu Naicken Street, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. 854/AM. 82/AU.III]

का० आ० 157.—सर्वश्री श्रुणा ट्रेडर्स, 18 मुब्बराय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936054-सो०-एक्स०-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को अक्षितगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने अक्षितगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री श्रुणा ट्रेडर्स, 18, मुब्बराय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936054-सो०-एक्स०-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डॉ० एक०-1176-ए० एम०-82-एय० 3]

S.O. 157.—M/s. Aruna Traders 18, Subbaraya Chetty St., Madras-600012, were granted a licence No. P/Z/1936054/C/XX/82/M/81 dated 5th March 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Account-

tant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20th September, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936054/C/XX/82/M/81, dated 5th March, 1982 issued to M/s. Aruna Traders, 18, Subbaraya Chetty St., Madras-600012 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1176/AM. 82/AU.III]

का० आ० 158.—सर्वश्री जया मुरुगन स्टोर्स, 46, एम० एस० कोइल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936048 सो०-एक्स०-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को अक्षितगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने अक्षितगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जया मुरुगन स्टोर्स, 46, एम० एस० कोइल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936048-सो०-एक्स०-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 को रद्द करता हूं।

[संख्या डॉ० एक०-1183-ए० एम० 82-एय० 3]

S.O. 158.—M/s. Jaya Murugan Stores, 46, M.S. Koil St., Royapuram, Madras-13, were granted a Licence No. P/Z/1936048/C/XX/82/M/81, dated 5th March, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936048/C/XX/82/M/81 dated 5th March, 1982 issued to M/s. Jaya Muugan Stores, 46, M. S. Koil St., Royapuram, Madras-13, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1183/AM. 82/AU.III]

का० आ० 159.—मर्कशी तामन स्टोर, 2, न्यू
स्ट्रीट, ग्रीटिंग्स, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक
सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या
षी०-इजट-1936072-स००-एक्य० एक्य०-82-एम०-81 दिनाक
6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रभाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रभाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिनार्थ देने से, पाटो से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवलम्बन देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अब ने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न श्रान्ति के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रभाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, ग्राम्यात (नियंत्रण) आवेदन 1955 की धारा 9(1)
 (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्रो
 तामस स्टोर, 2, न्यू स्ट्रोट, भट्टाचार्य-12 को अप्रैल-मार्च, 1982
 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सुखे फलों का ग्राम्यात
 करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इटट
 1936072-सी०-एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82
 को एतद्वारा रद्द करता हू।

[सख्या छौं एफ०-1196-ए० एम० 82-एप्य० 3]

S.O. 159.—M/s. Thomas Stores 2, New Street, Otteri, Madras-600012, were granted a licence No. P/Z/1936072/C/XX/82/M/81, dated 11 March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20th September, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936072/C/XX/82[M]81, dated 6th March, 1982 issued to M/s. Thomas Store, 2, New Street, Madras-12, for import of dry fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

का० आ० 160.—सर्वश्री मोडी ट्रेडर्स, संख्या-11,
कासो चैट्टी स्ट्रीट, मद्रास,-600001 को रुपये 10,000
तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आवाज लाइसेन्स
संख्या पो०-इजट-1936070-सी०-एकम० एकम०-82 एम०-81
दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूत्पूर्व प्राप्ति के प्रमाणपत्र जारी करने के अधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्थितिकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नेटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अन्त मासने को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत रूपों लेखापाल प्रमाणपत्र के अधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेगा 1955 को धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रधिकारां का प्रयोग करने हुए, सर्वश्रोतों मेंडी ट्रैडस, संख्या-11, कासो चेट्री स्ट्रोट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए सुखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इंजट-1936070-स००-एक्स०० एक्स००-82-एम००-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता है।

[संख्या छौ० एफ०-1191-ए० एम० 82-एय० 3]

S.O. 160.—M/s. Modi Traders No. 11, Kasi Chetty Street, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1936070/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of dry fruits for Rs. 10,0005.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936070/C/XX/82|M|81 dated 6-3-82 issued to M/s. Modi Traders No. 11, Kasi Chetty Street Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000/- for April--March, 1982 period.

[No. DF/1196/AM, 82/AU. III]

का० आ० 161.—सर्वश्री राजा राजेश्वरी जेनरल मर्चेन्ट्स, 39/1, डीमेलोम रोड, मद्रास-600112 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936121-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाण-पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाण-पत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एदूरा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजा राजेश्वरी जेनरल मर्चेन्ट्स, 39/1, डीमेलोम रोड, मद्रास-600112 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936121-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डी० एफ०-1241-ए० एम० 82-ए० य० 3]

S.O. 161.—M/s. Raja Rajeswari General Merchant, 39/1 Demelows Road, Madras-600112 were granted a Licence No. P/Z/1936121/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the Party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936121/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Raja Rajeswari General Merchants 39/1 Demelows Road, Madras-600112 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1241/AM. 82/AU. III]

का० आ० 162.—सर्वश्री नाडार एण्ड कम्पनी, 74, रामस्वामी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936111-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एहमकीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नाडार एण्ड कम्पनी, 74, रामस्वामी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936 111-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डी० एफ०-1249-ए० एम० 82/ए० य० 3]

S.O. 162.—M/s. Nadar & Co., 74, Ramaswamy Street, Madras-600012 were granted a licence No. P/Z/1936111/C/XX/82/M/81, dated 6-3-1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936111/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Nadar & Co., 74, Ramaswamy St., Madras-600012 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1249/AM. 82/AU. III]

का० आ० 163.—सर्वश्री मूनस्टार एन्टरप्राइजेस, 11, तिरुवेङ्गइस्वामी स्ट्रीट, पुलियांतोप, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936108-सी०-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट

करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मूनस्टार एटरप्राइज़, 11, तिरुवेंडवामी स्ट्रीट, पुलियांतोप, मद्रास-600 012 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी० इजट-1936073-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1252-एम 82-एय०३]

S.O. 163.—M/s. Moonstar Enterprises, 11 Thiruvengadaswamy Street Pulianthope, Madras-600012 were granted a licence No. P/Z/1936108/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936108/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Moonstar Enterprises 11, Thiruvengadaswamy Street Pulianthope Madras-600012 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1252/AM. 82/AU. III]

का० आ० 164:—सर्वश्री ऐवणा स्टोर्स, संख्या-26, न्यू स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936-073-सी-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण विखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। आने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री ऐवणा

स्टोर्स, संख्या 26, न्यू स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गये लाइसेंस पी० इजट-1936073-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1186-एम 82-एय०३]

S.O. 164.—M/s. Sri Iyappa Stores, No. 26, New Street, Madras-600012 were granted a licence No. P/Z/1936073/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936073/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Iyappa Stores, 26 New Street, Madras-600012 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1186/AM '82/AU. III]

का० आ० 165 :—सर्वश्री निनोद सेल्स सेन्टर, संख्या-१, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935841-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण विखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। आने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री निनोद सेल्स सेन्टर, संख्या-१, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935841-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-856-ए एम 82-एय०३]

S.O. 165.—M/s. Vinod Sales Centre, No 9, Krishna Iyer Street, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935841/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Account-

tant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby Cancel the Import licence No. P/Z/1935841/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Vinod Sales Centre, No. 9 Krishna Iyer Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/856/AM. 82/AU. III]

का. आ. 163 :—सर्वश्री बीनस ट्रेडर्स, संख्या-4, तम्बु नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935842-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखानाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-1982 को व्यक्तिगत सन्नाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस वर्षों न रद्द कर दिया जाए। आने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सन्नाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत रानवी लेखानाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) अदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बीनस ट्रेडर्स, संख्या-4, तम्बु नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को श्रीन-मार्ज, 1982 की अवधि के निए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935842-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-857-एएग 82-एयू 3]

S.O. 166.—M/s. Venus Traders, No. 4, Thambu Naicken Street, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935842/C/XX/82/M/81, dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1935842/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Venus Traders, 4, Thambu Naicken street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/857/AM 82/AU. III]

का. आ. 167 :—सर्वश्री पापूलर ट्रेडर्स, संख्या-7, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों

का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935860-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखानाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-1982 को व्यक्तिगत सन्नाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस वर्षों न रद्द कर दिया जाए। आने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सन्नाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखानाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) अदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री पापूलर ट्रेडर्स, संख्या-7, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, क्रीता-मार्ज, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935860-सी-एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-857-एएग 82-एयू 3]

S.O. 167.—M/s. Popular Traders, No. 7, Kasi Chetty Lane, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935860/C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935860/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Popular Traders, No. 7, Kasi Chetty Lane Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April, March, 1982 period.

[No. DF/857/AM 82/AU. III]

का. आ. 168 :—सर्वश्री महेन्द्रा एजेन्सी, 27, नारायण मन्दीर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935851-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखानाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-1982 को व्यक्तिगत सन्नाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस वर्षों में रद्द कर दिया जाए। आने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सन्नाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखानाल

प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री महेन्द्रा एजेन्सीज, 27, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 की अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936851-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-867-एम 82-एम 3]

S.O. 168.—M/s. Mahendra Agencies, 27-Narayana Mudali street, Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/193585/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1935851/C/XX/82/M/81 dt. 18-2-82 issued to M/s. Mahendra Agencies, 27-Narayan Mudali street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/857/AM. 82/AU. III.]

का. आ. 169 :—सर्वश्री ए. के. एस. प्रोविजन्स, संख्या 1, जमालिया ग्राउन्ड, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936010-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखपाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ जारी किया गया था कि 30-7-1982 को अवधिकारी का अवधिकार देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस वर्धों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखपाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री ए. के. एस. प्रोविजन्स, संख्या-1, जमालिया ग्राउन्ड, मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936010-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-115-एम 82-एम 3]

जी. सी. फरनन्डज, उप-मुख्य नियंत्रक,
आयात तथा निर्णय

S.O. 169.—M/s. A K S Provisions, No. 1, Jamalia ground, Madras 12 were granted a Licence No. P/Z/1936010/C/XX/82/M/81, dt 3-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import Licence has been obtained by Producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936010/C/XX/82/M/81, dt. 3-3-82 issued to M/s. A. K. S. Provisions, No. 1 Jamalia ground, Madras 12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F. No. DF/115/AM. 82/AU. III]
C. G. FERNANDEZ, Dy. Chief Controller,
Imports and Exports

का. आ. 170.—सर्वश्री प्रभु जेनरल मर्चन्ट्स, 32/2, टी० के० मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600007 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936092-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखपाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ जारी किया गया था कि 20-8-82 को अवधिकारी सुनवाई का अवमर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं उस बात में संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखपाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री प्रभु जेनरल मर्चन्ट्स, 32/2, टी० के० मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600007 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936092-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1244-एम 82-एम 3]

S.O. 170.—M/s. Prabhu General Merchants 32/2, T.K. Mudali Street Madras-600007 were granted a licence No. P/Z/1936092/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-8-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the import (control) order, 1955 hereby cancel the import licence No P/Z/1936092/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 issued to M/s Prabhu General Merchants, 32/2 T. K. Mudali Street, Madras-600007 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1244/AM/82/AU. III]

का० आ० 171 :—सर्वश्री वो० एम० स्टोर, 27, वेस्ट कलमण्डलम रोड, रायपुरम, मद्रास-13 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936101-मी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से वह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्होंने जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बारे से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया लाइसेंस गलत रानदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एन्ड्रेड्रायर नाइर्स को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वो० एम० स्टोर, 27, वेस्ट कलमण्डलम रोड, रायपुरम, मद्रास-13 को, प्रब्रेल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936101-मी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 का एन्ड्रेड्रायर रद्द करता हूं।

[मंख्या : डोएफ / 1264/एम 82-एयू-3]

S.O. 171:—M/s. V. M. Store, 27, West Kalmandapam Road, Royapuram, Madras-13 were granted a licence No. P/Z/1936101/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936101/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. V. M. Store, 27, West Kalmandapam Road, Royapuram, Madras-13 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1264/AM. 82/AU. III]

का० आ० 172:—सर्वश्री अमर सेल्स कारपोरेशन, संख्या-7, नाईकन स्ट्रीट, मद्रास-1 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट—1935893-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 23-2-83 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिलाई देने से, पार्टी से वह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्होंने जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बारे में संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत रानदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एन्ड्रेड्रायर नाइर्स को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री अमर सेल्स कारपोरेशन, संख्या 7, नाईकन स्ट्रीट, मद्रास-1 को, प्रब्रेल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935893-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 को एन्ड्रेड्रायर रद्द करता हूं।

[मंख्या डोएफ-925 - एम - 82-एयू-3]

S.O. 172:—M/s. Amar Sales Corporation, No 7, Thambu Naicker Street, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1935893/C/XX/82/M/81, dated 23rd February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935893/C/XX/82/M/81 dated 23-2-1982, issued to M/s. Amar Sales Corporation No. 7, Thambu Naicker Street, Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/925/AM. 82/AU.III]

का० आ० 173 :—सर्वश्री सोलंकी एन्टरप्राइजेस, 82, नारायण भैदला स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935858-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्होंने जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेना हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सोलंकी एन्टरप्राइज़, 82, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, ब्रेल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935858-सी-एक्स-एम-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या: डीएफ-892-एम 82-एम 3]

S.O. 173.—M/s. Solanki Enterprises, 82, Narayana Mudali St., Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935858/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 23-9-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935858/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Solanki Enterprises, 82, Narayana Mudali St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/892/AM. 82/AU. III]

का० आ० 174.—सर्वश्री रिशब्देव एन्टरप्राइज़, 29, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935865-सी-एक्स-एम-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्होंने जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेना हूं।

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्होंने जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेना हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रिशब्देव एन्टरप्राइज़, 29, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, ब्रेल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935865-सी-एक्स-एम-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या: डीएफ-893-एम 82-एम 3]

S.O. 174.—M/s. Rishabdev Enterprises, 29, Narayana Mudali St., Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935865/G/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935865/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 issued to M/s. Rishabdev Enterprises 29-Narayana Mudali St. Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/893/A.M. 82/AU. III]

का० आ० 175.—सर्वश्री गणपति एन्टरप्राइज़, भंडार 32, भंडारन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935861-सी-एक्स-एम-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्होंने जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत

मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा नाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मर्वशी गणपति एन्टरप्राइज़, सख्ता-32, स्ट्रीट, मुख्य मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक मूले फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये नाइसेंस संख्या पी-इजट-1935861-सी-एक्स-एम-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-886-एम-82-एम-3]

S.O. 175.—M/s. Ganapati Enterprises, No 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras-600 001 were granted a licence No. P/Z/1935861/C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24-9-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935861/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Ganapati Enterprises, No. 32, Strotten Muthia Mudali Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March 1982 period.

[No. DF/886/AM. 82/AU. III]

का. आ. 176 :—सर्वश्री कासीमारी एजेंसीस्, 92, पोलू स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक मूले फलों का आयात करने के लिए आयात नाइसेंस संख्या पी-इजट-1936109-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वाय करने का कारण दिखाई देने से, पाटी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-1982 को व्यक्तिगत मुनाहाई का अवमर देने के पश्चात उनको जारी किया गया नाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत गुनवाही के लिए पाटी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस न गलत मनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए, सर्वश्री कासीमारी एजेंसीस्, 82, पोलू स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक मूले फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये नाइसेंस संख्या पी-इजट-1936109-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1247-एम 82-एम 3]

S.O. 176.—M/s. Kasimari Agencies, 92, Jolu Street, Madras 12, were granted a Licence No. P/Z/1936109/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-8-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in items of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936109/C/XX/82/M/81 issued to M/s. Kasimari Agencies 92, Polu street, Madras 12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F No. DF/1247/AM 82/AU. III]

का. आ. 177 .—सर्वश्री शक्ति प्रोविजन् स्टोर, 15, रामनाइक का स्ट्रीट, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक मूले फलों का आयात करने के लिए आयात नाइसेंस संख्या पी-इजट-1936099-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था ;

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अदास्तविकता के बारे में विश्वाय करने का कारण दिखाई देने से, पाटी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-1982 को व्यक्तिगत मुनाहाई का अवमर देने के पश्चात उनको जारी किया गया नाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत गुनवाही के लिए पाटी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस न गलत मनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री शक्ति प्रोविजन् स्टोर, 15, रामनाइक का स्ट्रीट, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक मूले फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये नाइसेंस संख्या पी-इजट-1936099-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1261-एम 82-एम 3]

S.O. 177.—Sakthi Provision Store, 15, Ramaaiken St., Madras-13 were granted a licence No. P/Z/1936099/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-8-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte

I in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936099/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 issued to M/s. Sakthi Provision Store, 15, Ramaaiken St., Madras-13 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1261/A.M 82/AU. III]

का. आ. 178 :—सर्वश्री श्रीनीवासा किराना एण्ड जेनरल मचेन्ट्स, 79, सोलैण्डन स्ट्रीट, मद्रास-000021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए कायात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935977-सी-एक्सएक्स-82-एम-31 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सर्वश्री लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पृछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जा किया गया था कि 30-7-1982 को व्यक्तिगत सूनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत भूनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्रीनीवासा किराना एण्ड जेनरल मचेन्ट्स, 79, सोलैण्डन स्ट्रीट, मद्रास-21 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपय 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935977-सी-एक्सएक्स-82-एम-31 दिनांक 1-3-82 को युतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1071-एम 82-एम 3]

S.O. 178.—M/s. Srinivasa Kirana & General Merchants 79, Sohappam Street, Madras-600021 were granted Licence No. P/Z/1935977/C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935977/C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 issued to M/s. Srinivasa Kirana & General Merchants, 79, Salaippam Street, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1071/AM 82/AU. III]

का. आ. 179.—सर्वश्री बाबू प्रोविजन स्टोर्स, संख्या-15, पोन्नपाट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935997-सी-एक्सएक्स-82-एम-31 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पृछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-1982 को व्यक्तिगत भूनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत भूनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

इस नात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बाबू प्रोविजन स्टोर्स, संख्या-15, पोन्नपाट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935997-सी-एक्सएक्स-82-एम-31 दिनांक 2-3-82 एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1028-एम 82-एम 3]

S.O. 179.—M/s. Babu Provision Stores, No. 15, Ponnappachetty Street, Madras-3 were granted a Licence No. P/Z/1935997/C/XX/82/M/81 dated 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, A Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935997/C/XX/82/M/81 dated 2-3-82 issued to M/s. Babu Provision Stores, No. 15, Ponnappachetty Street, Madras-3 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1082/AM. 82/AU. III]

का. आ. 180.—सर्वश्री तंगम स्टोर्स, 53/1, साथन्न नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-600007 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935914-सी-एक्सएक्स-82-एम-31 दिनांक 2-5-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पृछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत भूनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत भूनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री तंगम स्टोर्स, 53/1, साथन्न नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-600007 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000

सक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935914-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता है।

[संख्या : डीएफ/952/एएम 82-एयू 3]

S.O. 180.—M/s. Thangam Stores, 53/1-Sahanna Naicken St., Madras—600007 were granted a Licence No. P/Z/1935914/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935914/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 issued to M/s. Thangam Stores, 53/1-Sahanna Naicken St., Madras-600 007 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/952/AM. 82/AU. III.]

का०आ० 181.—सर्वश्री दास जेनरल स्टोर्स, 64, अंगालम्बन कोइल स्ट्रीट, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1925984-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने वे, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न, रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत युनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री दास जेनरल स्टोर्स, 64, अंगालम्बन कोइल स्ट्रीट, मद्रास 600112 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935984-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ/1077/एएम/82/एयू 3]

S.O. 181.—M/s. Dass General Stores, 64, Angalamma Street, Madras, 600 012 were granted a Licence No. P/Z/1935984/C/XX/82/M/81 dt. 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licensee has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935984/C/XX/82,M,81, dt. 2-3-82 issued to M/s. Doss General Store, 64, Angalammman koll Street, Madras-600112 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F. No. DF/1077/AM. 82/AU. III.]

का०आ० 182.—सर्वश्री अब्दुल मलाम, गंड्या 5, तिरुप्पुर कुमरन स्ट्रीट, पम्मल, मद्रास-75 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935956-सी-एक्सएक्स 82-एम-81 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न, रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत युनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री अब्दुल मलाम, गंड्या-5, तिरुप्पुर कुमरन स्ट्रीट, पम्मल, मद्रास-75 को, अप्रैल-मार्च 1982 का अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935956-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ/1015-एएम 82/एयू 3]

S.O.182.—M/s. Abdul Salam No. 5, Tirupur Kumaran St., Pammal, Madras, 75 were granted a Licence No. P/Z/1935956/C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 43,000.

As there was a reason to believe that the above import licensee has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon

the Licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935956/C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 issued to M/s. Abdul Salam No. 5 Tirupur Kumaran Street, Pammal Madras-75 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1015/AM. 82/AU. III]

का० आ० 183.—सर्वश्री माया मर्चेन्ट्स, 75/2-टी-के मुदली स्ट्रीट, मद्रास- 600007 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935901-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्वों न रद्द कर दिया जाए। अपने भासले को स्पष्ट करने अविकल्पत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस का रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री माया मर्चेन्ट्स, 75/2-टी-के-मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600007 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935901-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ/940/एम 82/एयू 3]

S.O. 183.—M/s. Maya Merchants, 75/2, T.K. Mudali Street, Madras-600007 were granted a Licence No. P/Z/1935901/C/XX/82/M/81 dated 26-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby

cancel the Import Licence No. P/Z/1935901/C/XX/82/M/81 dated 24-2-82 issued to M/s. Maya Merchants, 75/2-T. K. Mudali St., Madras-600007 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/940/AM. 82/AU. III]

का० आ० 184.—सर्वश्री जैन एक्टरप्राइज़, 38, एकाम्बरेश्वरर अग्रहारम, मद्रास-3 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936114-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्वों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को संष्ट प्रमाणपत्र के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जैन एक्टरप्राइज़, 38, एकाम्बरेश्वरर अग्रहारम, मद्रास-3 का, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936114-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 का एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डी एफ/1254-एम/82-एयू 3]

S.O. 184.—M/s. Jain Enterprises, 18, Ekambareswarar Agrahearam, Madras-3, were granted a Licence No. P/Z/1936114/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936114/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Jain Enterprises, 18, Ekambareswarar Agrahearam Street, Madras-3 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1254/AM. 82/AU. III]

का०आ० 185 :- सर्वेश्वी बाबुलाल एण्ड कम्पनी, संख्या 6, कासी स्टटी स्ट्रीट, मद्रास-1 का रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936047-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त गलत लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) शादेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी बाबुलाल एण्ड कम्पनी, संख्या-6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936047-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ/1172/एम 82-एयू 3]

S.O. 185.—M/s. Babulal & Co., No. 6, Kasi Chetty Street Madras-1, were granted a licence No. P/Z/1936047/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936047/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 issued to M/s. Babulal & Co., No. 6, Kasi Chetty St., Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1172/AM. 82/AU. III]

का०आ० 186:- सर्वेश्वी गुरुनाथ प्राविजन स्टोर्स, 48, एम०पी० कोइल स्ट्रीट, मद्रास-12 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936005-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) शादेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्वी गुरुनाथ प्राविजन स्टोर्स, 48, एम०पी० कोइल स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936005-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ/1112-एम 82-एयू 3]

S.O. 186.—M/s. Gurunath Provision Stores, 48, S. P. Koil Street, Madras-12, were granted a licence No. P/Z/1936005/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936005/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Gurunath Provision Stores, 48, S. P. Koil Street, Madras-12 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1112/AM. 82/AU. III]

का०आ० 187 :- सर्वेश्वी रमेश ट्रेइम्स, संख्या-14, पिल्लैयार कोइल स्ट्रीट, मद्रास-3 को रूपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935993-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-83 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी

किया गया नाइमेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने वाक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा नाइमेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता है।

मैं, आयात (नियंत्रण) श्रादेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रमेश ट्रेडर्स, संख्या-14 पिल्लैयार कोइल स्ट्रीट, मद्रास-3 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गयेलाइसेंस संख्या पी-इजट-1935993-सी-एकम एक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

(संख्या डीएफ-1079-एम 82-एम 3)

S.O. 187.—M/s. Ramesh Traders, No. 14, Pillar Koil Street, Madras-3, were granted a licence No. P/Z/1935993/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

1. in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import licence No. P/Z/1935993/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 issued to M/s. Ramesh Traders, No. 14, Pillar Koil St., Madras-3 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1079/AM. 82/AU. III]

कांग्रा० 188 :—सर्वश्री एम०बी०एम० एन्टरप्राइज़्स, 42, वेस्ट कलमण्डवम रोड, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात नाइमेंस नंख्या पी-इजट-1936120-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त नाइमेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण छिवाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 2-2-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया नाइमेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने वाक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त नाइमेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा नाइमेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) श्रादेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री बो०एम० एन्टरप्राइज़्स, 42, वेस्ट कलमण्डवम रोड मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये नाइमेंस संख्या पी-इजट-1936120-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ-1266एम-82-एम 3]

S.O. 188.—M/s. S. B. M, Enterprises, 42, West Kalmandapam Road, Madras-13, were granted a Licence No. P/Z/1936120/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936120/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. S. B. M, Enterprises, 42, West Kalmandapam Road, Madras 13 for import of Dry fruits for Rs 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/1266/AM. 82/AU. III]

कांग्रा० 189 :—सर्वश्री माकनचन्द नेमीचन्द, 23 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात नाइमेंस संख्या पी-इजट-1935866-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त नाइमेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 2-2-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया नाइमेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने वाक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त नाइमेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा नाइमेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) श्रादेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री शा माकनचन्द नेमीचन्द, 23 नारायण मुदली स्ट्रीट

मद्रास-1 को, प्रैल—मार्च 1982 की घबंधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935866-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-882-एम 82-एयू 3]

S.O. 189.—M/s. Sha Makanchand Nemichand, 23, Narayana Mudali Street, Madras-1, were granted a licence No. P/Z/1935866/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935866/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 issued to M/s. Sha Makanchand Nemichand—Madras-1 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/882/AM. 82/AU. III]

कांग्रा० 199 :—सर्वेशी रामा प्रोविजन स्टोर, 9, रामा नाइक्कन स्ट्रीट, रायपुरम मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936100-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण विखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी रामा प्रोविजन स्टोर, 9 रामा नाइक्कन स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को, प्रैल—मार्च 1982 की घबंधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936100-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1262-एम 82-एयू 3]

S.O. 190.—M/s. Rama Provision Store, 9, Rama Naicken Street, Royapuram, Madras-13, were granted a Licence No. P/Z/1936100/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936100/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Rama Provision Store, 9, Rama Naicken Street, Royapuram, Madras-13 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1262/AM. 82/AU. III]

कांग्रा० 191 :—सर्वेशी ए० करीम प्रोविजन स्टोर, 24 तुलसी नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935892-सी-एक्सएक्स-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण विखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी ए० करीम प्रोविजन स्टोर, 24, तुलसी नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-12 को, प्रैल—मार्च 1982 की घबंधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935892-सी-एक्सएक्स-एम-81 दिनांक 23-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-924-एम 82-एयू 3]

S.O. 191.—M/s. A. Kareem Provision Stores, 24-Thulasi Naicken Street, Madras-12, were granted a Licence No. P/Z/1935892/C/XX/M/81 dated 23rd February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon

the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935978/C/XX/82/M/81 dated 23rd February, 1982 issued to M/s. A. Kareem Provision Stores, 24-Thulasi Naik Street, Madras-12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/924/AM. 82/AU. III]

का० धा० 192—सर्वेश्री श्री सायबाबा स्टोर्स, संख्या-4, श्री रंगमाल लेन, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935978-सी-एक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण अतिथि नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने भास्तु को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के भंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्री श्री सायबाबा स्टोर्स, संख्या-4, श्री रंगमाल लेन, मद्रास-21 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935978-सी-एक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 का एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ-1074-एम-82-एम-3]

S.O. 192.—M/s. Sri Saibaba Stores, No. 4, Sri Rangammal Lane, Madras-600021, were granted a licence No. P/Z/1935978/C/XX/82/M/81 dated 1st March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence had been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935978/C/XX/82/M/81 dated 1st March, 1982 issued to M/s. Sri Saibaba Stores, No. 4, Sri Rangammal Lane, Madras-21 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1074/AM. 82/AU. III]

का० धा० 193—सर्वेश्री गजलक्ष्मी स्टोर्स, 48, श्री रंगमाल स्ट्रीट, वासरमेनपेट, मद्रास-21 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935978-सी-एक्स-एम-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण अतिथि नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने भास्तु को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेश्री गजलक्ष्मी स्टोर्स 48 श्री रंगमाल स्ट्रीट, वासरमेनपेट, मद्रास-21 को, अप्रैल—मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935978-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ-1087-एम-82-एम-3]

S.O. 193.—M/s. Gajalakshmi Stores, 48, Srirangammal Street, Washermenpet, Madras-21 were granted a Licence No. P/Z/1935979/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935979/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 issued to M/s. Gajalakshmi Stores, 48, Sri Rangammal Street, Washermenpet, Madras-21 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1087/AM. 82/AU. III]

का० आ० 194.—सर्वश्री सेल्वम स्टोर्स, 5/3 तुलसी नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936011-सी-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस संदी सेल्वम स्टोर्स द्वारा भूतवूर्ब आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण अतामो नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत संदी सेल्वम स्टोर्स के प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सेल्वम स्टोर्स, 5/3, तुलसी नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल—मार्च 182 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936011-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 का एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या डीएफ-1113/एस-82/एप्यू 3]

S.O. 194.—M/s. Selvam Stores, 5/3 Tulasi Niacken Street, Madras-12, were granted a licence No. P/Z/1936011/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936011/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Selvam Stores, 5/3 Tulasi Niacken Street, Madras-12, for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1113/AM 82/AU. III]

का० आ० 195.—सर्वश्री मुरली एन्टरप्राइजेस, 16, सोमु चेट्टी स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936071-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस संदी सेल्वम स्टोर्स द्वारा भूतवूर्ब आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण अतामो नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत संदी सेल्वम स्टोर्स के प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मुरली एन्टरप्राइजेस, 16, सोमु चेट्टी स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936071-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : डी एफ-1189-एम 82-ए पू 3)

S.O. 195.—M/s. Murali Enterprises, 16 Somuchetty Street, Royapuram, Madras-13, were granted a licence No. P/Z/1936071/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936071/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Murali Enterprises, 16 Somuchetty Street, Royapuram, Madras-13, for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1189/AM 82/AU. III]

का० आ० 196.—सर्वश्री ए०जी० एस० स्टोर्स, 73, पेट वूर हाई रोड, मद्रास-600 012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936001-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस संदी सेल्वम स्टोर्स द्वारा भूतवूर्ब आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द, करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, भायात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त आधकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्रो ए०ज००ए०स्ट० स्टोर्स, 73, पेरम्बूर हाई रोड, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च 1982 का अधाध के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936001-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 का एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डॉ एफ/1116-ए एम 82-एयू 3]

S.O. 196.—M/s. A.G.S. Stores, 73, Perambur High Road, Madras-600012, were granted a Licence No. P/Z/1936001/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licensee holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936001/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. A.G.S. Stores, 73, Perambur High Road, Madras-600012, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.
To

[No. DF/1116/AM. 82/AU. III]

का०प्रा० 197.—सर्वश्री रत्ना स्टोर्स, 2, जी०ए० रोड, मद्रास-21 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1036000-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, भायात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त आधकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रत्ना स्टोर्स, 2, जी०ए० रोड, मद्रास-21 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936015-सी-एक्सएक्स-83 एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1108-एएम 82-एयू 3]

S.O. 197.—Rathna Stores, 2-G.A. Road, Madras-21 were granted a Licence No. P/Z/1936015/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936015/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Rathna Stores, No. 2, G.A. Road, Madras-21 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1108/AM. 82/AU. III]

का० प्रा० 198.—सर्वश्री मोहन प्राविजनल स्टोर्स, 50, पेरम्बूर हाई रोड, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936000-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, भायात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त आधकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोहन प्राविजनल स्टोर्स, 50, पेरम्बूर हाई रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1983 की अवधि के लिए

रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आरी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936000-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता है।

[संख्या छीएफ-1104-एम 82-एयू 3]

S.O. 198.—M/s. Mohan Provisional Stores, 50, Perambur High Road, Madras-12, were granted a Licence No. P/Z/1936000/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936000/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Mohan Provisional Stores, 50, Perambur High Road, Madras-12, for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1104/AM. 82/AU. III]

का० घा० 199:—सर्वेशी बालाजी ट्रेडर्स, 84, प्रणाराव गार्डन, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935915-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 आरी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाण पत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने भाग्य को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी बालाजी ट्रेडर्स, 84, प्रणाराव गार्डन, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935915-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : छी एफ/953-ए एम-82-एयू 3]

S.O. 199.—M/s. Balaji Traders, 84, Apparao Garden Madras-12 were granted a Licence No. P/Z/1935915/C/XX/82/M/81 dated 25th February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935915/C/XX/82/M/81, dated 25th February, 1982 issued to M/s. Balaji Traders, 84, Apparao Garden, Madras-600112 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

To

[No. DF/953/AM. 82/AU. III]

का० घा० 200:—सर्वेशी एस०एम० स्टोर, संख्या 39, पोन्नपत्टि चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट 1935998-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 आरी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूं।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वेशी एस०एम० स्टोर, संख्या 39, पोन्नपत्टि चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935998-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूं।

[संख्या : छी एफ/1030-ए एम-82-एयू 3]

S.O. 200.—M/s. S. M. Stores, No. 39, Ponnappachetty Stel, Madras-3, were granted a Licence No. P/Z/1935998/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the

licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935995/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 issued to M/s. S. M. Stores, No. 39, Ponnappachetty Street, Madras-3 for import of Dry fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/1030/AM. 82/AU. III]

का० घा० 201.—सर्वश्री सेल्वराज प्राविजन्स, ९०, बी० ए० रोड, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935995-मी०-एकत एक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस संख्या लेखापाल द्वारा भूत्युक्त आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण योग्यता होने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नीटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बचावात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्या न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सन्दर्भ लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियन्त्रण) आदेश, 1955 की धारा १(१) (ए) के अन्तर्गत प्रवत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सेल्वराज प्राविजन्स, ९०, बी० ए० रोड, मद्रास-21 को, अवैत-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935995-सो-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ/1078-एम/82-एय० ३]

आर० सेल्वराज, उप मुख्य नियंत्रक आयात संथा निर्यात

S.O. 201.—M/s. Selvaraj Provisions, 90, G.A. Road, Madras-600021 were granted a Licence No P/Z/1935995/C/XX/82/M.81 dated 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935995/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 issued to M/s. Selvaraj Provisions Stores, G.A. Road, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/1078/AM. 82/AU. III]
R. SELVARAJ, Dy. Chief Controller,
Imports & Exports.

उद्घोष भवानलय

(धौधोगिक विकास भवानलय)

आदेश

नई दिल्ली, 1982

**का० घा० 202.—फेन्ड्रीय सरकार, आवश्यक दस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्घोष भवानलय के आदेश सं० का० घा० 797 (अ), तारीख 12 नवम्बर, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करतो हैं, अर्थात् :—
उक्त आदेश में :—**

(1) पैरा 12 में राजपत्रित पंक्ति शब्दों के स्थान पर सहायक निवेशक या समतुल्य पंक्ति का प्रविकारी पद रखे जाएगे,

(2) अनुसूची में क्रम संख्याक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“क्रम संख्याक 11 मा० ४२५०—१९८०”।

टिप्पण :— हिस्सी पाठ में क्रम संख्याक 7 और 33 की प्रविष्टियां ठीक हैं। हस्तालिए उनका अनुवाद किया जाना आवश्यक नहीं है।

[का० सं० एस० एस० I(I)-24(62)/81]
एस०के० चक्रवर्ती, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th December, 1982

S.O. 202.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. S.O. 797(E) dated the 12th November, 1981, namely :—

In the said Order—

(i) in paragraph 12, for the words “Gazetted ranks”, the words “Assistant Director or Officer of equivalent rank” shall be substituted;

(ii) in the Schedule for S. Nos. 7, 11, and 33 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries thereof shall respectively be substituted, namely :—
“S. No. 7 IS : 1596—1977”;
“S. No. 11 IS : 4250—1980”; and
“S. No. 33 IS : 6446—1972.”;

[No. SSI(D)-24(62)/81].
S. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982

का०प्रा० 203—अधिग्रहण संचिदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) को धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड I अधिकारी श्री बी० नन्जुनदेवा को 6 दिसम्बर, 1982 के पूर्वाहन से वायदा बाजार आयोग, बम्बई के अध्यक्ष के रूप में आगे और आदेश होने तक के लिये, नियुक्त करते हैं।

[मिसिल संख्या ए-12011/17/82 प्रशा० 2]

बी०डी० गोपाला, भवर सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 8th December, 1982

S.O. 203.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby appoints Sh. B. Nanjundaiya, a Grade I Officer of the I.E.S., as Chairman, Forward Markets Commission, Bombay, with effect from the forenoon of 6th December, 1982 until further orders.

[File No. A. 12011/17/82-Estt. II]
B. D. GOPALA, Under Secy.

मथी दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

का०प्रा० 204—नागरिक पूर्ति मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, डा० पी०एल० कौल ने 6 दिसम्बर, 1982 के दोपहर के पहले से वायदा बाजार आयोग, बम्बई के सदस्य तथा साथ ही अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

नागरिक पूर्ति विभाग

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 19 82-11-24

का०प्रा० 205—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम (3) के उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन अहां अनुसूची में दिये भारतीय मानकों के संशोधन जारी किये गये हैं।

मनुसूची

| क्रम सं० | संशोधित भारतीय मानक की मदसंस्था और शीर्षक | जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक के तैयार होने की सूचना छपी थी। उसकी संख्या और तिथि | संशोधित मानक संख्या में भारतीय मानक के तैयार होने की संख्या और तिथि | संशोधित का संक्षिप्त विवरण | संशोधन लागू होने की तिथि |
|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. IS : 178—1965 सूती दिखल की विशिष्टि (पुनरीक्षित) | एस ओ० 1992 विनांक 1966-07-02 | सं० 2 जन० 1980 | खड 2.2.1 के पश्चात् एक नयी टिप्पणी जोड़ी गई है। | 19 80-01-31 | |
| 2. IS : 180—1965 सूती कमीज के कपड़ों की विशिष्टि (पुनरीक्षित) | सं० 2 जन० 1980 | खड 2.2.1 के पश्चात् एक टिप्पणी जोड़ी गई है। | 19 80-01-31 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------------|------------------|--|--|------------|---|
| 3. IS : 178—1965 स्थायी इकाइ के लिये भौती-कासी तरल स्थाही की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | एस ओ 1992 दिनांक 19 66-07-02 | सं० 1 दिस० 19 80 | IS : 8642—1977 “जल-प्राधारित लिखने की स्थाही की विशिष्टि” के प्रकाशन से जिस में इक-बल्यू रंजक की अपेक्षाएँ बी गई है। | IS : 224-7-1962 “स्थाही उद्घोग के लिये इक-बल्यू रंजक की विशिष्टि” को वापस लिया गया है। अतः यह संशोधन जारी किया गया है। | 1980-02-31 | |
| 4. IS : 453—1973 भरणी के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | एस ओ 4890 दिनांक 19 75-11-01 | सं० 1 दिस० 1979 | (1) खंड 4. 2 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है। (2) पृष्ठ 4 और 5 खंड 4. 2. 1 इन्हें काटिए। (3) परिशिष्ट ए के शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक दिया गया है। | (1) खंड 4. 2 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है। (2) पृष्ठ 4 और 5 खंड 4. 2. 1 इन्हें काटिए। (3) परिशिष्ट ए के शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक दिया गया है। | 1980-01-31 | |
| 5. IS : 694—1977 1100 बो० तक की कार्यकारी बोल्टता के पी० और सी रोधित केवल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | — | सं० 1 जन० 1980 | (1) पृष्ठ 3 पर कमांक संख्या 11 और 12 के सामने विशेष धातु को संशोधित किया गया है। (2) खण्ड 0. 3 के पश्चात् एक नया खण्ड 0. 4 जोड़ा गया है और तत्पश्चात् खण्डों की कमांक संख्या को तदानुसार ठीक किया गया है। (3) खण्ड 1. 1, 1. 2, 9. 4, 10. 1, 11, 11. 1, 12, 12. 1, 12. 3. 1 और ए०-१ को संशोधित किया गया है। (4) खण्ड 2. 4, 11. 4, 12. 2, 12. 3, ए-२ से ए-३. 1 और बी० 1. 1 के स्थान पर नये खण्ड लाये गये हैं। (5) खण्ड 8. 1 के नीचे वर्तमान टिप्पणी को “टिप्पणी 1” संख्या दी गई है और एक नयी “टिप्पणी 2” जोड़ी गयी है। (6) खण्ड 9. 4 के पश्चात् एक नया खण्ड 9. 5 जोड़ा गया है और तत्पश्चात् खण्डों का नम्बर तदानुसार बदला गया है। (7) खण्ड 13. 2 के पश्चात् एक टिप्पणी जोड़ी गयी है। | (1) पृष्ठ 3 पर कमांक संख्या 11 और 12 के सामने विशेष धातु को संशोधित किया गया है। (2) खण्ड 0. 3 के पश्चात् एक नया खण्ड 0. 4 जोड़ा गया है और तत्पश्चात् खण्डों की कमांक संख्या को तदानुसार ठीक किया गया है। (3) खण्ड 1. 1, 1. 2, 9. 4, 10. 1, 11, 11. 1, 12, 12. 1, 12. 3. 1 और ए०-१ को संशोधित किया गया है। (4) खण्ड 2. 4, 11. 4, 12. 2, 12. 3, ए-२ से ए-३. 1 और बी० 1. 1 के स्थान पर नये खण्ड लाये गये हैं। (5) खण्ड 8. 1 के नीचे वर्तमान टिप्पणी को “टिप्पणी 1” संख्या दी गई है और एक नयी “टिप्पणी 2” जोड़ी गयी है। (6) खण्ड 9. 4 के पश्चात् एक नया खण्ड 9. 5 जोड़ा गया है और तत्पश्चात् खण्डों का नम्बर तदानुसार बदला गया है। (7) खण्ड 13. 2 के पश्चात् एक टिप्पणी जोड़ी गयी है। | 1680-12-31 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|--|---------------|---|------------|-----|
| | | | (8) मद 'पी' के परचात या "कू" जोड़ा गया है। | | |
| | | | (9) (पृष्ठ 15, छांड वी 1. 1, टिप्पणी) -- इसे लाटिए। | | |
| | | | (10) (पृष्ठ 16, खण्ड वी 2.3 अनौपचारिक सारणी, पहला खाना, दूसरी प्रविष्टि) -- शब्द "50" और उसके सक काटिए। | | |
| 6. IS : 732--1963 विद्युत ग्राम- एम ओ 1147 | सं० 6 | | खण्ड 5.8.1 (इ) के स्थान पर एक नया खण्ड रखा गया है। | 1980-01-31 | |
| रिंग संम्पर्कार (यार्फ़िक्स बोलटन) दिनांक 1963-04-20 जन० 1930 650 ओ० तक) की रीनिस्ट्रिक्शन (पुनरीक्षण) | | | | | |
| 7. JS : 750—1976 हथकरघे पर बनी सूती लगी की विशिष्टि (पहला पुनरेक्षण) | -- | सं० 2 1980 | सारणी 1 का संशोधन किया गया है। | 1080-01-31 | |
| 8. JS : 774—1971 अंग्रेजी एम ओ 231 टड़ी और मूत्रान्तरों के लिये ज्ञान की टिकियों (वाल्व रहित साइ- फन आधारित किरण वाले) की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण) | सं० 5* | | (1) खण्ड 4. 3, 4. 4, 4. 8 और 4. 8. 1 के स्थान पर नये खण्ड रखे गए हैं। (2) खण्ड 2. 2 और 3. 2 के उपरान्त कमरा नये खण्ड 2. 3 और 3. 2. 1 जोड़े गये हैं। | 1980-01-31 | |
| 9. IS : 902—1974 विद्युत ग्राम एम ओ 1596 उपयोग के लिये चृष्ण हात दिनांक 1976-05-08 दिन० 1979 कपलिंग की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण) | सं० 3 | | सारणियों 1ए, 1बी, 2ए और 2बी का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 | |
| 10. IS : 1169-- 1967 विद्युत के एम ओ 1720 पेडेन्टल वाले पंछे और रेग्यूलेटर दिनांक 1968-05-18 जन० 1980 को विशिष्टि (पहला पुनरेक्षण) | सं० 4 | | खण्ड 16. 2. 1 और 16. 2. 12 के नोंबे दी गयी टिप्पणियों के स्थान पर नयी टिप्पणी दी गई है। | 1980-01-31 | |
| 11. IS : 1235—1958 पर्सनटर अजल की विशिष्टि | एम ओ 1949 दिनांक 1958-09-27 दिन० 1979 | सं० 1 | खण्ड बी-2.3 2.1 का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 | |
| 12. IS : 1266—1938 हथकरघे पर बनी सर्ज की विशिष्टि | एम० ओ० 1654 दिनांक 2958-12-27 दिन० 1979 | सं० 1 | यह संशोधन संगादकीय ह्रेर फेर करने और विभिन्न अपेक्षाओं की परीक्षण विधियों के भारतीय भावकों के नवोत्तरम संस्करणों का उल्लेख करने के लिये जारी किया गया है। | 1979-12-31 | |

*मार्च 1980 स्थाया प्रमाणन योग्यता के लिये यह संशोधन 1980-03-01 से लागू होगा।

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------|--|------------|
| 13. IS : 1288--1973 | खनिज जिपसम और जिपसम पदार्थों की परीक्षण पद्धतियाँ (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 4690 दिनांक 1975-11-01 | सं० 2 जन० 1980 | (1) खण्ड 10.2.2 और 11.2. 1.3 को संशोधित किया गया है। (2) (पृष्ठ 12, खण्ड 10.2.3 सूत्र)—"140.2" की जगह "280.4" करिए। (3) (पृष्ठ 14, खण्ड 11.2.3 सूत्र "100.8" की जगह "201.6" करिए। | 1980-01-31 |
| 14. IS : 1423--1973 | सूती गैब- डीन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)। | एस ओ 2558 दिनांक 1975-08-09 | सं० 1 जन० 1980 | सारणी 1 का संशोधन किया गया है। | 1980-01-31 |
| 15. IS : 1445--1977 | 1000 ओ एस ओ तक की नामिक बोल्टता तक की गिरावरि विद्युतरोधकों की (दूसरा पुनरीक्षण) | खट्टरी विशिष्टि दिनांक 1972-07-08 | सं० 1 दिस० 1979 | (पृष्ठ 11, खंड 7 और 7.1 इनको काटिए तत्पश्चात् खंडों खंडों का नम्बर बदलिए। | 1979-12-31 |
| 16. SI : 1492--1970 | मीटरी सर्वेक्षण जंजीर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 1635 दिनांक 1961-10-28 | सं० 2 दिस० 1979 | खंड 5.1 का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 |
| 17. IS : 1776--1961 | विन सेप वाले मुड़वां डिब्बा बनाने के गसे की विशिष्टि। | एस ओ 2534 दिनांक 1961-10-28 | सं० 3 दिस० 1979 | सारणी 1 और 2 का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 |
| 18. IS : 1886--1967 | ट्रांसफार्मर संस्थापन और वेख रेख की रीति सर्हिना | एस ओ 2789 दिनांक 1967-08-19 | सं० 4 जन० 1980 | (पृष्ठ 11, चित्र 1, टिप्पणी 1, लाइन 1)—शब्द "लगभग 500 किलो ए क्षमता के" काटिए। | 1980-01-31 |
| 19. IS : 2037--1962 | अनुरेखण कंपडे की विशिष्टि | एस ओ 2562 दिनांक 1962-08-11 | सं० 3 दिस० 1979 | (1) इसरे पुनर्मुद्रण में खंड सौ-2.1 और तीव्रे पुनर्मुद्रण में खंड सी-1.2 के स्थान पर नये खंड दिए गए हैं। (2) पहले पुनर्मुद्रण में पृष्ठ 10 पर खंड सी-2.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। | 1979-12-31 |
| 20. IS : 2081 (भाग 1)--1976 | वाहन गाड़ियों की बैटरी के गाब- दुम सिरों के केबल संयोजक की विशिष्टि भाग 1 पीतल वाले संयोजक (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 3882 दिनांक 1979-11-24 | सं० 1 जन० 1980 | (1) सारणी 1 का संशोधन किया गया है। (2) रेखाचित्र 1 की जगह एक नया रेखाचित्र दिया गया है। (3) खंड 3.1 के नीचे एक नयी टिप्पणी जोड़ी गयी है। | 1980-01-31 |
| 21. IS : 2361--1970 | बुलडाग चिमटियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 1277 दिनांक 1972-05-27 | सं० 3 दिस० 1979 | खंड 2.1.2 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है। | 1979-12-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|--|--------------------------------|--------------------|--|------------|
| 22. | IS : 2413—1978 मूर्ती सुतली की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | — | सं० 1 जन० 1980 | खंड 6.5 की अनौपचारिक सारणी का संशोधन किया गया है। | 1980-01-31 |
| 23. | IS : 2453—1978 केबल बल वाले मूर्ती रस्से की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण) | — | सं० 1 जन० 1980 | खंड 0.2, 0.4 और सारणी 1 का संशोधन किया गया है। | 1980-01-31 |
| 24. | IS : 2490 (भाग 1)—1974 एस ओ 182 भौतिक प्रदेश की सतह जलराशि में विस्तृत श्रीदर्थगिक नियाक के लिये सहनशीलता सीमाएं भाग 1 सामान्य सीमाएं (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 182 दिनांक 1976-01-10 | सं० 1 दिस० 1979 | (पृष्ठ 7, सारणी 1, क्रम संख्या (24) —इसकी काटिए। | 1979-12-31 |
| 25. | IS : 2582 (भाग 2)—1972 खराद स्पिडल नोज और केस प्लेट के परिमाप, भाग 2 स्पिडल भोज-कैमरांक किस्म के (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 2081 दिनांक 1975-07-25 | सं० 1 दिस० 1979 | रेखाचित्र 1 और सारणी 1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं। | 1979-12-31 |
| 26. | IS : 3775—1966 विरंजित मूर्ती खादी तृकबैंक तौलिए कपड़े की विशिष्टि | एस ओ 913 दिनांक 1967-03-18 | सं० 2 जन० 1980 | सारणी 1 के नीचे टिप्पणी 4 के स्थान पर नयी टिप्पणी दी गई है। | 1980-01-31 |
| 27. | IS : 4651—(भाग 4)—1969 जहाज गोदी और बंदरगाह संरचनाओं के लिए डिजाइन करने और निर्माण की रीति संहिता भाग 4 शीट पाइस की स्तम्भन दीवारें। | एस ओ 436 दिनांक 1970-02-07 | सं० 1 जन० 1980 | (IS : 4651 (1 भाग 1) — 1974 और IS : 4651 (भाग 3) 1974 के प्रकाशन उपरांत और IS : 7314—1974 बंदरगाह और पतन इंजीनियरिंग से संबंधित शब्दावली के प्रकाशन के बाद आवश्यक था कि IS : 4651 (भाग 4) — 1969 का संशोधन किया जाए। | 1980-01-31 |
| 28. | IS : 4890—1968 खुले जल-मापों में नियन्त्रित तालियाँ मापने की विधियाँ | एस ओ 3929 दिनांक 1969-09-27 | सं० 1 दिस० 1979 | खंड 4.5.3 के पञ्चात् एक नया खंड 4.5.3.1 जोड़ा गया है। | 1979-12-31 |
| 29. | IS : 5204—1969 अनु-संधान सूक्ष्मदर्शक की विशिष्टि | एस ओ 4848 दिनांक 1969-12-06 | सं० 1 दिस० 1979 | (1) खंड 4.6 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है। (2) (पृष्ठ 7, खंड 4-9-1-1, पंक्ति 2) “0.001 मिमी” के स्थान पर “0.01 मिमी” पढ़िए। | 1979-12-31 |
| 30. | IS : 5920—1970 प्रकाशिक अवयवों और प्रणालियों के रेखाचित्र तैयार करने की सिफारिशें | एस ओ 1555 दिनांक 1972-06-24 | सं० 1 जन० 1980 | (पृष्ठ 7, सारणी 1, तीसरा कॉलम “श्रेणी किस्म”—इसे काटिए | 1980-01-31 |
| 31. | IS : 6234—1971 जल वाले (स्थायी वायु दबाव वाले) सुवाहा अविनशामक की विशिष्टि। | एस ओ 1549 दिनांक 1973-06-02 | सं० 4 जन० 1980 | (1) खंड 4.1 के नीचे टिप्पणी के स्थान पर नयी टिप्पणी दी गई है। (2) खंड 4.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। | 1980-01-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--|--------------------------------|---------------------|-----|---|------------|
| | | | | (3) (पृष्ठ 5, खंड 4-4-3)--- इसे काटिए | |
| | | | | (4) खंड 9.1, 9.3 और 9.3.1 1 को संशोधित किया गया है। | |
| | | | | (5) पृष्ठ 12 पर “+” और “\$” चिह्न वाली पादटिप्पणी का संशोधन किया गया है। | |
| | | | | (6) खण्ड 7.2-11 के पश्चात एक नई टिप्पणी दी गई है। | |
| 32. IS : 6425—1971 डाइप्टो- मीटर (लैसमापी) की विशिष्टि | एस ओ 751 दिनांक 1974-03-16 | सं० 1 जन० 1980 | | खंड 4.2 का संशोधन किया गया है। | 1980 01-31 |
| 33. IS : 6488—1975 व्यक्तिक बेब सुजस्तमान के लिये सूती वेबिंग की विशिष्टि। (पहला पुनरीक्षण) | एस ओ 2240 दिनांक 1978-08-06 | सं० 1 जन० 1980 | | (1) सारणी 1 और 3 का संशो- धन किया गया है। (2) (पृष्ठ 7 खंड 7.1 7.1.1 7.1.2 और 7.2)—वर्तमान खंडों के स्थान पर निम्नलिखित रखिए—“7.1 प्रतिक्षयन योजना परीक्षण नमूनों की संखा और अनुस्पता की कमीटी वही होगी जो सी | 1980-01-31 |
| | | | | IS : 7777—1975* के खंड 7 और 8 में दी गयी है। (3) “*” और “+” चिह्न वाली पादटिप्पणी के स्थान पर नयी टिप्पणियाँ दी गई हैं। | |
| 34. IS : 6638—1972 द्रैक्टर पर जमाए स्प्रिंग-लौडे ड क्लटीवेटर की विशिष्टि | एस ओ 770 दिनांक 1975-03-08 | सं० दिस० 1976 | | खण्ड 5.1 का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 |
| 35. IS : 7056—1973 सूती हस्का वैक तौलिए की विशिष्टि | एस ओ 2939 दिनांक 1975-09-06 | सं० 2 दिस० 1979 | | सारणी 1 का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 |
| 36. IS : 7777—1975 मुड़े किनारों वाली सूती निवाड़ की विशिष्टि | एस ओ 3351 दिनांक 1978-11-25 | सं० 2 दिस० 1979 | | सारणी 1 और 2 का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 |
| 37. IS : 8081—1976 खांचेदार खंडों की विशिष्टि | एस ओ 3820 दिनांक 1979-11-24 | सं० 2 1979-11-24 | | (1) खंड 2.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। (2) (पृष्ठ 5, खंड 5.4 पॉकेट 3)—“समान परिष्कृति में दिया जायेगा” शब्द काटिए। (3) (पृष्ठ 9, खंड 6.6.2.1 पंक्ति 1)—“अवश्य होगा” में बदलिए। | 1979-12-31 |
| 38. IS : 8130—1976 रोधित विद्युत केबल और लचीली डोरियो के लिये चालकों की विशिष्टि | एस ओ 99 दिनांक 1980-01-12 | सं० 1 जन० 1980 | | सारणी 8 और 9 का संशोधन किया गया है। | 1980-01-31 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|--------------------|--|-----------------------|------------|---|------------|
| 39. IS : 8308—1976 | रोधित एम आ० 419 दिनाक नेबलों के एल्यूमिनियम चालकों के लिये संरीणत किस्म के नला- कार इनलाइन संयोजनों की वि- शिष्टि | सं० 1 1980-02-23 | परं 1980 | (1) खंड 1 और 3 का संशोधन किया गया है। (2) (पृष्ठ 1 खंड 4.1) — इसे काटिए और बाद वाले खड़ों की संख्या को तदनुसार बदलिए। (3) (पृष्ठ 3 संरगो 2) इसे काटिए। (4) खंड 5 और 6 का संशोधन किया गया है। (5) संरणी 1 का संशोधन किया गया है। | 1980-02-29 |
| 40. IS : 8438—1977 | 1100 वो एम और 616 दिनाक तक की थोल्ट वाले केवल के निये ड्वले रेजिन पर आधारित संरीण भार पार जोड़ों के सांचों की विशिष्टि | सं० 1 1980-03-15 | दिसं० 1979 | (पृष्ठ 6 सारणी 1 टिप्पणी) — इसे काटिए | 1979-12-31 |
| 41. IS : 8810—1978 | रोलेट नमूने की अशु भेली रजिन की विशिष्टि | — सं० 1 अग्न० 1980 | — | (पृष्ठ 1, खंड 1, परिन 1) “स्वच्छमंडल” के स्थान पर “अशु” पढ़िए। | 1980-01-31 |
| 42. IS : 8914—1978 | कौतांब हनेमल उद्योग के लिये जल गुणता संबंधी छूटें। | — सं० 1 दिसं० 1979 | — | सारणी 1 का संशोधन किया गया है। | 1979-12-31 |

[संख्या सो०एम०डी०/13:5]

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 24th November, 1982

S. O. 205.—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

THE SCHEDULE

| Sl. No. and title of the Indian Standard No. | Amended | No. and Date of Gazette Notifi- cation in which the establishment of the Indian Standard was notified | No. and Date of the Amendment | Brief particulars of the Amendment | Date from which the amend- ment shall have effect |
|---|-------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. IS : 178-1965 Specification for cotton twills (Revised) | SO 1932 dt.d 1966-07-02 | No. 2 Jan 1980 | A new note has been added after clause 2.2.1 1980-01-31 | | |
| 2. IS : 180-1965 Specification for cotton sheetings (Revised) | do | No. 2 Jan 1980 | A note has been added after clause 2.2.1. 1980-01-31 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------------|-----------------|---|------------|-----|
| 3. IS : 221-1977 Specification for ink, fluid blue black, for permanent records (Second Revision) | — | No. 1 Dec 1979 | In view of the publication of IS : 8642-1977 'Specification for dyes for water-based writing inks' in which the requirements of 'dye, ink blue, have been covered, IS : 2247-1962 'Specification for dye, ink blue for ink industry' has been withdrawn. Hence this amendment is being issued. | 1979-12-31 | |
| 4. IS : 435-1973 Specification for castor oil (Second Revision) | S.O. 4690 dated 1975-11-01 | No. 1 Dec 1979 | (i) Clause 4.2 has been substituted by a new one (ii) (Pages 4 and 5 clauses 4.2.1 and 4.2.2 Delete (iii) Title of Appendix A has been substituted by a new | 1979-12-31 | |
| 5. IS : 694-1977 Specification for PVC insulated cables for working voltages up to and including 1100 volts (Second Revision) | — | No. 1 Jan 1980 | (i) Contents at page 3 against Sl. No. 11 and 12 have been amended. (ii) New clause 0.4 has been added after clause 0.3 and the subsequent clauses have been re-numbered accordingly. (iii) Clauses 1.1, 1.2, 9.4 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 12.3.1 and A-1 have been amended. (iv) Clause 2.4, 11.4, 12.2, 12.3, A-2 to A-3.1 and B-1 have been substituted by new ones. (v) Existing note has been redesignated as 'Note 1' and a new 'Note 2' has been added under clause 8.1 (vi) New clause 9.5 has been added after clause 9.4 and the subsequent clauses have been re-numbered accordingly. (vii) A note has been added after clause 13.2 (viii) A new item (q) has been added after item (P) (ix) (Page 15, clause B-1.1, Note)—Delete (x) (Page 16, clause B-2.3, informal table, first column, second entry)—Delete the words 'and up to and including 50'. | 1980 01-31 | |
| 6. IS : 732-1963 Code of practice for electrical wiring installations (system voltage not exceeding 650 volts) (Revised) | S.O. 1147 dated 1963-04-20 | No. 6 Jan 1980 | Clause 5.8.1 (e) has been substituted by a new one | 1980-01-31 | |
| 7. IS : 750-1976 Specification for handloom cotton lungies (First Revision) | — | No. 2 Jan 1980 | Table 1 has been amended | 1980-01-31 | |
| 8. IS : 774-1971 Specification for flushing cisterns for water closets and urinals (valveless siphonic type) (Third Revision) | S.O. 231 dated 1974-01-26 | *No. 5 Jan 1980 | (i) Clauses 4.3, 4.4, 4.8 and 4.8.1, have been substituted by new ones (ii) New clauses 2.3 and 3.2.1 have been added after clauses 2.2 and 3.2 respectively | 1980-01-31 | |
| 9. IS : 902-1974 Specification for suction hose couplings for fire fighting purposes (Second Revision) | S.O. 1596 dated 1976 05-08 | No. 3 Dec 1979 | Tables 1A, 1B, 2A, 2B have been amended | 1979-12-31 | |
| 10. IS : 1169-1967 Specification for electric pedestal type fans and regulators (First Revision) | S.O. 1720 dated 1968-05-18 | No. 4 Jun 1980 | Existing Notes under clauses 16.2.1 and 16.2.1.2 have been substituted by new ones | 1980-01-31 | |
| 11. IS : 1235-1958 Specification for acetic anhydride | S.O. 1949 dated 1958-09-27 | No. 1 Dec 1979 | Clause B-2.3.2.1 has been amended | 1979-12-31 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------------|-----------------|--|-----|--------------------------|
| 12. IS: 1266-1968 Specification for handloom serge | S.O. 2654 dated 1958-12-27 | No. 1 Dec 1979 | This amendment is being issued to incorporate editorial changes and for referring the latest version of Indian Standards on methods of tests for different characteristics. | | 1979-12-31 |
| 13. IS: 1288-1973 Methods of test for mineral gypsum and gypsum products (First Revision) | S.O. 4690 dated 1975-11-01 | No. 2 Jan 1980 | (i) Clauses 10.2.2 and 11.2.1.3 have been amended. (ii) (Page 12, clause 10.2.3, formula)—Substitute '280.4' for '140.2'. (iii) (Page 14, clause 11.2.3, formula)—Substitute '201.6' for '100.8'. | | 1980-01-31 |
| 14. IS : 1423-1973 Specification for cotton gaberdine (First Revision) | S.O. 2558 dated 1975-08-09 | No. 1 Jan 1980 | Table I has been amended | | 1980-01-31 |
| 15. IS : 1445-1977 Specification for porcelain insulators for overhead power lines with a nominal voltage up to and including 1 000 V (Second Revision) | — | No. 1 Dec 1979 | (Page 11 clauses 7 and 7.1)—Delete and renumber the subsequent clauses accordingly. | | 1979-12-31 |
| 16. IS : 1492—1970 Specification for metric surveying chains (First Revision) | S.O. 1635 dated 1972-07-08 | No. 2 Dec. 1979 | Clause 5.1 has been amended | | 1979-12-31 |
| 17. IS : 1776—1961 Specification for folding box board, uncoated | S.O. 2534 dated 1961-10-28 | No. 3 Dec 1979 | Tables I and II have been amended | | 1979-12-31 |
| 18. IS : 1886—1967 Code of practice for installation and maintenance of transformers (First Revision) | S.O. 2789 dated 1967-08-19 | No. 4 Jan 1980 | (Page 11, Fig. 1, Note 1, Line 1)—Delete the words 'of about 500 kVA rating'. | | 1980-01-31 |
| 19. IS : 2037—1962 Specification for tracing cloth | S.O. 2562 dated 1962-08-11 | No. 3 Dec 1979 | (i) Clause C-2.1 of second reprint and clause C-1.2 of third reprint have been substituted by new ones. (ii) Clause C-2.1 (Page 10 of first reprint) has been substituted by a new one. (i) Table 1 has been amended (ii) Fig. 1 has been substituted by a new one. (iii) A new note has been added after clause 3.1 | | 1979-12-31 1980-01-31 |
| 20. IS : 2081 (Pt I)—1976 Specification for taper terminal cable connectors for automobile batteries Part I brass type connectors (First Revision) | S.O. 3822 dated 1979-11-24 | No. 1 Jan 1980 | | | |
| 21. IS : 2361—1970 Specification for bulldog grips (First Revision) | S.O. 1277 dated 1972-05-27 | No. 3 Dec 1979 | Clause 2.1.2 has been substituted by a new one. | | 1979-12-31 |
| 22. IS : 2413—1978 Specification for cotton twine (First Revision) | — | No. 1 Jan 1980 | Informal table of clause 6.5 has been amended. | | 1980-01-31 |
| 23. IS : 2453—1978 Specification for cable-laid cotton rope (First Revision) | — | No. 1 Jan 1980 | Clause 0.2, 0.4 and Table 1 have been amended | | 1980-01-31 |
| 24. IS : 2490 (Pt I)—1974 Tolerance limits for industrial effluents discharged into inland surface waters Part I General limits (First Revision) | S.O. 182 dated 1976-01-10 | No. 1 Dec 1979 | [Page 7, Table 1, Sl. No. (xxiv)—Delete.] | | 1979-12-31 |
| 25. IS : 2582 (Pt II)—1972 Dimensions for lathe spindle noses and face plates Part II spindle noses—camlock type (First Revision) | S.O. 2081 dated 1975-07-05 | No. 1 Dec 1979 | Fig. 1 and table 1 have been substituted by a new one. | | 1979-12-31 |
| 26. IS : 3775—1966 Specification for huckaback towels, cotton khadi, bleached | S.O. 913 dated 1967-03-18 | No. 2 Jan 1980 | Note 4 under table 1 has been substituted by a new one. | | 1980-01-31 |
| 27. IS : 4651 (Pt IV)—1969 Code of practice for design and construction of dock and harbour structures Part IV sheet pile retaining walls | S.O. 436 dated 1970-02-07 | No. 1 Jan 1980 | [Consequent to the revision of IS : 4651 (Part I)—1974 and IS : 4651 (Part III)—1974 and also publishing a standard on Glossary, namely, IS : 7314—1974 Glossary of terms relating to port and harbour engineering, it became necessary to issue an Amendment to IS : 4651 (Part IV)—1969] | | 1980-01-31 |

* For purposes of 'ISI Certification Marks Scheme'; this amendment shall come into force with effect from 1980-03-01

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|----------------------------|----------------|--|------------|-----|
| 28. IS : 4890—1968 Methods for measurement of suspended sediment in open channels | S.O. 3929 dated 1969-09-27 | No. 1 Dec 1979 | A new clause 4.5.3.1. has been added after clause 4.5.3 | 1979-12-31 | |
| 29. IS : 5204—1969 Specification for research microscope | S.O. 4848 dated 1969-12-06 | No. 1 Dec 1979 | (i) Clause 4.6 has been substituted by a new one. (ii) (Page 7, clause 4.9.1.1, line 2)—Substitute '0.01 mm' for '0.001 mm'. (Page 7, Table 1, third column 'Glass Type')—Delete. | 1979-12-31 | |
| 30. IS : 5920—1970 Recommendations for the preparation of drawings for optical elements and systems | S.O. 1555 dated 1972-06-24 | No. 1 Jan 1980 | | 1980-01-31 | |
| 31. IS : 6234—1971 Specification for portable fire extinguishers, water type (constant air pressure) | S.O. 1549 dated 1973-06-02 | No. 4 Jan 1980 | (i) Note under clause 4.1 has been substituted by a new one. (ii) Clause 4.1 has been substituted by a new one. (iii) (Page 5, clause 4.4.3)—Delete. (iv) Clause 9.1, 9.3 and 9.3.1.1 have been amended. (v) Foot notes with 'f' and 'g' marks at page 12 have been substituted by new ones. (vi) A new note has been added after clause 7.2.11. | 1980-01-31 | |
| 32. IS : 6425—1971 Specification for dioptometer (lensometer) | S.O. 751 dated 1974-03-16 | No. 1 Jan 1980 | Clause 4.2 has been amended | 1980-01-31 | |
| 33. IS : 6488—1975 Specification for cotton webbing for personal web equipment (First Revision) | S.O. 2240 dated 1978-08-05 | No. 1 Jan 1980 | (i) Table 1 and 3 have been amended. (ii) (Page 7, clauses 7.1, 7.1.1, 7.1.2 and 7.2)—Substitute the following for the existing clauses : ‘7.1 The sampling plan, number of test specimens and criteria for conformity shall be as given 7 and 8 of IS : 7777—1975’ (iii) Foot notes with ‘*’, ‘+’ and ‘†’ marks have been substituted by a new one. Clause 5.1 has been amended | 1980-01-31 | |
| 34. IS : 6638—1972 Specification for tractor-mounted spring-loaded cultivators | S.O. 770 dated 1975-03-08 | No. 3 Dec 1979 | | 1979-12-31 | |
| 35. IS : 7056—1973 Specification for cotton huckaback towels | S.O. 2939 dated 1975-09-06 | No. 2 Dec 1969 | Table 1 has been substituted by a new one | 1979-12-31 | |
| 36. IS : 7777—1975 Specification for Cotton webbing, rolled, edges | S.O. 3351 dated 1978-11-25 | No. 2 Dec 1979 | Table 1 and 2 have been amended | 1979-12-31 | |
| 37. IS : 8031—1976 Specification for slotted sections | S.O. 3820 dated 1979-11-24 | No. 1 Dec 1979 | (i) Clause 2.1 has been substituted by a new one. (ii) (Page 5, clause 5.4, line 3)—Delete the words shall be given as even finish. (iii) (Page 9, clause 6.6.2.1, line 1)—Substitute 'shall' for 'will'. Tables 8 and 9 have been amended. | 1979-12-31 | |
| 38. IS : 8130—1976 Specification for conductors for insulated electric cables and flexible cords | S.O. 99 dated 1980-01-12 | No. 1 Jan 1980 | | 1980-01-31 | |
| 39. IS : 8308—1976 Specification for compression Type tubular in-line connectors for aluminium conductors for insulated cables | S.O. 419 dated 1980-02-23 | No. 1 Feb 1980 | (i) Clauses 1 and 3 have been substituted by new ones. (ii) (Page 1, Clause 4.1)—Delete and renumber subsequent clauses accordingly. (iii) (Page 3, table 2)—Delete. (iv) Clauses 5 and 6 have been amended. (v) Table 1 has been amended | 1980-02-29 | |
| 40. IS : 8438—1977 Specification for moulds for cast resin based straight through joints for cables for voltages up to and including 1100 volts | S.O. 618 dated 1980-03-15 | No. 1 Dec 1979 | (Page 6, table 1, note)—Delete. | 1979-12-31 | |
| 41. IS : 8810—1978 Specification for roughing for lacrimal SAC, Collet's pattern | — | No. 1 Jan 1980 | (Page 1, clause 1, line 1)—Substitute 'lacrimal' for 'corneal'. | 1980-01-31 | |
| 42. IS : 8914—1978 Quality tolerances for water for vitreous enamel industry | — | No. 1 Dec 1979 | Table 1 has been amended | 1979-12-31 | |

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhurbaneshwar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kathput, Madras, Patna and Trivandrum.

नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 1982

का. ना. 206.—भारतीय मानक यंस्या को और ने एवं द्वारा प्रधिसूचित किया जाता है कि स्त 2 और 3 में वो गई विभिन्न उत्पादों से अंतर्भुक्ती मुहर लगाने का शर्त स्वयं 4 और 5 में उल्लेख के प्रस्तुत पुनरोधित किया रखा है। मुहर लगाने का पुनरीक्षित शुल्क दिनांक 1982-02-01 से आया होगा।

अनुमोदी

| क्रम सं. | उत्पाद सं. | भारतीय मानक को संख्या | इकाई फीस | प्रति इकाई मुहर लगाने को मास के राजात्र भाग 2 वर्ष 3 उत्तर्व (2) में 2 का संदर्भ | अधिकमित एवं ओर संख्या | | विधि प्रयोगी प्रयोगी |
|---|----------------|--------------------------|--|--|--------------------------|------------|----------------------------|
| | | | | | (6) | (7) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | |
| 1. बीएसी (एनसीएच) धूलत चूर्ण | IS : 561-1978 | एक मीटरी टन | रु 3.00 | — | 1231 | 1975-04-19 | 1973-04-30 |
| 2. बीएसी (एनसीएच) जल विसर्जनीय सान्द्र चूर्ण | IS : 562-1978 | एक मीटरी टन | रु 10.00 | — | — | — | — |
| 3. डीडीटी धूल चूर्ण | IS : 564-1975 | एक मीटरी टन | रु 3.00 | 2326 | — | — | 1962-07-28 |
| 4. डीटीटी जल विसर्जनीय मानक चूर्ण | IS : 565-1975 | एक मीटरी टन | रु 10.00 | 117 | — | — | 1963-02-09 |
| 5. ग.स. बीएसी (लिटर) | IS : 632-1978 | 100 लिटर | रु 20.00 | — | 1231 | 1975-04-19 | 1975-04-03 |
| पायसनीय मानक | | | | | — | — | 1975-04-19 |
| 6. डीटीटी पायसनीय मानक | IS : 633-1975 | 100 लिटर | रु 15.00 | 1232 | — | — | 1975-04-03 |
| | | | | 1975-04-03 | | | |
| 7. इथाइलिन डाइकरोहड | IS : 634-1965 | 100 लिटर | रु 15.00 | — | 831 | 1977-03-19 | 1977-02-24 |
| कार्बन टेट्राक्लोरोराहड मिश्रण | | | | | | | |
| 8. कोटाणुनारी तरल पदार्थ | IS : 1061-1975 | एक किलो लिटर | रु 10.00 | 1232 | — | — | — |
| | | | | 1975-04-03 | | | |
| 9. एल्किन पायसनीय मानक | IS : 1307-1973 | 100 लिटर | रु 15.00 | — | 1231 | 1975-04-19 | 1975-04-03 |
| | | | | | | | |
| 10. एल्किन, धूलत, चूर्ण | IS : 1308-1974 | एक मीटरी टन | रु 5.00 | — | — | — | — |
| | | | | | | | |
| 11. साम्र आकर्मिक्लोयाइड धूलत चूर्ण | IS : 1506-1977 | एक मीटरी टन | रु 5.00 | 685 | — | — | 1976-02-14 |
| | | | | 1976-01-21 | | | |
| 12. ताम्र आकर्मिक्लोयाइड जल विसर्जनीय पायसनीय मानक | IS : 1507-1977 | एक मीटरी टन | रु 10.00 | 30 | — | — | 1976-01-17 |
| | | | | 1960-12-26 | | | |
| 13. स्थिरिकृत मेथायमी इथाइल पाराक्लोरोराहड मानक से बने धौधिक पदार्थ | IS : 2358-1963 | 100 किलोग्राम | रु 5.00 | — | 1231 | 1975-04-19 | 1975-04-03 |
| | | | | | | | |
| 14. भालयियोन पायसनीय गान्धी | IS : 2567-1978 | 100 लिटर | रु 15.00 | 1232 | — | — | — |
| | | | | 1975-04-03 | | | |
| 15. मार्गियोन धूलत चूर्ण | IS : 2568-1978 | एक मीटरी टन | रु 15.00 | — | — | — | — |
| | | | | | | | |
| 16. मालाथियान जल विसर्जनीय मानक चूर्ण | IS : 2569-1978 | एक मीटरी टन | (1) रु 15.00 पहली 3267 1000 इकाइयों के 1967-09-01 लिए (2) रु 10.00 अगली 1001 वीं 2000 तक की इकाइयों के लिए (3) रु 2.00 शेष 2001वीं से आगे की इकाइयों के लिए | — | — | — | 1967-09-16 |
| | | | | | | | |
| 17. क्लोरोऐन पायसनीय मानक | IS : 2682-1968 | 100 लिटर | रु 15.00 | 1232 | — | — | 1975-04-19 |
| | | | | 1975-04-30 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|-----|--|----------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 18. | ज्ञानजिनान पायसनीय सांख्र | IS : 2861-1980 | 100 निटर | ₹ 15.00 | — | 1231 1975-04-30 | 1975-04-19 | |
| 19. | कोरोडेन भूलन चूर्ण | IS : 2864-1973 | एक मीटरी टन | ₹ 15.00 पहली 1975-04-03 | 1232 | — | — गति— | |
| 20. | मिशाइल पैरायिल, पायसनीय सांख्र | IS : 2865-1973 | 100 निटर | (1) ₹ 15.00 पहली 500 इकाइयों के निए (2) ₹ 10.00 भगली 501वाँ से 1500 तक की इकाइयों के निए (3) ₹ 2.00 शेष 1501वाँ और इसमें शामि की इकाइयों के निए | 592 1979-09-31 | — | 1231 1979-02-17 | 1979-02-17 |
| 21. | बीजों में लगाने का सुख पारा यौगिक | IS : 3284-1965 | 100 फिलोप्राम | ₹ 3.00 | 1232 1975-04-03 | — | 1975-04-19 | |
| 22. | चिनेज, जन विरासति चूर्ण | IS : 3899-1966 | एक मीटरी टन | ₹ 10.00 | 1713 1968-05-01 | — | 1968-05-18 | |
| 23. | जीराम, जल विरासति चूर्ण | IS : 3901-1975 | एक मीटरी टन | ₹ 10.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 | |
| 24. | डाइमिकोट्ट, पायसनीय सांख्र | IS : 3901-1975 | 100 निटर | ₹ 10.00 | — | — गति— | — गति— | |
| 25. | थायमेट्रोन, पायसनीय सांख्र | IS : 3905-1966 | 100 निटर | ₹ 15.00 | 4702 1975-09-23 | — | 1975-11-01 | |
| 26. | एंडासल्फेन, भूलन चूर्ण | IS : 4323-1967 | एक मीटरी टा | ₹ 5.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 | |
| 27. | एंडोसल्फो चायसनीय सांख्र | IS : 4323-1980 | 100 निटर | (1) ₹ 15.00 पहली 500 इकाइयों के निए (2) ₹ 10.00 भगली 1500 इकाइयों के निए (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के निए | 1389 1979-04-09 | — | 1231 1979-04-21 | 1979-04-21 |
| 28. | विराम जल विरासति चूर्ण | IS : 4766-1968 | एक मीटरी टन | ₹ 10.00 | 1232 1975-05-03 | — | 1975-04-19 | |
| 29. | बीजों में लगाने का विदाम यौगिक पदार्थ | IS : 4783-1968 | 100 फिलोप्राम | ₹ 10.00 | — गति— | — | — गति— | |
| 30. | पायरेटम पायसनीय सांख्र | IS : 4808-1968 | 100 निटर | ₹ 15.00 | — | 4502 1976-11-05 | 1976-11-27 | |
| 31. | डायक्सोरोबोस, पायसनीय सांख्र | IS : 5277-1978 | 100 नीटर | (1) ₹ 10.00 पहली 500 इकाइयों के निए (2) ₹ 5.00 भगली 1500 इकाइयों के निए (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के निए | 2136 1974-08-30 | — | 1974-09-31 | 1974-09-31 |
| 32. | ड्रायकोफोल, पायसनीय सांख्र | IS : 5279-1969 | 100 निटर | ₹ 15.00 | — | 4503 1976-11-05 | 1976-11-27 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|--|-----------------|----------------|---|--------------------|-------------------|------------|------------|
| 33. फिनीट्रोचियात, पायसनीय गांव | IS : 5281--1979 | 100 मिटर | (1) ₹ 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) ₹ 10.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए, (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के लिए | 592 1979-01-31 | — | — | 1979-02-17 |
| 34. पायरेट्र से बना पायसनीय लार्विसाइक्ल सेन | IS : 6014--1978 | 100 मिटर | ₹ 10.00 | — | 616 1980-02-25 | — | 1980-04-15 |
| 35. कास्कमिडन जल धुनताली सांद्र | IS : 6177--1981 | 100 सोटर | (1) ₹ 15.00 पहली 100 इकाइयों के लिए, (2) ₹ 10.00 अगली 600 इकाइयों के लिए | 1659 1981-05-14 | — | — | 1981-06-16 |
| 36. हैट्टाक्सोर, धूलन चूर्ण | IS : 6429--1972 | एक मीटरी टन | ₹ 15.00 | 1694 1975-09-19 | — | — | 1975-11-01 |
| 37. एस्ट्रोमिनियम कार्सेट में बनी टीकिया | IS : 6438--1980 | एक मीटरी टन | ₹ 15.00 | — 1975-04-03 | 12.31 | 1975-04-19 | — |
| 38. हैट्टाक्सोर, पायसनीय सांद्र | IS : 6439--1978 | 100 लीटर | ₹ 20.00 | 953 1978-03-18 | — | — | 1975-03-29 |
| 39. कार्बाइड जल विसर्जनीय सान्द्र चूर्ण | IS : 7121--1973 | एक मीटरी टन | (1) ₹ 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) ₹ 5.00 अगली 1000 इकाइयों के लिए, (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के लिए | 2929 1974-10-21 | — | — | 1974-11-09 |
| 40. कार्बाइड, धूलन चूर्ण | IS : 7122--1973 | एक मीटरी टन | (1) ₹ 2.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) ₹ 1.00 अगली 1000 इकाइयों के लिए, (3) ₹ 0.50 शेष इकाइयों के लिए | 2929 1974-10-21 | — | — | 1974-11-09 |
| 41. टाक्साफैन, पायसनीय सांद्र | IS : 7946--1976 | 100 लीटर | ₹ 15.00 | 76 1977-12-27 | — | — | 1978-01-14 |
| 42. टाक्साफैन, धूलन चूर्ण | IS : 7947--1976 | एक मीटर टन | ₹ 10.00 | 2880 1978-09-14 | — | — | 1978-09-30 |
| 43. क्वीनोलफोम, पायसनीय सांद्र | IS : 8028--1976 | 100 लीटर | (1) ₹ 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) ₹ 5.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए, और (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के लिए | — 1977-08-02 | 2610 | — | 1977-08-20 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|--|------------|------|------------|
| 44. मोनी कॉटोफास जल धूलनशील साइ | IS: 8074—1976 | 100 लीटर | (1) ₹ 20.00 पहली 100 इकाइयों के लिए, (2) ₹ 10.00 प्रत्या 600 इकाइयों के लिए प्रीर (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के लिए | -- | 1977 | 1980-07-26 |
| | | | | 1980-07-09 | | |
| 45. प्राक्तीडेवटोन, मिथाडम, पाय- सनाय साइ | IS: 8259—1976 | 100 लीटर | ₹ 20.00 | 1523 | -- | 1979-05-12 |
| | | | | 1979-04-27 | | |
| 46. फैब्रिएट, पायसनीय साइ | IS: 8291—1976 | 100 लीटर | (1) ₹ 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, प्रीर (2) ₹ 5.00 शेष इकाइयों के लिए | -- | 313 | 1978-02-04 |
| | | | | 1978-01-13 | | |
| 47. कार्बनडेजिम, अल विंजनीय साइ चूर्ण | IS: 8446—1977 | 100 किलो ग्राम | (1) ₹ 20.00 पहला 250 इकाइयों के लिए, (2) ₹ 10.00 प्रत्या 500 इकाइयों के लिए प्रीर (3) ₹ 3.00 शेष इकाइयों के लिए | -- | 3415 | 1980-12-13 |
| | | | | 1980-11-21 | | |
| 48. कोसालोन, पायसनीय साइ | IS: 8487—1977 | 100 लीटर | (1) ₹ 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) ₹ 5.00 प्रत्या 1500 इकाइयों के लिए, प्रीर (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के लिए | 3056 | -- | 1978-10-21 |
| | | | | 1978-09-29 | | |
| 49. कोसालोन, धूलन चूर्ण | IS: 8489—1977 | एक मीटरी | (1) ₹ 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) ₹ 3.00 शेष इकाइयों के लिए | 2352 | -- | 1978-08-19 |
| | | | | 1978-07-31 | | |
| 50. पेराक्टेट डाक्सोराइड साइ ओल | IS: 8497—1977 | 100 लिटर | (1) ₹ 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) ₹ 10.00 प्रत्या 1500 इकाइयों के लिए, प्रीर (3) ₹ 2.00 शेष इकाइयों के लिए | -- | 621 | 1981-02-21 |
| | | | | 1981-01-27 | | |
| 51. क्लोरापायर्टफोस पायसनीय गांड | IS: 8944—1978 | 100 लिटर | ₹ 20.00 | 1391 | -- | 1979-04-28 |
| | | | | 1979-04-11 | | |
| 52. एडिफेनफास, पायसनीय साइ | IS: 8955 — 1978 | 100 लीटर | ₹ 20.00 | -- | | |
| 53. फ्लूक्सोरालिन, पायसनीय साइ | IS: 8959—1978 | 100 लीटर | ₹ 15.00 | -- | 3415 | 1980-12-13 |
| | | | | 1980-11-31 | | |
| 54. मिथाइल पैराधियन धूलन चूर्ण | IS: 8960—1978 | एक मीटरी दर | ₹ 3.00 | -- | 2461 | 1981-03-19 |
| | | | | 1981-03-19 | | |
| 55. बूटाक्लोर, पायसनीय साइ | IS: 9356—1980 | 100 लीटर | ₹ 15.00 | | | |

New Delhi, the 15 December, 1982

S.O. 206.—The Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 2 and 3 of the following Schedule have been revised as mentioned in Col. 4 and 5 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1982-02-01 :

SCHEDULE

| Sl. No. | Product | IS : No. | Unit | Marking Fee per Unit | Reference to Govt. of India Gazette Notification Part-II, Sub-section (ii) | | |
|------------|--|----------------|---------------|--|--|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | Superseed S.O. No. | Partially Modified S.O. No. | Date of Issue |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | BHC (HCH) dusting powders. | IS : 561—1978 | One Tonne | Rs. 3.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 2. | BHC (HCH) water dispersible powder concentrates. | IS : 562—1978 | One Tonne | Rs. 10.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 3. | DDT dusting powders | IS : 564—1975 | One Tonne | Rs. 3.00 | 2326 1962-07-17 | — | 1962-07-28 |
| 4. | DDT water dispersible powder concentrates. | IS : 565—1975 | One Tonne | Rs. 10.00 | 417 1963-02-01 | — | 1963-02-09 |
| 5. | Gamma BHC (indane) EC. | IS : 632—1978 | 100 Litres | Rs. 20.00 | — — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 6. | DDT emulsifiable concentrates | IS : 633—1975 | 100 Litres | Rs. 15.00 | 1232 1975-04-03 | — | 1975-04-19 |
| 7. | Ethylene dichloride-carbon tetrachloride mixture. | IS : 634—1965 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | 831 1977-02-24 | 1977-03-19 |
| 8. | Disinfectant fluids | IS : 1061—1975 | One Kilolitre | Rs. 10.00 | 1232 1975-04-03 | — | 1975-04-19 |
| 9. | Aldrin EC | IS : 1307—1973 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 10. | Aldrin, DP | IS : 1308—1974 | One Tonne | Rs. 5.00 | — | -do- | -do- |
| 11. | Copper oxychloride, DP | IS : 1506—1977 | One Tonne | Rs. 5.00 | 685 1976-01-31 | — | 1976-02-14 |
| 12. | Copper oxychloride, WDPC | IS : 1507—1977 | One Tonne | Rs. 10.00 | 30 1960-12-26 | — | 1961-01-07 |
| 13. | Formulation based on stabilized methoxy ethyl-mercury chloride concentrates. | IS : 2358—1963 | 100 kg | Rs. 5.00 | — — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 14. | Malathion, EC | IS : 2567—1978 | 100 Litre | Rs. 15.00 | 1232 1975-04-03 | — | -do- |
| 15. | Malathion, DP | IS : 2568—1978 | One Tonne | Rs. 15.00 | -do- | — | -do- |
| 16. | Malathion, WDPC | IS : 2569—1978 | One Tonne | (i) Rs. 15.00 per unit for the first 1000 units (ii) Rs. 10.00 per unit for the 1001st to 2000 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 2001st unit and above. | 3267 1967-09-01 | — | 1967-09-16 |
| 17. | Chloradane, EC | IS : 2682—1965 | 100 Litres | Rs. 15.00 | 1232 1975-04-03 | — | 1975-04-19 |
| 18. | Diazinon, EC | IS : 2861—1980 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | 1231 1975-04-03 | -do- |
| 19. | Chloradane, DP | IS : 2864—1973 | One Tonne | Rs. 15.00 | 1232 1975-04-03 | — | -do- |
| 20. | Methyl parathion, EC | IS : 2965—1978 | 100 Litres | (i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above. | 592 1979-01-31 | — | 1979-02-17 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|---|----------------|------------|---|--------------------|--------------------|------------|
| 21. | Organic mercurial dry seed-dressing formulations. | IS : 3284—1965 | 100 kg | Rs. 3.00 | 1232 1975-04-03 | — | 1975-04-19 |
| 22. | Zineb water dispersible powder. | IS : 3899—1966 | One tonne | Rs. 10.00 | 1718 1968-05-01 | — | 1968-05-18 |
| 23. | Ziram, water dispersible powder. | IS : 3901—1975 | One Tonne | Rs. 10.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 24. | Dimethoate, EC | IS : 3903—1975 | 100 Litres | Rs. 10.00 | — | —do- | |
| 25. | Thiometon, EC | IS : 3905—1966 | 100 Litres | Rs. 15.00 | 4702 1975-09-03 | — | 1975-11-01 |
| 26. | Endosulfan, DP | IS : 4322—1967 | One tonne | Rs. 5.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 27. | Endosulfan, EC | IS : 4323—1980 | 100 Litre, | (i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above. | 1389 1979-04-09 | — | 1979-04-21 |
| 28. | Thiram water dispersible powder. | IS : 4766—1968 | One Tonne | Rs. 10.00 | 1232 1975-04-03 | — | 1975-04-19 |
| 29. | Thiram seed dressing formulations. | IS : 4783—1968 | 100 kg | Rs. 10.00 | —do- | — | —do- |
| 30. | Pyrethrum, EC | IS : 4808—1968 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | 4502 1976-11-05 | 1976-11-27 |
| 31. | Dichlorvos, EC | IS : 5277—1978 | 100 Litres | (i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above. | 2436 1975-08-30 | — | 1974-09-21 |
| 32. | Dicofol, EC | IS : 5279—1969 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | 4503 1976-11-05 | 1976-11-27 |
| 33. | Fenitrothion, EC | IS : 5281—1979 | 100 Litres | (i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above. | 592 1979-01-31 | — | 1979-02-17 |
| 34. | Emulsifiable larvical oil, pyrethrum based. | IS : 6014—1978 | 100 Litres | Rs. 10.00 | — | 616 1980-02-25 | 1980-03-15 |
| 35. | Phosphamidon water soluble concentrates. | IS : 6177—1981 | 100 Litres | (i) Rs. 15.00 per unit for the first 100 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 101st unit to 600 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 601st unit and above. | 1659 1981-05-14 | — | 1981-06-06 |
| 36. | Heptachlor, DP | IS : 6429—1972 | One Tonne | Rs. 15.00 | 4694 1975-09-19 | — | 1975-11-01 |
| 37. | Aluminium phosphate tablet formulation. | IS : 6438—1980 | One Tonne | Rs. 15.00 | — | 1231 1975-04-03 | 1975-04-19 |
| 38. | Heptachlor, EC | IS : 6439—1978 | 100 Litre | Rs. 20.00 | 953 1975-03-18 | — | 1975-03-29 |
| 39. | Carbaryl, WDPC | IS : 7121—1973 | One Tonne | (i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1000 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1001st unit and above. | 2929 1974-10-21 | — | 1974-11-09 |
| 40. | Carbaryl, DP | IS : 122—1973 | One Tonne | (i) Rs. 2.00 per unit for the first 5000 units; (ii) Rs. 1.00 per unit for the 5001st to 10000 units; and (iii) Rs. 50 Paise per unit for the 10001st unit and above. | 2929 1974-10-21 | — | 1974-11-09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|----------------|------------|---|--------------------|----------------------|------------|
| 41. | Toxaphene, EC | IS : 7946—1976 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | 76 1977-12-27 | 1978-01-14 |
| 42. | Toxaphene, DP | IS : 7947—1976 | One Tonne | Rs. 10.00 | 2880 1978-09-14 | — | 1978-09-30 |
| 43. | Quinolphos, EC | IS : 8028—1976 | 100 Litres | (i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above | — | 2610 1977-08-02 | 1987-08-20 |
| 44. | Monocrotophos water soluble concentrate | IS : 8074—1976 | 100 Litres | (i) Rs. 20.00 per unit for the first 100 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 101st to 600 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 601st unit and above | — | 1997 1980-07-09 | 1980-07-26 |
| 45. | Oxydemeton-methyl, EC | IS : 8259—1976 | 100 Litres | Rs. 20.00 | 1523 1979-04-27 | — | 1979-05-12 |
| 46. | Phenthate, EC | IS : 8291—1976 | 100 Litres | (i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; and (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st unit and above | — | 313 1978-01-13 | 1978-02-04 |
| 47. | Carbendazim, WDPC | IS : 8446—1977 | 100 kg | (i) Rs. 20.00 per unit for the first 250 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 251st unit to 500 units; and (iii) Rs. 3.00 per unit for the 501st unit and above | — | 3421.5 1980-11-21 | 1980-12-13 |
| 48. | Phosalone, EC | IS : 8487—1977 | 100 Litres | (i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above | 3056 1978-09-29 | — | 1978-10-11 |
| 49. | Phosalone DP | IS : 8489—1977 | One Tonne | (i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; and (ii) Rs. 3.00 per unit for the 501st unit and above | 2352 1978-07-31 | — | 1978-08-19 |
| 50. | Paraquat dichloride salt aqueous solution | IS : 8497—1977 | 100 Litres | (i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above | — | 621 1981-01-27 | 1981-02-21 |
| 51. | Chlorpyrifos, EC | IS : 8944—1978 | 100 Litres | Rs. 20.00 | 1391 1979-04-11 | — | 1979-04-22 |
| 52. | Edisophos, EC | IS : 8955—1978 | 100 Litres | Rs. 20.00 | — | — | — |
| 53. | Fluchlorelvin, EC | IS : 8959—1978 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | 341.5 1980-11-21 | 1980-12-13 |
| 54. | Methyl parathion, DP | IS : 8960—1978 | One Tonne | Rs. 3.00 | — | 461 1981-08-19 | 1981-09-19 |
| 55. | Biotachlor, EC | IS : 9356—1980 | 100 Litres | Rs. 15.00 | — | — | — |

[No. CMD/13 : 10]

प्रधिसूचना

का० आ० 207--भारतीय मानक सम्बाद प्रोग्राम संबंधी अधिसूचित किया जाता है कि स्तर 1, 2 और 3 में दो वर्ष त्रिपुष्टि उपादान से सम्बन्धी मुहर लगाने का शुल्क संस्कृत 4 और 5 में उच्चतम के अनुग्राम प्रतिशतित किया गया है। मुहर लगाने का पुनर्गणित शुल्क प्रत्येक के आगे दो वर्ष त्रिपुष्टि रो साझा होगा।

अनुमती

| क्रम संख्या | उत्पाद की संख्या | वर्तीय सानक का की संख्या | इकाई | प्रति इकाई मूद्रा लगान का फार्म | परा ५ राजपत्र भा० २ खंड ३ उपग्रह (ii) म म ५ का सदर्श | पांच होने की तिथि | | |
|--|------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|----------------------|------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 प्र०मी०प्र० आर० के लिए | IS 398 (भा० 2) 1976 | प्र०मीटरी टन | रु० 4 00 मर्मी | -- | 1125 1979-04-22 | 1981 10-16 | 1978-04-04 | |
| | | | | | | | | |
| 2 धूष का पाउडर IS 1165 1975 | प्र०मीटरी टन | (1) रु० 12 00 पहला 500 इकाइयों के लिए | 312 1983-01-21 | -- | 1963-02-02 | 1981-11-01 | | |
| | | (2) रु० 8 00 अगला 500 इकाइयों के लिए | | | | | | |
| | | (3) रु० 5 00 बीष इकाइयों के लिए | | | | | | |
| 3 सघनिक धूष IS 1166-1973 | प्र०मीटरी टन | (1) 12 00 पहला 500 इकाइयों के लिए | 2724 1963-09-12 | -- | 1963-09-21 | 1981 11-01 | | |
| | | (2) रु० 8 00 अगला 500 इकाइयों वा लिए | | | | | | |
| | | (3) रु० 5 00 बीष इकाइयों के लिए | | | | | | |
| 4 मिगू के लिए IS 1547-1969 दुर्घट अहार | प्र०मीटरी टन | (1) रु० 12 00 पहली 500 इकाइयों के लिए | 311 1963-01-21 | -- | 1963-02-02 | 1981-11-01 | | |
| | | (2) रु० 8 00 अगला 500 इका- इयों के लिए | | | | | | |
| | | (3) रु० 5 00 बीष इकाइयों के लिए | | | | | | |
| 5 टेडजाइन, खाद्य IS 1693-1974 खाद्य प्रैदृ | प्र० किनोग्राम | रु० 0 40 मर्मी | 2573 1974-09-23 | -- | 1974-10-25 | 1981-10-16 | | |
| 6 मूर्यासन पीला IS 1695-1974 एफ० सी एफ० खाद्य प्रैदृ | प्र० किला ग्राम | रु० 0 10 मर्मी | --वह-- | | वही | वहा | | |
| 7 अम्बेल खाद्य IS 1696-1974 | प्र० किनोग्राम | रु० 0 10 मर्मी | वही | -- | वही | वही | | |
| 8 अम्बेल खाद्य, IS 1697-1974 खाद्य प्रैदृ | प्र० किनोग्राम | रु० 0 10 मर्मी | 2583 1974-09-23 | -- | वही | वही | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|---|--|--|--------------------|--------------------|------------|------------|-----|
| 9. | इंडिगो कार्माइन IS : 1698-1974] आध प्रेड | एक किलोग्राम | ₹ 0. 40 सभी | बही | -- | बही | बही | |
| 10. | पांसों 4 आर० IS : 2558-1974 आधप्रेड | एक किलोग्राम ₹ 0. 40 सभी | बही | -- | बही | बही | | |
| 11. | आइसक्रीम । IS : 2802-1964 | 100 मिटर (1) ₹ 5. 00 पहली 1000 इकाइयों के लिए (2) ₹ 2. 00 प्रत्यां 1000 इकाइयों के लिए (3) ₹ 1. 50 सेव इकाइयों के के लिए | 122 1968-12-27 | | -- | 1969-01-11 | 1981-11-01 | |
| 12. | कामबोसाइन IS : 2923-1974 आध प्रेड | एक किलोग्राम | ₹ 0. 40 सभी | 2583 1974-09-23 | -- | 1974-10-05 | 1981-10-16 | |
| 13. | पक्का लाल ई IS : 2924-1974 आध प्रेड | एक मीटरी ₹ 0. 40 सभी दर | --बही | -- | बही | बही | | |
| 14. | केली पर IS : 3975-1979 कवच चाढ़ाने के लिए मृदु इस्पात के तार पट्टियां और देष्ट | एक मीटरी ₹ 2. 50 सभी एक | -- | 2241 1978-07-19 | 1978-08-05 | 1981-01-16 | | |
| 15. | चमकदारनीला IS : 6406-1977 एफ०सी०एफ० आध प्रेड | एक किलोग्राम | ₹ 0. 40 सभी | -- | 3168 1980-10-24 | 1980-11-16 | 1981-10-16 | |
| 16. | चुंहगम और IS : 6747-1981 बबतगम | एक किलोग्राम | (1) ₹ 0. 10 50000 इकाइयों के लिए (2) ₹ 0. 75 150000 इकाइयों के लिए (3) ₹ 0. 50 सेव इकाइयों के लिए | -- 1976-10-27 | 4391 | 1976-11-20 | 1981-10-01 | |
| 17. | छोटे साइज के IS : 7347-1974 चिपारी ग्रन्ट : दाहीइंजन की कार्यकारिता का निष्पादन | एक इंजन | (1) 1. 00 पहली 10000 इकाइयों के लिए (2) ₹ 0. 50 सेव इकाइयों के लिए | 2452 1975-07-07 | -- | 1975-08-02 | 1981-11-16 | |

[सं० सी० एम० डी०/13: 10]

ए० पी० बनर्जी अपर महानिदेशक

S.O. 207.—The Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 2 and 3 of the following Schedule have been revised as mentioned in Col 4 and 5 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from the dates shown against each :

1085 GI/82—23.

SCHEDULE

| Sl. No. | Product | IS : No. | Unit | Marking Fee per Unit | Reference to Govt. of India Gazette Notification—Part-II, Section-3, Sub- Section (ii) | | | Date of Effect |
|------------|--|-------------------------|------------|---|--|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Superseded S.O. No. | Partially modified S.O. No. | Date of Issue | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Steel core wire for ACSR | IS : 398 (Part II)—1976 | One Tonne | Rs. 4.00 All | — | 1125 1978-04-04 | 1978-04-02 | 1981-10-16 |
| 2. | Milk powder | IS : 1165—1975 | One Tonne | (i) Rs. 12.00 First 500 (ii) Rs. 8.00 Next 500 (iii) Rs. 5.00 Remaining | 312 1963-01-21 | — | 1963-02-02 | 1981-11-01 |
| 3. | Condensed milk | IS : 1166—1973 | One Tonne | (i) Rs. 12.00 First 500 (ii) Rs. 8.00 Next 500 (iii) Rs. 5.00 Remaining | 2724 1963-09-12 | — | 1963-09-21 | 1981-11-01 |
| 4. | Infant milk foods | IS : 1547—1968 | One Tonne | (i) Rs. 12.00 First 500 (ii) Rs. 8.00 Next 500 (iii) Rs. 5.00 Remaining | 311 1963-01-21 | — | 1963-02-02 | 1981-11-01 |
| 5. | Tartazine, food grade | IS : 1694—1974 | One kg | Rs. 0.40 All | 2579 1974-09-23 | — | 1974-10-25 | 1981-10-16 |
| 6. | Sunset yellow, FCF, food grade | IS : 1695—1974 | One kg | Rs. 0.40 All | -do- | — | 1974-10-25 | 1981-10-16 |
| 7. | Amaranth, food grade | IS : 1696—1974 | One kg | Rs. 0.40 All | -do- | — | 1974-10-25 | 1981-10-16 |
| 8. | Erythrosine, food grade | IS : 1697—1974 | One kg | Rs. 0.40 All | 2583 1974-09-23 | — | 1974-10-25 | 1981-10-16 |
| 9. | Indigo carmine, food grade | IS : 1698—1974 | One kg | Rs. 0.40 All | -do- | — | 1974-10-25 | 1981-10-16 |
| 10. | Ponceau 4 R, food grade | IS : 2558—1974 | One kg. | Rs. 0.40 All | -do- | — | 1974-10-25 | 1981-10-16 |
| 11. | Ice-cream | IS : 2802—1964 | 100 Litres | (i) Rs. 5.00 First 1000 (ii) Rs. 2.00 Next 1000 (iii) Rs. 1.50 Remaining | 122 1968-12-27 | — | 1969-01-11 | 1981-11-01 |
| 12. | Carmoisine, food grade | IS : 2923—1974 | One kg | Rs. 0.40 All | 2583 1974-09-23 | — | 1974-10-05 | 1981-10-16 |
| 13. | Fast red E, food grade | IS : 2924—1974 | One kg | Rs. 0.40 All | -do- | — | 1974-10-05 | 1981-10-16 |
| 14. | Mild steel wires, strips and tapes for armouring of cables | IS : 3975—1979 | One Tonne | Rs. 2.50 All | — | 2241 1978-07-19 | 1978-08-05 | 1981-10-16 |
| 15. | Brilliant blue, FCF, food grade | IS : 6406—1977 | One kg | Rs. 0.40 All | — | 3168 1980-10-24 | 1980-11-15 | 1981-10-16 |
| 16. | Chewing gum and bubble gum | IS : 6747—1981 | One kg | (i) Rs. 0.10 First 50000 (ii) Rs. 0.75 next 150000 (iii) Rs. 0.05 Remaining | — 1976-10-27 | 4391 | 1976-11-0 | 1981-10-01 |
| 17. | Perfomance of small size spark | IS : 7347—1974 | One Engine | (i) Rs. 1.00 First 10000 (ii) Rs. 0.50 Remaining | 2452 1925-07-07 | — | 1975-08-0 | 1981-11-01 |

[No. CMD/13 : 10]

A.P. BANERJEE, Additional Director General

मंत्री मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का०आ० 208.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सी टो एफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाने चाहिए;

ओर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः शब्द पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का आना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

बताते कि उक्त भूमि में द्वितीय कोई व्यक्ति, उस भूमि के नोंच पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा 9 को इस अधिकार सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह यह बाहरा है कि उन्हीं सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विरमगाम से सी टो एफ कलोल तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाणा तालुका: कडी

| गांव | सर्वे नं० | हेक्टेयर | ए. आर | सेटो-अर |
|--------|------------|----------|-------|---------|
| वसाथवी | कार्टट्रैक | 0 | 00 | 75 |
| | 211 | 0 | 35 | 85 |
| | 209 | 0 | 27 | 75 |
| | 248 | 0 | 11 | 70 |
| | कार्टट्रैक | 0 | 04 | 20 |
| | 219 | | 14 | 25 |
| | 222 | | 09 | 60 |
| | 220 | | 29 | 55 |
| | 221 | | 13 | 20 |
| | कार्टट्रैक | 0 | 00 | 60 |

[सं० ओ-12016/62/82-प्र०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 208.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

| Village | Survey No. | Hecto- tares | Acre Centiares |
|----------|------------|-----------------|-------------------|
| Valavedi | Cart Track | 0 | 00 75 |
| | 211 | 0 | 35 85 |
| | 209 | 0 | 27 75 |
| | 248 | 0 | 11 70 |
| | Cart Track | 0 | 04 20 |
| | 219 | 0 | 14 25 |
| | 222 | 0 | 09 60 |
| | 220 | 0 | 29 55 |
| | 221 | 0 | 13 20 |
| | Cart Track | 0 | 00 60 |

[(No. O-12016/62/82-Prod.

का०आ० 209.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम में सी टो एफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जाने चाहिए;

ओर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः शब्द पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितधद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-९ को इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता पहुँ भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कड़ी]

| गांव | सर्वे नं० | हेक्टर | भार | सेटीयर |
|-----------|------------|--------|-----|--------|
| इश्वरपुरा | 41 0 28 20 | | | |

[सं० ०-१२०१६/६३/८२-प्र०]

S.O. 209.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (30 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

| Village | Survey No. | Hec-tare | Acre | Cen-tiare |
|------------|------------|----------|------|-----------|
| Ishwarpura | 41 | 0 | 28 | 20 |

[No. O-12016/63/82-प्र०]

का० आ० 210.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में वह शावशक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सी टी एफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्राप्ति करना आवश्यक है।

यह: अब पेट्रोलियम और अनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अवैन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त अनियतों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार प्राप्ति करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितधद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-९ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता पहुँ भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइपलाईन बिछाने के लिए

| राज्य : गुजरात | जिला : मेहसाना | तालुका—कड़ी | | |
|----------------|----------------|-------------|-----|--------|
| गांव | सर्वे नं० | हेक्टर | भार | सेटीयर |
| बिनायकपुरा | 46 | 0 | 07 | 80 |
| | 47 | 0 | 01 | 80 |
| | 45 | 0 | 24 | 90 |
| | 42 | 0 | 10 | 95 |
| | 41 | 0 | 07 | 80 |
| | 40 | 0 | 07 | 50 |
| | 38 | 0 | 09 | 00 |
| | 39 | 0 | 00 | 80 |
| | 25 | 0 | 04 | 05 |
| | 27 | 0 | 24 | 75 |
| | 32 | 0 | 02 | 00 |
| | 28 | 0 | 04 | 00 |
| | 29 | 0 | 08 | 25 |
| | 30 | 0 | 20 | 25 |
| | 19 | 0 | 09 | 45 |

[सं० ०-१२०१६/५९/८२-प्र०]

S.O. 210.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol

| State : Gujarat | District : Mehsana | Taluka : Kadi | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|
| Village | Survey No. | Hec-tare | Are Centiare |
| Vinayakpura | 46 | 0 07 | 80 |
| | 47 | 0 01 | 80 |
| | 45 | 0 24 | 90 |
| | 42 | 0 10 | 95 |
| | 41 | 0 07 | 80 |
| | 40 | 0 07 | 50 |
| | 38 | 0 09 | 00 |
| | 39 | 0 00 | 60 |
| | 25 | 0 04 | 05 |
| | 27 | 0 24 | 75 |
| | 32 | 0 02 | 00 |
| | 28 | 0 04 | 00 |
| | 29 | 0 08 | 25 |
| | 30 | 0 20 | 25 |
| | 19 | 0 09 | 45 |

[No. 0-12016/59/82-Prod.]

का० आ० 211 :—यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन०के०ए०एम० से जी०जी०एस० कम सी०टी०एफ० कड़ी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आलय एतद्वारा घोषित किया है।

बताते कि उक्त भूमि में हिस्तबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निमिण और देशभाल प्रभाग,

मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी करेगा कि क्या वह यह बाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि अवसायी की माफ़त।

अनुसूची

एन० के ०५० एम० से जी०जी०एस० कम सी०टी०एफ० कड़ी तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात ज़िला: अहमदाबाद तालुका: विरमगाम

| गांव | सर्वे नं० | हेक्टेयर | एकारी | सेन्टीआर |
|---------|-----------|----------|-------|----------|
| बालसासण | 280/1 | 0 | 05 | 40 |
| | 280/2 | 0 | 10 | 20 |
| | 264/1 | 0 | 18 | 60 |
| | 264/2 | 0 | 13 | 80 |
| | 265 | 0 | 09 | 60 |
| | 269 | 0 | 05 | 04 |
| | 268/3 | 0 | 06 | 84 |
| | 288/1 | 0 | 05 | 28 |
| | 249 | 0 | 20 | 28 |
| | 250/1 | 0 | 17 | 40 |

[सं० ०-१२०१६/६४/८२-प्रोड०]

S.O. 211.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKAM to GGS Cum CTF Kadi in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline D.S. NKAM to GGS-Cum-CTF Kadi
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

| Village | Survey No. | Hec-tare | Are Centiare |
|----------|------------|----------|--------------|
| Balsasan | 280/1 | 0 | 05 |
| | 280/2 | 0 | 10 |
| | 264/1 | 0 | 18 |
| | 264/2 | 0 | 13 |
| | 265 | 0 | 09 |
| | 269 | 0 | 05 |
| | 268/3 | 0 | 06 |
| | 268/1 | 0 | 05 |
| | 249 | 0 | 20 |
| | 250/1 | 0 | 17 |

[No. 0-12016/64/82-Prod.]

कांग्रा० 212 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सीटीएफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपावड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के प्रधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस सूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राविकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

अनुसूची

विरमगाम से सीटीएफ कलोल तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

| राज्य : गुजरात | जिला : मेहसाना | तालुका : कडो | | |
|----------------|----------------|--------------|----|----------|
| गांव | सर्वे नं० | हेक्टेयर | आर | सेन्टीयर |
| कलयाणपुरा | 233/2 | 0 | 21 | 65 |
| | 233/1 | 0 | 14 | 00 |
| | 234 | 0 | 03 | 20 |
| | 280 | 0 | 00 | 80 |
| | 279/2 | 0 | 31 | 80 |
| | 279/1 | 0 | 07 | 35 |
| | 277 | 0 | 15 | 75 |
| काट्टे ट्रैक | Cart Track | 0 | 02 | 25 |
| | 243 | 0 | 27 | 30 |
| | 273 | 0 | 22 | 20 |
| | 272 | 0 | 37 | 80 |
| | 261 | 0 | 06 | 75 |
| | 260 | 0 | 05 | 25 |
| | 259 | 0 | 02 | 25 |
| | 253/2 | 0 | 06 | 75 |
| | 254 | 0 | 04 | 50 |
| | 256 | 0 | 12 | 30 |

[सं० O-12016/60/82-प्रोड०]

S.O. 212.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL is Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

| Village | Survey No. | Hectare | Are | Centi- ares |
|------------|------------|---------|-----|----------------|
| Kalyanpura | 233/2 | 0 | 21 | 65 |
| | 233/1 | 0 | 14 | 00 |
| | 234 | 0 | 03 | 20 |
| | 280 | 0 | 00 | 80 |
| | 279/2 | 0 | 31 | 80 |
| | 279/1 | 0 | 07 | 35 |
| | 277 | 0 | 15 | 75 |
| Cart Track | Cart Track | 0 | 02 | 25 |
| | 243 | 0 | 27 | 30 |
| | 273 | 0 | 22 | 20 |
| | 272 | 0 | 37 | 80 |
| | 261 | 0 | 06 | 75 |
| | 260 | 0 | 05 | 25 |
| | 259 | 0 | 02 | 25 |
| | 253/2 | 0 | 06 | 75 |
| | 254 | 0 | 04 | 50 |
| | 256 | 0 | 12 | 30 |

[No. 0-12016/60/82-Prod.]

कांग्रा० 213 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सीटीएफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपावड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) धारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशर्ते कि उक्त भूमि में हिंडबद्द कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आधेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस प्रधिष्ठूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आधेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टा यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विरमगाम से सी०टी०एफ० कलोत तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

| राज्य: गुजरात | जिला : मेहसाना | तालुका : कडी | गांव | सर्वे नं० | हेक्टेमर | एकारहै | सेन्टीमर |
|---------------|----------------|--------------|------|-----------|----------|--------|----------|
| जेसांगपुरा | 100 | 0 | 16 | 20 | | | |
| | 99 | 0 | 13 | 60 | | | |
| | 115 | 0 | 01 | 40 | | | |
| | 103/2 | 0 | 07 | 35 | | | |
| | 113 | 0 | 17 | 40 | | | |
| | 112 | 0 | 08 | 10 | | | |
| | 109 | 0 | 25 | 50 | | | |
| | 107 | 0 | 36 | 30 | | | |
| | कार्ट ट्रैक | 0 | 01 | 65 | | | |
| | 187 | 0 | 01 | 20 | | | |
| | 191 | 0 | 30 | 00 | | | |
| | 190 | 0 | 00 | 15 | | | |
| | 192 | 0 | 15 | 75 | | | |
| | 193 | 0 | 12 | 00 | | | |

[सं० ०-१२०१६/६१/८२-प्र०३०]

S.O. 214.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provident that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol
State : Gujarat Distt. : Mehsana Taluka : Kadi

| Village | Survey No. | Hec-tare | Acre | Centiare |
|------------|------------|----------|------|----------|
| Jesangpura | 100 | 0 | 16 | 20 |
| | 99 | 0 | 13 | 60 |
| | 115 | 0 | 01 | 40 |
| | 103/2 | 0 | 07 | 35 |
| | 113 | 0 | 17 | 40 |
| | 112 | 0 | 08 | 10 |
| | 109 | 0 | 25 | 50 |
| | 107 | 0 | 36 | 30 |
| Cart Track | 0 | 01 | 65 | |
| | 187 | 0 | 01 | 20 |
| | 191 | 0 | 30 | 00 |
| | 190 | 0 | 00 | 15 |
| | 192 | 0 | 15 | 75 |
| | 193 | 0 | 12 | 00 |

[No. 0-12016/61/82-Prod.]

का० आ० 214:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि नोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी०टी०एफ० कलोत से विरमगाम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोग के लिये एतद्वारा अनुसूची में घण्टि भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

यतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशर्ते कि उक्त भूमि में हिंडबद्द कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आधेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस प्रधिष्ठूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आधेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइप लाईन
बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात ज़िला: अहमदाबाद तालुका: विरमगाम

| गांव | ब्लॉक नं० | हेक्टेयर | एकार्ड सेंटीयर |
|------------|-----------|----------|----------------|
| मोटी कुमाद | 158 | 0 05 | 85 |
| | 157 | 0 07 | 20 |

[सं० O-12016/56/82-प्र०-I]

S.O. 214.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from C.T.F. KALOL to Viramgam in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpurā Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Kalol to Viramgam

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

| Village | Block No. | Hec-tare | Are | Centi- tiare |
|------------|-----------|----------|-----|-----------------|
| Moti Kumad | 158 | 0 | 05 | 85 |
| | 157 | 0 | 07 | 20 |

[No. O-12016/56/82-Prod. I]

का०आ० 215.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की शारा 3 की उपचारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बास्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई अविक्षित, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देवभूमि प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आवेदन करने वाला हर अविक्षित विनियिष्टः यह भी कथम करेगा कि क्या वह यह आहता है कि उसकी सुनवाई अविक्षितगत हो या किसी विधि अवसायी की माफ़ैत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

| गांव | ब्लॉक नं० | हेक्टर | एकार्ड सेंटीयर | |
|------------|-------------|--------|----------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मासी कुमाद | 105 | 0 | 51 | 15 |
| | 106 | 0 | 00 | 10 |
| | 107 | 0 | 15 | 30 |
| | 111 | 0 | 28 | 50 |
| | 112 | 0 | 04 | 35 |
| | कार्ट ट्रैक | 0 | 04 | 05 |
| | 100 | 0 | 25 | 20 |
| | 101 | 0 | 07 | 20 |
| | 99 | 0 | 25 | 65 |
| | 98 | 0 | 11 | 25 |
| | 81 | 0 | 16 | 65 |
| | 82 | 0 | 00 | 15 |
| | 83 | 0 | 00 | 75 |
| | 88 | 0 | 14 | 25 |
| | 90 | 0 | 31 | 95 |
| | 57 | 0 | 25 | 20 |
| | 58 | 0 | 36 | 45 |
| | 59 | 0 | 17 | 25 |
| | 52 | 0 | 09 | 30 |
| | 9 | 0 | 00 | 15 |
| | 51 | 0 | 10 | 35 |
| | 49 | 0 | 00 | 25 |
| | 50 | 0 | 11 | 45 |
| | 46 | 0 | 10 | 05 |
| | 47 | 0 | 10 | 35 |
| | 43 | 0 | 12 | 00 |
| | 42 | 0 | 10 | 80 |
| | 39 | 0 | 17 | 05 |
| | 38 | 0 | 05 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|---|----|----|
| | 37 | 0 | 00 | 20 |
| | 36 | 0 | 03 | 00 |
| | 35 | 0 | 07 | 50 |
| | 34 | 0 | 08 | 40 |
| | 33 | 0 | 17 | 85 |
| | 32 | 0 | 08 | 40 |
| | 31 | 0 | 07 | 50 |
| | 30 | 0 | 07 | 50 |
| | 29 | 0 | 08 | 10 |
| | 28 | 0 | 02 | 55 |

[सं. O-12016/56/82-प्रोड]

S.O. 215.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from C.T.F. KALOL to Viramgam in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Kalol to Viramgam

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

| Village | Block No. | Hec-tare | Arc | Centi-are |
|------------|------------|----------|-----|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nani Kumad | 105 | 0 | 51 | 15 |
| | 106 | 0 | 00 | 10 |
| | 107 | 0 | 15 | 30 |
| | 111 | 0 | 28 | 50 |
| | 112 | 0 | 04 | 35 |
| | Cart Track | 0 | 04 | 05 |
| | 100 | 0 | 25 | 20 |
| | 101 | 0 | 07 | 20 |
| | 99 | 0 | 25 | 65 |
| | 98 | 0 | 11 | 25 |
| | 81 | 0 | 16 | 65 |
| | 82 | 0 | 00 | 15 |
| | 83 | 0 | 00 | 75 |
| | 88 | 0 | 14 | 25 |
| | 90 | 0 | 31 | 95 |
| | 57 | 0 | 25 | 20 |
| | 58 | 0 | 36 | 35 |
| | 49 | 0 | 17 | 25 |
| | 52 | 0 | 09 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|---|----|----|
| | 9 | 0 | 00 | 15 |
| | 51 | 0 | 10 | 35 |
| | 49 | 0 | 00 | 25 |
| | 50 | 0 | 11 | 45 |
| | 46 | 0 | 10 | 05 |
| | 47 | 0 | 10 | 35 |
| | 43 | 0 | 12 | 00 |
| | 42 | 0 | 10 | 80 |
| | 39 | 0 | 17 | 05 |
| | 38 | 0 | 05 | 80 |
| | 37 | 0 | 00 | 20 |
| | 36 | 0 | 03 | 00 |
| | 35 | 0 | 07 | 50 |
| | 34 | 0 | 08 | 40 |
| | 33 | 0 | 17 | 85 |
| | 32 | 0 | 08 | 40 |
| | 31 | 0 | 07 | 50 |
| | 30 | 0 | 07 | 50 |
| | 29 | 0 | 08 | 10 |
| | 28 | 0 | 02 | 55 |

[No. O-12016/56/82-Prod.]

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1982

S.O. 216.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस०एन०रोड से एस०एन०ए०एच० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एनदीपा बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने के अपना आवाय एतद्वारा घोषित किया है ।

बास्तें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस०एन०जे० से एम०एन०ए०प० तक पाइपलाईन विछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला ग तालुका : मेहसाना

| गांव | सं. नं. | हेक्टेयर | एशरई | सेटीयर |
|-------|---------|----------|------|--------|
| संथाल | 612/1 | 0 | 06 | 98 |
| | 605 | 0 | 15 | 72 |
| | 564 | 0 | 05 | 16 |
| | 565 | 0 | 13 | 08 |
| | 566 | 0 | 14 | 04 |
| | 437 | 0 | 05 | 16 |

[म० O-12016/54/82-प्र०ड०]

New Delhi, the 18th November, 1982

S.O. 216.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNZ to SNAH in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009).

And every person making such an objection shall also State specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNZ to SNAH

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana.

| Village | Survey No. | Hec-tare | Arc-tiare | Cen-tiare |
|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Santhal | 612/1 | 0 | 06 | 98 |
| | 605 | 0 | 15 | 72 |
| | 564 | 0 | 05 | 16 |
| | 565 | 0 | 13 | 08 |
| | 566 | 0 | 14 | 04 |
| | 437 | 0 | 05 | 16 |

[No. O-12016/54/82-Prod.]

S.O. 217.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ज एन एम से जे एन ए नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये

पाइपलाईन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयाग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोग के लिये एनदीपायद्ध अनुसूची में अंजित भूमि में उपयोग वा अधिकार अंजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार वा अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (iii) तारा प्रदन शर्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अंजित करने का अपना आशंका एनदीपायद्ध किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिन्दवड़ कोई व्यक्ति, उप भूमि के नीचे पाइपलाईन विछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयाग, निर्माण और देवदाराल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडावडा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों वाली भित्ति कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि वया यह चाहना है कि उसकी सुनवाई अविकल्प हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत

अनुसूची

जे०एन०एम० से जे०एन०ए० तक पाइपलाईन विछाने के लिये

राज्य : गुजरात

जिला और तालुका : मेहसाना

| गांव | लोकाल नं. | हेक्टेयर | एशरई | सेटीयर |
|---------|-----------|----------|------|--------|
| मिडोसना | 125 | 0 | 14 | 40 |
| | 114 | 0 | 06 | 60 |
| | 112 | 0 | 04 | 80 |
| | 111 | 0 | 12 | 60 |
| | 108 | 0 | 00 | 50 |
| | 109 | 0 | 14 | 75 |
| | 102 | 0 | 10 | 80 |
| | 100 | 0 | 09 | 60 |

[म० O-12016/53/82-प्र०ड०]

S.O. 217.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from JNM to JNA in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Roard Vadodara (390009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from D.S. No. JNA to JNM

State : Gujarat

District & Taluka : Mehsana

| Village | Block No | Hec-tare | Arc- | Cent- |
|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | titare | titare |
| Sidosaon | 125 | 0 | 14 | 40 |
| | 111 | 0 | 66 | 60 |
| | 112 | 0 | 04 | 80 |
| | 111 | 0 | 12 | 60 |
| | 103 | 0 | 00 | 50 |
| | 102 | 0 | 14 | 75 |
| | 102 | 0 | 10 | 80 |
| | 100 | 0 | 09 | 60 |

[No. O-12016/53/82-Prod.]

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

का० प्रा० 218.—गृ. भारत सरकार की अधिकृतता के द्वारा त्रैग्रीष्ठ रात्रुद्धो में निर्दिष्ट फिल्म गत है और पेट्रोलिन गैस इंडस्ट्रीज (भूमि में उपयोग के अधिकार का विषय) अधिकार, 1962 के खण्ड 6 के उपचारण (i) के प्रभाग प्रारंभिक फिल्म गता है, गुजरात राज्य के रासाना तेज़ क्षेत्र में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में अधिन स्थल गं० ऐ० एन० एन० एन० ने प्रह्लादाबाद-18 तक पेट्रोलियम पर्सरवहन के लिए भूमि उपलब्ध के अवकाश अर्जित विषय गये हैं।

तेज़ एवं प्रारंभिक गैस रात्रि उपर्युक्त विवरण के खण्ड 7 के उपचारण (i) को भारत (1) विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-2-82 से उपलब्ध कर दिया गया है।

ग्रा० शब्द पेट्रोलिन गैस इंडस्ट्रीज (भूमि में उपयोग के अधिकार का विषय) विधान, 1963 के विधान-4 के अन्तर्गत संसाम प्राधिकारों, प्रारंभिक उक्त विधि को कार्य समाप्त की तिथि अधिकृत बना दी गई।

अनुसूची

ए० एच० एन० से प्रह्लादाबाद-18 तक गाइ लाइन कार्य उपलब्ध

| मान्यता का गाइ का०प्रा०न० | भारत के राज कार्य समाप्ति |
|---------------------------|------------------------------------|
| नाम | पात्र में की विधि प्राप्ति की विधि |

| पेट्रोलियम | रात्रि कार्य इंडस्ट्रीज | 300 | 30-1-82 | 28-2-82 |
|-----------------|-------------------------|-----|---------|---------|
| उर्बेरन नेटवर्क | | | | |

[सं० 12016/37/82-प्रोड]
ए० एच० एन० गाइ, विदेश

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 218.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. AHN to AHMEDABAD-18 in Ramol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 28-2-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FROM
D. S. AHN TO AHMEDABAD-18

| Name of Ministry | Villages | S.O. No. | Date of publication | Date of termination in the Gazette of operation India |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------------|---|
| Petroleum, Chemicals & Fertilizer | Hathujan | 300 | 30-1-82 | 28-2-82 |

[No. 12016/37/82-Prod.]
L. M. GOYAL, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1982

का० प्रा० 219.—प्रांगणी और प्रसाधन सामग्री अधिकृत, 1940 (1940 का 23) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 6 अक्टूबर 1977 की अधिकृता सं० एन० ओ० 3363, का अधिकारण करते हुए कर्त्तव्य सरकार नियन्त्रित विषयक्तियां

1. डा० एम० एन० मक्सेना, निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसीली, और
2. डा० (श्रोता) एन० माहुजा, उपनिवेशक (चिकित्सा) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसीली।

संपूर्ण भारत के लिए नोचे दिए गए अधिकारी वर्गों के लिए सरकारी विनियोग के स्पष्ट में करते हैं :—

1. सीए
2. दूरध्वेशन के प्रयोजनार्थ सोरम प्रोटीन्स का घोल
3. बैकलीने
4. टोकसीन्स
5. एण्टोजन्स

6. एण्टी टोकसीन्स
7. विसंत्रमित सर्जिकल लिगेचर और विसंत्रमित सर्जिकल स्पूचर
8. बैक्टीरियोफेजिज

[सं. एक्स० 11014/2/82-डी० एम० एस० एण्ड पी० एक० ए०]

जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th December, 1982

S.O. 219.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 3363, dated the 6th October, 1977, the Central Government hereby appoints—

1. Dr. S. N. Saxena, Director, Central Research Institute, Kasauli; and
2. Dr. (Mrs.) S. Ahuja, Deputy Director (Medical) Central Research Institute, Kasauli,

to be Government Analysts for the whole of India in respect of the following classes of drugs, namely :—

1. Sera
2. Solution of Serum proteins intended for injection.
3. Vaccines.
4. Toxins.
5. Antigens.
6. Antitoxins
7. Sterilized Surgical ligature and sterilized surgical suture.
8. Bacteriophages.

[No. X. 11014/2/82-DMS&PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

मिर्जान और भाष्यास मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982

का०आ० 220—यतः निम्नान्ति क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली की बृहद योजना में प्रस्तावित करते हैं तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 10-7-1982 के नोटिस सं. एक 20 (37)/80-एम पो द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11 क को उपधारा (3) में अपेक्षित प्राप्ति/सुझाव इस नोटिस का तारीख से 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत आमंत्रित किया गया थे।

श्री यतः उक्त संशोधनों के बारे में कोई प्राप्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की बृहद योजना में संशोधन करने का निर्णय किया गया है।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (2) द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते

हुए भारत के राजपत्र में इस प्रधिसूचना के प्रकाशन को तारीख से दिल्ली की बृहद योजना में निम्ननिवित संशोधन करती है नामतः— संशोधन

1. “लगभग 210.43 हेक्टर (52 एकड़ि) भूमि जो नरेला टाउन के समोप स्थित है और अम्बाला जाने वाली रेलवे लाइन के पश्चिम में पड़ती है, का भूमि उपयोग ‘कृषि हरित पट्टी’ से बदल कर व्यवसायिक (गोदाम एवं भण्डारण छिपो) किया जाता है।”

2. “लगभग 21.043 हेक्टर (52 एकड़ि) भूमि, जो घेरा गांव के समोप स्थित है और रोहतक जाने वाली रेलवे लाइन के उत्तर में पड़ती है, का भूमि उपयोग ‘कृषि हरित पट्टी’ से बदल कर व्यवसायिक (गोदाम एवं भण्डारण छिपो) किया जाता है।”

[सं. के० 13011/4/81-डी०डी०-II ए
बी०बी० रामानाथन, डेस्क प्रधिकारी

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 8th December, 1982

S.O. 220.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(37)/80-MP dated the 10th July, 1982 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice ;

And whereas no objections and suggestions have been received with regard to the said modifications, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this modification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATION :

- (i) “The land use of an area measuring about 21.043 hectcs. (52 acres) located near Naicla Town and situated on the west of Railway line to Ambala is changed from ‘Agricultural Green Belt’ to ‘Commercial (Warehousing and storage depots).’
- (ii) “The land use of an area measuring about 21.043 hectcs. (52 acres) located near Village Ghevra and situated on the North of Railway line to Rohtak is changed from ‘Agricultural Green Belt’ to ‘Commercial (Warehousing and storage depots).’”

[No. K-13011/4/81-DDIIA]
V. V. RAMANATHAN, Desk Officer

संपदा निवेशालय

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1982

का०आ० 221—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (प्राधिकृत प्रधिमोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा विधि, आवास और शहरी विकास मंत्रालय (नियोजन आवास और शहरी विकास विभाग) की अधिसूचना सं. क्र. ०३९११ तारीख १७ दिसम्बर, १९६९ का निम्नान्वित संगोष्ठन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में संनग्न मारणों के संबंध (1) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नान्वित प्रविष्टि रखा जाएगा।

‘उप निदेशक (प्रमाणात)

स्नातकोन्तर ग्राम्यविज्ञान

शिक्षा और प्रतुराधान संस्थान चंडीगढ़।’

[क्र. सं. १२०१३(६)/७८ वल्यूम III]

ग्राम्यसं. बूद्ध, उपनिदेशक

(Directorate of Estate)

New Delhi, the 27th November, 1982

S.O. 221.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (No. 40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works and Housing and Urban Development) No. S.O. 3911 dated the 17th September 1969, namely :—

In the Table appended to the said Notification for the entry in column (1) the following entry shall be substituted
“Deputy Director (Administration) Postgraduates Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.”

[F. No. 12013(6)/78-Vol. III]

R. S. SOOD, Dy. Secy. Estates

प्रिली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1983

क्र. ०३९१० २२२.—वंगना साहिब रोड क्षेत्र के पुनर्विकास प्रारूप को प्रकाशित कराने एवं तैयार किये जाने हेतु दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा-10(1) जिसे दिल्ली विकास नियम, 1959 (मुख्य योजना तथा धौलीय वितान योजना) के नियम 5 तथा 15 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत नोटिस।

1. (ए) वंगना साहिब रोड क्षेत्र के पुनर्विकास का एक प्रारूप तैयार किया गया है तथा

(बी) उक्त प्रारूप की एक प्रति नीचे लिखे कार्यालयों में भवित्वार को छोड़कर सभी कार्यालय दिनों में 11.00 बजे (पूर्वो) से 3.00 बजे (अपराह्न) तक और नीचे पैरा-3 में दी गई तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय-विकास मीनार, इन्ड्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

(2) नई दिल्ली नगर पालिका कार्यालय, टाउन हाल, नई दिल्ली।

(3) दिल्ली नगर निगम कार्यालय, टाउन हाल, नई दिल्ली।

(4) कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, दिल्ली केन्ट बॉर्ड, दिल्ली केन्ट-10

2. बंगना साहिब रोड क्षेत्र के पुनर्विकास प्रारूप के संबंध में एतद्वारा आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

3. आपत्ति या सुझाव दिनांक 30-1-1983 तक सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास मीनार, इन्ड्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दे।

4. जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दे, वह अपना नाम एवं पता लिखें।

[सं. एफ १६(४६)/८०-एम०पी०]

नाथूराम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st January, 1983

S.O. 222—Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft Redevelopment of Bangla Sahib Road Area.

1. (a) a draft of the Redevelopment of Bangla Sahib Road Area has been prepared; and

(b) a copy thereof will be available for inspection at the following offices between the hours of 11.00 a.m. and 3 p.m. on all working days except Saturdays, till the date mentioned in para 3 hereafter.

(i) Office of the Delhi Development Authority Delhi Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi.

(ii) Office of the N.D.M.C., Town Hall, New Delhi

(iii) Office of the M.C.D. Town Hall, Delhi.

(iv) Office of the Executive Officer, Delhi Cantt Board, Delhi Cantt-10.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to the draft Redevelopment of Bangla Sahib Road Area.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi by the 30th January, 1983.

4. Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F. 16(46)/80-MP]
NATHU RAM, Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1982

का०आ० 223.—चूंकि भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संघर्षा का०आ० 2482 दिनांक 10 जुलाई, 1982 के तहत श्री आर०सी० बैनर्जी के जिहोरे यथा पर छोड़ दिया है, स्थान पर श्री क० रामकृष्ण राव को विधायक पदगति डिक्टेवर वीड़ का सदस्य नियुक्त करनी है और उप प्रबोजन के लिए भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना में का०आ० 2432 दिनांक 10 जुलाई, 1982 में संशोधन करनी है जो इस प्रकार है—

और चूंकि विशाखापत्तनम स्टोमशिप एजेंट्स एसोसिएशन श्री क० रामकृष्णराव को विदेशी नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गये थे,

और चूंकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि श्री आर०सी० बैनर्जी, गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (5) के खंड (1) के तहत अब सदस्य नहीं रहे हैं,

और चूंकि उक्त डाक लेवर बोर्ड में एक व्यापार रिप्रॉ हो गया है,

अतः अब गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के तहत केन्द्रीय सरकार उक्त खालों पद को अधिसूचित करती है।

[फा०सं० एल०डो०वी०/6/82-यूएस (एल)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 10th December, 1982

S.O. 223.—Whereas Shri R. C. Banerjee was appointed as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board being a representative of the Overseas Shipping Interests by notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2482, dated the 10th July, 1982 ;

And whereas the Visakhapatnam Steamship Agents' Association has nominated Shri K. Ramakrishna Rao as the representative of the Overseas Shipping Interests ;

And whereas the Central Government is of the opinion that Shri R. C. Banerjee is deemed to have vacated his office under clause (vi) of sub-rule (5) of rule 4 of Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 ;

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[File No. LDV/6/82-US(L)]

का०आ० 224.—गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1962 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा

(1) के दूसरे परन्तुके साथ पंथित गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) 1948 की धारा 5 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नान्त संकारण श्री आर०सी० बैनर्जी के जिहोरे यथा पर छोड़ दिया है, स्थान पर श्री क० रामकृष्ण राव को विधायक पदगति डिक्टेवर वीड़ का सदस्य नियुक्त करनी है और उप प्रबोजन के लिए भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना में का०आ० 2432 दिनांक 10 जुलाई, 1982 में संशोधन करनी है जो इस प्रकार है—

उक्त अधिसूचना में योदी कर्मचारियों और नौवहन सम्पर्कियों का प्रतिनिधित्व करते वाले सदस्य शोषक के अन्वर्गित भद्र संघर्षा 4 में “श्री आर०सी० बैनर्जी” के स्थान पर “श्री क० रामकृष्णराव” लिखा जाय।

[फा०सं० एल०डी०वी०/6/82-यूएस (एल)]

धामस नेथ्यू, अवर् सचिव

S.O. 224.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5-A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules 1962, the Central Government hereby appoints Shri K. Ramakrishna Rao as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board vice Shri R. C. Banerjee, who has vacated his office and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2482, dated the 10th July, 1982, as follows :—

In the said notification, under the heading “Members representing the employers of dock workers and Shipping Companies”, against item No. 4, for the entry “Shri R. C. Banerjee”, the entry “Shri K. Ramakrishna Rao” shall be substituted.

[File No. LDV/6/82-US(L)]
THOMAS MATHEW, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1982

का०आ० 225.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 6 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमन्त्रिक अधिकारी, बम्बई डाक लेवर बोर्ड को उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[फा०सं० एल०डी०वी०/32/82 एम-4]

New Delhi, the 15th December, 1982

S.O. 225.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints the Administrative Officer, Bombay Dock Labour Board to be Inspector for the purpose of the said Act.

[F. No. LDV/32/82-L IV]

अम खण्ड

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का०आ० 226.—कांडलो डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 का संशोधन करने के लिए एक

पास्ता छोड़, डॉकर्स कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उद्धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नीबहन और परिवर्तन बंदरगाह (परिवहन पद) वी अधिवृचता मंडलांक का० उा० 2172 नारीय 22 मई, 1982 के अग्रीत भारत के राजपत्र, भाग 2 अंग 3, उपलब्ध (ii) नारीय 12 जून, 1982 पृष्ठ पर प्रकाशित की गयी थी, जिसमें उक्त अधिवृचता के राजपत्र से प्रकाशन की तर्जस्व में काठ दिन की अवधि से लापत्त तक उन यांत्रिकियों ने आक्षेप और मुकाबला प्राप्त किया था, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजान्त 27 जनवरी, 1982 को जनता को उपलब्ध जौश दिया गया था,

अग्रीत भारत सरकार को जनता से उक्त प्राप्त्य स्कीम की आवश्यकता को गढ़ाकर अतिरिक्त मुआव आप्ति गई है;

इति. श्रद्धा, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उद्धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 का और नंगोधन करने के लिए निम्नलिखित स्तीम बनातो है। अर्थात् :—

1. नियान नाम और प्रारंभ :—(1) इस स्कीम का नियान नाम कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (रजिस्ट्रेशन, 1982 है।

2. कांडला डॉकर्स कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 वा—

(1) खण्ड 6 के म्यान तार, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की सेवा के नियावधन और गति और उत्तरों नियुक्ति—

(1) बाईं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के बारे में सेवा के नियावधन और गति जिनके अंतर्गत बेनत तथा भर्तों के नियन्त्रण और घाँटे भी हैं जो वह छोड़कर समझे, विहिन फर सकेंगा :

उत्तरु बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व ग्रन्तमोदत्त के बिना, ऐसा कोई पद सूचित नहीं करेगा जिनका अधिकार बेनत, उत्तरों को छोड़कर, मौलह या पचास रुपये प्रतिमास और उपर्युक्त हो।

(2) अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति स्कीम में उनके लिए अन्यत्र अवधार उपबंधित के नियावधन द्वारा की जाएगी ;

परन्तु अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पूर्व ग्रन्तमोदत्त के बिना, उन पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा जिनका अधिकार बेनत, भर्तों को छोड़कर, मौलह या पचास रुपये प्रतिमास और उपर्युक्त हो।

परन्तु यह और कि एक साम से अनधिक की अवधि के लिए छुट्टी के कारण हुई किसी रिस्क पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।"

(2) खण्ड 8 में,—

(क) उपलब्ध (1), (ख), (ग), और (ट) का लोप हिया जाएगा।

(ख) उपलब्ध (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपलब्ध रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) खण्ड 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदों के सृजन की मंजूरी दे सकेगा।"

(3) खण्ड 10 के उप खण्ड (1) में,—

(क) मद (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मदे रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(क) रजिस्टरों और पूर्वानुमानित अपेक्षाओं के कानूनिक पुनरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विभिन्न प्रवर्गों के अधीन कर्मकारों की संख्या विधित करना और किसी प्रवर्ग की रजिस्टर में दी गई कर्मकारों की संख्या को, समय समय पर यथा आवश्यक बढ़ाना या घटाना ;

(ख) किसी प्रवर्ग में कर्मकारों की किसी विनिर्दिष्ट संख्या के, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्री-करण की मंजूरी देना;"

(4) खण्ड 17 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17क : अदला-बदली—(क) अध्यक्ष को यह शक्ति होगी कि वह किसी प्रवर्ग के अधिकारियों कर्मकारों को उस प्रवर्ग में जिसमें कर्मकारों की कमी है और कांडला अरजिस्ट्री-करण द्वाकर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1968 के अंतर्गत प्राप्त यांत्रिकरणों के किसी प्रवर्ग में, अधिनियोजित करे किन्तु ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अधिनियोजन से पिछली सेवा की मजदूरी में कमी या प्रभुविधाओं में हानि नहीं होगी ;

टिप्पण : यदि स्कीम के उम प्रवर्ग में जिसमें कमी है, मजदूरी या प्रभुविधा कम है तो स्थानान्तरण ज्वेष्टन के आवार पर किया जाएगा अर्थात् कनिष्ठतम व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जाएगा और उसके द्वारा उपबोग की जा रही मजदूरी और प्रभुविधाओं को उमके लिए वैयक्तिक समझ कर संरक्षित किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष को यह भी शक्ति होगी कि वह कांडला एन्ज न्यास के अधिकारियों कर्मकारों को उस प्रवर्ग में अधिनियोजित करे जिसमें कर्मकारों की कमी है किन्तु ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अधिनियोजन

में पिछली सेवा की मजदूरी में कमी या प्रमुखिया में हानि नहीं होगी।”;

(5) खण्ड 18 में,—

(i) “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहाँ कहीं वह ग्राता है, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

(ii) उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) अध्यक्ष, प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित कर्मकारों की संख्या का कालिकानः पुनर्विलोकन करेगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उस संख्या का समायोजन करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।”;

(6) खण्ड 19 में,—

(i) उपखण्ड (3) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा :

(ii) उपखण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) ऐसे किसी भी प्रवर्ग में, जिसमें डाक कर्मकार को पहले ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकूट किया जा चुका हो, कोई भी नई भर्ती चाहे वह अस्पायी तौर पर हो या स्थायी तौर पर, स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकूट कर्मकारों में से ही की जाएगी। किन्तु यदि कांडला पत्तन न्यास द्वारा नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में अधिशिल्प कर्मकार हैं तो ऐसे अधिशिल्प कर्मकारों को इस स्कीम के अधीन स्थानान्तरित और रजिस्ट्रीकूट किया जाएगा। स्थानान्तरण के पश्चात् यदि अध्यरेखा किए जाने के दिन रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों को ले लेने के पश्चात् सीधी भर्ती की जा सकेगी।”;

(7) खण्ड 45 में उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) श्रम अधिकारी, उपखण्ड (1) या (2) के अधीन किसी भी मामले पर विवार करेगा और यदि प्रारम्भिक अन्वेषण के पश्चात् तथा उस कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकूट डाक कर्मकार यथापूर्वकृत किसी विधिपूर्ण आदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश पारित करेगा कि उस रजिस्ट्रीकूट डाक कर्मकार को खण्ड 44 के अधीन उतनी प्रवधि के लिए संदाय नहीं किया जाएगा जितनी श्रम अधिकारी उचित समझे।”;

(8) खण्ड 46 में,—

(i) उपखण्ड (1) की मद (ii) की उपमद (ब्र) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहाँ कहीं वह ग्राता है “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा :

(ii) उपखण्ड (5) में मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(ग) उसके बैतत में कटींगी करेगी और या उसे निम्नतर प्रवर्ग में प्रव्यावरित कर देगा;” ;

(9) स्कीम की अनुसूची-1 में, मद 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(1क) यदि कांडला डाक श्रम बोर्ड में अधिग्रेष हो और पत्तन न्यास के अधीन स्थोरा हस्तलन कर्मकारों के तत्समान प्रत्यर्ग में कमी हो तो साधारण स्थोरा (अर्थात्, पंज स्थोरा में भिन्न) को तट पर उठाई-धराई अर्थात् घाट पर स्लिंगों में से स्थोरा की लदाई / उत्तराई तथा उसे घाट से अभिवहन क्षेत्र में और, विवरयेन् ले जाना, अभिवहन क्षेत्र में स्थिरा की उठाई-धराई।”।

[फा० सं० एल डीके/19/81-एल 4]

(Labour Division)

New Delhi, the 18th December, 1982

S.O. 226.—Whereas certain draft scheme to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 was published as required by sub-section (1) of Section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 2251—54 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 12th June, 1982 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2172 dated the 22nd May, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 27th January, 1982;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft scheme by the Government of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, namely :—

1. Short title and commencement.—This Scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1982.

2. In the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969.

(1) For clause 6, the following clause shall be substituted, namely :—

“6. Terms and Conditions of service and appointment of Officers and other staff :—

(1) The Board may prescribe the terms and conditions of service including those of salaries and allowances, as it may deem fit, in respect of officers and other members of staff;

Provided that no post the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be created by the Board except with the previous approval of the Central Government.

(2) The appointment of officers and other members of staff shall be made by the Chairman except as otherwise provided for elsewhere in the Scheme:

Provided that no appointment to posts the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be made by the Chairman except with the previous approval of the Central Government :

Provided further that the approval of the Central Government shall not be necessary to any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than one month."

(2) in clause 8,—

(a) sub-clauses (a), (b), (c) and (k) shall be deleted.

(b) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(1) subject to the provision of clause 6, sanction to creation of posts.";

(3) in clause 10,—

in sub-clause (1),

(a) for items (a) & (b), the following items shall be substituted, namely :—

"(a) to fix the number of workers under various categories and to increase or decrease the number of workers in any category on the Register from time to time as may be necessary after a periodical review of Registers and anticipated requirements with the previous approval of the Central Government ;

(b) to sanction the temporary registration of a specified number of workers in any category for a specified period.";

(4) after clause 17, the following new clause shall be inserted, namely :—

"17A : Interchangeability.—(a) The Chairman shall have power to deploy surplus workers in a category to the category wherein there is a shortage of workers, as also under any one of the categories of workers covered by the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 subject to the condition that such deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from the past service ;

Note.—If the category of Scheme in which there is a shortage carries lower wage or benefit, transfer will be made on the basis of seniority, junior-most person being transferred and the wages and benefit being enjoyed by them protected as personal to them.

(b) The Chairman shall also have the power to deploy any surplus worker employed under the Kandla Port Trust in a category in which there is a shortage subject to the condition that deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from past service",

(5) in clause 18,—

(i) for the word "Board" wherever it occurs, the word "Chairman" shall be substituted.

(ii) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(1A) The Chairman shall periodically review the number of workers required in each category and shall take suitable action to adjust the number with the approval of the Central Government".

(6) in clause 19,—

(i) In sub clause (3) for the word "Board" the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) for sub-clause (4) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(4) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis, in any category in which dock workers have already been registered under the Scheme shall be done from amongst the workers registered with the local Employment Exchange. If however, there is a surplus in any category of workers employed by the Kandla Port Trust such surplus workers may be transferred and registered under this scheme. After the transfer, if the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition direct recruitment may be made after absorbing suitable men from the Employment Exchange register.";

(7) in clause 45, for sub-clause (3) the following shall be substituted, namely :—

"(3) The Labour Officer shall consider any matter under sub-clause (1) or (2) and if, after preliminary investigation and after giving reasonable opportunity to the worker of being heard, he is satisfied that the registered dock worker has failed to comply with a lawful order as aforesaid, issue an order that the registered dock worker shall not be paid under clause 44 for such period as Labour Officer thinks fit";

(8) In clause 46 —

(i) in sub-clause (1) item (i) sub-item (b) for the word "Board" wherever it occurs the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (5) after item (c) the following item shall be substituted, namely :—

"(c) effect reduction in his pay and/or revert him to the lower category";

(9) in Schedule-I of the Scheme after item 1 the following item shall be inserted, namely :—

"(a) Shore handling of general cargo (ie other than bulk cargo) i.e. loading/unloading of the cargo into/from the slings on the wharf and carrying the same from wharf to the transit area and vice versa handling of the cargo within the transit area in case there is surplus in the Kandla Dock Labour Board and shortage in the corresponding categories of cargo handling workers under the Port Trust"

TE. No. T.DK/10/21 T.VI

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

का० आ० 227.—मोरमगाश्री डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 का भंगोधन करने के लिए एक प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षासार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना मंड्याक का० आ० 2246 तारीख 29 मई, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपग्रहण (ii) तारीख 19 जून, 1982 के पृष्ठ 2317—19 पर प्रकाशित की गयी थी जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों में आक्षेप और सुझाव मार्गे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त गजपत्र 5 जुलाई, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

श्री भारत सरकार को जनता से उक्त प्राप्ति की बाबत कोई आक्षेप और सुमाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोरमुगाओं डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन), स्कीम 1965 का श्री रसाधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारभ:—इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मारमुगाओं डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1982 है।

2. मोरमुगाओं डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1965 में,

(1) खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

6 अधिकारियों श्री और अन्य कर्मचारिवृन्द की सेवा के निवन्धन श्री और शर्तें श्री डाकी नियुक्ति,

(1) बोर्ड, अधिकारियों श्री और अन्य कर्मचारिवृन्द के बारे में सेवा के निवन्धन श्री और शर्तें जिनके अन्तर्गत वेतन तथा भत्तों के निवन्धन श्री और शर्तें भी हैं जो वह ठीक समझे, विहित कर सकेंगे:

परन्तु बोर्ड केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा कोई पद सूचित नहीं करेगा जिसका अधिकतम वेतन, भत्तों को छाड़कर सोलह सौ पचास रुपए, प्रतिमास और उससे अधिक हो।

(2) अधिकारियों श्री और अन्य कर्मचारिवृन्द को नियुक्ति स्कीम में उसके लिए अन्यत्र अन्यथा उपर्युक्त के सिवाय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु अध्यक्ष केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उन पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा जिनका अधिकतम वेतन-भत्तों को छाड़कर सोलह सौ पचास रुपए, प्रतिमास श्री और उससे अधिक हो :

परन्तु यह श्री कि एक मास से अनधिक की अवधि के लिए छूटटी के कारण हुई किसी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए केंद्रीय राजकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।";

(2) खण्ड 8 में,—

(क) उपखण्ड (क), (घ), (ग) श्री और (ट) का लोप किया जाएगा।

(ख) उपखण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ठ) खण्ड 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

पदों के सूचन की मंजूरी दे सकेगा ;";

(3) खण्ड 10 के उप खण्ड (1) में,—

(क) भद्र (क) श्री और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद्दें रखी जाएँगी, अर्थात्:—

"(क) रजिस्टरों श्री और पूर्वोनुमानित अपेक्षाओं के कालिक पुनरीक्षण के पश्चात केंद्रीय सरकार के पूर्वनिमोदन से विभिन्न प्रवर्गों के अधीन कर्मकारों की संख्या नियत करना श्री और किसी प्रवर्ग को रजिस्टर में दी गई कर्मकारों की संख्या को समय समय पर यथा आवश्यक बढ़ाना या घटाना;

(ख) किसी प्रवर्ग में कर्मकारों की फिरी विनिर्दिष्ट मंस्तक के विसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अन्यथा रजिस्टर करण की मंजूरी देना;"

(4) खण्ड 17 के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"17क: अदला बदली (क) अध्यक्ष को यह शक्ति श्री श्री कि वह किसी प्रवर्ग के अधिशिष्ट कर्मकारों की उस प्रवर्ग में जिसमें कर्मकारों की कमी है अधिनियमोंजित करे कि तुम ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अधिनियमोंजन से पिछली सेवा की मंजूरी में कभी या प्रसुविधाओं में हानि नहीं होगी।

टिप्पण: यदि स्कीम के उभ प्रवर्ग में जिसमें कमी है मंजूरी या प्रसुविधा कम है तो स्थानान्तरण ज्येष्ठता के अधार पर किया जाएगा अर्थात् कनिष्ठतम व्यक्ति के स्थानान्तरित किया जाएगा श्री और उसके द्वारा उपभाग की जा रही मंजूरी श्री और प्रसुविधाओं को उसके लिए वैयक्तिक समझ कर संरक्षित किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष को यह भी शक्ति होगी कि वह— मोरमुगाओं पुतन न्याम के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस प्रवर्ग में अधिनियमोंजित करे जिसमें कर्मकारों की कमी है कि तुम ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अधिनियमोंजन से पिछली सेवा की मंजूरी में कभी या प्रसुविधा में हानि नहीं होगी";

(5) खण्ड 18 में,—

(i) "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, जहां कही वह आता है, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा।

(ii) उपखण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) अध्यक्ष, प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित कर्मकारों की संख्या का कालिकत : पुनर्विलोकन करेगा श्री केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उस संख्या का समायोजन करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।";

(6) खण्ड 19 में,—

(i) उपखण्ड (3) में “बोर्ड” शब्द के स्थान पर “अधिक” शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपखण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा अर्थातः—

“(4) ऐसे किसी भी प्रवर्ग में जिसमें डाक कर्मकार को पहले ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकूट किया जा चुका हो कोई भी नई भर्ती चाहे वह अस्थायी तौर पर हो या स्थायी तौर पर, स्थानोंवाले रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकूट कर्मकारों में से ही की जाएगी। किन्तु यदि सौरमुशाओं पत्तन न्याय द्वारा नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में अधिगिष्ठ कर्मकार है तो ऐसे अधिगिष्ठ कर्मकारों को इस स्कीम के अधीन स्थानन्तरण और रजिस्ट्रीकूट किया जाएगा। स्थानान्तरण के पश्चात यदि अध्यपेक्षा किए जाने के दिन रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या से प्रधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों को ने लेने के पश्चात सीधी भर्ती की जा सकेगी।

(7) खण्ड 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

“35 प्राशान्नग राशि : जब कोई आरवित सूलगत कर्मकार कार्य के लिए उपस्थित हो और किसी कारणवश, वह कार्य जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है आरम्भ न हो सके या आगे न चल सके तो वह पूर्ण काल दर मजदूरी का हकदार होगा, किन्तु इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह पूरी पारी में उपस्थित रहे और दिया जाने वाला बैकल्पिक नियोजन स्वीकार करे।”;

(8) खण्ड 36 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

“36. छुटिया —प्रत्येक कर्मकार ऐसी दरों पर जो बार्ड द्वारा विहित की जाए, एक वर्ष में 11 दिन के सर्वतोन्तक अवकाश का हकदार होगा, जिसमें बार्ड द्वारा बन्द अवकाश दिनों के रूप में घोषित दिन भी होंगे जो 7 में अधिक नहीं होंगे। इस खण्ड के अधीन किया गया कोई संदाय खंड 32 के अधीन संगणित संदाय के अतिरिक्त होगा।”;

(9) खण्ड 45 में, उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

“(3) अम प्रधिकारी, उपखण्ड (1) या (2) के अधीन किसी भी मायने पर विवार करेगा और यदि प्रारम्भिक अन्वेषण के पश्चात तथा उस कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात

उसका यह समाधान हो जाना है कि रजिस्ट्रीकूट डाक कर्मकार यथापूर्वोन्न किसी विधिपूर्ण आदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश पारित करेगा कि उस रजिस्ट्रीकूट डाक कर्मकार को खण्ड 44 के अधीन उतनी अवधि के लिए संदाय नहीं किया जाएगा जितनी अम प्रधिकारी उचित समझे।”;

(10) खण्ड 46 में,—

(i) उपखण्ड (1) की मद (ii) की उपमद (ब) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहाँ कही वह आता है, “अधिक” शब्द रखा जाएगा।

(ii) उपखण्ड (5) में मद (ग) के पश्चात निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थातः—

“(ग) उसके बेतन में कटीती करेगा और/या उसे निम्नतर प्रवर्ग में प्रत्यावर्तित कर देगा;”।

[का० सं० एल डी जी / 36 / 81-एल 4]

बी० शंकरालिगम, उप सचिव

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 227.—Whereas certain draft scheme to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 2317-19 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 19th June, 1982 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2246 dated the 29th May, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 5th July, 1982;

And whereas no objections and suggestions have been received from the Public on the said draft scheme by the Government of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965; namely :—

1. Short title and commencement.—This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1982.

2. In the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965,

(1) for clause 6, the following clause shall be substituted, namely :—

“6. Terms and conditions of service and appointment of officers and other staff.

(1) The Board may prescribe the terms and conditions of service including those of salaries and allowances, as it may deem fit, in respect of officers and other members of staff :

Provided that no post the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be created by the Board except with the previous approval of the Central Government.

(2) The appointment of officers and other members of staff shall be made by the Chairman except as otherwise provided for elsewhere in the Scheme :

Provided that no appointment to posts the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be made by the Chairman except with the previous approval of the Central Government:

Provided further that the approval of the Central Government shall not be necessary to any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than one month."

(2) in clause 8,

(a) sub-clauses (a), (b), (c) and (k) shall be deleted.

(b) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(1) subject to the provision of clause 6, sanction to creation of posts;"

(3) in clause 10, in sub-clause (1),

(a) for items (a) and (b) the following item shall be substituted, namely :—

"(a) to fix the number of workers under various categories and to increase or decrease the number of workers in any category on the Register from time to time as may be necessary after a periodical review of Registers and anticipated requirements with the previous approval of the Central Government;

(b) to sanction the temporary registration of a specified number of workers in any category for a specified period;"

(4) after clause 17, the following new clause shall be inserted, namely :—

17A. Interchangeability.—(a) The Chairman shall have power to deploy surplus workers in a category, to the category wherein there is a shortage of workers, subject to the condition that such deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from the past service;

Note.—If the category of Scheme in which there is a shortage carries lower wage or benefit, transfer will be made on the basis of seniority, junior-most person being transferred and the wages and benefits being enjoyed by them protected as personal to them.

(b) The Chairman shall also have the power to deploy any surplus worker employed under the Mormugao Port Trust in a category in which there is a shortage subject to the condition that deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from past service;

(5) in clause 18,

(i) for the word "Board" wherever it occurs, the word "Chairman" shall be substituted.

(ii) after sub-clause (1) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(1A) The Chairman shall periodically review the number of workers required in each category and shall take suitable action to adjust the number with the approval of the Central Government."

(6) in clause 19,

(i) in sub-clause (3) for the word "Board", the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) for sub-clause (4) the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(4) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis, in any category in which dock workers have already been registered under the scheme shall be done from amongst the

workers registered with the local Employment Exchange. If, however, there is a surplus in any category of workers employed by the Mormugao Port Trust, such surplus workers may be transferred and registered under this Scheme. After the transfer, if the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition, direct recruitment may be made after absorbing suitable men from the Employment Exchange register."

(7) for clause 35, the following shall be substituted, namely :—

"35. Disappointment Money.—Where a worker in the reserve pool presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed, he shall be entitled to full time rate wages, subject to the condition that he is available throughout the shift and accepts alternative employment if provided."

(8) for clause 36, the following shall be substituted, namely :—

"36 Holidays.—Each worker shall be entitled in a year to 11 holidays with pay at such rates as may be prescribed by the Board including all such days which shall not exceed 7 in a year as are declared by the Board as closed holidays. Any payment under this clause shall be exclusive of payment calculated under clause 32.

(9) in clause 45, for sub-clause (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) The Labour Officer shall consider any matter under sub-clause (1) or (2) and if, after preliminary investigation and after giving reasonable opportunity to the worker of being heard, he is satisfied that the registered dock worker has failed to comply with a lawful order as aforesaid, pass an order that the registered dock worker shall not be paid under clause 44 for such period as Labour Officer thinks fit."

(10) In clause 46,

(i) in sub-clause (ii)(b), for the word 'Board' wherever it occurs, the word 'Chairman' shall be substituted.

(ii) in sub-clause (5), after item (c), the following shall be substituted, namely :—

"(ca) effect reduction in his pay and/or revert him to lower category."

[F. No. LDG/36/81-LJV]
V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1982

का० प्रा० 228.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के श्रद्धीय भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 दिसम्बर, 81 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3353 तारीख 24 नवम्बर, 1981 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 1010.00 एकड़ (लगभग) या 408.72 हेक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वीक्षण करने के अपने आवश्यकीय की सूचना दी थी ;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अधिनियम है;

अतः, श्रीर केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (प्रजन श्रीर विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित 1010.00 एकड़ (लगभग) या 408.72 हैक्टर (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पणि-1. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण, उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कॉलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पणि-2. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन श्रीर विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है—

8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितवद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के श्रथत्वतर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है श्रीर ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति का नहीं करना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी श्रीर सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा मुनावाई का अवसर देगा श्रीर ऐसा सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् श्रीर ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपना सिफारिशों श्रीर उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अधिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितवद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हक्कदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

टिप्पणि-3. केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

उरी मेरी ब्लाक विस्तार—1 (बलरामपुर)

(दक्षिणी करमपुरा कोयला क्षेत्र)

जिला हजारीबाग (बिहार)

झाइंग सं० राजस्व 36/82

तारीख ३-५-१९८२

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि वर्णित की गई है)

सभी अधिकार

| क्रम सं० | ग्राम | थाना | थाना सं० | जिला | क्षेत्र | टिप्पणिया |
|------------|-----------|------|----------|--------|---------|-----------|
| 1. उरीमेरी | बरका गांव | 155 | हजारीबाग | 610.01 | भाग | |
| 2. जरजरा | बरका गांव | 156 | हजारीबाग | 399.99 | भाग | |

| | | |
|-------------|---|---------------|
| कुल क्षेत्र | — | 1010.00 |
| या | | एकड़ (लगभग) |
| | | 408.72 |
| | | हैक्टर (लगभग) |

ग्राम उरीमेरी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक

ग्राम जरजरा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक—
सीमा वर्णन :

क-ख रेखा ग्राम उरीमेरी में प्लाट संख्यांक 788, 790, 789, 791 और 802 से होकर जाती है [जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जित और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित उरीमेरी की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है] और बिन्दु 'क' पर मिलती है।

ख-ग रेखा ग्राम उरीमेरी में प्लाट संख्यांक 802, 521, 439 से होकर प्लाट संख्यांक 438 की उत्तरी, सीमा के साथ साथ प्लाट संख्यांक 313 से होकर फिर प्लाट संख्यांक 134, 146 की उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लाट संख्यांक 148, 162, 163 160, 158, 181, 194, 196, 195, 281, 280, 287, 288, 272, 620, 544, 546, 551, 552, 557, 558, 563, 562, 644, 645, 643, 646, 732 और 755 से होकर जाती है [जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जित और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित उरीमेरी ब्लाक की भागतः सम्मिलित सीमा बनाती है] और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ रेखा ग्राम उरीमेरी में दामोदर नदी के भागतः बाएँ किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।

घ-ड रेखा ग्राम उरीमेरी और गरमुला की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'ड' पर मिलती है।

ड-च रेखा ग्राम जरजरा और गरमुला की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'च' पर मिलती है।

च-छ रेखा ग्राम जरजरा के प्लाट संख्यांक 1060, 947, 951, 1059, 1061, 1056, 1059, 972, 1081, 1048, 1031, 1050, 1031, 200, 199, 88, 199 और 200 से होकर प्लाट संख्यांक 339 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।

छ-ज-फ रेखा ग्राम जरजरा में प्लाट संख्यांक 339, 196, 198, 89, 64, 65, 71, 78, 77, 78, 71 और 70 से होकर जाती है और बिन्दु 'झ' पर मिलती है।

झ-झ रेखा ग्राम जरजरा और पोटांगा की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु 'झ' पर मिलती है।

ज-क रेखा ग्राम उरीमेरी और पोटांगा की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा० सं० 19/53/82-सी० एल०]
स्वर्ण सिंह, अध्यक्ष सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 26th October, 1982

S.O. 228.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3353 dated the 24th November, 1981, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 12th December, 1981, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 1010.00 acres (approximately) or 408.72 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 1010.00 acres (approximately) or 408.72 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1.—The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957), which provides as follows:

8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the Notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any right in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act".

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

Drg. No. Rev/36/82 dated 3-5-1982
(showing lands to be acquired).

Urimari Block Extension-I (Balrampur)
(South Karanpura Coalfield).
Dist. Hazaribagh (Bihar)

All Rights

| Serial No. | Village | Tank | Thana No. | District | Area | Remarks |
|--------------|---------|----------|-----------|------------|---------------------------------|---------|
| 1. | Urimari | Barkagan | 155 | Hazaribagh | 610.01 | Part |
| 2. | Jarjara | Barkagan | 156 | " | 399.99 | " |
| Total area : | | | | | 1010.00 Acres (approximately) | |
| or | | | | | 408.72 Hectares (approximately) | |

Plot numbers to be acquired in village Urimari :

1 to 133, 148 (part), 149 to 157, 158(part), 159, 160(part), 161, 162(part), 163(part), 181(part), 194(part), 195(part), 196(part), 197 to 271, 272(part), 273 to 279, 280(part), 281 (part), 287 (part), 288(part), 313 (part), 439(part), 440 to 520, 521(part), 522, 544(part), 545, 546(part), 547 to 550, 551(part), 552(part), 554 to 556; 557(part), 558(part), 561, 562(part), 563(part), 564 to 619, 620(part), 621 to 642, 643(part), 644(part), 645(part), 646(part), 732(part), 733 to 751, 753, 754, 755(part), 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 780 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788(part), 789(part), 790(part), 791(part), 802(part), & 803.

Plot numbers to be acquired in village Jarjara :—

64(part), 65(part), 70(part), 71(part), 72 to 76, 77(part), 78(part), 79 to 87, 88(part), 89(part), 196(part), 197, 198(part), 199, (part), 200(part), 339(part), 947(part), 951(part), 972(part), 1031(part), 1048(part), 1050 (part), 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056 (part) 1059(part), 1060 (part), 1061(part) & 1075.

Boundary Description

- A—B line passes through plot numbers 783, 790, 789, 791 & 802 in village Urimari (which forms part common boundary of the Urimari Block acquired u/s 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 and meets at point 'B'.
- B—C line passes through plot numbers 802, 521, 439, along the northern boundary of plot number 438 through plot number 313 than along the northern boundary of plot numbers 134, 146' through plot numbers 148, 162, 163, 160, 158, 181 194, 196, 195, 281, 280' 287, 288, 272, 620, 544, 546, 551, 552, 557, 558, 563, 562, 644, 645, 643, 646, 732 & 753 village Urimari (which form part common boundary of Urimari Block acquired u/s 9(1) of the Coal Bearing Area (Acquisition & Development) Act, 1957 and meets at point 'C'.
- C—D line passes along the part left bank of Damodar River in village Urimari and meets at point 'D'.
- D—E line passes along the common boundary of villages Urimari and Garsula and meets at point 'E'.
- E—F line passes along the part common boundary of villages Jarjara & Garsula and meets at point 'F'.
- F—G line passes through plot numbers 1060, 947, 951, 1059, 1051, 1056, 1059, 972, 1031, 1048, 1031, 1050, 1031, 200, 199, 88, 199 & 200 eastern boundary of plot number 339 in village Jarjara and meets at point 'G'.
- G—H—I lines pass through plot numbers 339, 196, 198, 89, 64, 65, 71, 78, 77, 78, 71 & 70 in village Jarjara and meets at point 'I'.
- J—J line passes along the part common boundary of villages Jarjara & Potanga and meets at point 'I'.
- J—A line passes along the part common boundary of villages Urimari & Potanga and meets at starting point 'A'.

[No. 19/53/82-CL]

SWARAN SINGH, Under Secy.

के स्थान पर "रेखांक सं० डब्ल्यू सी प्ला/
पी एल जी/सी-1(ई)/III/जे० आर०/197-
0881 क" पढ़ें।

- (2) बीसापुर ग्राम में अर्जित किए गए टाट संख्यांक में :—
- (क) "259 (भाग) से 261 तक, 262/2" के स्थान पर "259 (भाग) से 261 (भाग) तक 262/1, 262/2" पढ़ें।
- (ख) "277 से 291 ए बी तक" के स्थान पर "277 से 291 तक" पढ़ें।
- (3) ग्राम बल्लारपुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में :—
- (क) "1X1" के स्थान पर "1/1" पढ़ें।

का० आ० 229.—भारत के राजपत्र तारीख 19 जून,
1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 2302-
2307 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय
(कोयला विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2241
तारीख 4 जून, 1982 में :—

पृष्ठ 2303 पर

- (1) अनुसूची "क" में "रेखांक सं० डब्ल्यू सी एल/
पी एल जी सी-1(ई)/III/जे आर 197-088/क"

- (ख) “3/1, 3/3 के स्थान पर “3/1 से 3/3 तक” पढ़ें।
- (ग) “16/17 (भाग)” के स्थान पर “16/1, 17 (भाग)” पढ़ें।
- (घ) “74, 85, 76/1” के स्थान पर “74, 75, 76/1” पढ़ें।
- (१) “ग्राम कोडली में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक” के स्थान पर “ग्राम कडोली में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक” पढ़ें।
- (२) ग्राम बाबापुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में “59, 61 से 66 तक” के स्थान पर “59, 60 (भाग), 61 से 66 तक” पढ़ें।

पृष्ठ 2304 पर—

- (१) ग्राम गोरी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में “62 से 63 तक” के स्थान पर “62 से 73 तक” पढ़ें।
- (२) सीमा वर्णन में :—
- (क) रेखा “छ—ज—झ में” बल्लपूर” के स्थान पर “ग्राम बल्लारपूर” पढ़ें।
- (ख) रेखा “झ—ट—ट1—ठ—झ” के स्थान पर भ—ट—ट1—ठ—ड” पढ़ें।
- (ग) रेखा “त—थ—थ—द—ध” के स्थान पर “त—थ थ1—द—ध” पढ़ें।
- (घ) रेखा “ध—ध1—क” के स्थान पर “ध—ध1—क” पढ़ें।
- (३) अनुसूची “ख” में :—
- (१) “(रेखांक सं० डब्ल्यू सी० एल०/पी० एल० जी०/ सी०-१(ई)/111/ जे० आर०/197-088/ख)” के स्थान पर “(रेखांक सं० डब्ल्यू० सी० एल०/ पी० एल० जी०/सी०-१(ई)/111/जे० आर०/197- 0881 ख” पढ़ें।
- (२) क्रम सं० २ में ग्राम का नाम स्तंभ के नीचे “बहमानी”— के स्थान पर “बाहमनी” पढ़ें और जहाँ कहीं भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है उसके स्थान पर “बाहमनी” पढ़ें।

पृष्ठ 2305 पर

- (१) कुल क्षेत्र में “2331.46 एकड़” के स्थान पर “2331.48 एकड़” पढ़ें।
- (२) बल्लारपूर ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में :
- (क) (199/1 जे० 199/5 तक” के स्थान पर “199/1 से 199/5 तक” पढ़ें।

- (ख) “201/1 202 201/3 (भाग” के स्थान पर “201/1, 201/2 201/3 (भाग” पढ़ें।
- (३) बाहमणी ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में “275ए, 274 वी 276 से 277” के स्थान पर “275 ए, 275 वी, 276 और 277” पढ़ें।
- (४) दुधुली ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में “86 ए, 68 वी” के स्थान पर “68 ए, 68 वी” पढ़ें।
- (५) दहेली ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में :
- (क) “157 से 147 तक” के स्थान पर “137” से 147 तक” पढ़ें।
- (ख) 159 ए” के स्थान पर “158 ए” पढ़ें।
- (६) सीमा वर्णन में :
- (क) प—फ रेखा में “करवडेन नाले” के स्थान पर “काखडेन नाले” पढ़ें।
- (ख) फ—व२ रेखा में “दहेली और दुधुली ग्रामों के स्थान पर “दहेली और दुधुला ग्रामों में” पढ़ें।
- (क) रेखा भ—म—प—य१—न में :—
- “201/1, 201/2, 201/3” के स्थान पर “202/1 202/2, 201/3” और “201/11, 2041/12, 203/1” के स्थान पर “201/11, 201/12, 203” पढ़ें।

[सं० 19/117/81-सी एल]
पी० सरकार, निदेशक

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd December, 1982

S.O. 229.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2241 dated 4th June, 1982 published at pages 2305—2307 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th June, 1982, at page 2307,—

- (1) (a) in column 1, in line 13, for “36”, read “37”.
(b) in column 2, line 5, for “Manoi” read “Manoli”;
- (2) in schedule “B”,
- (a) against serial number 1, under the column “Govt. land”, for “40.2” read “4.02”.
(b) under the heading “Plot numbers acquired in village Daheli”,—
(i) for “49B” read “149B”.
(ii) for “171A, 172B” read “171A, 171B, 172A, 172B”.

[No. 19/117/81-CL]

का० आ० 233.—चुकि रामवरप्पाडु टेलीफोन एक्स-
चेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में बदली किए जाने के लिए
एक संवादाधारण सूचना जैसा कि भारतीय तार नियमाबलों
1951 के नियम 434(iii) (बोधी) में विभिन्न है, राम-
वरप्पाडु के रामाचार पटवों में गिरलांगशी थीं और जिन लोगों
पर इसका प्रभाव पड़ने का संभावना था, उनमें कहा गया था
कि यदि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति हो वा उन्हें कोई
सुझाव हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से
30 दिनों के भीतर यउनी आपत्ति/सुझाव भेज दें;

ओर यहाँ उक्त सूचना जर्वेनाधारण की जनकारी के
लिए 31-7-82 के ईडिटरियल्स प्रेस के विजयवाडा संस्करण
तथा 31-7-82 के प्राप्त योगी के विजयवाडा संस्करण
प्रकाशित थी;

और चुकि उक्त सूचना उत्तर में जनसाधारण से कोई
आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त नहीं हुए,

अतः यदि उक्त नियमाबलों के नियम 434 (iii) (बोधी)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक तार महानिदेशक
ने घोषित किया है कि नारोब 30-11-82 से रामवर-
प्पाडु का स्थानीय संशोधन शीर्ष इत प्रकार होगा :

रामवरप्पाडु टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

रामवरप्पाडु का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो रामवरप्पाडु
टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० की अवधि तूरे के भीतर
पड़ता है। किन्तु यह सीमा उत्तर में विजयवाडा-मुर्खानाड़ा,
पश्चिम में विजयवाडा नगरपालिका की नई सीमा और दक्षिण
में दानपा रोड और कनूर के सरपन्कलों रोड तक सेमिन होगी।
टिण्ठों जो उपभोक्ता गुंडाला क्षेत्र में नवनिर्धारित क्षेत्र
जिसे रामवरप्पाडु एक्सचेंज से सेवा प्रदान को जा
रही है, के अंतर्गत आते हैं वे उसी एक्सचेंज प्रणाली
द्वारा स्थानीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बताए गए

उक्त सेवा प्राप्त करते रहेंगे जब तो कि वे शिवप्र-
वाडा टेलीफोन प्रणाली के एक्सचेंज को अंतरित
नहीं किए जाते।

[रा० 3-2/74-PH ० प्र० बो० (पी०य००)]
ए० बो० रामामूर्ति, निदेशक, फोन(ई)

S.O. 233.—Whereas a public notice for revising the local area of Ramavarappadu Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Ramavarappadu, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 30-11-82 the revised local area of Ramavarappadu shall be as under :

Ramavarappadu Telephone Exchange System

The Local area of Ramavarappadu shall cover an area falling within 5 K.M. radial distance from the Ramavarappadu Telephone Exchange.

Provided that this limit shall be restricted to Vijayawada—Mustabad Railway line in the north, new boundary of Vijayawada Municipality in the west and Danka Road and Kannur-Kesarapalli Road in the South.

Note :—

Subscribers falling in the newly defined area in Gundala area which are now being served by Ramavarappadu Exchange shall continue to be served by that exchange system as its local area subscribers till they are transferred to the exchanges in the Vijayawada Telephone System.

[No. 3-2/74-PH (P)]
M. B. RAMAMURTHY, Director, Phones (E)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर, 1982

का० आ० 234:—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, निर्बन्धण और असीज) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ
पठित नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ब) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक-तार) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 620 तारीख
20 फरवरी, 1957 का नियमित और संशोधन करते हैं, अध्यत् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :—

(क) भाग 2, माधारण कन्द्रोय सेवा, ममूङ “ब” में, “डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन्द्र”, शोर्पे के नीचे की प्रविलियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविलिया रखी जाएंगी, अर्थात् :-

| पद का वर्णन | नियुक्त प्राधिकारी | शास्ति प्रधिरोपित करने के लिए गक्षम प्राधिकारी और वे शास्तिर्यां जो वह प्रधिरोपित कर सकता है (नियम 13 की मद सङ्घायों के पत्तिनिवेश में | श्रीम प्राधिकारी |
|---|--|--|--|
| | | प्राधिकारी | शास्तिर्यां |
| डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन्द्र उच्च और निम्न चयन श्रेणियों में लिपिकवर्गीय कर्मचारियों उच्च और निम्न चयन श्रेणियों में अनु- देशक डाक घरों और रेल डाक में सा- केन्द्रीयों को और बहायक अधी- कारों के काउरो, में अनुदेशक; तार यातायात के तार मास्टरों- या सहायक अधीकारों के काउर में तार अनुदेशक, निवामीय चिकित्सा प्रधिकारी, कलाकार हिंजाइनर | प्रधानाचार्य/निदेशक प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक प्रशिक्षण) (डाक प्रशिक्षण) (डाक प्रशिक्षण) | सभी डाक-तार निदेशालय डाक तार निदेशालय | उपमहानिदेशक (डाक) डाक-तार निदेशालय |
| लिपिकीय काउरो में सचिवीय कर्म- चारीवृन्द प्रधान अनुदेशक; शारी- रिक प्रशिक्षण पन्दुदेशक | उपप्रधानाचार्य लिपिकवर्गीय प्रशासनिक प्रधिकारी | सभी (1) से (4) उपप्रधानाचार्य/निदेशक (डाक प्रशिक्षण), डाक-तार निदेशालय | प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक प्रशिक्षण) |
| पालिक; मोटर चालक, कम्पाउंडर फाल्कार | उपप्रधानाचार्य प्रशासनिक प्रधिकारी | सभी (1) से (4) उपप्रधानाचार्य प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय | प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) |
| प्रशिक्षण के लिए व तिनियुक्ति विभागीय प्रधिकारी सभी अन्य पद | -- उपप्रधानाचार्य प्रशासनिक प्रधिकारी | उपप्रधानाचार्य (1) से (4) उपप्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय उपप्रधानाचार्य (1) से (4) उपप्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय उपप्रधानाचार्य (1) से (4) उपप्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय | प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय |

(ख) भाग 3- - माधारण केन्द्रीय सेवा ममूङ “ब” में, शोर्पे 3 “डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन्द्र” के नीचे की प्रविलियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविलिया रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| सभी पद प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त विभागीय प्रधिकारी | प्रशासनिक प्रधिकारी प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी | सभी उपप्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य |
|--|---|---|
| | -- प्रशासनिक प्रधिकारी | (1) से (4) |

New Delhi, the 18th. December, 1982

S.O. 224.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of Sub-rule (2) of rule 12, and Sub-rule (1) of rule 24, read with rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs) No. SRO 620, dated the 28th February 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification :—

(a) In Part II—General Central Service, Group 'C' for the entries under the heading "Posts and Telegraphs Training Centre and Postal Training Centre", the following entries shall be substituted, namely :—

| Description of Post | Appointing authority | Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 13). | | Appellate authority |
|--|---|--|-------------|---|
| | | Authority | Penalties | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Posts and Telegraphs Training Centre and Postal Training Centre | | | | |
| (1) Ministerial staff in Higher and Lower Selection grades; Instructors in Higher and Lower Selection grades; Instructors in the cadre of Inspectors and Assistant Superintendents of Post Offices and Railway Mail Services; Telegraph Instructors in the cadre of Telegraph Masters or Assistant Superintendent of Telegraph Traffic; Resident Medical Officer, Artist Designer. | Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate. | Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate. | All | Deputy Director General (Postal) Posts and Telegraphs Directorate. |
| Ministerial staff in clerical cadres; Principal Instructor; Physical Training Instructor. | Vice-Principal | Vice-Principal | (i) to (iv) | Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate. |
| Mechanics; Motor Driver; Compounder; Carpenter. | Vice-Principal | Vice-Principal | All | Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate. |
| Departmental Officials deputed for training. | — | Administrative Officer. | (i) to (iv) | Vice-Principal. |
| All other posts. | Vice-Principal | Vice-Principal | All | Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate. |
| | | Administrative Officer. | (i) to (iv) | Vice-Principal. |

(b) In Part III—General Central Services Group 'D' for the entries under the heading "Posts and Telegraphs Training Centre and Postal Training Centre", the following entries shall be substituted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| All Posts | Administrative Officer | Administrative Officer | All | Vice-Principal. |
| Departmental Officials deputed for training. | — | Administrative Officer. | (i) to (iv) | Vice-Principal. |

[No. 154/5/81-Vig. III]

Sd/ Illegible

Assistant Director General (Vig. B)/

रेल संचालन

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली 7 दिसंबर, 1982

का० आ० 235.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के दियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) उत्तर रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहाँ कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है:—

उत्तर रेलवे :

1. सहायक अधिकारी का कार्यालय, वाराणसी।
2. स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय, वाराणसी।
3. सहायक अधिकारी का कार्यालय, फैजाबाद।
4. सहायक अधिकारी का कार्यालय, प्रयाग।
5. मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, लालगढ़, बीकानेर।
6. मंडल यातायात अधीक्षक (अब क्षेत्रीय अधीक्षक) कार्यालय, दिल्ली क्षेत्रसं रोड।
7. मंडल सहायक सुधा अधिकारी का कार्यालय, बीकानेर।
8. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज का कार्यालय, बीकानेर।
9. सहायक अधिकारी का कार्यालय, बीकानेर।
10. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज (परिवार नियोजन) का कार्यालय, लालगढ़।
11. सहायक अधिकारी का कार्यालय, रत्नगढ़।
12. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, रत्नगढ़।
13. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, चुरु।
14. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, साड़ुलपुर।
15. सहायक मंडल चिकित्सा इंचार्ज का कार्यालय, रेवाड़।
16. सहायक परिचालन अधीक्षक का कार्यालय, रेवाड़।
17. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय, रेवाड़।
18. सहायक अधिकारी का कार्यालय, रेवाड़।
19. सहायक अधीक्षक का कार्यालय, दिल्ली क्षेत्रसं रोड।
20. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय, दिल्ली क्षेत्रसं रोड।
21. सहायक चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, दिल्ली सराय रोहिल्ला।
22. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, हिंतार।
23. सहायक अधिकारी का कार्यालय, सिरसा।
24. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, सिरसा।
25. सहायक परिचालन अधीक्षक, निर्भंवण कार्यालय, मानगढ़।

26. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, हनुमानगढ़।
27. सहायक अधिकारी-1 का कार्यालय, हनुमानगढ़।
28. उद्यापर अधिकारी-2 का कार्यालय, हनुमानगढ़।
29. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, सूखंतगढ़।
30. सहायक अधिकारी का कार्यालय, लोहार।

[स० हिन्दौ-82/रा०आ०-1/12/3]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 7th December, 1982

S.O. 235.—In pursuance of sub-rule (2) and (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the undermentioned offices of the Northern Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi :—

Northern Railway :

1. Office of the Assistant Engineer, Varanasi.
2. Office of the Station Superintendent, Varanasi.
3. Office of the Assistant Engineer, Faizabad.
4. Office of the Assistant Engineer, Prayag.
5. Office of the Divisional Medical Officer, Laigarh, Bikaner.
6. Office of the Divisional Traffic Superintendent, Delhi, Queens Road (Now Area Superintendent).
7. Office of the Assistant Divisional Security Officer, Bikaner.
8. Office of the Assistant Divisional Medical Officer Incharge, Bikaner.
9. Office of the Assistant Engineer, Bikaner.
10. Office of the Assistant Divisional Medical Officer Incharge (F.P.), Lalgarh.
11. Office of the Assistant Engineer, Ratangarh.
12. Office of Assistant Divisional Medical Officer, Ratangarh.
13. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Churu.
14. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Sadulpur.
15. Office of the Assistant Divisional Medical Incharge, Rewari.
16. Office of the Assistant Operating Superintendent, Rewari.
17. Office of the Assistant Traffic Superintendent, Rewari.
18. Office of the Assistant Engineer, Rewari.
19. Office of the Assistant Superintendent, Delhi Queens Road.
20. Office of the Assistant Traffic Superintendent, Delhi Queens Road.
21. Office of the Assistant Medical Officer, Delhi Sarai Rohilla.
22. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Hissar.
23. Office of the Assistant Engineer, Sisra.
24. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Sisra.

25. Office of the Assistant operating Superintendent, Central Office, Hanumangarh.
26. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Hanumangarh.
27. Office of the Assistant Engineer I, Hanumangarh.
28. Office of the Assistant Engineer II, Hanumangarh.
29. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Suratgarh.
30. Office of the Assistant Engineer, Loharu.

[No. Hindi-82/OL-L/12[3]

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1982

का०आ० 236 —सरकारी स्थान (प्रशासिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार रेल मंत्रालय को दि० 29 नवम्बर, 1978 की अधिसूचना सा० आ० संख्या 3642, दि० 17 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना स० आ० संख्या 2645 तथा दि० 23 जुलाई 1981 की सा० आ० संख्या 2151 के अधिक्रमण में राष्ट्रपति, उक्त अधिसूचना के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों के प्रतिरक्षण, एतद्वारा नोचे दो गई तालिका के कालम 1 में उलिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजान् अधिकारों हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करते हैं और आगे यह निर्देश देतो हैं। उक्त अधिकारों सम्पदा अधिकारियों को उक्त अधिनियम के द्वारा यथा अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग तथा उा पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन उक्त तालिका के कालम (2) में तदनुसूची प्रविष्ट में विनियिष्ट सरकारी स्थानों के सबध में अपने अधिकार को स्थानीय सामाज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तालिका

अधिकारियों का नाम सरकारी स्थानों को कोटिया तथा अधिकारी को स्थानीय सीमाओं ।

1

2

1. मंडल रेल प्रबंधक, मध्य उत्तर के अपने-अपने अधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत रेलवे, बम्बई, भुमावल, नागपुर, जग्नपुर, झाशो और शोलापुर
2. मंडल इजोनियर, पूर्व उत्तर के अपने-अपने अधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत रेलवे, बांद्रा, आसनसोल धनबाद, दानापुर, सिलाल-दह और मुगालसहित।

1 2

3. मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर उत्तर के अपने-अपने अधिकार रेलवे, इलाहाबाद, फिरोज नो स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत पुर, जोधपुर, नावनक, गंत स्थित उत्तर रेलवे के मुशाबाद, इति रिल्या प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। और धोकाने।
4. मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर उत्तर के अपने-अपने अधिकार रेलवे इज्जत नगर, लखनऊ को स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वाराणसी, ममतापुर तथा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।
5. बर्टिडम डॉन इजोनियर, पूर्वोत्तर मामा रेलवे, कटिहार, अलीपुर द्वारा जक्षन और लार्डिङ। उत्तर के अपने-अपने अधिकार का स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पूर्वोत्तर सामा रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में स्थित परिसर।
6. गङ्गा रेल प्रबंधक, दक्षिण उत्तर के अपने-अपने अधिकार मध्य रेलवे मद्रास, मैसूर, पालघाट, मदुरै, निष्ठाचारा-पल्ला श्रीर विवेन्द्रम। उत्तर के अपने-अपने अधिकार का स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित दक्षिण रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में स्थित परिसर।
7. मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण उत्तर के अपने-अपने अधिकार मध्य रेलवे, नाइन लाइन हैदरगाबाद गंत स्थित दक्षिण-मध्य (मोटर लाइन) विजयदाह रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण क्षेत्रों और गुल कर।
8. मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम उत्तर के अपने-अपने अधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत रेलवे, बरबई बड़ोदरा, रत्नाम, काटा, जगपुर, अजमेर तथा नाथवार। स्थित पश्चिम रेलवे के प्रशासनिक नियंत्रण में परिसर।
9. पश्चिम रेलवे के बम्बई, उत्तर के पर्याप्त अधिकार वडोदरा जगपुर नाजकोट तथा को स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत भावनगर मंडल कर्निल स्थित पश्चिम रेलवे के प्रशासन इजोनियर और मंडल सनिक नियंत्रण में परिसर। इजोनियर।

[फाइल नं० 82/उद्यू 2/14/35]

New Delhi, the 11th December 1982

S.O. 236.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971) and in supersession of Government of

India, Ministry of Railways (Railway B, U) Notification S.O. No. 3642 dated 29th November, 1978, Section No. S.O. No. 2645 dated the 17th September 1981, S.O. No. 2151 dated 23rd July, 1981, the President hereby approves the officers mentioned in column 1 of the Table below, being Gazetted Officers of the Government to be Estate Officers for the purpose of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act with the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

| Designation of the officers | Categories of public premises and local limits of jurisdiction |
|---|--|
| 1 | 2 |
| 1. Divisional Railway Managers Central Railway Bombay, Bhusawal, Nagpur, Jabalpur, Jhansi and Sholapur. | Premises under the administrative control of the Central Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 2. Divisional Engineers Eastern Railway, Howrah, Asansol, Dhanbad, Danapur, Sealdah and Mughalsarai. | Premises under the administrative control of the Eastern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 3. Divisional Railway Managers, Northern Railway, Allahabad, Ferozpur, Jodhpur, Lucknow, Moradabad, New Delhi & Bikaner | Premises under the administrative control of the Northern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 4. Divisional Railway Managers, North Eastern Railway, Itanagar, Lucknow, Varanasi, Samastipur and Sonarpur. | Premises under the administrative control of the North Eastern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 5. Senior Divisional Engineers, Northeast Frontier Railway, Katihar Alipurduar Junction and Lumding. | Premises under the administrative control of the Northeast Frontier Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 6. Divisional Railway Managers, Southern Railway, Madras, Mysore, Palghat, Madurai, Tiruchirapalli and Trivandrum. | Premises under the administrative control of the Southern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |

- | | |
|---|---|
| 7. Divisional Railway Managers, South Central Railway Secunderabad (B.G.), Hyderabad (M.G.), Vijayawada, Hubli and Guntakal. | Premises under the administrative control of the South Central Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 8. Divisional Railway Managers, Western Railway, Bombay, Vadodara, Ratlam, Kota, Jaipur, Ajmer, and Bhavnagar. | Premises under the administrative control of the Western Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 9. Senior Divisional Engineers and Divisional Engineers of Bombay, Vadodara, Jaipur, Rajkot and Bhavnagar Divisions of Western Railway. | Premises under the administrative control of the Western Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |

[File No. 82/W2/14/35]

मुद्रित पत्र

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का० आ० 237.—इस मंस्तालय की 3-11-82 की सम-
संख्या० अधिभूतना की तीसरी/चौथी लाइन से 'यांत्रिक' शब्द
को निकाल दे।

[सं० हिन्दी-82/रा०भा० 1/12/3]

हिम्मत सिंह, सचिव,

रेलवे बोर्ड

एवं पदेन संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th December, 1982

S.O. 237.—The word "Mechanical" may please be deleted from 3rd/4th line of this Ministry's notification of even number dated 3rd November, 1982.

[No. Hindi-82/OL-I/12/3]

HIMMAT SINGH, Secy.
Railway Board,
& Ex. officio Jt. Secy.

